



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 14, 2014/फाल्गुन 23, 1935

No. 76]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 14, 2014/PHALGUNA 23, 1935

लोक सभा

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2014

संख्या 29/2/सी1/2014.—5 मार्च, 2014 के लोक सभा समाचार भाग-2 में प्रकाशित निम्नलिखित पैरा एतद्द्वारा सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है :—

“संख्या 6211

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों
का

लिंग-तटस्थ बनाया जाना

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (14वां संस्करण) के नियम 331 के उप-नियम (3) के अनुसरण में लोक सभा द्वारा यथा-अनुमोदित लोक सभा के लिंग-तटस्थ प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये नियम 13 फरवरी, 2014 से प्रभावी समझे जाएंगे।

अध्याय 1

संक्षिप्त नाम और परिभाषाएं

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम ‘लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम’ है।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

“लोक सभा समाचार” का तात्पर्य सभा के समाचार से है, जिसमें (क) सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख; (ख) सभा के कार्य के बारे में या उससे

संबंधित किसी वि-य पर या अन्य वि-य पर, जो अध्यक्ष की राय में उसमें सम्मिलित किया जा सके, जानकारी, और (ग) संसदीय समितियों के बारे में जानकारी अंतर्वि-ट हो;

‘संविधान’ का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

‘परिषद्’ का तात्पर्य राज्य-परिषद् (राज्य सभा) से है;

‘वित्त मंत्री’ के अंतर्गत कोई भी मंत्री है;

‘गजट’ का तात्पर्य भारत के राजपत्र से है;

‘सभा’ का तात्पर्य लोक सभा से है;

‘सदनों’ का तात्पर्य राज्य सभा तथा लोक सभा से है;

‘सभा का नेता’ का तात्पर्य प्रधान मंत्री से, यदि प्रधान मंत्री सभा का सदस्य हो, अथवा उस मंत्री से है जो सभा का सदस्य है और सभा के नेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो;

‘लॉबी’ का तात्पर्य उस बंद बरामदे से है जो सभा भवन के बिल्कुल सन्निकट है और जो सभा के भवन के साथ ही समाप्त होता है।

‘लोक सभा सचिवालय/सचिवालय’ से तात्पर्य दिल्ली स्थित लोक सभा सचिवालय और उस समय अध्यक्ष के लिए अथवा उसके अधिकार के अंतर्गत दिल्ली के बाहर स्थापित किसी शिविर कार्यालय से और उसे मिलाकर है।

‘सदस्य’ का तात्पर्य लोक सभा के सदस्य से है;

‘विधेयक का प्रभावी’ सदस्य का तात्पर्य उस सदस्य से है जिसने विधेयक पुरःस्थापित किया है और किसी सरकारी विधेयक की अवस्था में किसी मंत्री से है;

‘मंत्री’ का तात्पर्य मंत्रिपरि-द के किसी सदस्य (जिसमें मंत्रिमंडल का कोई सदस्य भी शामिल है,)¹ राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव से है;

(व्याख्या: संसदीय सचिव, जो सभा का सदस्य नहीं है इसकी बैठकों में भाग लेने का हकदार नहीं है।)²

‘संसदीय समिति’ का तात्पर्य उस समिति से है जिसे सभा नियुक्त या निर्वाचित करे या जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाए और जो अध्यक्ष के निर्देश के अंतर्गत काम करे और अपना प्रतिवेदन सभा या अध्यक्ष को दे और जिसके सचिवालय की व्यवस्था लोक सभा सचिवालय द्वारा की जाए;

‘सभा के परिसर’ का तात्पर्य सभा भवन, लॉबी, दीर्घाओं और उनको मिलाकर ऐसे अन्य स्थानों से है जिनका अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उल्लेख किया जाए;

‘गैर-सरकारी सदस्य’ का तात्पर्य मंत्री के अतिरिक्त किसी सदस्य से है;

‘महासचिव’ का तात्पर्य लोक सभा के महासचिव से और किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो उस समय महासचिव का कार्य कर रहा हो;

‘पटल’ का तात्पर्य सभा पटल से है।

(2) संविधान और इस नियमावली में प्रयुक्त शब्दों तथा पदावलियों के अर्थ, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, वही होंगे जो उन्हें संविधान में दिए गए हैं।

अध्याय 2

सदस्यों को आमंत्रण, उनका बैठना, शपथ या प्रतिज्ञान और सदस्यों की नामावली

3. आमंत्रण.—महासचिव द्वारा सभा के सत्र के लिए तिथि तथा स्थान का उल्लेख करते हुए प्रत्येक सदस्य को आमंत्रण भेजा जाएगा :

परंतु जब सत्र अल्प सूचना पर या आपात में बुलाया जाए तो आमंत्रण प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग चाहे न भेजा जाए, किंतु सत्र की तिथि तथा स्थान की घो-णा गजट में और समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जाएगी और सदस्यों को तार द्वारा सूचना दी जा सकेगी ।

4. बैठने का क्रम.—सदस्य ऐसे क्रम में बैठेंगे जो कि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाए।

5. शपथ या प्रतिज्ञान.—ऐसे किसी सदस्य द्वारा जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 1999 के अनुसरण में पहले ही शपथ न ली गई हो या प्रतिज्ञान न किया गया, महासचिव को लिखित रूप में पूर्व सूचना देकर किसी भी दिन सभा

की बैठक के प्रारंभ अथवा सभा की बैठक के किसी अन्य समय पर, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे, ऐसा किया जा सकता है।

6. सदस्यों की नामावली.—सभा के सदस्यों की एक नामावली होगी जिस पर प्रत्येक सदस्य द्वारा अपने स्वयं के स्थान पर बैठने से पहले महासचिव के सामने हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

अध्याय 3

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा सभापति तालिका का नामनिर्देशन

7. अध्यक्ष का निर्वाचन.—(1) अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि रा-द्रुपति द्वारा नियत की जाए और महासचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजी जाएगी।

(2) इस प्रकार निश्चित तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी समय इस प्रस्ताव की कि किसी अन्य सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुना जाए, महासचिव को संबोधित लिखित रूप में सूचना दी जा सकेगी और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरे सदस्य द्वारा किया जाएगा तथा उसके साथ उस सदस्य का, जिसका नाम सूचना में प्रस्तावित किया जाए, यह कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी है:

परन्तु किसी भी सदस्य द्वारा अपने स्वयं के नाम का प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, न अपने नाम का प्रस्ताव करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा अथवा न ही एक से अधिक स्वयं के प्रस्तावों का प्रस्ताव या अनुमोदित किया जाएगा ।

[(3) कार्य सूची में, जिस सदस्य के नाम का कोई प्रस्ताव हो वह, जब तक यह नहीं कहता है/कहती है कि वह प्रस्ताव नहीं करना चाहता/चाहती, प्रस्ताव के लिए पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा/करेगी। किसी भी मामले में वह अपना कथन इस बात तक सीमित रखेगा कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करता/करती है या कि वह प्रस्तुत करना नहीं चाहता/चाहती है;]¹

(4) जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत अनुमोदित हो गए हों वे एक-एक करके उसी क्रम में रखे जाएंगे जिसमें कि वे प्रस्तुत किए गए हों और, यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो पीठासीन व्यक्ति द्वारा बाद के प्रस्तावों को रखे बिना यह घो-नित किया जाएगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्तावित सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है।

¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, 9.5.1989 पैरा 2930 द्वारा अंतःस्थापित।

² वही, जोड़ा गया।

¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, 09.05.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

8. उपाध्यक्ष का निर्वाचन.—(1) उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए और महासचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजी जाएगी।

(2) इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व-दिन के मध्याह्न से पहले किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी समय इस प्रस्ताव की कि किसी अन्य सदस्य को सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए, महासचिव को संबोधित लिखित रूप में सूचना दी जा सकेगी और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरे सदस्य द्वारा किया जाएगा तथा उसके साथ उस सदस्य का, जिसका नाम सूचना का प्रस्ताव किया जाए, यह कथन संलग्न होगा कि प्रस्तावित सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी है:

परन्तु किसी भी सदस्य द्वारा अपने स्वयं के नाम का प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, न अपने स्वयं के नाम का प्रस्ताव करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा और न ही एक से अधिक प्रस्तावों का प्रस्ताव या अनुमोदन किया जाएगा।

[(3) ऐसे किसी सदस्य द्वारा जिसके नाम में कार्य सूची में, कोई प्रस्ताव हो, जब तक कि प्रस्ताव न लाए जाने की अनिच्छा व्यक्त करने संबंधी कथन न किया जाए, प्रस्ताव लाने के लिए पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा; दोनों ही दशाओं में, सदस्य द्वारा अपना कथन प्रस्ताव लाने या प्रस्ताव न लाए जाने तक ही सीमित रखा जाएगा।²

(4) जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत अनुमोदित हो गए हों वे एक-एक करके उसी क्रम में रखे जाएंगे जिसमें कि वे प्रस्तुत किए गए हों और यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो पीठासीन व्यक्ति द्वारा बाद के प्रस्तावों को रखे बिना यह घोषित किया जाएगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्तावित सदस्य सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है/ली गई है।

9. सभापति तालिका का नाम-निर्देशन.—(1) अध्यक्ष द्वारा यथास्थिति सभा के प्रारंभ पर या समय-समय पर सदस्यों में से अधिक से अधिक दस³ सभापतियों की एक तालिका नामनिर्देशित की जाएगी जिसमें से कोई एक अध्यक्ष के या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के कहने पर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा में पीठासीन हो सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत नामनिर्देशित सभापति एक नई सभापति-तालिका नामनिर्देशित किए जाने तक पद धारण करेगा।

10. उपाध्यक्ष या पीठासीन अन्य सदस्य की शक्तियां.—उपाध्यक्ष या संविधान अथवा इस नियमावली के अन्तर्गत सभा के बैठक में पीठासीन होने के लिए सक्षम किसी अन्य सदस्य की, जब वह पीठासीन हो, वहीं शक्तियां होंगी जो कि पीठासीन होने पर अध्यक्ष की होती हैं और इन परिस्थितियों में इस नियमावली में अध्यक्ष के प्रति सब संदर्भ इस तरह पीठासीन ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति संदर्भ समझे जाएंगे।

अध्याय 4

सभा की बैठकें

11. विधिवत गठित बैठक.—सभा की बैठक तभी विधिवत गठित होगी जबकि उसमें अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य पीठासीन हो जो संविधान अथवा इस नियमावली के अंतर्गत सभा की बैठक में पीठासीन होने के लिए सक्षम हो।

12. बैठक का प्रारंभ और समाप्ति.—[जब तक अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, सभा की बैठक प्रतिदिन साधारणतया 11.00 बजे प्रारंभ होगी तथा 18.00 बजे समाप्त हो जाएगी जिसमें एक घंटे का मध्याह्न भोजनावकाश होगा जो साधारणतया 13.00 बजे से 14.00 बजे तक होगा।]¹

13. बैठकों के दिन.—सभा की बैठकें उन दिनों को होंगी जिनके प्रति अध्यक्ष द्वारा सभा के कार्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर निदेश दिया जाए।

14. $^{} (****)^2$**

15. सभा का स्थगन (और पुनः बुलाने की प्रक्रिया)।^१—(1) अध्यक्ष द्वारा वह समय निर्धारित किया जाएगा जब सभा की विशिष्ट बैठक अनिश्चितकाल के लिए या किसी दिन तक के लिए या उसी दिन के किसी समय या भाग तक के लिए स्थगित की जाएगी:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा, यदि उचित समझे, उस तिथि विशेष-या समय से पूर्व, जब तक के लिए कि सभा की बैठक स्थगित की गई हो, या सभा के अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित होने के बाद किसी भी समय, सभा की बैठक बुलाई जा सकेगी।

(2) [यदि सभा के स्थगन के बाद उप-नियम (1) के परन्तुक के अधीन सभा पुनः बुलाई जाती है तो महासचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को सत्र के अगले भाग की तिथि, समय, स्थान तथा अवधि की सूचना दी जाएगी।]⁴

अध्याय 5

रा-द्रुपति का अभिभा-ण और सभा को संदेश

16. अभिभा-ण पर चर्चा के लिए समय का नियतन.—अध्यक्ष द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अधीन

² लोक सभा समाचार भाग-दो, 9.5.1989, पैरा 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ लोक सभा समाचार भाग-दो, 4.8.1993, पैरा 2298 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, 9.5.1989, पैरा 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

² वही, लोप किया गया।

³ वही, जोड़ा गया।

⁴ वही, जोड़ा गया।

सदनों के सामने दिए गए रा-ट्रपति के अभिभा-ण में निर्दि-ट वि-यों की चर्चा के लिए, सदन-नेता के परामर्श से समय नियत किया जाएगा।

17. चर्चा की व्याप्ति.—ऐसे दिन या दिनों में या किसी दिन के भाग में सभा, किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐसे अभिभा-ण में निर्दि-ट वि-यों की चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होगी।

18. संशोधन.—ऐसे धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐसे रूप में संशोधन प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जिसे अध्यक्ष उचित समझे।

19. अन्य कार्य जो किया जा सकेगा.—(1) इस बात के होते हुए भी कि रा-ट्रपति के अभिभा-ण पर चर्चा के लिए कोई दिन नियत किया जा चुका है :

(क) ऐसे दिन विधेयक या विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव किए जा सकेंगे और विधेयक या विधेयकों को पुरःस्थापित किया जा सकेगा; और

(ख) ऐसे दिन अभिभा-ण पर सभा द्वारा चर्चा आरंभ किए जाने या जारी रखे जाने से पूर्व औपचारिक रूप से अन्य कार्य किया जा सकेगा।

(2) यह प्रस्ताव किए जाने पर कि अभिभा-ण पर चर्चा अध्यक्ष द्वारा नियत किए जाने वाले बाद के किसी दिन तक के लिए स्थगित की जाए, उस अभिभा-ण पर चर्चा किसी सरकारी विधेयक या अन्य सरकारी कार्य के पक्ष में विलंबित की जा सकेगी। अध्यक्ष द्वारा तुरंत वह प्रश्न रखा जाएगा और किसी संशोधन या वाद-विवाद की अनुमति नहीं होगी।

(3) किसी बैठक के दौरान में नियम 61 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव द्वारा अभिभा-ण पर चर्चा रोक दी जाएगी।

20. उत्तर देने का अधिकार¹.—(1) सरकार की ओर से प्रधानमंत्री या किस अन्य मंत्री को, चाहे चर्चा में पहले भाग लिया गया हो या नहीं, चर्चा के अंत में सरकार की स्थिति स्प-ट करने का सामान्य अधिकार होगा और अध्यक्ष द्वारा यह पूछा जा सकेगा कि भा-ण के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी जिससे चर्चा समाप्त होने का समय निश्चित किया जा सके।

[(2) प्रस्तावक अथवा प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले को प्रधानमंत्री अथवा किसी अन्य मंत्री द्वारा सरकार की स्थिति स्प-ट किए जाने के बाद चर्चा के अंत में उत्तर देने का अधिकार नहीं होगा।]¹

21. भा-णों के लिए समय-सीमा.—अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए, सभा का अभिप्राय जानकर भा-णों के लिए समय-सीमा विहित की जा सकेगी।

22. संविधान के अनुच्छेद 86(1) के अंतर्गत रा-ट्रपति का अभिभा-ण.—संविधान के अनुच्छेद 86(1) के अंतर्गत रा-ट्रपति के अभिभा-ण में निर्दि-ट वि-यों की चर्चा के लिए अध्यक्ष द्वारा समय नियत किया जा सकेगा।

23. रा-ट्रपति से संदेश.—अध्यक्ष द्वारा सभा के लिए संविधान के अनुच्छेद 86 के खंड (2) के अंतर्गत रा-ट्रपति से संदेश मिलने पर सभा को ऐसा संदेश पढ़कर सुनाया जाएगा और संदेश में निर्दि-ट वि-यों पर विचार करने के लिए अनुकरणीय प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक निदेश दिए जाएंगे। ऐसे निदेश देने में अध्यक्ष को उस सीमा तक नियमों को निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति होगी, जो कि आवश्यक हो।

24. सत्रावसान पर रा-ट्रपति का अभिभा-ण.—रा-ट्रपति द्वारा सभा या सदनों का सत्रावसान करने पर यथास्थिति, सभा या सदनों के सामने अभिभा-ण दिया जा सकेगा।

अध्याय 6

कार्य-विन्यास और कार्य-सूची

25. सरकारी कार्य का विन्यास.—सरकारी कार्य के संपादन के लिए नियत किए गए दिनों में ऐसे कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और महासचिव द्वारा उस कार्य का विन्यास ऐसे क्रम में किया जाएगा जैसा कि अध्यक्ष द्वारा सदन-नेता से परामर्श करने के बाद निर्धारित किया जाए:

परन्तु जिस दिन वह कार्य निपटाने के लिए रखा गया हो उस दिन कार्य के ऐसे क्रम में तब तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक अध्यक्ष का यह समाधान न हो जाए कि ऐसे परिवर्तन के लिए पर्याप्त आधार है।

26. गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए समय का नियतन.—शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के संपादन के लिए नियत किए जाएंगे:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा भिन्न-भिन्न वर्गों के ऐसे कार्य के निपटाने के लिए भिन्न-भिन्न शुक्रवार नियत किए जाए सकेंगे और किसी वर्ग विशेष के कार्य के लिए इस प्रकार नियत शुक्रवारों को उस वर्ग के कार्य की पूर्ववर्तिता होगी:

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष द्वारा सदन-नेता के परामर्श से, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के सम्पादन के लिए शुक्रवार के अतिरिक्त कोई और दिन नियत किया जा सकेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि शुक्रवार को सभा की बैठक न हो तो अध्यक्ष यह निदेश दे सकेगा/सकेगी कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए सप्ताह में किसी अन्य दिन ढाई घंटे नियत कर दिए जाएं।

¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 09.05.1989, पैरा 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

27. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की पूर्ववर्तिता.—

(1) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को निपटाने के लिए नियत किए गए दिन ऐसे विधेयकों की निम्नलिखित क्रम में सापेक्ष पूर्ववर्तिता होगी, अर्थात्:—

(क) वे विधेयक जिनके संबंध में प्रस्ताव यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए;

(ख) वे विधेयक जो रा-द्रूपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत संदेश के साथ लौटाए गए हैं;

(ग) वे विधेयक जो सभा द्वारा पारित तथा राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाए गए हों;

(घ) वे विधेयक जो राज्य सभा द्वारा पारित तथा सभा को पहुंचाए गए हों;

(ङ) वे विधेयक जिनके संबंध में यह प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो कि विधेयक पर विचार किया जाए;

(च) वे विधेयक जिनके संबंध में किसी संयुक्त या प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका हो;

(छ) वे विधेयक जो राय जानने के लिए परिचालित किए गए हों;

(ज) वे विधेयक जो पुरःस्थापित किए गए हों और जिनके संबंध में कोई अग्रेतर प्रस्ताव न किया गया हो या स्वीकृत न हुआ हो; और

(झ) अन्य विधेयक ।

(2) उप-नियम (1) के एक ही खंड के अंतर्गत आने वाले विधेयकों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार होने वाली शलाका द्वारा ऐसे दिन और ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, निर्धारित की जाएगी:

परन्तु उप-नियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत आने वाले विधेयकों के संबंध में प्रस्ताव कार्य-सूची में उस क्रम में दर्ज किया जाएगा जिस क्रम में ऐसे प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हो:

परन्तु यह और भी कि उप-नियम (1) के खंड (ज) के अंतर्गत आने वाले उन विधेयकों की, जो गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति द्वारा वर्ग 'क' में वर्गित किए गए हों, वर्ग 'ख' में रखे गए विधेयकों पर पूर्ववर्तिता होगी, और यह कि इनमें से प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत आने वाले विधेयकों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता शलाका द्वारा अलग-अलग निर्धारित की जाएगी:

[परन्तु यह और भी कि जहां गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति ने उप-नियम (1) के खंड (ज) के अंतर्गत आने वाले विधेयकों को श्रेणी 'क' के रूप में वर्गीकृत किया हो, और ऐसे विधेयकों की संख्या 20

या उससे अधिक हो तो श्रेणी 'ख' के विधेयकों का बैलट नहीं किया जाएगा]¹:

परन्तु यह और भी कि यदि समिति ने उप-नियम (1) के खंड (ज) के अंतर्गत आने वाले विधेयकों को वर्ग 'क' तथा वर्ग 'ख' में न रखा हो तो ऐसे विधेयकों के कार्य-सूची में रखे जाने का क्रम शलाका द्वारा ऐसे निदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा जो उसके लिए अध्यक्ष दे।

(3) अध्यक्ष विशेष-आदेश द्वारा, जो सभा में विधो-नित किया जाएगा उप-नियम (1) में दिए हुए विधेयकों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता में ऐसे परिवर्तन कर सकेगा/सकेगी जो अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझे।

28. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की पूर्ववर्तिता.—

संकल्प प्रस्तुत करने के इच्छुक सदस्यों के नामों का बैलट (शलाका) अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार ऐसे दिन किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष निदेश दें।

29. दिन के अंत में गैर-सरकारी सदस्यों का अवशिष्ट कार्य.—गैर-सरकारी सदस्यों का वह कार्य जो उस वर्ग के कार्य के लिए नियत किए गए दिन के लिए रखा गया हो और उस दिन जिसे निपटाया न गया हो, किसी बाद के दिन के लिए तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक उसे उस दिन के संबंध में की गई शलाका में पूर्ववर्तिता प्राप्त न हो गई हो:

परन्तु नियम 27 तथा 28 में किसी बात के अंतर्वि-ट होते हुए भी ऐसा कोई कार्य, जो उस दिन के अंत में चर्चाधीन हो, उस वर्ग के कार्य के लिए नियत अग्रिम दिन के लिए रखा जाएगा और उसकी उस दिन के लिए रखे गए अन्य सब कार्यों पर पूर्ववर्तिता होगी।

30. गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक या संकल्प पर स्थगित वाद-विवाद का पुनःआरंभ.—(1) जब किसी प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर किसी गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक या संकल्प पर वाद-विवाद उसी या अगले सत्र में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत किए गए अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया जाए तो उसे आगे चर्चा के लिए तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि उसे शलाका में पूर्ववर्तिता प्राप्त न की गई हो ।

(2) जब गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक या संकल्प पर वाद-विवाद अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया जाए, और यदि, विधेयक का प्रभारी सदस्य या संकल्प का प्रस्तावक, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत बाद के किसी दिन ऐसे विधेयक या संकल्प पर चर्चा जारी रखना चाहता हो, स्थगित वाद-विवाद को पुनः आरंभ करने के लिए सूचना दे सकेगा और ऐसी सूचना मिलने पर विधेयक या संकल्प की सापेक्ष पूर्ववर्तिता शलाका द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 09.05.1989, पैरा 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

31. कार्य-सूची.—(1) महासचिव द्वारा प्रत्येक दिन के लिए एक कार्य-सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर, अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी बैठक में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जो उस दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित न हो।

(3) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर, ऐसे किसी कार्य को, जिसके लिए सूचना अपेक्षित हो, उस कार्य के वर्ग के लिए अपेक्षित सूचना की कालावधि समाप्त होने के बाद वाले दिन से पूर्व किसी दिन के लिए नहीं रखा जाएगा।

(4) जब तक अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों को निपटाने के लिए नियत किसी दिन की कार्य-सूची में तीन से अधिक संकल्पों (किसी ऐसे संकल्प के अतिरिक्त जो नियम 29 के परन्तुक के अंतर्गत अवशिष्ट हों) नहीं रखे जाएंगे।

अध्याय 7

प्रश्न

32. प्रश्न काल.—जब तक अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा।

33. सूचना की अवधि.—जब तक अध्यक्ष द्वारा, अन्यथा निदेश न दिया जाए, प्रश्न के लिए [कम से कम पूरे पंद्रह दिन]¹ की सूचना दी जाएगी।

34. सूचना का रूप.—(1) प्रश्न की सूचना महासचिव को लिखित रूप में दी जाएगी और इसमें इन बातों का उल्लेख होगा।

²(क) प्रश्न का पाठ;

³(ख) प्रश्न जिस मंत्री को संबोधित हो उसके पद का नाम;

(ग) वह तिथि जिसको कि प्रश्न के उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में रखवाने का विचार है; और

⁴[(घ) यदि कोई सदस्य एक ही दिन के लिए प्रश्नों की एक से अधिक सूचनाएं देता/देती है तो प्रश्न-सूची में रखे जाने के लिए प्राथमिकता क्रम, यदि कोई हो।]

(2) जब किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हों तो वह सूचना केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी गई मानी जाएगी।

(कार्य मंत्रणा समिति और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति से संबंधित नियमों के लिए इस नियमावली का अध्याय 26 देखिए)

¹लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 19.3.2010, पैरा संख्या 1265 द्वारा प्रतिस्थापित।

²लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा 2930 द्वारा अंतःस्थापित।

35. गृहीत प्रश्नों की मंत्रियों को सूचना.—जब तक अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, कोई प्रश्न उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक कि महासचिव द्वारा ऐसे प्रश्न की सूचना उस मंत्री को, जिसे वह सम्बोधित हो, दिये हुए पांच दिन न बीत गये हों।

36. तारांकित प्रश्न.—जो सदस्य अपने प्रश्न का मौखिक उत्तर चाहता/चाहती हो वह तारांक लगाकर उसका विभेद करेगा/करेगी। यदि सदस्य द्वारा प्रश्न पर तारांक लगाकर विभेद न किया जाए तो वह प्रश्न लिखित उत्तर के लिये प्रश्नों की सूची में रखा जाएगा।

37. तारांकित प्रश्नों की संख्या पर सीमा.—(1) मौखिक उत्तर के लिए किसी एक दिन को प्रश्न-सूची में एक⁵ ही सदस्य का एक तारांक लगाकर विभेद किया गया एक से अनधिक प्रश्न तथा कुल मिलाकर बीस से अधिक प्रश्न नहीं रखे जाएंगे:

परन्तु जब कोई प्रश्न स्थगित कर दिया जाता है या मौखिक उत्तर के लिए किसी प्रश्न-सूची से अन्य प्रश्न-सूची में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो एक सदस्य के नाम में एक से अधिक प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं तथा प्रश्नों की कुल संख्या इस प्रकार स्थगित अथवा स्थानांतरित प्रश्न संख्या के अनुसार बढ़ सकती है।

[(2) जब तक अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, यदि सदस्य द्वारा प्रश्नों के लिए एक ही दिन के लिए तारांक लगाकर एक से अधिक सूचनाएं दी जाती हैं तो मौखिक उत्तर की प्रश्न-सूची के लिए सदस्य का प्रश्न सदस्य द्वारा दर्शाए गए, क्रम में चुना जाएगा और यदि कोई क्रम नहीं दर्शाया गया है तो इनमें से किसी भी प्रश्न को मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में उस क्रम में रखा जाएगा, जिस समय-क्रम में उनकी सूचनाएं प्राप्त हुई हों]⁶

38. प्रश्नों के लिए दिनों का चक्रानुक्रमानुसार नियतन.—प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध समय, ऐसे मंत्रालय या मंत्रालयों से संबद्ध प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भिन्न-भिन्न दिनों में चक्रानुक्रम से उस प्रकार नियत किया जाए जैसा कि अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उपबंधित किया जाए, और प्रत्येक ऐसे दिन जब तक कि अध्यक्ष द्वारा संबद्ध मंत्री की सम्मति से अन्यथा निदेश न दिया जाए केवल ऐसे मंत्रालय या मंत्रालयों से संबद्ध प्रश्न ही, जिनके लिए उस दिन समय

³वही, वर्तमान खण्ड (क) और (ख) को क्रमशः (ख) और (ग) के रूप में पुनराक्षरंकित किया गया।

⁴वही, जोड़ा गया।

⁵लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁶वही, जोड़ा गया।

नियत किया गया हो, मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में रखे जाएंगे।

39. अतारांकित प्रश्न.—(1) यदि किसी प्रश्न पर तारांक लगाकर विभेद न किया गया हो, अथवा यदि किसी दिन मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में रखे गए किसी प्रश्न को उस दिन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध समय में उत्तर के लिए न पुकारा जाए [***]⁷ तो उस प्रश्न का लिखित उत्तर, जिस मंत्री को प्रश्न संबोधित हो उसके द्वारा प्रश्न काल की समाप्ति पर अथवा मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों के निपटाए जाने के पश्चात् यथास्थिति सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा;

[***]⁸

[(2) यदि बैठक के रद्द किए जाने या कोई कार्य किए बिना इसके स्थगन किए जाने के कारण प्रश्न काल न हो, तो मौखिक और लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूचियों में शामिल किए गए प्रश्नों के उत्तर, उन मंत्रियों के द्वारा जिन्हें वे प्रश्न संबोधित किए गए हों, प्रश्न काल के पश्चात् सभा की आगामी बैठक में सभा पटल पर रखे गए माने जाएंगे और उस दिन की कार्यवाही का भाग बन जाएंगे।]⁹

(3) यदि किसी दिन प्रश्न काल किसी [***]¹⁰ [***]¹¹ कारण से समाप्त कर दिया जाता है, तो उस दिन के लिए मौखिक तथा लिखित उत्तरों की प्रश्न-सूचियों में शामिल किए गए प्रश्नों के उत्तर, उन मंत्रियों के द्वारा जिन्हें ऐसे प्रश्न संबोधित किए गए हों, सभा पटल पर रखे गए माने जाएंगे और उस दिन की कार्यवाही का भाग बन जाएंगे:

परन्तु यदि सभा प्रश्न काल समाप्त [***]¹² करने के पश्चात् अपनी बैठक को जारी नहीं रखती है तो उस दिन के लिए मौखिक तथा लिखित उत्तर की प्रश्न-सूचियों में शामिल किए गए प्रश्नों के उत्तर सभा की अगली बैठक में प्रश्न काल के पश्चात् सभा पटल पर रखे माने जाएंगे और उस दिन की कार्यवाही का भाग बन जाएंगे:

परन्तु यह भी कि यदि प्रश्न काल में मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची को ले लिए जाने के पश्चात् व्यवधान पड़ जाता है और सूची आंशिक रूप से निपटायी जाती है और बैठक जारी रहती है तो मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची के शेष प्रश्नों के उत्तर तथा लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची प्रश्नों के उत्तर 12 बजे के पश्चात् सभा पटल पर रखे गए माने जाएंगे और उस दिन की कार्यवाही का भाग बन जाएंगे।

[(4) यदि किसी सत्र की अंतिम बैठक रद्द हो जाती है तो उस दिन के लिए मौखिक तथा लिखित उत्तर के लिए

प्रश्नों की सूचियों में रखे गए प्रश्न व्यपगत हो जाएंगे।]¹³

40. गैर-सरकारी सदस्यों से प्रश्न.—प्रश्न किसी अन्य गैर-सरकारी सदस्य को संबोधित किया जा सकेगा, यदि प्रश्न का वि-य किसी ऐसे विधेयक, संकल्प अथवा सभा के कार्य के अन्य वि-य से संबंधित हो, जिसके लिए वह सदस्य उत्तरदायी हो और ऐसे प्रश्नों के संबंध में यथासंभव उसी प्रक्रिया का, जो किसी मंत्री को संबोधित प्रश्नों के संबंध में प्रयुक्त की जाती है, ऐसे परिवर्तनों के साथ अनुसरण किया जाएगा जो अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझे।

41. प्रश्नों की ग्राह्यता.—(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक-महत्व के किसी ऐसे वि-य पर जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकेगा जो उस मंत्री के विशेष-संज्ञान में हो जिसे वह संबोधित किया गया हो।

(2) प्रश्न पूछने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

[(एक) यह स्प-ट और सूक्ष्म रूप से अभिव्यक्त किया जाएगा तथा इतना अधिक सामान्य नहीं होगा कि उसका कोई विशि-ट उत्तर न दिया जा सके अथवा सूचक प्रश्न के रूप में नहीं होगा।]¹⁴

¹⁵(दो) उसमें कोई ऐसा नाम या कथन नहीं होगा जो प्रश्न को सुबोध बनाने के लिए सर्वथा आवश्यक न हो;

(तीन) यदि उसमें कोई कथन हो, तो सदस्य को उस कथन की परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा;

(चार) उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यासोपण विशेष-ण या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे;

(पांच) उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि संबंधी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए नहीं पूछा जाएगा;

(छः) उसमें किसी व्यक्ति के पदेन या सार्वजनिक हैसियत के उस व्यक्ति के चरित्र या आचरण के बारे में नहीं पूछा जाएगा;

(सात) उसमें साधारणतया 150 से अधिक शब्द नहीं होंगे;

(आठ) वह उस वि-य से संबंधित नहीं होगा तो मुख्यतया भारत सरकार का वि-य न हो;

(नौ) उसमें किसी समिति की ऐसी कार्यवाही के बारे में नहीं पूछा जाएगा जो समिति के प्रतिवेदन द्वारा सभा के सामने न रखी गई हो;

⁷ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 19.3.2010, पैरा 1265 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁸ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा 2930 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

^{9, 10, 11} लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 19.3.2010, पैरा 1265 द्वारा लोप किया गया।

¹² लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 19.03.2010 पैरा 1265 द्वारा लोप किया गया।

¹³ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 09.05.2010 पैरा 2930 द्वारा जोड़ा गया।

¹⁴ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा 2930 द्वारा अंतःस्थापित किया गया।

¹⁵ वही, पुनराक्षरांकित।

(दस) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर अभ्युक्ति नहीं की जाएगी जिसके आचरण पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो;

(ग्यारह) उसमें व्यक्तिगत स्वयं रूप का दो-आरोपण नहीं किया जाएगा और न वह दो-आरोपण ध्वनित होगा;

(बारह) उसमें ऐसी नीति के प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे जो इतनी विस्तीर्ण हो कि प्रश्न के उत्तर की सीमा के भीतर न आ सके;

(तेरह) उसमें ऐसे प्रश्नों की सारतः पुनरुक्ति नहीं की जाएगी जिनके उत्तर पहले दिए जा चुके हों या जिनका उत्तर देना अस्वीकार कर दिया गया हो;

(चौदह) उसमें तुच्छ वि-यों पर जानकारी नहीं मांगी जाएगी;

(पंद्रह) उसमें साधारणतया विगत इतिहास के वि-यों पर जानकारी नहीं मांगी जाएगी;

(सोलह) उसमें ऐसी जानकारी नहीं मांगी जाएगी जो प्राप्त दस्तावेज या साधारण निर्देश ग्रंथों में दी गई हो;

(सत्रह) उसमें ऐसे निकायों या व्यक्तियों के नियंत्रण के अंतर्गत वि-य नहीं उठाए जाएंगे जो मुख्यतया भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी न हो;

(अठारह) उसमें किसी ऐसे वि-य पर जानकारी नहीं मांगी जाएगी जो भारत के किसी भाग में अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायनिर्णय के अंतर्गत हो;

(उन्नीस) उसका किसी ऐसे वि-य से संबंध नहीं होगा जिससे मंत्री का पदेन कोई [सरोकार]¹⁶ न हो;

(बीस) उसमें किसी मित्र देश के प्रति अविनयपूर्ण निर्देश नहीं होगा;

[(इक्कीस) उसमें ऐसे वि-यों के बारे में जानकारी नहीं मांगी जाएगी जो गोपनीय स्वरूप के हों जैसे मंत्रिमंडल समितियों की रचना, मंत्रिमंडल में की जाने वाली चर्चाएं या रा-द्रुपति को किसी ऐसे वि-य में दी गई मंत्रणा जिसके संबंध में जानकारी प्रकट न करने का संवैधानिक, संविहित या रूढ़िगत दायित्व हो]¹⁷

(बाइस) उसमें साधारणतया ऐसे वि-यों पर जानकारी नहीं मांगी जाएगी जो किसी संसदीय समिति के विचाराधीन हो; और

(तेइस) उसमें साधारणतया ऐसे वि-यों के बारे में नहीं पूछा जाएगा जो कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक कृत्य करने वाली किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित

प्राधिकारी के या किसी वि-य की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो किंतु उसमें जांच की प्रक्रिया या न्यायालय के सामने विचाराधीन हो किंतु उसमें जांच की प्रक्रिया या वि-य या प्रक्रम में संबंधित वि-यों की ओर निर्देश किया जा सकेगा, यदि उससे न्यायाधिकरण या आयोग या जांच-पड़ताल द्वारा उस वि-य के विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना न हो]

42. भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच पत्र-व्यवहार के वि-यों पर प्रश्न.—जिन वि-यों पर भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच पत्र-व्यवहार हो रहा हो या हो चुका हो, उसके बारे में तथ्य वि-यों को छोड़कर, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, और उत्तर तथ्य कथन तक ही सीमित होगा ।

43. अध्यक्ष प्रश्नों की ग्राह्यता का विनिश्चय करेगा.—

(1) अध्यक्ष द्वारा यह विनिश्चय किया जाएगा कि कोई प्रश्न या उसका कोई भाग इन नियमों के अंतर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और ऐसे किसी प्रश्न या उसके किसी भाग को अस्वीकृत किया जा सकेगा जो अध्यक्ष की राय में वह प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किया गया हो या इन नियमों के उल्लंघन में हो।

(2) नियम 38 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष द्वारा यह निदेश दिया जा सकेगा कि किसी प्रश्न को प्रश्न-सूची में उत्तर के लिए सदस्य द्वारा अपनी सूचना में उल्लिखित तिथि के बाद की किसी तिथि को रखा जाए, यदि अध्यक्ष की राय हो कि यह विनिश्चित करने के लिए, कि प्रश्न ग्राह्य है या नहीं, अधिक समय की आवश्यकता है।

44. अध्यक्ष द्वारा यह विनिश्चय किया जाना कि कोई प्रश्न तारांकित माना जाए या अतारांकित.—यदि अध्यक्ष की राय में मौखिक उत्तर के लिए रखा गया कोई प्रश्न ऐसे स्वरूप का है कि उसका लिखित उत्तर अधिक उचित होगा तो अध्यक्ष द्वारा यह निदेश दिया जा सकेगा कि ऐसा प्रश्न लिखित उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में रख दिया जाए:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा, यदि ठीक समझा जाए, मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्य से मौखिक उत्तर चाहने के कारणों को संक्षेप में बताने की अपेक्षा की जा सकेगी और उन पर विचार करने के बाद निदेश दिया जा सकेगा कि प्रश्न लिखित उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में सम्मिलित किया जाए ।

45. [अतारांकित प्रश्नों की संख्या सीमा]¹⁸.—(1) जो प्रश्न गृहीत कर लिए गए हों और मौखिक उत्तर के

¹⁶ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹⁷ वही, प्रतिस्थापित।

¹⁸ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

लिए प्रश्न-सूची में शामिल न किए गए हों, अध्यक्ष के आदेश के अनुसार लिखित उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में दर्ज कर दिए जाएंगे।

(2) किसी दिन की लिखित उत्तर के लिए प्रश्न सूची में एक सदस्य के, यदि मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में उसका एक प्रश्न दर्ज है, चार से अनधिक और यदि मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में सदस्य का एक भी प्रश्न दर्ज नहीं है तो पांच से अनधिक तथा कुल मिलाकर 230 से अनधिक प्रश्न दर्ज किए जाएंगे:

परन्तु ये सीमाएं लिखित उत्तर के लिए किसी प्रश्न-सूची से अन्य प्रश्न-सूची में स्थानांतरित अथवा स्थगित प्रश्न संख्या के अनुसार बढ़ाई जा सकेगी:

परन्तु यह भी कि किसी दिन की लिखित उत्तर के लिए प्रश्न सूची में 230 प्रश्नों की कुल सीमा रा-ट्रपति शासन के अधीन राज्य अथवा राज्यों से संबंधित प्रश्न संख्या जो अधिक से अधिक 25 होगी, के अनुसार बढ़ सकेगी।

46. तारांकित प्रश्नों के पुकारे जाने का क्रम.—मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न, [***]¹⁹⁻²⁰ उस क्रम से पुकारे जाएंगे जिसमें कि वे सूची में दिए हों:

परन्तु जिस प्रश्न का मौखिक उत्तर देने के लिए समय नहीं बचा हो तो उसका उत्तर प्रश्न के काल के समय के अंत में, यदि मंत्री द्वारा अध्यक्ष से अभ्यावेदन किया जाए कि वह प्रश्न विशेष-लोकहित का है और उसका मंत्री उत्तर देना चाहता है/चाहती है, अध्यक्ष की अनुज्ञा से दिया जा सकेगा।

47. प्रश्नों की वापसी या स्थगन.—कोई सदस्य उस बैठक से पहले, जिसके लिए ऐसे सदस्य का प्रश्न सूची में रखा गया है, किसी भी समय सूचना देकर प्रश्न को वापस ले सकेगा/सकेगी या उसे सूचना में उल्लिखित किसी बाद के दिन के लिए स्थगित करा सकेगा/सकेगी और बाद के ऐसे दिन वह प्रश्न, नियम 38 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सूची में उन सब प्रश्नों के बाद रखा जाएगा जो इस तरह स्थगित न किए गए हों:

परन्तु स्थगित किया गया कोई प्रश्न सूची में तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि महासचिव को स्थगन की सूचना प्राप्त हुए पूरे दो दिन समाप्त न हो गए हों।

48. प्रश्न पूछने की रीति.—(1) प्रश्न पूछने का समय आने पर अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जिसके नाम में प्रश्न-सूची में कोई प्रश्न हो, क्रमवार पुकारा जाएगा।

(2) इस प्रकार पुकारा गया सदस्य, अपने स्वयं के स्थान पर खड़ा होगा/होगी और, जब तक वह सदस्य जिसे

उस सदस्य के नाम में रखे हुए प्रश्न को पूछने की अनिच्छा व्यक्त नहीं करता/करती है, उस प्रश्न की प्रश्न-सूची में उसी क्रम संख्या का उल्लेख करके पूछेगा/पूछेगी।

(3) यदि कोई प्रश्न पुकारे जाने पर न पूछा जाए [अथवा]²¹ वह सदस्य जिसके नाम में प्रश्न हों, अनुपस्थित हो, तो अध्यक्ष द्वारा [***]²² निदेश दिया जा सकेगा कि उसका उत्तर दिया जाए।

49. [*]²³**

[50. अनुपूरक प्रश्न.—(1) कोई सदस्य, जिसका नाम मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में प्रश्न दर्ज है अथवा कोई अन्य सदस्य, अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर किसी ऐसे तथ्यात्मक वि-य के अग्रेतर विशदीकरण के प्रयोजन के लिए जिसके बारे में उत्तर दिया गया है, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेगा/सकेगी।

(2) किसी अनुपूरक प्रश्न को अध्यक्ष द्वारा नियम के विरुद्ध ठहराया जाएगा यदि उसकी राय में;

(एक) वह मुख्य प्रश्न अथवा उसके उत्तर से उत्पन्न नहीं होता;

(दो) वह जानकारी मांगने की अपेक्षा, जानकारी देता है;

(तीन) उसमें एक से अधिक अलग प्रश्न अंतर्गस्त हैं;

(चार) उससे किसी राय की पु-टि अथवा अस्वीकृति के बारे में जानकारी मांगी गई है; और

(पांच) वह प्रश्नों के बारे में किसी नियम के उल्लंघन में है।

(3) नियम 32 के अंतर्गत प्रश्नों के समय में किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर के संबंध में चर्चा की अनुज्ञा नहीं होगी।²⁴

51. उत्तर में राज्य सभा की कार्यवाही की ओर निर्देश नहीं किया जाएगा.—सभा में किसी प्रश्न के उत्तर में राज्य सभा के चालू सत्र के दौरान दिए गए किसी प्रश्न के उत्तर या राज्य सभा की कार्यवाही की ओर निर्देश नहीं किया जाएगा।

52. सदस्यों को निर्दिष्ट लंबित प्रश्नों का व्यपगत होना.—जब किसी सदस्य से किसी प्रश्न की सूचना के संबंध में कुछ पूछा जाए और कोई उत्तर न मिले या ऐसे सदस्य से उत्तर इतनी देर से मिले कि अध्यक्ष उस पर विचार न कर

¹⁹⁻²⁰ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 19.3.2010, पैरा 1265 द्वारा लोप किया गया।

²¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 19.3.2010, पैरा 1265 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

^{22,23} वही, लोप किया गया।

²⁴ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

सके और प्रश्न, यदि ग्राह्य होने पर उचित तिथि की प्रश्न-सूची में न रखा जा सके, तो ऐसी सूचना व्यपगत समझी जाएगी ।

53. उत्तरों के पूर्व प्रकाशन पर रोक.—प्रश्नों के उत्तर जो मंत्री सभा में देना चाहते हों, तब तक प्रकाशनार्थ नहीं दिए जाएंगे जब तक वास्तव में वे सभा में न दिए जा चुके हों या पटल पर न रखे जा चुके हों ।

54. अल्प-सूचना प्रश्न.—(1) लोक महत्व के वि-य के संबंध में कोई प्रश्न पूरे दस दिन से कम की सूचना पर पूछा जा सकेगा और यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न अविलंबनीय प्रकार का है तो अध्यक्ष द्वारा यह निदेश दिया जा सकेगा कि संबंधित मंत्री से पूछताछ की जाए कि मंत्री उत्तर देने की स्थिति में है या नहीं और यदि हां, तो किस तिथि को ।

(2) यदि संबंधित मंत्री उत्तर देने के लिए सहमत हो तो ऐसे प्रश्न का उत्तर मंत्री द्वारा दर्शाए गए दिन को दिया जाएगा और वह प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में दिए गए प्रश्नों के निपटाए जाने के तुरंत पश्चात् पुकारा जाएगा ।

(3) यदि मंत्री अल्प-सूचना पर प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो और अध्यक्ष की यह राय हो प्रश्न पर्याप्त लोक-महत्व का है कि सभा में उसका मौखिक उत्तर दिया जाना चाहिए तो अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया जा सकेगा कि प्रश्न उस दिन प्रश्न-सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाए, जिस दिन कि नियम 33 के अंतर्गत उसका उत्तर दिया जा सकता हो:

परन्तु किसी एक दिन की प्रश्न-सूची में ऐसे एक से अधिक प्रश्न को प्रथम पूर्ववर्तिता प्रदान नहीं की जाएगी।

(3क) जब अल्प-सूचना प्रश्न की सूचना पर एक से अधिक सदस्य ने हस्ताक्षर किए हों तो यह सूचना केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा ही मानी जाएगी ।

(4) जब दो या अधिक सदस्य एक ही वि-य पर अल्प-सूचना प्रश्न रखें और उनमें से एक प्रश्न अल्प-सूचना पर उत्तर के लिए स्वीकार कर लिया जाए तो जिस सदस्य की सूचना स्वीकार कर ली गई हो, उसके अतिरिक्त, बैलट द्वारा निर्धारित रूप में अधिक से अधिक चार सदस्यों के नाम स्वीकृत प्रश्न के सामने दिए जाएंगे:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा यह निदेश दिया जा सकेगा कि सब सूचनाओं को एक ही सूचना में समेकित कर दिया जाए, यदि अध्यक्ष की राय में एक ही स्वयंपूर्ण ऐसा प्रश्न तैयार करना वांछनीय हो जिसमें सदस्यों द्वारा उठाई गई सब महत्वपूर्ण बातें आ जाएं और तब मंत्री द्वारा उस समेकित प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि समेकित प्रश्न की अवस्था में, जिस सदस्य की सूचना स्वीकार कर ली गई हो, उसके

अतिरिक्त, बैलट द्वारा निर्धारित रूप से अधिक से अधिक चार सदस्यों के नाम प्रश्न के सामने दिए जाएंगे ।

(5) यदि कोई सदस्य किसी प्रश्न का मौखिक उत्तर अल्प-सूचना पर चाहे तो ऐसा सदस्य संक्षेप में अल्प-सूचना पर प्रश्न पूछने के कारण बताएगा । यदि प्रश्न की सूचना में कोई कारण न दिए गए हों तो प्रश्न सदस्य को लौटा दिया जाएगा।

(6) वह सदस्य, जिसने प्रश्न की सूचना दी हो वह उस समय प्रश्नों की सूची में उस प्रश्न की संख्या का हवाला देकर प्रश्न पूछने के लिए अपने स्वयं के स्थान पर होगा जब अध्यक्ष द्वारा पुकारा जाए और संबंधित मंत्री तुरंत उत्तर देगा/देगी:

परन्तु जब कोई प्रश्न एक से अधिक सदस्यों के नाम से दिखाया गया हो तो अध्यक्ष द्वारा, प्रथम सदस्य का नाम या उस सदस्य की अनुपस्थिति में किसी अन्य नाम को पुकारा जाएगा।

(7) अन्य प्रकरणों में अल्प-सूचना प्रश्नों के लिए प्रक्रिया, ऐसे रूप भेदों के साथ, जो अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझे, वही होगी जो मौखिक उत्तर के लिए साधारण प्रश्नों के लिए है।

अध्याय 8

आधे घंटे की चर्चा

55. प्रश्नों के उत्तर से उठने वाले वि-यों पर चर्चा.—

(1) अध्यक्ष द्वारा एक सप्ताह में तीन बैठकों में आधा घंटा, ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के वि-य पर चर्चा उठाने के लिए नियत किया जा सकेगा जो हाल ही में किसी मौखिक या लिखित प्रश्न का वि-य रह चुका हो और जिसके उत्तर का किसी तथ्य वि-य के संबंध में विशुद्धीकरण आवश्यक हो।

(2) ऐसा सदस्य जो कोई वि-य उठाना चाहे, उस दिन से, जिस दिन उस वि-य को उठाए जाने की वांछा की गई हो, तीन दिन पहले महासचिव को लिखित सूचना देगा/देगी और संक्षेप में उस बात या बातों का उल्लेख करेगा/करेगी जिन्हें ऐसा सदस्य उठाना चाहता/चाहती हो:

परन्तु सूचना के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न होगी जिसमें उस वि-य पर चर्चा उठाने के कारण दिए होंगे:

परन्तु यह और भी कि यदि सूचना पर एक से अधिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हो तो वह सूचना केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दी गई मानी जाएगी:

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष संबंधित मंत्री की सम्मति से सूचना की कालावधि संबंधी आवश्यकता को हटा सकेगा/सकेगी ।

(3) अध्यक्ष द्वारा यह विनिश्चय किया जाएगा कि वि-य चर्चा के लिए रखे जाने के पर्याप्त लोक-महत्व का है

या नहीं, और किसी ऐसी सूचना को अग्राह्य किया जाएगा जिसका उद्देश्य अध्यक्ष की राय में सरकार की नीति में परिवर्तन करना हो ।

(4) यदि दो से अधिक सूचनाएं प्राप्त हुई हों और अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य कर ली गई हों तो महासचिव द्वारा दो सूचनाएं निकालने के लिए शलाका द्वारा निर्णय किया जाएगा और सूचनाएं उस क्रम में रखी जाएंगी जिस समय-क्रम में वे प्राप्त हुई हों:

परन्तु यदि किसी विशेष दिन चर्चा के लिए रखा गया कोई वि-य उस दिन न निपटाया जाए तो वह किसी अन्य दिन के लिए तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि सदस्य ऐसा न चाहे और उस अवस्था में उसे अगले प्राप्त दिन के लिए शलाका में सम्मिलित कर लिया जाएगा ।

(5) सभा के सामने न तो कोई औपचारिकता प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा । [जिन सदस्यों ने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया हो वे किसी तथ्य वि-य के अग्रेतर विशुद्धीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछ सकेंगे । तत्पश्चात् मंत्री संक्षेप में उत्तर देगा/देगी।]¹:

परन्तु अधिक से अधिक चार सदस्यों को, जिन्होंने महासचिव को पहले सूचित कर दिया हो, किसी तथ्य वि-य के अग्रेतर विशुद्धीकरण के प्रयोजन से एक-एक प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

व्याख्या: जो सदस्य प्रश्न पूछना चाहे वह जिस दिन चर्चा होनी हो उस दिन बैठक के आरंभ होने से पहले इसके लिए लिखित रूप में प्रार्थना करेगा/करेगी। यदि ऐसी प्रार्थनाएं चार से अधिक सदस्यों से प्राप्त होंगी तो पहले चार सदस्यों के नाम निर्धारित करने के लिए बैलट किया जाएगा जिन्हें एक-एक प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

अध्याय 9

स्थगन प्रस्ताव

56. अध्यक्ष की सहमति.—इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अविलम्बनीय लोक-महत्व के किसी निश्चित वि-य की चर्चा के प्रयोजन से सभा के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सहमति से किया जा सकेगा ।

57. सूचना.—[स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन, जिस दिन कि प्रस्ताव करने का विचार हो, 10.00 बजे तक महासचिव को दी जाएगी और उसकी प्रतियां निम्नलिखित को पृ-ठांकित की जाएंगी :

- (1) अध्यक्ष;
- (2) संबंधित मंत्री;
- (3) संसदीय कार्य मंत्री;

परन्तु 10.00 बजे के बाद प्राप्त सूचनाओं को सभा की अगली बैठक के दिन 10.00 बजे प्राप्त हुआ समझा जाएगा:

परन्तु यह भी कि किसी भी सदस्य द्वारा किसी एक बैठक के लिए एक से अधिक सूचना नहीं दी जाएगी ।

व्याख्या—(एक) जहां किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर हों वहां यह समझा जाएगा कि उसे केवल प्रथम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिया गया है।

(दो) किसी बैठक के लिए एक ही वि-य पर वैध सभी सूचनाओं की सापेक्ष वरीयता निर्धारित करने के लिए बैलट किया जाएगा।¹

58. प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का निर्बन्धन.—अविलम्बनीय लोक-महत्व के किसी निश्चित वि-य पर चर्चा करने के प्रयोजन से सभा को स्थगित करने के प्रस्ताव का अधिकार निम्नलिखित निर्बन्धन के अधीन होगा, अर्थात् :—

(एक) एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा;

(दो) एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक वि-य पर चर्चा नहीं होगी;

(तीन) प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशि-ट वि-य [जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की]² तक सीमित रहेगा;

(चार) प्रस्ताव द्वारा विशेष-ाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा;

(पांच) प्रस्ताव द्वारा ऐसे वि-य पर फिर चर्चा नहीं की जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो;

(छह) प्रस्ताव में उस वि-य की पूर्वाशा न की जाएगी जो विचार के लिए पहले ही नियत किया जा चुका हो। यह निर्धारित करने के लिए कि पूर्वाशा के आधार पर चर्चा नियमबाह्य है या नहीं; अध्यक्ष द्वारा उचित समय के भीतर पूर्वाशित वि-य के सभा के सामने आने की संभावना का ध्यान रखा जाएगा;

(सात) प्रस्ताव किसी ऐसे वि-य के संबंध में नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णयन के अंतर्गत हो; और

(आठ) प्रस्ताव में ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा जो संविधान या इन नियमों के अंतर्गत महासचिव को

¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 09.05.1989 पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित ।

² वही, अंतःस्थापित किया गया।

लिखित सूचना देकर अलग प्रस्ताव द्वारा ही उठाया जा सकता हो ।

59. न्यायाधिकरणों, आयोगों आदि के विचाराधीन वि-अय.—साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जो किसी ऐसे वि-अय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाली किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी वि-अय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित हो:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे वि-अय को सभा में उठाने की अनुमति दी जा सकेगी जो जांच की प्रक्रिया या वि-अय या प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाए कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी या जांच न्यायालय द्वारा उस वि-अय के विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

60. स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति.—(1) यदि अध्यक्ष द्वारा नियम 56 के अंतर्गत सम्मति दी जाए और यह मान्य ठहराया जाए कि चर्चा के लिए प्रस्तावित वि-अय नियमानुकूल है तो अध्यक्ष द्वारा संबंधित सदस्य को पुकारा जाएगा जो अपने स्वयं के स्थान पर खड़ा होगा और सभा के स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेगा:

परन्तु जब अध्यक्ष द्वारा नियम 56 के अंतर्गत सम्मति देने से इंकार कर दिया गया हो या अध्यक्ष की यह राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्तावित वि-अय नियमानुकूल नहीं है तो अध्यक्ष द्वारा यदि आवश्यक समझा जाए, उस प्रस्ताव की सूचना को पढ़कर सुनाया जा सकेगा और सम्मति देने से इंकार करने या प्रस्ताव को नियमानुकूल न ठहराने के कारण बताए जा सकेंगे:

परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष उसमें उल्लिखित मामले के बारे में पूर्ण तथ्यों से अवगत न हो तो अध्यक्ष द्वारा सम्मति देने या देने से इंकार करने के पूर्व उस प्रस्ताव की सूचना को पढ़कर सुनाया जा सकेगा और सम्बन्धित मंत्री या सदस्यों से तथ्यों पर संक्षिप्त विवरण की सुनवाई की जा सकेगी और उसके बाद प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय दिया जा सकेगा ।

(2) यदि अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जाए तो अध्यक्ष द्वारा उन सदस्यों से जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कहा जाएगा और तदनुसार यदि कम से कम पचास सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष द्वारा यह सूचित किया जाएगा कि अनुमति दी जाती है। यदि पचास से कम सदस्य उठें, तो अध्यक्ष द्वारा सदस्य को सूचित किया जाएगा कि उसे सभा की अनुमति नहीं है।

61. प्रस्ताव को लेने का समय.—प्रस्ताव "कि सभा अब स्थगित हो" 16.00 बजे या यदि अध्यक्ष, सभा में कार्य की

स्थिति पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश दे तो उससे पहले किसी भी समय लिया जाएगा।

62. वाद-विवाद का समापन.—अध्यक्ष द्वारा यह समाधान होने पर कि पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है, 18.30 बजे या ऐसे अन्य समय, जो वाद-विवाद प्रारम्भ होने के समय से ढाई घंटे से कम न हो, प्रश्न रखा जा सकेगा।

63. भा-णों के लिए समय-सीमा.—अध्यक्ष भा-णों के लिए समय-सीमा विहित करेगा।

अध्याय 10

विधान

1. सभा में प्रारम्भ होने वाले विधेयक

(विधेयकों का पुरःस्थापन और प्रकाशन)

64. पुरःस्थापन से पहले विधेयक का राजपत्र.—अध्यक्ष द्वारा, प्रार्थना की जाने पर, किसी विधेयक (उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण, विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन सम्बन्धी ज्ञापन और उससे संलग्न वित्तीय ज्ञापन सहित) के गजट में प्रकाशन का आदेश दिया जा सकेगा भले ही विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव न रखा गया हो। उस अवस्था में विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं होगा और यदि विधेयक बाद में पुरःस्थापित किया जाये तो उसको फिर प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

65. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति की सूचना.—(1) मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य, जो किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करना चाहता हो, अपने इस अभिप्राय की सूचना देगा और सूचना के साथ विधेयक की एक प्रति और उद्देश्यों और कारणों का एक व्याख्यात्मक विवरण जिसमें प्रतर्क नहीं होंगे, भेजेगा:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए, उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

(2) यदि विधेयक एक ऐसा विधेयक हो जो संविधान के अन्तर्गत रा-द्रूपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश के बिना पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, तो सदस्य सूचना के साथ मंत्री के माध्यम से भेजी गई मंजूरी या सिफारिश अनुबद्ध करेगा, और सूचना तब तक मान्य नहीं होगी जब तक इस अपेक्षा का पालन न हो जाये।

(3) इस नियम के अन्तर्गत विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की कालावधि एक मास होगी यदि अध्यक्ष द्वारा इससे कम समय की सूचना पर प्रस्ताव किये जाने की अनुमति न दे दी जाए।

(4) अध्यक्ष द्वारा किसी विधेयक की सूचना को अस्वीकार किया जा सकेगा यदि विधेयक में इस नियम के उपनियम (2) या नियम 69 या 70 की अपेक्षाओं का पालन न किया गया हो।

66. लम्बित किसी अन्य विधेयक पर निर्भर विधेयक.— कोई विधेयक जो सभा में लम्बित किसी अन्य विधेयक पर पूर्णतः या अंशतः निर्भर है, उस विधेयक के पारित हो जाने की पूर्वाशा में जिस पर कि वह निर्भर है, सभा में पुरःस्थापित किया जा सकेगा:

परन्तु दूसरा विधेयक सभा में विचार किये जाने तथा पारित किये जाने के लिए केवल तभी लिया जायेगा जबकि पहला विधेयक सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो और रा-ट्रपति द्वारा उस पर अनुमति दी जा चुकी हो।

67. समान विधेयक.—जब कोई विधेयक सभा में लम्बित हो, तब किसी समान विधेयक की सूचना, चाहे वह लम्बित विधेयक के पुरःस्थापन से पूर्व या पश्चात् प्राप्त हुई हो, लम्बित सूचनाओं की सूची में से, यथास्थिति, निकाल दी जायेगी अथवा उसमें दर्ज नहीं की जायेगी, जब तक अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए।

68. विधेयक पर रा-ट्रपति की सिफारिश पहुंचाना.— किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने या उस पर विचार किये जाने की मंजूरी देने या रोक लेने अथवा सिफारिश करने या रोक लेने के रा-ट्रपति के आदेश सम्बन्धित मंत्री द्वारा लिखित रूप में महासचिव को पहुंचाये जायेंगे।

69. वित्तीय ज्ञापन और व्यय संबंधी खंड.—(1) जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेष-तया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि के रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।

(2) विधेयकों के जिन खंडों या उपबन्धों में भारत की संचित निधि में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो वे मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में छापे जायेंगे:

¹[परन्तु जहां किसी विधेयक में कोई खंड जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त हो अनजाने में मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में न छपा जाये, विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से ऐसे खंडों को सभा की जानकारी में लाया जाएगा।]

70. प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन.—जिस विधेयक में विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन के प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त हों उसके साथ अग्रेतर एक ज्ञापन होगा जिसमें ऐसे प्रस्ताव की

व्याख्या होगी और उनकी व्याप्ति की ओर ध्यान दिलाया जायेगा तथा यह भी बताया जायेगा कि वे सामान्य रूप की हैं या अपवाद स्वरूप की।

71. अध्यादेशों के बारे में विवरण.—(1) जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यादेश के स्थान में उसमें रूपभेद सहित या उसके बिना सभा में पुरःस्थापित किया जाए तो सभा के सामने विधेयक के साथ उन परिस्थितियों को स्प-ट करने वाला एक विवरण भी रखा जायेगा; जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था।

(2) जब कभी कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित किया जाये, जिसमें सभा के सामने लंबित किसी विधेयक के उपबन्ध पूर्णतः या अंशतः या रूपभेद सहित समावि-ट हों तो उन परिस्थितियों को स्प-ट करने वाला एक विवरण, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था, अध्यादेश को प्रख्यापित करने के बाद के सत्र के प्रारम्भ में पटल पर रख दिया जाएगा।

72. विधेयक की पुरःस्थापना का विरोध होने पर प्रक्रिया.—

(1) यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये, तो अध्यक्ष द्वारा, यदि ठीक समझा जाए, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर वाद-विवाद के प्रश्न को रखा जा सकेगा:

परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष द्वारा उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दी जा सकेगी:

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष द्वारा वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव तुरन्त मतदान के लिए रखा जाएगा।

²[(2) किसी विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करने की सूचना ³(उठाई जाने वाली आपत्तियों को स्प-ट और संक्षिप्त रूप में विनिर्दि-ट करते हुए) महासचिव को संबोधित की जाएगी और जिस दिन विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव को कार्य-सूची में शामिल किया गया हो उस दिन 10.00 बजे तक दी जाएगी]

73. पुरःस्थापन के बाद विधेयक का राजपत्र में प्रकाशन.— विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने के बाद यथासम्भव शीघ्र

¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

² लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा जोड़ा गया।

³ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 10.12.2004, पैरा संख्या 710 द्वारा अंतःस्थापित किया गया।

विधेयक गजट में प्रकाशित कर दिया जायेगा, यदि वह पहले ही प्रकाशित न किया जा चुका हो।

विधेयकों के पुरःस्थापन के बाद प्रस्ताव तथा वाद-विवाद की व्याप्ति

74. विधेयकों के पुरःस्थापन के बाद प्रस्ताव.—विधेयक जब पुरःस्थापित किया जाये तब या उसके बाद किसी अवसर पर, प्रभारी सदस्य अपने स्वयं के विधेयक के बारे में निम्न प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी, अर्थात्—

(एक) कि उस पर विचार किया जाये; या

(दो) कि उसे सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाये; या

(तीन) कि उसे राज्य सभा की सहमति से दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये; या

(चार) कि उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाये:

परन्तु खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट कोई ऐसा प्रस्ताव किसी ऐसे विधेयक के सम्बन्ध में नहीं दिया जायेगा ⁴[यदि उसमें केवल ऐसे उपबन्ध हों जो संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (क) से (छ) में उल्लिखित सभी वि-यों या उनमें से किसी वि-य से संबंधित हो]

परन्तु यह और भी कि ऐसा प्रस्ताव उस समय तक नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न कर दी गई हों और यदि विधेयक की प्रतियां प्रस्ताव करने के दिन से दो दिन पहले इस तरह उपलब्ध न कर दी गई हों तो कोई सदस्य ऐसे किसी प्रस्ताव के किए जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि अध्यक्ष प्रस्ताव किये जाने की अनुमति न दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

75. विधेयक के सिद्धान्त पर चर्चा.—(1) नियम 74 में निर्दिष्ट किसी प्रस्ताव के किए जाने पर विधेयक के सिद्धान्त और उसके उपबन्धों पर सामान्य रूप से चर्चा की जा सकेगी किन्तु विधेयक के ब्यौरे पर उससे अग्रेतर चर्चा नहीं होगी जितनी कि उसके सिद्धान्तों की व्याख्या के लिए आवश्यक हो।

(2) इस प्रक्रम पर विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे, किन्तु—

(क) यदि प्रभारी सदस्य प्रस्ताव करे कि विधेयक पर विचार किया जाये तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह

प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि विधेयक सदन की प्रवर समिति या, राज्य सभा की सहमति से, दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये या प्रस्ताव में उल्लिखित की जाने वाली तिथि तक उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया जाये;

(ख) यदि प्रभारी सदस्य प्रस्ताव करे कि विधेयक सदन की प्रवर समिति, या राज्य सभा की सहमति से दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि विधेयक, यथास्थिति राज्य सभा की सहमति से सदनों की संयुक्त समिति को अथवा एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, या विधेयक को प्रस्ताव में उल्लिखित की जाने वाली तिथि तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।

(3) जब यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाये कि विधेयक पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए और विधेयक उस निदेश के अनुसार परिचालित किया जा चुका हो और उस पर राय प्राप्त हो गई हों तो प्रभारी सदस्य, यदि विधेयक पर उसके आगे कार्यवाही करना चाहता/चाहती हो, यह प्रस्ताव करेगा/करेगी कि विधेयक सदन की प्रवर समिति या, राज्य सभा की सहमति से, दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, यदि अध्यक्ष द्वारा यह प्रस्ताव करने की अनुमति न दे दी जाए कि विधेयक पर विचार किया जाये:

परन्तु यदि इस उपनियम के अन्तर्गत कोई संशोधन या प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति की नियुक्ति के लिए कोई प्रस्ताव किया गया हो, तो कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि सभा, प्रवर समिति या संयुक्त समिति को जिसे यह विधेयक में कुछ खास या अतिरिक्त उपबन्ध करने और यदि आवश्यक या सुविधाजनक हो तो ऐसे संशोधनों पर जो उस मूल अधिनियम के सम्बन्ध में प्रस्तावित किये जायें, जिसे विधेयक द्वारा संशोधित किया जा रहा हो, विचार करने और प्रतिवेदन देने का अनुदेश दे:

परन्तु यह और भी कि इस उपनियम के अन्तर्गत कोई संशोधन या संयुक्त समिति की नियुक्ति के लिए कोई प्रस्ताव किसी ऐसे विधेयक के सम्बन्ध में नहीं किया जाएगा [यदि उसमें केवल ऐसे उपबन्ध हों जो संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उपखंड (क) से (छ) में उल्लिखित सभी वि-यों या उनमें से किसी वि-य से संबंधित हों]⁵

76. सदस्य विधेयकों के सम्बन्ध में प्रस्ताव कर सकेगा.—विधेयक के प्रभारी सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य

⁴ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁵ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा जोड़ा गया।

सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव नहीं किया जाएगा कि विधेयक पर विचार किया जाये या विधेयक को पारित किया जाये और विधेयक के प्रभारी सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा, विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा किए गये प्रस्ताव पर संशोधन के रूप के अतिरिक्त यह प्रस्ताव नहीं किया जाएगा कि विधेयक सभा की प्रवर समिति या राज्य सभा की सहमति से दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये या राय जानने के लिए परिचालित किया जाये:

परन्तु यदि किसी विधेयक का प्रभारी सदस्य, ऐसे कारणों से जिन्हें अध्यक्ष पर्याप्त समझे, उसके पुरःस्थापन के बाद के किसी प्रक्रम पर उस विधेयक के बारे में अगले प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो वह सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से उस प्रस्ताव विशेष-1 को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य सदस्य को अधिकृत कर सकेगा/सकेगी ।

व्याख्या—परन्तुक में दिये गये उपबन्धों के होते हुए भी वह सदस्य जिसने विधेयक को पुरःस्थापित किया है, प्रभारी सदस्य बना रहेगा/रहेगी।

(विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों वि-1यक नियमों के लिए इस नियमावली का अध्याय 26 देखिए)

प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के बाद प्रस्ताव और वाद-विवाद की व्याप्ति

77. प्रवर/संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के बाद प्रस्तुत प्रस्ताव.—(1) किसी विधेयक पर, यथास्थिति, सदनों की संयुक्त समिति या सदन की प्रवर समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के बाद, प्रभारी सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी—

(क) कि यथास्थिति, सदनों की एक संयुक्त समिति या सभा की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाए; या

(ख) कि यथास्थिति, सभा की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक को राज्य सभा की सहमति से या तो उसी प्रवर समिति या एक नयी प्रवर समिति या उसी संयुक्त समिति या एक नई संयुक्त समिति को—

(एक) परिसीमा के बिना; अथवा

(दो) केवल खास खण्डों या संशोधनों के सम्बन्ध में ही; अथवा

(तीन) समिति को विधेयक में कोई खास या कोई अतिरिक्त उपबन्ध करने के अनुदेशों के साथ पुनः सौंपा जाये; अथवा

(ग) सदनों की संयुक्त समिति या सभा की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक, यथास्थिति, उस पर राय या अग्रेतर राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित या पुनः परिचालित किया जाये:

परन्तु यदि प्रतिवेदन की प्रति सदस्यों के उपयोग के लिए प्रस्ताव किये जाने के दिन से दो दिन पहले उपलब्ध न कर दी गई हो, तो कोई सदस्य ऐसे किसी प्रस्ताव के किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा/सकेगी और यदि अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव किये जाने की अनुमति न दे दी जाए तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

(2) यदि विधेयक का प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव करे कि यथास्थिति, सदनों की संयुक्त समिति या सभा की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाये, तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि विधेयक समिति को पुनः सौंपा जाये या उस पर राय या अग्रेतर राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित या पुनः परिचालित किया जाये।

78. प्रवर/संयुक्त समिति के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद की व्याप्ति.—इस प्रस्ताव पर कि, यथास्थिति, सदनों को संयुक्त समिति या सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाए, वाद-विवाद समिति के प्रतिवेदन के विचार तक और उस प्रतिवेदन में निर्दिष्ट वि-1यों तक या विधेयक के सिद्धांत से सुसंगत किन्हीं वैकल्पिक सुझावों तक ही सीमित रहेगा।

खंडों आदि का संशोधन तथा विधेयकों पर खंडवार विचार

79. खण्डों अथवा अनुसूचियों पर संशोधनों की सूचना.—

(1) यदि विधेयक के किसी खण्ड या अनुसूची के किसी संशोधन की सूचना उस दिन से एक दिन पूर्व न दी गई हो जिस दिन कि विधेयक पर विचार किया जाना हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा/सकेगी और यदि अध्यक्ष द्वारा संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दी जाए, तो आपत्ति अभिभावी होगी:

परन्तु किसी सरकारी विधेयक की अवस्था में ऐसा संशोधन, जिसकी सूचना प्रभारी सदस्य से मिली हो, इस कारण व्यपगत नहीं होगा कि प्रभारी सदस्य मंत्री या सदस्य नहीं रहा/रही है और ऐसा संशोधन विधेयक के नये प्रभारी सदस्य के नाम से छपा जायेगा।

(2) यदि समय हो तो महासचिव द्वारा सदस्यों को, समय-समय पर, उन संशोधनों की सूचियां उपलब्ध कराई जाएंगी जिनकी सूचनायें प्राप्त हो चुकी हों।

80. संशोधनों की ग्राह्यता.—किसी विधेयक के खंडों या अनुसूचियों के संशोधनों की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:—

(एक) संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका सम्बन्ध हो उसके वि-नय से संगत होगा।

(दो) संशोधन सभा के उसी प्रश्न पर किसी पूर्व विनिश्चय से असंगत नहीं होगा।

(तीन) संशोधन ऐसा नहीं होगा कि जिससे वह खण्ड, जिसे संशोधन करने का उसमें प्रस्ताव हो, दुर्बोध या व्याकरण के अनुसार अशुद्ध हो जाये।

(चार) यदि संशोधन में बाद के किसी संशोधन या अनुसूची की ओर निर्देश किया जाने या उसके बिना वह बोधगम्य न हो तो प्रथम संशोधन का प्रस्ताव करने से पहले बाद के संशोधन या अनुसूची की सूचना दी जायेगी, जिससे कि संशोधन माला पूर्ण रूप में बोधगम्य हो जाये।

(पांच) अध्यक्ष द्वारा वह स्थान निर्धारित किया जाए जहां संशोधन प्रस्तुत किया जायेगा।

(छः) अध्यक्ष द्वारा ऐसे संशोधन का प्रस्ताव करने से इंकार किया जा सकेगा जो अध्यक्ष की राय में तुच्छ या अर्थहीन हो।

(सात) जो संशोधन अध्यक्ष द्वारा पहले ही प्रस्तावित हो चुका हो उसमें संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

81. संशोधनों के बारे में रा-द्रूपति की सिफारिश.—यदि कोई सदस्य ऐसा संशोधन प्रस्तुत करना चाहता/चाहती हो जो संविधान के अन्तर्गत रा-द्रूपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश के बिना पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता, तो सदस्य द्वारा इन नियमों द्वारा अपेक्षित सूचना के साथ किसी मंत्री के माध्यम से भेजी गई ऐसी मंजूरी या सिफारिश अनुबद्ध की जाएगी और सूचना तब तक मान्य नहीं होगी जब तक इस अपेक्षा का पालन नहीं हो जाता:

परन्तु रा-द्रूपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश आवश्यक नहीं होगी यदि संशोधन में—

(क) विधेयक या किसी संशोधन में प्रस्तावित कर की सीमाओं को समाप्त या कम करने, या

(ख) ऐसे कर को किसी विद्यमान कर की सीमाओं तक बढ़ाने की अपेक्षा हो।

82. रा-द्रूपति की सिफारिश पहुंचाना.—किसी विधेयक के संशोधन की मंजूरी देने या रोक लेने अथवा सिफारिश करने या रोक लेने के रा-द्रूपति के संबंधित आदेश मंत्री द्वारा लिखित रूप में महासचिव को पहुंचाये जायेंगे।

83. नये खण्डों या संशोधनों को चुनना.—अध्यक्ष को प्रस्ताव किये जाने वाले नए खण्ड या संशोधन चुनने की

शक्ति होगी और यदि अध्यक्ष ठीक समझे तो किसी सदस्य से, जिसने संशोधन की सूचना दी हो, उस संशोधन के उद्देश्य की ऐसी व्याख्या करने के लिए कह सकेगा जिससे कि अध्यक्ष द्वारा उस पर कोई निर्णय किया जा सके।

84. संशोधनों का विन्यास.—जिन संशोधनों की सूचना दी जा चुकी हो उनका विन्यास समय-समय पर निगमित संशोधन सूची में यथासाध्य उसी क्रम में किया जायेगा जिसमें कि वे पुकारे जायें। किसी खण्ड के एक ही वि-नय पर एक-सा ही प्रश्न उठाने वाले संशोधनों का विन्यास करते समय विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा [प्रस्तावित]⁶ संशोधन को पूर्ववर्तिता दी जा सकेगी। उपर्युक्त के अधीन रहते हुए संशोधनों का विन्यास उस क्रम में किया जा सकेगा जिसमें कि उनकी सूचनाएं प्राप्त हुई हों।

85. संशोधनों का क्रम.—(1) साधारणतया संशोधनों पर विधेयक के उन खण्डों के क्रम में विचार किया जायेगा जिनसे कि वे क्रमशः सम्बन्धित हों; और ऐसे किसी खण्ड के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव किया गया समझा जायेगा, "कि यह खण्ड विधेयक का अंग बने"।

(2) अध्यक्ष द्वारा, यदि ठीक समझा जाए, किसी खण्ड के एक से संशोधनों को एक प्रश्न के रूप में रखा जा सकेगा:

परन्तु यदि किसी सदस्य द्वारा प्रार्थना की जाए कि कोई संशोधन अलग से रखा जाये तो अध्यक्ष द्वारा उस संशोधन को अलग से रखा जाएगा।

86. संशोधन प्रस्तुत करना.—जब यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया हो कि विधेयक पर विचार किया जाये तो कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर विधेयक में वह संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा/सकेगी जिसकी सदस्य ने पहले सूचना दे दी हो:

परन्तु समय बचाने और तर्कों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एक दूसरे पर आश्रित कितने ही संशोधनों के संबंध में एक ही चर्चा करने की अनुमति दी जा सकेगी।

87. संशोधनों की वापसी.—प्रस्तुत किया गया कोई संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य की प्रार्थना पर सभा की अनुमति से ही वापिस लिया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। यदि किसी संशोधन में संशोधन प्रस्तावित किया गया हो, तो मूल संशोधन तब तक वापस नहीं लिया जायेगा जब तक कि उसमें प्रस्तावित संशोधन न निपटा दिया जाये।

88. विधेयक का खण्डशः रखा जाना.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष द्वारा, जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाये स्वीकृत हो गया हो, विधेयक को, या विधेयक के किसी भाग को, खण्डवार सभा के सामने रखा जा सकेगा। अध्यक्ष द्वारा, प्रत्येक खंड को अलग-अलग से पुकारा जा सकेगा और जब उससे सम्बन्धित संशोधन निपटा दिये गये हों, यह प्रश्न रखा जाएगा "कि यह खंड (या,

⁶ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

कि यह खंड संशोधित रूप में यथास्थिति), विधेयक का अंग बने।”

89. खंड का विलम्बन.—अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए, खंड पर विचार विलम्बित किया जा सकेगा।

90. अनुसूचियों पर विचार.—यदि कोई अनुसूची या अनुसूचियां हों तो उन पर विचार, खंडों पर विचार के बाद होगा, अनुसूचियां सभापति द्वारा उसी रीति से रखी और संशोधित की जा सकेंगी जैसे कि खंड; और नयी अनुसूचियों पर विचार मूल अनुसूचियों के विचार के बाद किया जायेगा। तब यह प्रश्न रखा जायेगा: “कि यह अनुसूची (या, कि यह अनुसूची संशोधित रूप में, यथास्थिति), विधेयक का अंग बने”:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा अनुसूची या अनुसूचियों पर, यदि कोई हो, खंडों के निपटारे जाने के पहले या किसी खंड के साथ या अन्यथा जैसा अध्यक्ष द्वारा ठीक समझा जाए, विचार किये जाने की अनुमति दी जा सकेगी।

91. खंडों और अनुसूचियों के समूह पर मतदान.—अध्यक्ष द्वारा यदि उचित समझा जाए, खण्डों और/या अनुसूचियों को, अथवा संशोधित रूप में खंडों और/या अनुसूचियों को, यथास्थिति, एक साथ एक प्रश्न के रूप में सभा के मतदान के लिए रखा जा सकता है:

परन्तु यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि कोई खण्ड या अनुसूची अथवा संशोधित रूप में कोई खंड या अनुसूची, यथास्थिति, पृथक रूप से मतदान के लिए रखी जाये तो अध्यक्ष द्वारा उस खण्ड या अनुसूची को, अथवा संशोधित रूप में खण्ड या अनुसूची को, यथास्थिति, पृथक रूप से रखा जाएगा।

92. विधेयक का खंड एक, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और नाम.—विधेयक का खंड एक, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना यदि कोई हो, और नाम पर विचार तब तक विलम्बित रखा जायेगा जब तक कि अन्य खंड तथा अनुसूचियां (नये खंड तथा नयी अनुसूचियों सहित) न निपटा दी जायें और अध्यक्ष द्वारा तब यह प्रश्न रखा जाएगा: “कि खंड 1 या अधिनियमन सूत्र, या प्रस्तावना या नाम (या, कि संशोधित रूप में खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना या नाम यथास्थिति), विधेयक का अंग बने।”

विधेयकों का पारण

93. विधेयक पारित करने का प्रस्ताव.—(1) जब यह प्रस्ताव, कि विधेयक पर विचार किया जाए, स्वीकार हो गया हो और विधेयक में कोई संशोधन न किया जाए, तब प्रभासी सदस्य तुरंत ही यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि विधेयक पारित किया जाए।

(2) जब किसी विधेयक में संशोधन किए गए हों कि यह प्रस्ताव कि, विधेयक को संशोधित रूप से पारित किया जाए,

उस दिन प्रस्तुत न किया जाएगा जिस दिन उस विधेयक पर विचार समाप्त हुआ हो, जब तक अध्यक्ष उस प्रस्ताव की अनुमति न दे।

(3) ऐसे प्रस्ताव पर कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा जो या तो औपचारिक या शाब्दिक न हो या विधेयक पर विचार किए जाने के बाद किए गए संशोधन के कारण आनु-गिक न हो।

94. विधेयक पारित करने के प्रस्ताव पर वाद-विवाद की व्याप्ति.—इस प्रस्ताव पर कि विधेयक या विधेयक संशोधित रूप में, यथास्थिति पारित किया जाए, चर्चा विधेयक के समर्थन में या उसे अस्वीकार करने के लिए दिए गए प्रतर्कों तक सीमित होगी। भा-ण करते समय सदस्य विधेयक के ब्यौरे का उससे अधिक उल्लेख नहीं करेगा/करेगी जितना कि उसके प्रतर्कों के प्रयोजन के लिए जो कि सामान्य रूप के होंगे, आवश्यक हो।

95. प्रत्यक्ष गलतियों की शुद्धि.—जब कोई विधेयक सभा द्वारा पारित हो जाए, तब अध्यक्ष को विधेयक में प्रत्यक्ष गलतियों को शुद्ध करने और ऐसे अन्य परिवर्तन करने की शक्ति होगी जो सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों से आनु-गिक हों।

96. विधेयकों को राज्य सभा में पहुंचाना.—(1) जब कोई विधेयक सभा द्वारा पारित हो जाए तो वह राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए उस संबंध में संदेश के साथ पहुंचाया जाएगा।

(2) राज्य सभा को इस प्रकार पहुंचाये गए विधेयक के प्रथम पृ-ठ के ऊपर महासचिव द्वारा निम्न प्रकार से प्रमाणित किया जाएगा:—

“यह विधेयक20 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया है।

दिनांक20 महासचिव”

परन्तु यदि वह संविधान के अनुच्छेद 110 के अर्थ के अनुसार एक धन विधेयक हो तो विधेयक के अंत में अध्यक्ष का प्रमाणपत्र निम्न प्रकार से अंकित होगा:—

“मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 के अर्थ के अंतर्गत एक धन विधेयक है।

दिनांक20 अध्यक्ष”

97. धन विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विधेयकों के बारे में राज्य सभा का संदेश.—यदि धन विधेयक के अतिरिक्त सभा द्वारा पारित तथा राज्य सभा को पहुंचाया गया कोई विधेयक

राज्य सभा द्वारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाए तो उस वि-य में राज्य सभा से प्राप्त संदेश यदि सभा का सत्र चल रहा हो तो महासचिव द्वारा सभा को प्रतिवेदित किया जाएगा या यदि सभा का सत्र न चल रहा हो तो सदस्यों की जानकारी के लिए लोक सभा समाचार में प्रकाशित किया जाएगा।

धन विधेयकों के अतिरिक्त राज्य सभा द्वारा लौटाए गए विधेयक

98. संशोधन सहित लौटाया गया विधेयक.—यदि धन विधेयक के अतिरिक्त सभा द्वारा पारित तथा राज्य सभा को पहुंचाया गया कोई विधेयक सभा को संशोधन सहित लौटाया जाए, तो वह प्राप्त होने पर पटल पर रखा जाएगा।

99. संशोधनों पर विचार करने की सूचना.—संशोधित विधेयक के पटल पर रखे जाने के बाद, सरकारी विधेयक की अवस्था में कोई मंत्री या किसी अन्य अवस्था में कोई सदस्य, दो दिन की सूचना या अध्यक्ष की सहमति से, बिना सूचना दिए यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि संशोधनों पर विचार किया जाए।

100. संशोधनों पर विचार.—(1) यदि यह प्रस्ताव कि संशोधनों पर विचार किया जाए, स्वीकृत हो जाए, तो अध्यक्ष द्वारा ऐसे संशोधनों को सभा के सामने ऐसी रीति से रखा जाएगा जिसे उन पर विचार करने के लिए अध्यक्ष द्वारा सबसे अधिक सुविधाजनक समझा जाए।

(2) राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन के वि-य से संगत कोई संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा, किन्तु विधेयक में कोई अग्रेतर संशोधन तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह राज्य सभा द्वारा किए गए किसी संशोधन का आनु-गिक या वैकल्पिक न हो।

101. राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों का निपटाया जाना.—सभा, यदि वह राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन से सहमत हो, तो राज्य सभा को उस आशय का एक संदेश भेजेगी किन्तु यदि वह उस संशोधन से असहमत हो या कोई अग्रेतर संशोधन अथवा वैकल्पिक संशोधन प्रस्तावित करे तो सभा विधेयक को या अग्रेतर संशोधित रूप में विधेयक को उस आशय के एक संदेश के साथ राज्य सभा को लौटा देगी।

राज्य सभा द्वारा लौटाए गए धन विधेयक

102. संशोधनों के बारे में सदनों के बीच असहमति.—यदि विधेयक सभा को इस संदेश के साथ लौटा दिया जाए कि राज्य सभा उस संशोधन या उन संशोधनों पर आग्रह करती है, जिनसे सभा असहमत है, तो यह समझा जाएगा कि

संशोधन या संशोधनों के बारे में दोनों सदन अन्तिम रूप से असहमत हो गए हैं।

राज्य सभा द्वारा लौटाए गए धन विधेयक

103. बिना सिफारिश के लौटाया गया धन विधेयक.—यदि सभा द्वारा पारित तथा राज्य सभा को पहुंचाया गया कोई धन विधेयक सभा को बिना सिफारिश के लौटा दिया जाए तो उस आशय का उसका संदेश यदि सभा का सत्र चल रहा हो तो महासचिव द्वारा सभा को प्रतिवेदित किया जाएगा या यदि सभा का सत्र न चल रहा हो सदस्यों की जानकारी के लिए लोक सभा समाचार में प्रकाशित किया जाएगा। फिर विधेयक अनुमति के लिए रा-द्रूपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

104. सिफारिश के साथ लौटाया गया धन विधेयक.—यदि सभा द्वारा पारित तथा राज्य सभा को पहुंचाया गया कोई धन विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों सहित सभा को लौटाया जाए तो वह प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखा जाएगा।

105. राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों पर विचार करने के प्रस्ताव की सूचना.—विधेयक के राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों सहित पटल पर रखे जाने के बाद सरकारी विधेयक की अवस्था में कोई मंत्री या किसी अन्य अवस्था में कोई सदस्य दो दिन की सूचना देने के बाद या अध्यक्ष की सम्मति से बिना सूचना के, प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए।

106. राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों पर विचार करने की प्रक्रिया.—यदि यह प्रस्ताव, कि राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए, स्वीकृत हो जाए, तो अध्यक्ष द्वारा राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए ऐसे संशोधनों को सभा के सामने ऐसी रीति से रखा जाएगा जो अध्यक्ष के अनुसार उन पर विचार के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक हो।

107. राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों का निपटाया जाना.—यदि सभा, राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन या संशोधनों को स्वीकार कर ले, तो विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए तथा सभा द्वारा स्वीकृत संशोधन या संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा और उस संबंध में एक संदेश राज्य सभा को भेजा जाएगा।

108. सभा द्वारा राज्य सभा की सिफारिशें स्वीकार न किए जाने पर विधेयक पारित माना जाएगा.—यदि सभा, राज्य सभा की सिफारिशों में से किसी को भी स्वीकार न करे, तो विधेयक सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों में से किसी

के बिना उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें कि वह सभा द्वारा पारित किया गया था और उस संबंध में एक संदेश राज्य सभा को भेजा जाएगा।

विधेयकों पर वाद-विवाद का स्थगन और उनको वापस लेना तथा हटाना

109. विधेयकों पर वाद-विवाद का स्थगन.—सभा में चर्चाधीन विधेयक के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष की सहमति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाए।

110. विधेयक का वापस लिया जाना.—विधेयक का प्रभारी सदस्य विधेयक के किसी प्रक्रम पर विधेयक को इस आधार पर वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि—

(क) विधेयक में अंतर्वि-ट विधायिनी प्रस्ताव समाप्त किया जाना है; या

(ख) बाद में उस विधेयक के स्थान में एक नया विधेयक लाया जाना है जिससे इसमें अंतर्वि-ट उपबंध में सारवान रूप से फेरबदल हो जाएगा; या

(ग) बाद में उस विधेयक के स्थान पर नया विधेयक लाया जाना है जिसमें अन्य उपबंधों के अतिरिक्त उसके सभी या कोई उपबंध सम्मिलित हो ;

और यदि ऐसी अनुमति दी जाए तो उस विधेयक के संबंध में कोई अग्रेतर प्रस्ताव नहीं किया जाएगा:

परंतु जब कोई विधेयक, यथास्थिति, सभा की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति के विचाराधीन हो, तो विधेयक की वापसी के प्रस्ताव की सूचना स्वतः समिति को सौंपी गई मानी जाएगी और समिति द्वारा सभा को दिए गए प्रतिवेदन में राय व्यक्त करने के बाद प्रस्ताव कार्य-सूची में रखा जाएगा:

परंतु आगे यह भी यदि किसी विधेयक का सूत्रपात राज्य सभा में हुआ हो और वह सभा में विचाराधीन हो, तो प्रभारी सदस्य सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा/करेगी जिसमें राज्य सभा से यह सिफारिश की जाएगी कि राज्य सभा विधेयक को वापस लेने की अनुमति देने से सहमत हो जाए और जब यह प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया जाए और उस पर राज्य सभा की सहमति प्राप्त हो जाए, तो प्रभारी सदस्य विधेयक को वापस लेने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेगा/करेगी।

111. विधेयक को वापस लिए जाने का विरोध किए जाने पर प्रक्रिया.—यदि किसी विधेयक को वापस लेने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष, द्वारा यदि ठीक समझा जाए, प्रस्ताव का विरोध करने वाले तथा

प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों⁷ को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और उसके बाद, अग्रेतर वाद-विवाद के बिना, प्रश्न रखा जा सकेगा।

112. विधेयकों की पंजी से विधेयक का हटाया जाना.—

(1) जब सभा द्वारा किसी विधेयक के बारे में इन नियमों के विधेयकों के अंतर्गत प्रभारी सदस्य द्वारा किए गए निम्नलिखित प्रस्तावों में से कोई प्रस्ताव अस्वीकार किया जाए, तो उस विधेयक के संबंध में कोई और प्रस्ताव नहीं किया जायेगा और ऐसा विधेयक सभा में लम्बित विधेयकों की पंजी में से हटा दिया जायेगा।

(एक) कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए;

(दो) कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए;

(तीन) कि विधेयक राज्य सभा की सहमति से सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए;

(चार) कि विधेयक पर विचार किया जाए;

(पांच) कि, यथास्थिति, सभा की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाए; और

(छह) विधेयक को (या विधेयक को, संशोधित रूप में यथास्थिति) पारित किया जाए।

(2) सभा के सामने लंबित विधेयक का सभा द्वारा सारवन रूप से समान विधेयक को पारित करने या नियम 110 के अंतर्गत विधेयक वापस लिए जाने की अवस्था में सभा में लंबित विधेयकों को पंजी में से हटा दिया जाएगा।

व्याख्या:—सभा के सामने लंबित विधेयक में ये सम्मिलित होंगे:

(एक) सभा में पुरःस्थापित विधेयक जो इस नियम या नियम 113 में उल्लिखित विधेयकों के वर्गों के अंदर नहीं आता;

(दो) राज्य सभा को पहुंचाया गया तथा राज्य सभा द्वारा/यथास्थिति संशोधन, या सिफारिश सहित, लौटाया गया और नियम 98 अथवा 104 के अंतर्गत पटल पर रखा गया विधेयक;

(तीन) राज्य सभा में, प्रारंभ हुआ और सभा को पहुंचाया गया और नियम 114 या 122 के अंतर्गत पटल पर रखा गया विधेयक; और

(चार) संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत रा-द्रूपित द्वारा संदेश के साथ लौटाया गया विधेयक।

⁷ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 09.05.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

113. विधेयकों की पंजी से गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक हटाने के लिए अतिरिक्त उपबंध.—सभा के सामने लंबित कोई गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक भी सभा में लंबित विधेयकों की पंजी में से हटा दिया जाएगा यदि:—

(क) प्रभारी सदस्य सभा का सदस्य न रहे;

(ख) प्रभारी सदस्य मंत्री नियुक्त किया जाये।

2. राज्य सभा में आरम्भ होने वाले तथा सभा को पहुँचाए गये विधेयक

114. विधेयकों का पटल पर रखा जाना.—जब राज्य सभा में आरंभ होने वाला कोई विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित हो गया हो और सभा को पहुँचाया जाए, तो विधेयक, यथासंभव शीघ्र, पटल पर रखा जाएगा।

115. विचार किए जाने की सूचना.—विधेयक के इस प्रकार पटल पर रखे जाने के बाद किसी भी समय सरकारी विधेयक की अवस्था में कोई मंत्री, या किसी अन्य अवस्था में कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगा कि विधेयक पर विचार किया जाए।

116. विचार करने का प्रस्ताव.—उस दिन जिस दिन के लिए विचार करने का प्रस्ताव कार्य-सूची में रखा जाए जो जब तक कि अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, सूचना प्राप्त होने के समय से कम से कम दो दिन बाद होगा, सूचना देने वाला सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि विधेयक पर विचार किया जाए।

117. विधेयक के सिद्धांत पर चर्चा.—जिस दिन ऐसा प्रस्ताव किया जाए उस दिन या उसके बाद किसी दिन जिसके लिए चर्चा स्थगित की जाए, विधेयक के सिद्धांत और सामान्य उपबंधों पर चर्चा की जा सकेगी किंतु विधेयक के ब्यौरे पर उससे अग्रेतर चर्चा नहीं की जानी चाहिए जितना कि उसके सिद्धांतों की व्याख्या के लिए आवश्यक हो।

118. प्रवर समिति को सौंपा जाना.—कोई भी सदस्य, यदि विधेयक पहले ही दोनों सदनों की किसी संयुक्त समिति को न सौंप दिया गया हो, संशोधन के रूप में प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए और यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाएगा, और तब सभा में आरंभ होने वाले विधेयकों पर प्रवर समितियों से संबंधित नियम लागू होंगे।

119. विधेयकों पर विचार तथा उनको पारित करना.—यदि यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाए, स्वीकृत हो जाए, तो विधेयक पर खंड-वार विचार किया जाएगा और विधेयकों के संशोधनों पर विचार से संबंधित बाद की प्रक्रिया लागू होगी।

120. बिना संशोधनों के पारित विधेयक.—यदि विधेयक बिना किसी संशोधन के पारित हो जाए तो राज्य सभा को यह सूचित करते हुए संदेश भेजा जाएगा कि सभा ने विधेयक को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

121. संशोधनों के साथ पारित विधेयक.—(1) यदि विधेयक संशोधनों के साथ पारित किया जाए तो विधेयक इस संदेश के साथ राज्य सभा को लौटा दिया जाएगा कि संशोधनों पर अपनी सहमति दे।

(2) राज्य सभा को इस प्रकार लौटाए गए विधेयक के प्रथम पृष्ठ के ऊपर महासचिव द्वारा निम्न प्रकार से प्रमाणित किया जाएगा:—

“यह विधेयक20 को लोक सभा द्वारा संशोधित रूप में पारित किया गया है।

दिनांक20..... महासचिव”

122. राज्य सभा द्वारा संशोधनों के निपटान के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.—यदि राज्य सभा, सभा द्वारा किए गए संशोधनों या उनमें से किसी संशोधन से असहमत हो या सभा द्वारा किए गए संशोधनों में से किसी संशोधन को अग्रेतर संशोधनों के साथ स्वीकार करे या सभा द्वारा किए गए संशोधनों के स्थान पर अग्रेतर संशोधन का प्रस्ताव करे, तो विधेयक अग्रेतर संशोधित रूप में, सभा द्वारा प्राप्त किए जाने पर सभा पटल पर रखा जाएगा।

123. राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार.—संशोधित विधेयक के पटल पर रखे जाने के बाद सरकारी विधेयक की अवस्था में कोई मंत्री और किसी अन्य अवस्था में कोई सदस्य, दो दिन की सूचना देकर, या अध्यक्ष की सहमति से, बिना सूचना के, यह प्रस्ताव कर सकेगा कि संशोधनों पर विचार किया जाए।

124. संशोधनों पर विचार की प्रक्रिया.—(1) यदि यह प्रस्ताव कि संशोधनों पर विचार किया जाए, स्वीकृत हो जाए तो अध्यक्ष द्वारा संशोधनों को सभा के सामने ऐसी रीति से रखा जाएगा जिसे अध्यक्ष द्वारा उन पर विचार करने के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक समझा जाए।

(2) राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों के वि-य से संगत संशोधन प्रस्तुत किए जा सकेंगे किन्तु विधेयक में कोई अग्रेतर संशोधन तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह राज्य सभा द्वारा किए गए किसी संशोधन का आनु-गिक या वैकल्पिक न हो।

125. विधेयक और संशोधनों का निपटारा जाना.—सभा, यथास्थिति, या तो राज्य सभा द्वारा मूल रूप में पारित या राज्य सभा द्वारा अग्रेतर संशोधित विधेयक से सहमत हो

सकेगी या विधेयक को इस सन्देश के साथ लौटा सकेगी कि वह उस संशोधन या संशोधनों पर, जिनसे राज्य सभा असहमत है, आग्रह करती है।

126. संशोधनों के बारे में सदनों के बीच असहमति.—यदि कोई विधेयक इस संदेश के साथ लौटाया जाए कि सभा उन संशोधनों पर आग्रह करती है जिनसे राज्य सभा सहमत होने में असमर्थ है तो यह समझा जाएगा कि संशोधनों के बारे में दोनों सदन अन्तिम रूप से असहमत हो गए हैं।

127. विधेयक का अस्वीकार किया जाना.—जब राज्य सभा में आरंभ होने वाले तथा सभा को पहुंचाए गए किसी विधेयक के संबंध में निम्न प्रस्तावों में से कोई प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए तो यह समझा जाएगा कि विधेयक सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है:—

(एक) कि विधेयक पर विचार किया जाए;

(दो) कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए;

(तीन) कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाए; और

(चार) कि विधेयक को (या विधेयक को संशोधित रूप में, यथास्थिति) पारित किया जाए।

3. पारित किए गए विधेयकों का प्रमाणीकरण और उन पर अनुमति

128. प्रमाणीकरण और अनुमति.—(1) जब कोई विधेयक सदनों द्वारा पारित किया जाए और वह सभा के वश में हो तो विधेयक की दो प्रतियों पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उन्हें रा-ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु अध्यक्ष के नई दिल्ली में उपस्थित न होने पर अविलम्बनीयता की अवस्था में महासचिव द्वारा अध्यक्ष की ओर से विधेयक का प्रमाणीकरण किया जा सकेगा।

(2) इस प्रकार रा-ट्रपति द्वारा अनुमति-प्राप्त विधेयक की एक प्रति सत्यापन और अभिलेख के लिए सुरक्षित रख दी जाएगी और अध्यक्ष की अनुमति के बिना सभा की अभिरक्षा से बाहर ले जाने नहीं दी जाएगी।

4. रा-ट्रपति द्वारा लौटाए गए विधेयकों पर पुनर्विचार (सभा में प्रारम्भ होने वाले विधेयक)

129. रा-ट्रपति का संदेश.—(1) जब सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक सभा को रा-ट्रपति द्वारा एक संदेश के साथ लौटाया जाए जिसमें यह कहा गया हो कि सभा विधेयक पर अथवा उसके किन्हीं उल्लिखित उपबंधों पर अथवा किन्हीं संशोधनों पर जिनकी संदेश में सिफारिश की गई हो पुनर्विचार करे तो अध्यक्ष द्वारा रा-ट्रपति के संदेश को सभा में पढ़कर सुनाया जाएगा यदि वह सत्र में हो अथवा यदि सभा सत्र में

न हो तो यह निदेश दिया जाएगा कि उसे सदस्यों की जानकारी के लिए बुलेटिन (समाचार) में प्रकाशित कर दिया जाए।

(2) उसके पश्चात् विधेयक को सदनों द्वारा पारित और रा-ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए रूप में सभा पटल पर रखा जाएगा।

130. संशोधनों पर विचार करने की सूचना.—विधेयक के इस प्रकार पटल पर रखे जाने के पश्चात् किसी समय, सरकारी विधेयक की दशा में कोई मंत्री या किसी अन्य दशा में कोई सदस्य, यह प्रस्ताव रखने के अपने अभिप्राय की सूचना दे सकता है कि रा-ट्रपति द्वारा जिन संशोधनों की सिफारिश की गई है उन पर विचार किया जाए।

131. विचार करने का प्रस्ताव.—उस दिन, जिस दिन के लिए विचार करने का प्रस्ताव कार्य-सूची में रखा जाए, जो, यदि अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए सूचना प्राप्त होने के समय से कम-से-कम दो दिन बाद होगा, सूचना देने वाला सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि संशोधनों पर विचार किया जाए।

132. वाद-विवाद की व्याप्ति.—ऐसे प्रस्ताव पर वाद-विवाद, रा-ट्रपति के संदेश में निर्दिष्ट वि-यों तक या रा-ट्रपति द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के वि-य में संगत किसी सुझाव तक ही सीमित रहेगा।

133. संशोधनों पर विचार करने के प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.—यदि यह प्रस्ताव कि जिन संशोधनों की सिफारिश रा-ट्रपति ने की है उन पर विचार किया जाए, स्वीकृत हो जाए तो अध्यक्ष द्वारा उन संशोधनों को सभा के समक्ष ऐसी रीति से रखा जाएगा जिसे अध्यक्ष द्वारा उन पर विचार के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक समझा जाए।

134. संशोधन में संशोधन.—ऐसा कोई संशोधन, जो रा-ट्रपति द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के वि-य से संगत हो, प्रस्तावित किया जा सकता है किंतु विधेयक में अग्रेतर कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह रा-ट्रपति द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन का आनु-गिक, प्रासंगिक या वैकल्पिक संशोधन न हो।

135. विधेयक का पुनः पारण .—जब सभी संशोधन निपटाए जा चुके हों तो नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव की सूचना देने वाला सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि सदनों द्वारा मूल रूप में पारित विधेयक को यथास्थिति, पुनःपारित अथवा संशोधित रूप में पुनःपारित किया जाए।

136. संशोधनों पर विचार करने के प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.—यदि यह प्रस्ताव पारित न हो कि रा-ट्रपति द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए, तो नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव की सूचना देने वाला सदस्य तत्काल यह प्रस्ताव कर सकता है कि सदनों द्वारा मूल रूप में पारित विधेयक को बिना किसी संशोधन के पुनःपारित किया जाए ।

137. पुनः पारित विधेयक का राज्य सभा को पहुंचाया जाना.—(1) जब सभा द्वारा विधेयक को, यथास्थिति, संशोधन के साथ या बिना, पुनः पारित किया जाए, तब वह राज्य सभा को, सहमति के लिए उस आशय के संदेश के साथ पहुंचाया जाएगा।

(2) राज्य सभा को इस प्रकार पहुंचाए गए विधेयक के पहले पृ-ठ के ऊपर महासचिव द्वारा निम्न प्रकार से प्रमाणित किया जाएगा:—

“यह विधेयक, जो संसद के सदनों द्वारा पारित किया गया था और रा-ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया था, लोक सभा द्वारा 20..... को संशोधन के साथ/ बिना पुनः पारित किया गया है।

दिनांक , 20..... महासचिव”

138. विधेयक के पुनः पारण के बारे में राज्य सभा से संदेश.—यदि सभा द्वारा पुनः पारित और राज्य सभा को पहुंचाया गया विधेयक राज्य सभा द्वारा बिना संशोधन के पुनः पारित कर दिया जाए तो उस संबंध में राज्य सभा से प्राप्त संदेश यदि सभा का सत्र चल रहा हो तो महासचिव द्वारा सभा को प्रतिवेदित किया जाएगा या यदि सभा का सत्र न चल रहा हो तो सदस्यों की जानकारी के लिए बुलेटिन (समाचार) में प्रकाशित किया जाएगा।

139. राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाया गया विधेयक.—यदि सभा द्वारा पुनःपारित और राज्य सभा को पहुंचाया गया विधेयक संशोधनों के साथ सभा को लौटाया गया हो, तो यह प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखा जाएगा।

140. राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार.—संशोधित विधेयक को पटल पर रखे जाने के पश्चात् सरकारी विधेयक की दशा में कोई मंत्री, या किसी अन्य दशा में, कोई सदस्य, दो दिन की सूचना देकर या अध्यक्ष की अनुमति से, किसी सूचना के बिना, यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि संशोधनों पर विचार किया जाए।

141. संशोधनों पर विचार करने की प्रक्रिया.—(1) यदि संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए, तो अध्यक्ष द्वारा संशोधनों को सभा के समक्ष ऐसी रीति से रखा जाएगा जिसे अध्यक्ष द्वारा उस पर विचार करने के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक समझा जाए।

(2) ऐसा कोई संशोधन, जो राज्य सभा द्वारा किए गए किसी संशोधन के वि-य से संगत हो, प्रस्तावित किया जा सकता है, किन्तु विधेयक में अग्रेतर कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह राज्य सभा द्वारा किए गए किसी संशोधन के आनुषंगिक, प्रासंगिक या वैकल्पिक न हो।

142. राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों का निपटाया जाना.—यदि सभा, राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन से सहमत हो, तो वह इस आशय का एक संदेश राज्य सभा को भेजेगी, किंतु यदि वह उस संशोधन से असहमत हो अथवा किसी अग्रेतर संशोधन या वैकल्पिक संशोधन का प्रस्ताव करे तो सभा उस आशय के एक संदेश के साथ विधेयक को या अग्रेतर संशोधित रूप से विधेयक को राज्य सभा को लौटा देगी।

143. संशोधनों के बारे में सदनों के बीच असहमति.—यदि, राज्य सभा इस आशय के संदेश के साथ विधेयक को सभा के पास लौटा दे कि वह उसे संशोधन या संशोधनों पर जिनसे सभा असहमत है, आग्रह करती है तो यह समझा जाएगा कि उस संशोधन या संशोधनों पर दोनों सदन अन्तिम रूप से असहमत हैं ।

राज्य सभा में प्रारंभ होने वाले विधेयक

144. विधेयक का सभा पटल पर रखा जाना.—जब दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक को, जिसे रा-ट्रपति द्वारा राज्य सभा के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, राज्य सभा ने, संशोधनों के सहित या बिना, पुनःपारित कर दिया हो और सभा को भेज दिया हो तो उस विधेयक को रा-ट्रपति के संदेश के साथ, यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रखा जाएगा।

145. विचार करने का प्रस्ताव.—रा-ट्रपति के संदेश के साथ विधेयक के इस प्रकार पटल पर रखे जाने के पश्चात् किसी समय भी सरकारी विधेयक की दशा में कोई मंत्री या किसी अन्य दशा में कोई सदस्य दो दिन की सूचना देकर या अध्यक्ष की सहमति से, सूचना के बिना यह प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी कि विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पुनःपारित रूप में, विचार किया जाए।

146. विचार करने के प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.—(1) यदि राज्य सभा द्वारा विधेयक को पुनःपारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो अध्यक्ष द्वारा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों को, यदि कोई हों, सभा के समक्ष ऐसी रीति से रखा जाएगा जिसे अध्यक्ष द्वारा उन पर विचार करने के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक समझा जाए।

(2) राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों के वि-य से संगत संशोधन प्रस्तुत किए जा सकेंगे, किन्तु विधेयक में कोई अग्रेतर संशोधन तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह राज्य सभा द्वारा किए गए किसी संशोधन के आनु-ांगिक, प्रासंगिक या वैकल्पिक न हो:

परन्तु यदि रा-ट्रपति द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन से राज्य सभा सहमत नहीं हुई हो तो सदस्य, रा-ट्रपति द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन के वि-य से संगत कोई संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा/सकेगी।

147. संशोधन के बिना पुनःपारित विधेयक.—यदि राज्य सभा द्वारा पुनःपारित विधेयक को सभा द्वारा संशोधन के बिना पुनःपारित कर दिया जाए तो इस आशय का एक संदेश राज्य सभा को भेज दिया जाएगा।

148. संशोधनों सहित पुनःपारित विधेयक.—यदि सभा विधेयक को संशोधनों सहित पुनःपारित करे तो विधेयक को इस संदेश के साथ राज्य सभा को लौटाया जाएगा कि वह ऐसे संशोधनों से सहमत हो जाए।

149. राज्य सभा द्वारा संशोधनों के निपटाए जाने के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.—यदि राज्य सभा, सभा द्वारा किए गए संशोधनों या उनमें से किसी संशोधन से, सहमत हो या सभा द्वारा किए गए किसी संशोधन से अग्रेतर संशोधनों के साथ सहमत हो अथवा सभा द्वारा किए गए संशोधनों के स्थान पर नए संशोधनों का प्रस्ताव करे तो विधेयक को, अग्रेतर संशोधित रूप में, सभा को प्राप्त होने पर, पटल पर रखा जाएगा।

150. राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार.—संशोधित विधेयक के इस प्रकार पटल पर रखे जाने के पश्चात् सरकारी विधेयक की दशा में कोई मंत्री या किसी अन्य दशा में कोई सदस्य दो दिन की सूचना देकर या अध्यक्ष की सहमति से सूचना के बिना, यह प्रस्ताव कर सकता/सकती है कि संशोधन पर विचार किया जाए।

151. संशोधनों पर विचार करने की प्रक्रिया.—(1) यदि संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो अध्यक्ष द्वारा संशोधनों को सभा के समक्ष ऐसी रीति से, रखा जाएगा जिसे अध्यक्ष उन पर विचार करने के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक समझे।

(2) राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों के वि-य से संगत संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा किन्तु विधेयक में अग्रेतर संशोधन तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन के आनु-गिक, प्रासंगिक या वैकल्पिक न हो।

152. विधेयकों और संशोधनों का निपटाया जाना.—सभा राज्य सभा द्वारा, यथास्थिति, पुनःपारित रूप में या राज्य सभा द्वारा अग्रेतर संशोधित रूप में विधेयक से सहमत हो सकेगी या विधेयक को इस संदेश के साथ लौटा सकेगी कि वह उस संशोधन या संशोधनों पर, जिनसे राज्य सभा असहमत है, आग्रह करती है।

153. संशोधनों के बारे में सदनों के बीच असहमति.—यदि सभा इस आशय के संदेश के साथ विधेयक को लौटा दे कि वह उस संशोधन या संशोधनों पर, जिनसे राज्य सभा सहमत होने में असमर्थ है, आग्रह करती है तो यह समझा जाएगा कि

उस संशोधन या संशोधनों पर दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हैं।

सदनों द्वारा पुनःपारित विधेयकों का प्रमाणीकरण

154. प्रमाणीकरण.—जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पुनःपारित किया जाए तथा वह सभा के वश में हो, तो उसकी दो प्रतियों पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उन्हें रा-ट्रपति के समक्ष निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा:

‘उक्त विधेयक संविधान के अनुच्छेद 111 के परन्तुक के अनुसरण में संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनःपारित किया गया है।

दिनांक.....20.....

अध्यक्ष’:

परन्तु अध्यक्ष के नई दिल्ली में उपस्थित न होने पर अविलम्बनीयता की अवस्था में महासचिव द्वारा अध्यक्ष की ओर से विधेयक का प्रमाणीकरण किया जा सकेगा।

अध्याय 11

संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक

155. खण्डों तथा अनुसूचियों पर मतदान.—संविधान में संशोधन की व्यवस्था करने वाले विधेयक का, यथास्थिति, प्रत्येक खण्ड या अनुसूची अथवा संशोधित रूप में खण्ड या अनुसूची सभा के मत के लिए अलग-अलग रखी जाएगी और विधेयक का अंग बन जाएगी यदि वह सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित हो जाये:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा सभा की सहमति से, यथास्थिति, खण्डों तथा/या अनुसूचियों को, अथवा संशोधित रूप से खण्डों तथा/या अनुसूचियों को सभा के मत के लिए एक साथ रखा जा सकेगा और उस अवस्था में मतदान का परिणाम प्रत्येक खंड या अनुसूची पर अलग-अलग लागू समझा जाएगा और कार्यवाही में उसी तरह दर्शाया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि यथास्थिति कोई खण्ड या अनुसूची अथवा संशोधित रूप में कोई खण्ड या अनुसूची पृथक रूप से मतदान के लिए रखी जाए तो अध्यक्ष द्वारा यथास्थिति उस खंड या अनुसूची को अथवा संशोधित रूप में खंड या अनुसूची को पृथक रूप से रखा जाएगा:

परन्तु यह और भी कि संक्षिप्त नाम, अधिनियम सूत्र और पूरा नाम साधारण बहुमत द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।

156. संशोधनों पर मतदान.—खंडों या अनुसूचियों के संशोधनों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से उसी रीति से होगा जैसा कि किसी अन्य विधेयक की अवस्था में।

157. प्रस्तावों पर मतदान.—यदि ऐसे विधेयक के संबंध में प्रस्ताव यह है कि:—

(एक) विधेयक पर विचार किया जाए; या

(दो) विधेयक पर सभा की, यथास्थिति, प्रवर समिति अथवा सदनों की संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाए; या

(तीन) यथास्थिति, विधेयक अथवा यथासंशोधित विधेयक पारित किया जाए;

तो वह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ समझा जाएगा यदि वह सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित हो जाए।

158. विभाजन द्वारा मतदान.—(1) जब कभी कोई प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत किया जाना हो तो मतदान विभाजन द्वारा होगा।

(2) यदि मतदान का परिणाम यह बतलाए कि सभा की समस्त सदस्य-संख्या बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है तो अध्यक्ष द्वारा परिणाम विधो-नित करते हुए यह कथन किया जाएगा कि प्रस्ताव सभा की समस्त संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हुआ है।

159. अवशिष्ट प्रक्रिया.—दूसरे सब प्रकरणों में, इन नियमों में अन्य विधेयकों के संबंध में दी गई प्रक्रिया लागू होगी।

व्याख्या—इन नियमों में निर्दिष्ट पदावलि "समस्त सदस्य-संख्या" का तात्पर्य सदस्यों की उस समस्त संख्या से है जिससे सभा सन्निर्मित हो चाहे किसी भी कारण कुछ रिक्रितियां या अनुपस्थितियां हों।

अध्याय 12

याचिकाएं

160. याचिकाओं की व्याप्ति.—किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की सम्मति से निम्न पर याचिकाएं सभा में उपस्थित की जा सकेंगी;¹

(एक) ऐसा विधेयक जो नियम 64 के अंतर्गत प्रकाशित हो चुका हो या जो सभा में पुरःस्थापित हो चुका हो;

(दो) सभा के सामने लंबित कार्य से संबंधित कोई वि-य; और

(तीन) सामान्य लोक-हित का कोई भी वि-य, परन्तु जब तक कि वह ऐसा न हो:—

(क) जो भारत के किसी भाग में अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय या किसी जांच न्यायालय या

किसी संविहित न्यायाधीकरण या प्राधिकारी या किसी अर्द्धन्यायिक निकाय या आयोग के संज्ञान में हो;

(ख) जो साधारणतया किसी राज्य के विधान मंडल में उठाया जाना चाहिए;

(ग) जो किसी मूल प्रस्ताव या संकल्प द्वारा उठाया जा सकता है; या

(घ) जिसके लिए विधि के अंतर्गत उपचार उपलब्ध है, और विधि में नियम, विनियम, उपनियम सम्मिलित हैं जो भारत सरकार या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा बनाए गए हों जिसे ऐसे नियम, विनियम आदि बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित हो।

160 क. वित्तीय वि-यों से संबंधित याचिकाएं.—ऐसी याचिका, जो अनुच्छेद 110 के खण्ड (1) के उप खण्डों (क) से (च) में उल्लिखित किसी वि-य से संबंधित हो अथवा जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय अंतर्गस्त हो, सभा में प्रस्तुत नहीं की जाएगी जब तक उस पर रा-ट्रूपति द्वारा सिफारिश न की गई हो।

161. याचिका का सामान्य प्रपत्र.—(1) पहली अनुसूची में दिया गया याचिका का सामान्य प्रपत्र ऐसे परिवर्तनों के साथ, जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों, उपयोग में लाया जा सकेगा और यदि उपयोग में लाया जाए तो वह पर्याप्त होगा।

(2) प्रत्येक याचिका सम्मानपूर्ण, शि-ट और संयत भा-ना में लिखी जाएगी।

(3) प्रत्येक याचिका या तो हिन्दी या अंग्रेजी भा-ना में ही होगी। यदि कोई याचिका किसी अन्य भारतीय भा-ना में दी जाए तो उसके साथ उसका हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद संलग्न होगा और उस पर याचिका देने वाले के हस्ताक्षर होंगे।

162. याचिका का प्रमाणीकरण.—(1) याचिका के प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम और पता उसमें दिया जाएगा और याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर से और यदि निश्चर हो तो याचिकाकर्ता के अंगूठे के निशान से प्रमाणीकृत किया जाएगा।

(2) जब किसी याचिका के एक से अधिक हस्ताक्षरकर्ता हों, तो उस पत्र पर जिस पर याचिका उत्कीर्ण की गई हो, कम-से-कम एक व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा अथवा, यदि ऐसा व्यक्ति निश्चर हो, तो अपने अंगूठे का निशान लगाएगा। यदि एक से अधिक पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हों अथवा अंगूठे के निशान लगाए गए हों, तो प्रत्येक पत्र के शी-र्ष पर याचिका की प्रार्थना को दोहराया जाएगा।

163. किसी याचिका के साथ दस्तावेज नहीं लगाया जाएगा.—किसी याचिका के साथ पत्र, शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं लगाया जाएगा।

¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 17.02.2014, पैरा संख्या 6174 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

164. प्रतिहस्ताक्षर.—(1) [प्रत्येक याचिका पर याचिका प्रस्तुत करने वाले सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।]² यदि याचिका हिन्दी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा में दी जाए तो उसके हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद पर भी याचिका प्रस्तुत करने वाले सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) सदस्य अपनी स्वयं की कोई याचिका प्रस्तुत नहीं करेगा/करेगी।

165. याचिका सभा को संबोधित की जाएगी.—प्रत्येक याचिका सभा को संबोधित की जाएगी और जिस वि-नय से उसका संबंध हो उसके बारे में याचिका देने वाले के निश्चित उद्देश्य का वर्णन करने वाली प्रार्थना के साथ समाप्त होगी।

166. प्रस्तुतिकरण की सूचना.—सदस्य महासचिव को याचिका प्रस्तुत करने के अपने विचार की पूर्व सूचना देगा/देगी।

167. याचिका का प्रस्तुतीकरण.—[याचिका सदस्य द्वारा सभा को प्रस्तुत की जा सकेगी। ऐसे प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण पर किसी वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी।]³

168. प्रस्तुतीकरण का रूप .—याचिका प्रस्तुत करने वाला सदस्य निम्न रूप में कथन करने तक ही सीमित रहेगा/रहेगी:—

महोदया/महोदय, मैं.....के संबंध में याचिका देने वाले (लों) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ और इस कथन पर किसी वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी।

169. याचिका समिति को निर्देश.—[प्रत्येक याचिका सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद]⁴ याचिका समिति को सौंपी गई समझी जाएगी।

[याचिका समिति संबंधी नियमों के लिए इस नियमावली का अध्याय 26 देखिये]

अध्याय 13

संकल्प

170. संकल्प की सूचना.—मंत्री को छोड़कर कोई सदस्य, जो गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत दिन संकल्प प्रस्तुत करना चाहता हो, शलाका (बैलट) की तारीख से कम-से-कम दो दिन पहले इस आशय की सूचना देगा/देगी। उन सब सदस्यों के नामों की, जिनसे ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, शलाका निकाली जाएगी (बैलट किया जाएगा) और जो सदस्य गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत दिन के लिए शलाका में पहले तीन स्थान प्राप्त करेंगे वे शलाका की तारीख के बाद दो दिन के अन्दर एक-एक संकल्प की सूचना दे सकेंगे।

171. संकल्प का रूप .—संकल्प राय की घोषणा अथवा सिफारिश के रूप में हो सकेगा या ऐसे रूप में हो सकेगा जिससे कि सरकार के किसी काम अथवा नीति का सभा द्वारा अनुमोदन या अननुमोदन अभिलिखित किया जाए या कोई संदेश दिया जाए या किसी कार्यवाही के लिये संस्तवन, अनुरोध या प्रार्थना की जाए या किसी वि-नय अथवा स्थिति पर सरकार द्वारा पुनर्विचार के लिए ध्यान आकर्षित किया जाए या किसी ऐसे अन्य रूप में हो सकेगा जो अध्यक्ष उचित समझे।

172. संकल्प का वि-नय.—इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य या मंत्री सामान्य लोक-हित के किसी वि-नय के संबंध में संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा।

173. संकल्प की ग्राह्यता.—कोई संकल्प ग्राह्य हो सके इसके लिए वह निम्न शर्तें पूरी करेगा, अर्थात्—

(एक) वह स्पष्टतया और सुतथ्यतया व्यक्त किया जाएगा;

(दो) उसमें सारवान रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जाएगा;

(तीन) उसमें प्रतर्क, अनुमान व्यंग्यात्मक पद, लांछन या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे;

(चार) उसमें व्यक्तियों के पदेन या सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उसके आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं होगा; और

(पांच) वह किसी ऐसे वि-नय से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायनिर्णयन के अन्तर्गत हो।

174. अध्यक्ष ग्राह्यता विनिश्चित करेगा.—अध्यक्ष द्वारा यह विनिश्चित किया जाएगा कि कोई संकल्प या उसका कोई भाग इन नियमों के अंतर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और किसी संकल्प अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकृत किया जा सकेगा जो अध्यक्ष की राय में संकल्प प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो अथवा सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये किया गया हो या इन नियमों के उल्लंघन में हो।

175. न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन मामले.—साधारणतया ऐसे संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जो किसी ऐसे वि-नय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी वि-नय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित हो:

² लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 17.02.2014, पैरा संख्या 6174 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

^{3, 4} लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 17.02.2014, पैरा संख्या 6174 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

परन्तु अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से ऐसे विनय को सभा में उठाने की अनुमति दी जा सकेगी जो जांच की प्रक्रिया का विनय या प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का यह समाधान हो जाए कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी, आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विनय के विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

176. संकल्प का प्रस्तुत किया जाना.—(1) कार्य-सूची में जिस सदस्य के नाम में संकल्प हो वह सदस्य सिवाय उस स्थिति में जबकि वह सदस्य उसे वापस लेना चाहता/चाहती हो, पुकारे जाने पर संकल्प प्रस्तुत करेगा/करेगी और उस अवस्था में, कार्य-सूची में दिए गए रूप में औपचारिक प्रस्ताव के साथ वह सदस्य अपना स्वयं का भा-ण प्रारम्भ करेगा/करेगी।

(2) कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुज्ञा से किसी अन्य सदस्य को, जिसके नाम में वही संकल्प कार्य-सूची में नीचे दिया हुआ हो, उसे अपनी ओर से प्रस्तुत करने का प्राधिकार दे सकेगा/सकेगी और इस तरह प्राधिकृत सदस्य उसे तदनुसार प्रस्तुत कर सकेगा/सकेगी।

(3) मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य यदि पुकारे जाने के समय अनुपस्थित हो तो उस सदस्य द्वारा उसकी ओर से लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष की अनुज्ञा से ऐसे सदस्य के नाम में रखा हुआ संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा/सकेगी।

177. संशोधन.—(1) संकल्प प्रस्तुत किये जाने के बाद कोई सदस्य, संकल्पों से संबंधित नियमों के अधीन रहते हुए संकल्प में संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) यदि ऐसे संशोधन की सूचना उस दिन से एक दिन पूर्व नहीं दी गई हो जिस दिन कि संकल्प प्रस्तुत किया जाए तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि अध्यक्ष संशोधन के प्रस्तुत किए जाने की अनुमति न दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

(3) यदि समय हो तो महासचिव द्वारा सदस्यों को समय-समय पर उन संशोधनों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी जिनकी सूचनाएं प्राप्त हुई हों।

178. भा-णों के लिए समय-सीमा.—किसी संकल्प पर भा-ण की अवधि, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, पन्द्रह मिनट से अधिक नहीं होगी:

परन्तु संकल्प का प्रस्तावक उसे प्रस्तुत करते समय और संबंधित मंत्री प्रथम बार भा-ण देते समय तीस मिनट तक या उससे इतने अधिक समय तक, जितने की अध्यक्ष अनुज्ञा दे, भा-ण दे सकेंगे।

179. चर्चा की व्याप्ति.—किसी संकल्प पर चर्चा संकल्प से सर्वथा संगत और उसकी व्याप्ति के भीतर होगी।

180. संकल्प और संशोधन की वापसी (1).—कार्य-सूची में जिस सदस्य के नाम में कोई संकल्प हो, वह सदस्य पुकारे

जाने पर संकल्प वापस ले सकेगा/सकेगी और उस अवस्था में वह सदस्य अपना कथन उस बात तक ही सीमित रखेगा/रखेगी।

(2) जिस सदस्य ने कोई संकल्प या संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया हो, वह उसे सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं लेगा/लेगी।

181. संकल्प को विभाजित करना.—जब अनेक विनयों से अंतर्ग्रस्त किसी संकल्प पर चर्चा हो चुकी हो तो अध्यक्ष द्वारा संकल्प को विभाजित किया जा सकेगा और जैसा अध्यक्ष द्वारा उचित समझा जाए प्रत्येक विनय या कोई विनय मत के लिये अलग-अलग रखा जा सकेगा।

182. संकल्प की पुनरुक्ति.—जब कोई संकल्प प्रस्तुत किया गया हो तो सारवान रूप से वही विनय उठाने वाला कोई संकल्प या संशोधन पूर्व संकल्प को प्रस्तुत करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा:

परन्तु जब कोई संकल्प सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया हो तो सारवान रूप से वही विनय उठाने वाला कोई संकल्प उसी सत्र के दौरान प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

183. मंत्री के पास पारित संकल्प भेजना.—प्रत्येक संकल्प की, जिसे सभा ने पारित किया हो, एक प्रति संबंधित मंत्री के पास भेजी जाएगी।

अध्याय 14

प्रस्ताव

184. लोक हित के किसी विषय पर चर्चा.—संविधान में या इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किए गए प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक हित के विनय पर कोई चर्चा नहीं होगी।

185. प्रस्ताव की सूचना.—प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप में दी जाएगी और महासचिव को सम्बोधित होगी।

186. प्रस्ताव की ग्राह्यता.—कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके इसके लिए वह निम्न शर्तें पूरी करेगा, अर्थात्—

(एक) उसमें सारवान रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जाएगा;

(दो) उसमें प्रतर्क, अनुमान व्यंग्यात्मक पद, लांछन या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे;

(तीन) उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं होगा;

(चार) वह किसी हाल ही में घटित विनय तक निर्बन्धित रहेगा;

(पांच) उसमें विश-नाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा;

(छह) उसमें ऐसे विनय पर फिर चर्चा नहीं चलाई जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो;

(सात) उसमें ऐसे विनय की पूर्वाशा नहीं की जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की संभावना हो;

(आठ) वह किसी ऐसे विनय से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायनिर्णयन के अंतर्गत हो;

[***]¹

(नौ) यदि उसमें कोई कथन हो तो सदस्य उस कथन की परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा/होगी;

(दस) उसमें गैर-सरकारी सदस्य द्वारा सभा पटल पर रखे गए दस्तावेज अथवा पत्र पर चर्चा की मांग नहीं की जाएगी;

(ग्यारह) सामान्यतया वह किसी संसदीय समिति के विचाराधीन मामलों से संबंधित नहीं होगा;

(बारह) उसमें राय प्रकट करने या किसी अमूर्त विधि संबंधी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए नहीं पूछा जाएगा;

(तेरह) वह उस विनय से संबंधित नहीं होगा जो मुख्यतया भारत सरकार का विनय न हो;

(चौदह) उसमें ऐसे निकायों या व्यक्तियों के नियंत्रणाधीन विषय नहीं उठाए जाएंगे जो मुख्यतया भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी न हों;

(पन्द्रह) उसका किसी ऐसे विनय से संबंध नहीं होगा जिसमें मंत्री पदेन संबंधित न हो;

(सोलह) उसमें किसी मित्र देश के प्रति अविनयपूर्ण निर्देश नहीं होगा;

(सत्रह) उसमें ऐसे विनयों के बारे में निर्देश नहीं किया जाएगा या उनके बारे में जानकारी प्रकट करने की मांग नहीं की जाएगी जो गोपनीय स्वरूप के हों, जैसे मंत्रिमंडल में की जाने वाली चर्चाएं या रा-द्रूपति को किसी ऐसे विनय के बारे में दी गई मंत्रणा जिसके संबंध में जानकारी प्रकट न करने का संवैधानिक, संविहित या रूढ़िगत दायित्व हो; और

(अठारह) वह किसी तुच्छ विनय से संबंधित नहीं होगा।]²

187. अध्यक्ष द्वारा ग्राह्यता विनिश्चित किया जाना.—अध्यक्ष द्वारा यह विनिश्चित किया जाएगा कि कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग इन नियमों के अंतर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और किसी प्रस्ताव या उसके किसी भाग को अस्वीकृत

किया जा सकेगा जो अध्यक्ष की राय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए हो या इन नियमों के उल्लंघन में हो।

188. न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन मामले.—साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जो किसी ऐसे विनय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विनय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो:

परन्तु अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से ऐसे विनय को सभा में उठाने की अनुमति दी जा सकेगी जो जांच की प्रक्रिया या विनय या प्रक्रम से संबंधित हो यदि अध्यक्ष का यह समाधान हो जाए कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकरण या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विनय के विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

189. गृहीत प्रस्तावों का प्रकाशन.—यदि अध्यक्ष द्वारा किसी प्रस्ताव की सूचना ग्रहण कर ली जाए और ऐसे प्रस्ताव की चर्चा के लिए कोई तिथि निश्चित न की जाए तो वह सूचना [*****]³ लोक सभा समाचार में, "अनियत दिन वाले प्रस्ताव" शीर्षक के साथ, अधिसूचित की जाएगी।

190. चर्चा के लिए समय का नियतन.—अध्यक्ष द्वारा सभा के कार्य की स्थिति पर विचार किए जाने के बाद और सभा नेता के परामर्श से [या कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर]⁴ ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत किया जा सकेगा।

191. निश्चित समय पर प्रश्न पूछा जाना.—अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, नियत दिन या नियत दिनों के अंतिम दिन निश्चित समय पर मूल प्रश्न पर सभा का विनिश्चय निर्धारित करने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरंत रखा जाएगा।

192. भा-णों के लिए समय-सीमा.—अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए, भा-णों के लिए समय-सीमा विहित की जा सकेगी।

अध्याय 15

अल्पकालीन चर्चा

193. चर्चा उठाने की सूचना.—अवलम्बनीय लोक-महत्व के विनय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाए जाने वाले विनय का स्प-टतया तथा सुतथ्यतया उल्लेख कर महासचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकेगा/सकेगी:

¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा लोप किया गया।

² लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा जोड़ा गया।

³ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा लोप किया गया।

⁴ वही, अंतःस्थापित किया गया।

परंतु सूचना के साथ उक्त वि-य पर चर्चा उठाने के कारण देते हुए एक व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न होगी:

परंतु यह और भी कि सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से होगा।

194. अध्यक्ष द्वारा ग्राह्यता का विनिश्चय और समय का नियमन किया जाना (1).—यदि अध्यक्ष का, सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद, जिसे अध्यक्ष आवश्यक समझे, समाधान हो जाए कि वि-य अविलम्बनीय है और सभा में जल्दी ही उठाए जाने के लिए पर्याप्त महत्व का है तो अध्यक्ष द्वारा सूचना ग्रहण की जा सकेगी:

परंतु यदि ऐसे वि-य पर चर्चा के लिए अन्यथा जल्दी अवसर उपलब्ध हो तो अध्यक्ष द्वारा सूचना ग्रहण करने से इंकार किया जा सकेगा।

(2) अध्यक्ष द्वारा एक सप्ताह में ऐसी दो बैठकें नियत की जा सकेंगी जब ऐसे वि-य चर्चा हेतु लिए जा सकें और चर्चा के लिए उतने समय की अनुमति दी जा सकेगी जितना कि अध्यक्ष परिस्थितियों में उचित समझे और जो बैठक की समाप्ति पर अथवा उससे पहले '[दो] घंटे से अधिक न हो।

195. कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा.—सभा के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न ही मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा/सकेगी और मंत्री द्वारा संक्षेप में उत्तर दिया जाएगा। जिस सदस्य ने अध्यक्ष को पहले से सूचित कर दिया हो उसे चर्चा में भाग लेने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

196. भा-णों के लिए समय सीमा.—अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए, भा-णों के लिए समय-सीमा विहित की जा सकेगी।

अध्याय 16

ध्यानाकर्षण

197. ध्यानाकर्षण के बारे में प्रक्रिया (1).—कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी वि-य पर मंत्री का ध्यान दिला सकेगा/सकेगी और मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा/सकेगी या बाद के किसी समय या तिथि को वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकेगा/सकेगी:

परंतु कोई सदस्य किसी एक बैठक के लिए ऐसी दो से अधिक सूचनाएं नहीं दे सकेगा/सकेगी।

(2) ¹[ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाए, कोई वाद-विवाद नहीं होगा, परंतु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य-सूची में मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से स्प-टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकेगा/सकेगी और ऐसे सभी प्रश्नों के अंत में मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया जाएगा:

परंतु कार्य-सूची में पांच से अधिक सदस्यों के नाम नहीं दिखाए जाएंगे।]

व्याख्या —(एक) जहां किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे वहां यह समझा जाएगा कि केवल पहले हस्ताक्षरकर्ता ने सूचना दी है।

(दो) किसी बैठक के लिए 10.00 बजे तक प्राप्त सूचनाओं को उसी दिन 10.00 बजे प्राप्त समझा जाएगा और एक ही वि-य पर प्रत्येक ऐसी सूचना की सापेक्ष पूर्ववर्तिता निर्धारित करने के लिए बैलट किया जाएगा। 10.00 बजे के पश्चात् प्राप्त सूचनाओं को अगली बैठक के लिए दिया गया समझा जाएगा।

²[(तीन) किसी सप्ताह में उसकी पहली बैठक से सप्ताह के अंतिम दिन 10.00 बजे तक जिस दिन सभा की बैठक हुई हो, प्राप्त सूचनाएं उस सप्ताह के लिए वैध होंगी, सप्ताह के अंतिम दिन, जिस दिन सभा की बैठक हुई हो 10.00 बजे के बाद प्राप्त सूचनाएं अगले सप्ताह के लिए वैध होंगी।

(चार) यदि अध्यक्ष द्वारा गृहीत किसी वि-य संबंधी सूचनाएं देने वाले सदस्यों की संख्या (पांच या पांच से कम)³ हो तो उनकी परस्पर वरीयता सूचना प्राप्त होने की तिथि और समय के अनुसार निर्धारित की जाएगी।]

(3) एक ही बैठक में दो से अधिक ऐसे वि-य नहीं उठाए जाएंगे:

परंतु दूसरा वि-य उन्हीं सदस्यों द्वारा नहीं उठाया जाएगा जिन्होंने पहला वि-य उठाया है और वह (ऐसे समय)⁴ उठाया जाएगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जाए।

(4) एक ही दिन के लिए एक से अधिक विषय प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में उस वि-य को पूर्ववर्तिता दी जाएगी जो अध्यक्ष की राय में अधिक अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण हो।

⁵[(5) वे सभी सूचनाएं जो उस सप्ताह में नहीं ली गई हैं, जिसके लिए वे दी गई थीं उस सप्ताह के अंत में व्यपगत हो जाएंगी, जब तक कि अध्यक्ष द्वारा उनमें किसी को किसी बाद की बैठक के लिए गृहीत न कर लिया हो:

¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 30.04.1987, पैरा संख्या 1639 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

² वही, जोड़ा गया।

³ लोक सभा समाचार भाग -दो, दिनांक 09.05.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

⁴ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 09.05.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

⁵ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 30.04.1987, पैरा संख्या 1639 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

परंतु मंत्री को तथ्यों की जानकारी के लिए भेजी गई सूचना तब तक व्यपगत नहीं होगी जब तक कि अध्यक्ष द्वारा उसे निपटा न दिया जाए।]

अध्याय 17

मंत्रिपरि-द् में अविश्वास का प्रस्ताव और पदत्याग करने वाले मंत्री का वक्तव्य

198. मंत्रिपरि-द् में अविश्वास का प्रस्ताव करने संबंधी प्रक्रिया(1).—मंत्रिपरि-द् में विश्वास का अभाव प्रकट करने का प्रस्ताव निम्नलिखित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) प्रस्ताव करने की अनुमति अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने पर सदस्य को मांगनी होगी;

(ख) अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन [दस बजे तक]¹ महासचिव के पास उस प्रस्ताव की, जिसे वह सदस्य प्रस्तुत करना चाहे, लिखित सूचना देनी होगी:

[परंतु 10.00 बजे के बाद प्राप्त सूचनाओं को सभा की अगले दिन होने वाली बैठक के 10.00 बजे तक प्राप्त हुआ माना जाएगा।]²

(2) यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रस्ताव नियमानुसार है तो अध्यक्ष द्वारा सभा में प्रस्ताव पढ़कर सुनाया जाएगा और उन सदस्यों से, जो अनुमति दिए जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों में खड़े होने के लिए प्रार्थना की जाएगी और यदि तदनुसार कम से कम पचास सदस्य खड़े हो जायें तो अध्यक्ष द्वारा यह सूचित किया जाएगा कि अनुमति दी जाती है और प्रस्ताव किसी ऐसे दिन लिया जाएगा जो अनुमति मांगने के दिन से दस दिन से अधिक बाद का न हो। यदि पचास से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष द्वारा सदस्य को यह सूचित किया जाएगा कि उस सदस्य को सभा की अनुमति नहीं है।

(3) यदि उपनियम (2) के अंतर्गत अनुमति दे दी जाए तो अध्यक्ष द्वारा सभा के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद, प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत किया जा सकेगा।

(4) अध्यक्ष द्वारा यथास्थिति, नियत दिन या नियत दिनों में से अंतिम दिन निश्चित समय पर, प्रस्ताव सभा का विनिश्चय निर्धारित करने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरंत रखा जाएगा।

(5) अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए, भा-णों के लिए समय-सीमा विहित की जा सकेगी।

199. मंत्री का वक्तव्य जिसने पदत्याग किया हो.—(1) जो सदस्य मंत्रिपद का त्याग कर दे वह सदस्य अध्यक्ष की

सम्मति से अपने पदत्याग के स्पष्टीकरण के लिए [उस सत्र के दौरान किसी दिन जिसमें रा-ट्रपति द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया गया हो, व्यक्तिगत वक्तव्य दे सकेगा/सकेगी:

परंतु यदि रा-ट्रपति द्वारा त्यागपत्र ऐसे समय स्वीकार किया जाता है जब सभा का सत्र न हो तो सदस्य सत्र शुरू होने की तारीख से सात दिन के भीतर शीघ्र ही किसी दिन ऐसा वक्तव्य दे सकेगा/सकेगी।]³

(2) जिस दिन वक्तव्य दिया जाए उससे [कम से कम]⁴ एक दिन पहले, उसकी एक प्रति अध्यक्ष और सभा-नेता को भेजी जाएगी:

[*** *** ***]⁵

(3) ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा, किन्तु उसके दिए जाने के बाद कोई मंत्री तत्संगत वक्तव्य दे सकेगा/सकेगी।

अध्याय 18

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संकल्प

200. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प की सूचना.—(1) कोई सदस्य जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 94 के खंड (ग) के अंतर्गत किसी संकल्प की सूचना देना चाहे तो वह लिखित रूप में महासचिव को देगा/देगी [और ऐसे संकल्प का पूर्णपाठ प्रस्तुत करेगा/करेगी।]¹

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए गए किसी दिन की कार्य-सूची में सम्बन्धित सदस्य के नाम में दर्ज कर दिया जाएगा, परन्तु उस तरह निश्चित किया गया दिन संकल्प की सूचना प्राप्त होने की तिथि से चौदह दिन बाद का कोई दिन होगा।

200क. संकल्प की ग्राह्यता.—[इस प्रकार के संकल्प को ग्राह्य बनाने के लिए उसे निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

(एक) वह आरोपों के संबंध में सुस्प-ट होगा;

(दो) वह स्प-ट और सही रूप से व्यक्त किया गया होगा;

(तीन) इसमें तर्क-वितर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक भा-ना, आरोप अथवा मानहानिकारक वक्तव्यों का समावेश नहीं होगा।]²

201. संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति.—(1) संविधान के अनुच्छेद 96 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,

¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 1.8.1989, पैरा संख्या 3091 द्वारा जोड़ा गया।

² वही, जोड़ा गया।

³ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 3091 द्वारा जोड़ा गया।

⁴ वही, अंतःस्थापित किया गया।

⁵ वही, लोप किया गया।

¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 1.8.1989, पैरा संख्या 3091 द्वारा जोड़ा गया।

² लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 1.8.1989, पैरा संख्या 3091 द्वारा, अंतःस्थापित किया गया।

जब नियम 200 के उपनियम (2) के अंतर्गत कोई प्रस्ताव विचार के लिए लिया जाये तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या संविधान के अनुच्छेद 95 के खंड (2) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा/होगी।

(2) कार्य-सूची में जिस सदस्य के नाम में प्रस्ताव हो वह सदस्य [जब तक वह सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए एक वक्तव्य नहीं देता/देती, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा/करेगी, किंतु इनमें से किसी भी मामले से]³ इस प्रक्रम पर भा-नण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(3) यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति द्वारा उसके बाद प्रस्ताव को सभा के सामने रखा जाएगा और उन सदस्यों से, जो अनुमति दिए जाने के पक्ष में हों अपने स्थानों में खड़े होने के लिए प्रार्थना की जाएगी। यदि तदनुसार कम से कम पचास सदस्य खड़े हो जाएं तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति द्वारा यह कथन किया जाएगा कि अनुमति दी गई है और यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति द्वारा यह कथन किया जाएगा कि संकल्प किसी ऐसे दिन लिया जाएगा जो यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति द्वारा या नियत किया जाए और जो अनुमति मांगने के दिन से दस दिन से अधिक बाद का न हो। यदि पचास से कम सदस्य खड़े हों तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति द्वारा सदस्य को सूचित किया जाएगा कि उस सदस्य को सभा की अनुमति नहीं है।

202. कार्य-सूची में संकल्प का सम्मिलित किया जाना.—संकल्प नियत दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

[202क. चर्चा की व्याप्ति.—संकल्प पर चर्चा पूरी तरह से संकल्प में लगाए गए आरोपों तक ही सीमित होगी।]⁴

203. भा-णों के लिए समय-सीमा.—किसी संकल्प पर भा-नण की अवधि, अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति की अनुमति के बिना, पन्द्रह मिनट से अधिक नहीं होगी:

परंतु संकल्प का प्रस्तावक उसे प्रस्तुत करते समय इतने अधिक समय तक भा-नण दे सकेगा/सकेगी जितने कि अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति द्वारा अनुज्ञा दी जाए।

अध्याय 19

वित्तीय कार्य

आय-व्ययक

204. आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण.—(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण या

³ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

प्राक्कलित आय और व्यय का विवरण (जिसे इसके पश्चात् “आय-व्ययक” कहा गया है) सभा में ऐसे दिन प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि रा-ट्रपति द्वारा निदेश दिया जाए।

(2) आय-व्ययक सभा के सामने ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जाएगा जो वित्त मंत्री द्वारा प्राक्कलन समिति के सुझावों पर, यदि कोई हों, विचार करने के बाद तय किया जाए।

205. प्रस्तुतिकरण के दिन चर्चा न होना.—आय-व्ययक पर उस दिन कोई चर्चा नहीं होगी जिस दिन कि वह सभा में प्रस्तुत किया जाए।

अनुदान की मांगें

206. अनुदानों की मांगें.—(1) प्रत्येक मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अनुदान के संबंध में साधारणतया एक पृथक मांग की जाएगी, परंतु वित्त मंत्री द्वारा दो या अधिक मंत्रालयों या विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों को एक मांग में सम्मिलित की जा सकेगी या ऐसे व्यय के संबंध में एक मांग की जा सकेगी, जिसका वर्गीकरण विशेष मंत्रालयों के अंतर्गत सहज में न किया जा सके।

(2) प्रत्येक मांग में पहले समस्त प्रस्तावित अनुदान का विवरण और उसके बाद मदों में विभाजित प्रत्येक अनुदान के अंतर्गत विस्तृत प्राक्कलन का विवरण होगा।

207. आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा(1).—जिस दिन आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाए उसके बाद अध्यक्ष द्वारा नियत किए जाने वाले दिन, और उतने समय के लिए, जितना कि अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किया जाए, सभा आय-व्ययक पर सम्पूर्ण रूप से या उसमें अन्तर्निहित सिद्धान्त के किसी प्रश्न पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होगी, किन्तु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और न ही आय-व्ययक सभा में मतदान के लिए रखा जाएगा।

(2) वित्त मंत्री को चर्चा के अन्त में उत्तर देने का सामान्य अधिकार होगा।

(3) अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए, भा-णों के लिए समय-सीमा विहित की जा सकेगी।

208. अनुदानों की मांगों पर मतदान.—(1) अध्यक्ष द्वारा, सभा नेता के परामर्श से, अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए उतने दिन नियत किए जाएंगे जो लोक हित से सुसंगत हों।

(2) अध्यक्ष द्वारा नियत दिनों के अन्तिम दिन 17.00 बजे अथवा किसी ऐसे अन्य समय पर जो अध्यक्ष द्वारा पहले से निश्चित कर दिया जाए अनुदानों की मांगों के संबंध में सभी अवशिष्ट वि-नयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरंत रखा जाएगा।

⁴ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 1.8.1989, पैरा संख्या 3091 द्वारा अंतःस्थापित किया गया।

(3) किसी अनुदान की मांग को कम करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

(4) किसी अनुदान की मांग को कम करने के प्रस्तावों में संशोधन की अनुज्ञा नहीं होगी।

(5) जब एक ही अनुदान की मांग से संबंधित कई प्रस्ताव दिए जायें तब उन पर क्रम से चर्चा होगी जिसमें कि उनसे संबंधित शीर्ष आय-व्ययक में दिए हों।

209. कटौती प्रस्ताव.—किसी मांग की राशि कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसी ढंग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा:—

(क) “कि मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए”, जो मांग में अन्तर्निहित नीति से अनुमोदन प्रकट करने के लिए हो। ऐसा प्रस्ताव “नीति अनुमोदन कटौती” कहा जाएगा। ऐसे प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्य द्वारा उस नीति का ब्योरा सुतथ्यतया दर्शित किया जाएगा जिस पर सदस्य चर्चा करना चाहता/चाहती हो। चर्चा, सूचना में उल्लिखित विशिष्ट बात या बातों तक ही सीमित रहेगी और सदस्य वैकल्पिक नीति का सुझाव दे सकेंगे।

(ख) “कि मांग की राशि में उल्लिखित राशि की कमी की जाए” जो की जा सकने वाली मितव्ययता का प्रतीक हो। ऐसी उल्लिखित राशि या तो मांग में से एकमुश्त घटाई जाने वाली राशि हो सकेगी या मांग की किसी मद का विलोपन अथवा उसमें घटाई जाने वाली राशि हो सकेगी। ऐसा प्रस्ताव “मितव्ययिता कटौती” कहा जाएगा।

सूचना में संक्षेप में और सुतथ्यतया वह विशेष विनय दर्शाया जायेगा, जिस पर चर्चा उठानी हो और भा-ण इस बात की चर्चा करने के लिए ही सीमित होंगे कि मितव्ययिता कैसे की जा सकती है;

(ग) “कि मांग की राशि में 100 रुपए की कमी की जाए”, जो ऐसी विशिष्ट शिकायत को प्रकट करने के लिए हो, जो भारत सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में हो, ऐसा प्रस्ताव “सांकेतिक कटौती” कहा जाएगा और उस पर चर्चा, प्रस्ताव में उल्लिखित विशेष शिकायत तक ही सीमित होगी।

210. कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता.—मांग की राशि कम करने की सूचना ग्राह्य हो सके, इसके लिए वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात्:—

(एक) उसका संबंध केवल एक मांग से होगा;

(दो) वह स्पष्ट-तया व्यक्त की जाएगी और उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, लांछन, विशेष-ण या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे;

(तीन) वह एक ही विशिष्ट विनय तक सीमित रखी जायेगी जिसका वर्णन सुतथ्य शब्दों में किया जाएगा;

(चार) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर अभ्युक्ति नहीं की जाएगी, जिसके आचरण पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो;

(पांच) उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन या निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिए जाएंगे;

(छह) वह ऐसे विनय का निर्देश नहीं करेगी, जो मुख्यतया भारत सरकार का विनय न हो;

(सात) उसका किसी ऐसे व्यय से संबंध नहीं होगा जो कि भारत की संचित निधि पर भारित हो;

(आठ) उसका किसी ऐसे विषय से संबंध नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायनिर्णयन के अंतर्गत हो;

(नौ) उसमें विशेष-नाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा;

(दस) उसमें ऐसे विनय पर फिर चर्चा नहीं की जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो और जिस पर विनिश्चय किया जा चुका हो;

(ग्यारह) उसमें उस विनय की पूर्वाशा नहीं की जाएगी, जो विचार के लिए पहले ही नियत किया जा चुका हो;

(बारह) उसमें साधारणतया ऐसे विनय पर चर्चा नहीं उठाई जाएगी जो कोई न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के, या किसी विनय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो;

परंतु अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से ऐसे विनय को सभा में उठाने की अनुमति दी जा सकेगी, जो जांच की प्रक्रिया अथवा प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का यह समाधान हो जाए कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी, आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विनय के विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है; और

(तेरह) उसका संबंध तुच्छ विनय से नहीं होगा।

211. अध्यक्ष ग्राह्यता का विनिश्चय करेगा.—अध्यक्ष द्वारा यह विनिश्चय किया जाएगा कि कोई कटौती प्रस्ताव इन नियमों के अंतर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और कोई कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत किया जा सकेगा जो अध्यक्ष की राय में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किया गया हो या इन नियमों के उल्लंघन में हो।

212. कटौती प्रस्ताव की सूचना.—यदि किसी मांग के अनुदान को कम करने के प्रस्ताव की उस दिन से एक दिन पूर्व सूचना दी गई हो, जिस दिन कि वह मांग विचाराधीन हो,

तो कोई भी सदस्य प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने की अनुमति न दी जाए, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

213. आय-व्यय का भागों में प्रस्तुतीकरण.—इससे पहले अंतर्वि-ट किसी नियम को सभा में आय-व्यय के दो या अधिक भागों में प्रस्तुत किए जाने से रोकने वाला नहीं समझा जायेगा और जब ऐसा प्रस्तुतीकरण हो तो प्रत्येक भाग पर इन नियमों के अनुसार उस प्रकार कार्रवाई की जायेगी जैसे कि वह आय-व्यय हो।

214. लेखानुदान(1).—लेखानुदान के प्रस्ताव में समस्त अपेक्षित राशि बतायी जाएगी और प्रत्येक मंत्रालय, विभाग या व्यय की मद के लिए आवश्यक विभिन्न धनराशियां, जिनसे वह राशि बनी है, प्रस्ताव में संलग्न अनुसूची में बतायी जाएगी।

(2) संपूर्ण अनुदान को कम करने के लिए या जिन मदों से मिलकर अनुदान बना हो, उनको कम करने या निकाल देने के लिए संशोधन प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

(3) प्रस्ताव पर या उस में प्रस्तावित किए गए संशोधनों पर सामान्य प्रकार की चर्चा की अनुमति दी जा सकेगी किंतु अनुदान के ब्योरे पर उससे अग्रेतर चर्चा नहीं होगी जितनी सामान्य विनयों को बताने के लिए आवश्यक हो।

(4) अन्य प्रकरणों में लेखानुदान के प्रस्ताव पर उसी प्रकार कार्रवाई की जायेगी जैसे कि वह अनुदान की मांग हो।

215. अनुपूरक आदि अनुदान तथा प्रत्ययानुदान.—अनुपूरक, अपर अतिरिक्त और अपवाद अनुदान तथा प्रत्ययानुदान ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो चाहे रूप भेद के हों या कुछ अंश जोड़कर या निकालकर बनाए गए हों जैसाकि अध्यक्ष द्वारा आवश्यक या वांछनीय समझा जाए, उसी प्रक्रिया से विनियमित होंगे जो अनुदानों की मांगों के संबंध में लागू होती हैं।

216. अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद की व्याप्ति.—अनुपूरक अनुदानों पर वाद-विवाद केवल उन मदों तक ही सीमित रहेगा जिनसे वे बने हों जहां तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्प-ट करने के लिए आवश्यक न हो, उस सीमा तक मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी।

217. सांकेतिक अनुदान.—जब किसी नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय के लिए पुनर्विनियोग द्वारा धन उपलब्ध किया जा सके तो किसी सांकेतिक राशि के अनुदान की मांग सभा में मतदान के लिए रखी जा सकेगी और यदि सभा मांग पर अनुमति दे दे तो धन इस तरह उपलब्ध किया जा सकेगा।

218. विनियोग विधेयक के बारे में प्रक्रिया(1).—संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विनियोग विधेयक के बारे में प्रक्रिया ऐसे रूप भेदों के साथ जैसे अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझे जाएं, वही होगी जो सामान्यतया विधेयकों के लिए होती है।

[(2) *** *** ***]¹

²[विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद लोक-महत्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों में अन्तर्निहित प्रशासकीय नीति के ऐसे विनयों तक सीमित रहेगा जो पहले ही उस समय न उठाये जा चुके हों जबकि संगत अनुदानों की मांगें विचाराधीन थीं।]

(3) अध्यक्ष द्वारा वाद-विवाद की पुनरुक्ति को रोकने की दृष्टि से विनियोग विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के इच्छुक सदस्यों द्वारा उन विशि-ट विनयों पर पूर्व सूचना दिए जाने की अपेक्षा की जा सकेगी जो वे उठाना चाहते हों और अध्यक्ष द्वारा ऐसे विनयों को उठाने के लिए अनुज्ञा रोकी जा सकेगी जो अध्यक्ष की राय में किसी अनुदान की मांग के संबंध में चर्चा किए गए विनयों की पुनरुक्ति प्रतीत होते हों या जो पर्याप्त लोक महत्व के न हों।

(4) यदि विनियोग विधेयक किसी वर्तमान सेवा के संबंध में अनुपूरक अनुदान के अनुसरण में हो तो चर्चा केवल उन्हीं मदों तक सीमित रहेगी जिनसे वह अनुदान बना हो और जहां तक चर्चाधीन खास मद की व्याख्या करने या उसे स्पष्ट करने के लिए आवश्यक न हो, उस सीमा तक मूल अनुदान पर या उससे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी।]

(5) अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए, भा-णों के लिए समय-सीमा विहित की जा सकेगी। ³[***]

वित्त विधेयक

219. वित्त विधेयक के बारे में प्रक्रिया (1).—इस नियम में “वित्त विधेयक” का तात्पर्य भारत सरकार की अगले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए साधारणतया प्रत्येक वर्ष पुरःस्थापित विधेयक से है और उसमें किसी कालावधि के लिए अनुपूरक वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने का विधेयक सम्मिलित है।

(2) सभा में वित्त विधेयक के पुरःस्थापित होने के बाद किसी भी समय अध्यक्ष द्वारा सभा द्वारा विधेयक के पारण में अन्तर्ग्रस्त सभी या किसी प्रक्रम को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से अलग-अलग एक या कई दिन नियत किया जा सकेगा और जब ऐसा नियत किया जा चुका है तो अध्यक्ष द्वारा यथास्थिति नियत दिन या नियत दिनों के अंतिम दिन [विनिर्दि-ट समय पर]⁴, उस प्रक्रम या प्रक्रमों के संबंध में, जिनके लिए एक या कई दिन नियत किए गए हों, सभी अवशि-ट विनयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरंत रखा जा सकेगा:

¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा लोप किया गया।

² वही, पुनराक्षरंकित ।

³ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा लोप किया गया।

⁴ वही, प्रतिस्थापित ।

परंतु यदि किसी मंत्री को उस प्रस्ताव पर वाद-विवाद का उत्तर देने का अधिकार हो, [जो विनिर्दिष्ट समय से एक घंटे पूर्व]⁵ चर्चाधीन हो और उसने उस समय उसका उत्तर देना आरम्भ न किया हो तो अध्यक्ष द्वारा उनसे पूछा जाएगा कि वह उत्तर देने के लिए कितना समय चाहता है, जो एक घंटे से अधिक न हो और सभा को तत्समय सम्बोधित कर रहे किसी भी सदस्य से ऐसे समय अपना आसन ग्रहण करने के लिए कहा जाएगा जिससे कि वह [विनिर्दिष्ट समय]⁶ से पहले उतना समय उपलब्ध रहे जितना मंत्री ने कहा है कि उसे अपने उत्तर के लिए आवश्यक है।

(3) जब उपनियम (2) के अनुसार, नियत दिन या नियत दिनों के अंतिम दिन [विनिर्दिष्ट समय]⁷ पर रखा जाने वाला प्रश्न या प्रश्नों में एक प्रश्न यह हो कि विधेयक पारित किया जाए तो इस बात के होते हुए भी कि विधेयक में संशोधन किए गए हैं, उपनियम (2) प्रभावी होगा।

(4) उपनियम (2) के परन्तुक के अधीन रहते हुए अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए, सभी या किसी प्रक्रम पर जिसके लिए उस उपनियम के अंतर्गत एक या अधिक दिन नियत किए गए हों, भाग-भागों के लिए समय-सीमा विहित की जा सकेगी।

(5) इस प्रस्ताव पर कि वित्त विधेयक पर विचार किया जाए, कोई सदस्य सामान्य प्रशासन, भारत सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में आने वाली स्थानीय शिकायतों या सरकार की धन या वित्तीय नीति से संबंधित विनयों की चर्चा कर सकेगा।

(6) अन्य प्रकरणों में इन नियमों के अध्याय 10 में विधेयकों पर लागू होने वाले नियम लागू होंगे।

220. वित्तीय कार्य के लिए नियत दिन को लिया जा सकने वाला कार्य।—इस बात के होते हुए भी कि नियम 207, 208, 218 या 219 के अंतर्गत वित्तीय कार्य के लिए कोई दिन नियत किया जा चुका हो, विधेयक या विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव किए जा सकेंगे और ऐसे दिन सभा द्वारा वह कार्य प्रारंभ करने से पहले जिसके लिए वह दिन नियत किया गया हो, विधेयक या विधेयकों को पुरःस्थापित किया जा सकेगा।

221. वित्तीय कार्य का समय पर पूरा किया जाना।—इन नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा जो समस्त वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करने के प्रयोजन के लिए, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य को निपटाने के लिए नियत समय सम्मिलित है, आवश्यक हों और जब इस तरह समय नियत किया जाए तो अध्यक्ष द्वारा निश्चित समय पर ऐसे प्रक्रम या प्रक्रमों से संबंधित, जिनके

लिए समय नियत किया गया हो, सब अवशिष्ट विनयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरंत रखा जाएगा।

व्याख्या—वित्तीय कार्य में कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित है जिसे अध्यक्ष द्वारा संविधान के अंतर्गत इस वर्ग का उहराया जाए।

[लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों संबंधी नियमों के लिए इस नियमावली का अध्याय 26 देखिए।]

अध्याय 20

विशेषाधिकार

विशेषाधिकार के प्रश्न

222. अध्यक्ष की अनुमति।—कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से, कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगा/सकेगी जिसमें या तो किसी सदस्य के या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का भंग अन्तर्गस्त हो।

223. विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना।—जो सदस्य विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहे वह उसकी लिखित सूचना उस दिन [10.00 बजे तक]¹ जिस दिन कि प्रश्न उठाने का विचार हो, महासचिव को देगा/देगी। यदि उठाया गया वह प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो तो सूचना के साथ वह दस्तावेज भी संलग्न होगा।

[परंतु 10.00 बजे के पश्चात् प्राप्त सूचनाओं को सभा की अगली बैठक के दिन 10.00 बजे प्राप्त हुई सूचनाएं समझा जाएगी।]²

224. विशेषाधिकार के प्रश्नों की ग्राह्यता।—विशेषाधिकार प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:—

(एक) एक ही बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे;

(दो) प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा;

(तीन) विषय में सभा का हस्तक्षेप अपेक्षित है।

225. विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की रीति (1).—अध्यक्ष द्वारा यदि नियम 222 के अंतर्गत सम्मति दी जाए और यह उहराया जाए कि चर्चा के लिए प्रस्तावित विनय नियमानुकूल है तो सम्बन्धित सदस्यों को पुकारा जाएगा जो अपने स्वयं के स्थान पर खड़े होंगे और विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति माँगते हुए उससे संगत एक संक्षिप्त वक्तव्य देंगे:

परंतु जब अध्यक्ष द्वारा इस नियम 222 के अंतर्गत अपनी सम्मति देने से इंकार कर दिया गया हो या अध्यक्ष की यह राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्तावित विनय नियमानुकूल नहीं हैं, तो

⁵ वही, प्रतिस्थापित।

⁶⁻⁷ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.05.2014, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

² वही, जोड़ा गया।

यदि आवश्यक समझा जाए, अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना को पढ़कर सुनाया जा सकेगा और यह कथन किया जा सकेगा कि सम्मति देने से इंकार किया जाता है या विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना नियमानुकूल नहीं है:

परंतु यह और भी कि यदि अध्यक्ष द्वारा विनय की अविलंबनीयता के संबंध में यह समाधान हो जाने पर प्रश्नों के निपटाए जाने के बाद बैठक के दौरान किसी भी समय विशेषाधिकार प्रश्न उठाए जाने की अनुमति दी जा सकेगी।

(2) यदि अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जाए तो अध्यक्ष द्वारा उन सदस्यों से जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कहा जाएगा और तदनुसार यदि कम से कम पच्चीस सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष द्वारा यह सूचित किया जाएगा कि उसे सभा की अनुमति दी जाती है। यदि पच्चीस से कम सदस्य खड़े हों, तो अध्यक्ष द्वारा सदस्य को यह सूचित किया जाएगा कि ऐसे सदस्य को सभा की अनुमति नहीं है।

226. विशेषाधिकार के प्रश्न पर सभा या समिति द्वारा विचार किया जाना.—यदि नियम 225 के अंतर्गत अनुमति दे दी जाए, तो सभा प्रश्न पर विचार कर सकेगी और विनिश्चय कर सकेगी या विशेषाधिकार प्रश्न उठाने वाले सदस्य द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगी।

227. अध्यक्ष द्वारा समिति को विशेषाधिकार के प्रश्न का सौंपा जाना.—इन नियमों में किसी बात के अन्तर्वि-ट होते हुए अध्यक्ष द्वारा कोई भी विशेषाधिकार प्रश्न जांच, अनुसंधान या प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकेगा।

228. अध्यक्ष की निदेश देने की शक्ति.—अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार समिति में या सभा में विशेषाधिकार प्रश्न पर विचार से संबंधित सब विनयों के बारे में प्रक्रिया विनियमन के लिए ऐसे निदेश दिए जा सकेंगे जो आवश्यक हों।

(अध्यक्ष को सदस्य के बन्दीकरण, निरोध आदि और रिहाई की सूचना)

229. सदस्य के बन्दीकरण, निरोध आदि के बारे में अध्यक्ष को सूचना.—जब कोई सदस्य किसी आपराधिक आरोप या किसी दंडापराध के लिए बन्दी बनाया जाए या उसे किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया जाए या किसी कार्यपालिका के आदेश के अंतर्गत निरुद्ध किया जाए, तो यथास्थिति, दंड देने वाला न्यायाधीश या दंडाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी तृतीय अनुसूची में दिए गए समुचित प्रपत्र में, यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध या दोष सिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना तुरंत अध्यक्ष को देगा/देगी।

230. सदस्य की रिहाई की अध्यक्ष को सूचना.—जब कोई सदस्य बन्दी बनाया जाए और दोन सिद्धि के बाद अपील लंबित होने तक जमानत पर रिहा किया जाए या अन्यथा रिहा किया जाए, तो ऐसे तथ्य की सूचना भी संबंधित प्राधिकारी द्वारा तृतीय अनुसूची में दिए गए समुचित प्रपत्र में अध्यक्ष को दी जाएगी।

231. बन्दीकरण, निरोध, रिहाई, आदि के बारे में प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई.—नियम 229 या नियम 230 में निर्दिष्ट संसूचना प्राप्त होने के बाद अध्यक्ष द्वारा यथासंभव शीघ्र उसे सभा में पढ़कर सुनाया जाएगा, यदि वह सत्र में हो या यदि सभा सत्र में न हो तो यह निदेश दिया जाएगा कि वह सदस्यों की जानकारी के लिए बुलेटिन (समाचार) में प्रकाशित कर दी जाए:

परंतु यदि किसी सदस्य की जमानत पर रिहाई या अपील पर मुक्ति की सूचना सभा को मूल बन्दीकरण की सूचना दी जाने से पहले ही प्राप्त हो जाए तो उसके बन्दीकरण या उसके बाद में रिहाई या मुक्ति का तथ्य अध्यक्ष चाहे तो सभा को सूचित न करे।

सभा के परिसर में बन्दीकरण और वैध आदेशों के निर्वहन के बारे में प्रक्रिया

232. सभा के परिसर में बन्दीकरण.—सभा के परिसर में अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त किए बिना कोई बन्दीकरण नहीं किया जाएगा।

233. वैध आदेश का निर्वहन.—सभा के परिसर में, अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी सिविल अथवा आपराधिक वैध आदेश का निर्वहन नहीं किया जाएगा।

[विशेषाधिकार समिति के नियमों के लिए इस नियमावली का अध्याय 26 देखिए]

अध्याय 21

अधीनस्थ विधान

234. विनियम, नियम आदि का पटल पर रखा जाना(1).—जब संविधान के या संसद द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में बनाए गए विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि सभा के सामने रखी जाए, तो संविधान या तत्संगत अधिनियम में उल्लिखित कालावधि जिसके लिए उसके रखे जाने की अपेक्षा हो, सभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने तथा बाद में सत्रावसान होने से पहले पूरी की जाएगी, जब तक कि संविधान या संगत अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो।

(2) जब उल्लिखित कालावधि इस तरह पूरी न हो, तो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि अनुवर्ती सत्र या सत्रों में पुनः रखे जाएंगे जब तक कि कथित कालावधि एक सत्र में पूरी न हो जाए।

235. विनियमों, नियमों आदि में संशोधनों पर विचार के लिए समय का नियतन.—अध्यक्ष द्वारा सदन-नेता के

परामर्श से, ऐसे विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि के किसी संशोधन पर, जिसकी किसी सदस्य द्वारा सूचना दी जाए, विचार करने और उसे पारित करने के लिए, एक या अधिक दिन या दिन का कोई भाग जैसा कि अध्यक्ष ठीक समझे, निश्चित किया जाएगा:

परंतु संशोधन की सूचना ऐसे रूप में होगी, जैसा कि अध्यक्ष समुचित समझे और उसमें इन नियमों का पालन किया जाएगा।

236. राज्य सभा को संशोधन भेजना.—संशोधन सभा द्वारा पारित किए जाने के बाद, राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए पहुंचाया जाएगा और राज्य सभा संशोधन की स्वीकृति का संदेश प्राप्त होने पर वह महासचिव द्वारा संबंधित मंत्री को भेजा जाएगा।

237. राज्य सभा द्वारा लौटाया गया संशोधन.—यदि राज्य सभा, सभा द्वारा पारित संशोधन से असहमत हो या उसे उसके अग्रेतर संशोधन के अधीन स्वीकार करे या उसके स्थान में अन्य संशोधन प्रस्तावित करे, तो सभा या तो संशोधन को छोड़ सकेगी या प्रस्तावित संशोधन में राज्य सभा से सहमत हो सकेगी या सभा द्वारा पारित मूल संशोधन पर आग्रह कर सकेगी। प्रत्येक दशा में राज्य सभा को संदेश भेजा जाएगा और यदि सभा, राज्य सभा द्वारा अग्रेतर संशोधित संशोधन से सहमत हो तो संशोधित संशोधन महासचिव द्वारा संबंधित मंत्री को भेजा जाएगा।

238. सदनों के बीच असहमति.—यदि सभा द्वारा पारित मूल संशोधन से राज्य सभा सहमत हो जाए, तो वह महासचिव द्वारा संबंधित मंत्री को भेजा जाएगा, किन्तु यदि राज्य सभा असहमत हो या ऐसे संशोधन पर आग्रह करे जिससे सभा सहमत न हुई हो तो समझा जाएगा कि दोनों सदन अन्तिम रूप से असहमत हो गए हैं और उस पर सब अग्रेतर कार्यवाही छोड़ दी जाएगी।

239. विनियम, नियम आदि का संशोधित रूप में पटल पर रखा जाना.—यदि किसी विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि में सदनों द्वारा पारित संशोधन के अनुसार रूप भेद किया जाए तो संशोधित विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि पटल पर रखे जाएंगे।

[अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के नियमों के लिए इस नियमावली का अध्याय 26 देखिए]

अध्याय 22

सभा में स्थानों का त्याग तथा उनकी रिक्तता

240. सभा में स्थानों का त्याग(1).—ऐसे किसी सदस्य द्वारा, जो सभा में अपने स्थान का त्याग करना चाहे सभा में अपने स्थान का त्याग करने के विचार की सूचना अध्यक्ष को संबोधित अपने स्वयं का हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा निम्न रूप में दी जाएगी और पदत्याग के लिए कोई कारण नहीं दिया जाएगा।

‘सेवा में,
अध्यक्ष,
लोक सभा,
नई दिल्ली।

महोदया/महोदय, मैं, एतद्द्वारा.....से सभा में अपने स्थान से पदत्याग करता/करती हूँ।

भवदीय,

स्थान.....तिथि.....

सभा सदस्य :

परंतु जब कोई सदस्य कोई कारण दे या कोई बाह्य विषय का उल्लेख करे तो अध्यक्ष द्वारा अपने, स्वविवेक का प्रयोग करते हुए ऐसे शब्दों, वाक्यांशों या विनय का लोप किया जाएगा और उन्हें सभा में नहीं पढ़ा जाएगा।

(1क) यदि कोई सदस्य अपना त्यागपत्र व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष को देता/देती है और सूचित करता/करती है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक एवं स्वाभाविक है एवं अध्यक्ष द्वारा/को इसके विपरीत कोई सूचना अथवा जानकारी न हो, तो अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र तत्काल स्वीकार कर लिया जाएगा।

(1ख) यदि त्यागपत्र अध्यक्ष को डाक द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति के जरिए प्राप्त होता है, तो अध्यक्ष द्वारा इस बात का समाधान करने के लिए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और स्वाभाविक है, ऐसी जाँच जो भी आवश्यक समझी जाए, की जा सकती है। यदि अध्यक्ष का स्वयं अपने द्वारा अथवा लोक सभा सचिवालय द्वारा अथवा किसी अन्य ऐसे अभिकरण द्वारा, जैसा अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझा जाए, की गई संक्षिप्त जांच के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक अथवा स्वाभाविक नहीं है तो अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(1ग) सदस्य द्वारा अपना त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने से पूर्व किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

(2) अध्यक्ष द्वारा सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र सभा को सूचित किया जाएगा कि अमुक सदस्य ने अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है और ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया गया है।

व्याख्या—यदि सभा का सत्र न चल रहा हो तो अध्यक्ष द्वारा सभा के पुनः समवेत होते ही सभा को इसकी सूचना दी जाएगी।

(3) अध्यक्ष द्वारा सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् महासचिव द्वारा, यथासंभव शीघ्र, वह जानकारी बुलेटिन तथा गजट में प्रकाशित कराई जाएगी तथा अधिसूचना

की एक प्रति निर्वाचन आयोग को इस प्रकार हुई रिक्तता की पूर्ति हेतु कार्रवाई करने के लिए भेजी जाएगी:

परंतु जब त्यागपत्र आगे की किसी तिथि से लागू होना है तो सूचना इसके लागू होने की तिथि से पूर्व बुलेटिन और गजट में प्रकाशित नहीं की जाएगी।

241. सभा में स्थानों का रिक्त होना(1).—संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड (4) के अंतर्गत किसी सदस्य का स्थान सभा की अनुमति से सदन-नेता के या किसी ऐसे अन्य सदस्य के प्रस्ताव पर, जिसे इस संबंध में कृत्यों का प्रत्यायोजन किया गया हो, रिक्त घोषित किया जाएगा,

(2) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो महासचिव द्वारा यह जानकारी गजट में प्रकाशित कराई जाएगी और अधिसूचना की एक प्रति निर्वाचन आयोग को इस प्रकार हुई रिक्तता की पूर्ति हेतु कार्रवाई करने के लिए भेजी जाएगी।

अध्याय 23

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

242. अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र(1).—ऐसा सदस्य, जो संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड (4) के अंतर्गत सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्राप्त करना चाहे, अध्यक्ष को लिखित रूप में आवेदन-पत्र देगा/देगी।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत आवेदन-पत्र में उस कालावधि का उल्लेख होगा, जिसके लिए अनुपस्थिति की अनुमति अपेक्षित हो और उसमें ऐसी अनुपस्थिति की अनुमति के आरंभ होने तथा समाप्त होने की तिथि और ऐसी अनुपस्थिति की अनुमति के आधार भी दर्शाए जाएंगे:

परंतु किसी एक समय साठ दिन की कालावधि से अधिक की अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया जाएगा।

243. समिति को आवेदन-पत्रों का प्रस्तुतीकरण.—नियम 242 के अंतर्गत सारे आवेदन-पत्र “सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति” संबंधी समिति को निर्दिष्ट होंगे।

244. सभा का विनिश्चय सदस्य को संसूचित किया जाना.—अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र के बारे में समिति की सिफारिश पर सभा द्वारा विनिश्चय व्यक्त किए जाने के पश्चात् महासचिव द्वारा यथासंभव शीघ्र, उस सदस्य को उसकी संसूचना दी जाएगी।

245. छुट्टी के असमाप्त भाग का व्यपगमन.—यदि कोई सदस्य, जिसे इन नियमों के अंतर्गत अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई हो, उस कालावधि के दौरान, जिसके लिए ऐसे सदस्य की अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई हो, सभा के सत्र में उपस्थित हो जाए तो सदस्य की पुनः उपस्थिति की तिथि से छुट्टी का असमाप्त भाग व्यपगत हो जाएगा।

[सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के नियमों के लिए इस नियमावली का अध्याय 26 देखिए।]

अध्याय 24

रा-द्रूपति तथा सभा के बीच संसूचना

246. रा-द्रूपति से सभा को संसूचना.—रा-द्रूपति से सभा को संसूचना रा-द्रूपति द्वारा हस्ताक्षर किए हुए लिखित संदेश द्वारा अध्यक्ष को दी जाएगी या यदि रा-द्रूपति सभा की बैठक के स्थान से अनुपस्थित हो तो वह संदेश मंत्री के माध्यम से अध्यक्ष को भेजा जाएगा।

247. सभा से रा-द्रूपति को संसूचना.—सभा से रा-द्रूपति को संसूचना—

(1) सभा में प्रस्ताव किए जाने और स्वीकृत हो जाने के बाद औपचारिक समावेदन द्वारा; और

(2) अध्यक्ष के माध्यम से,

दी जाएगी।

अध्याय 25

सभा की गोपनीय बैठक

248. गोपनीय बैठक(1).—सदन-नेता द्वारा प्रार्थना किए जाने पर अध्यक्ष द्वारा कोई दिन या उसका भाग सभा की गोपनीय बैठक के लिए निश्चित किया जाएगा।

(2) जब सभा की गोपनीय बैठक हो तो किसी बाहरी व्यक्ति को सभा-भवन, सभाकक्ष या दीर्घाओं में उपस्थित रहने की अनुज्ञा नहीं होगी:

परंतु राज्य सभा के सदस्य अपनी दीर्घा में उपस्थित रह सकेंगे:

परंतु यह और भी कि अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सभा-भवन, सभाकक्ष या दीर्घाओं में उपस्थित रह सकेंगे।

249. कार्यवाही का वृत्तांत.—अध्यक्ष द्वारा किसी गोपनीय बैठक की कार्यवाही का वृत्तांत ऐसी रीति से निकलवाया जा सकेगा जो अध्यक्ष ठीक समझे परंतु कोई अन्य उपस्थित व्यक्ति गोपनीय बैठक की किसी कार्यवाही या विनिश्चयों की, चाहे अंशतः अथवा पूर्णतः कोई टिप्पणी या अभिलेख नहीं रखेगा और न ऐसी कार्यवाही का वृत्तांत निकालेगा, न ही उसके वर्णन की चे-टा करेगा।

250. अन्य प्रकरणों में प्रक्रिया.—गोपनीय बैठक के संबंध में अन्य सब प्रकरणों में प्रक्रिया ऐसे निदेशों के अनुसार होगी जो अध्यक्ष द्वारा दिए जाएं।

251. कार्यवाही के प्रकाशन पर लगे प्रतिबंध का हटाया जाना(1).—जब यह समझा जाए कि किसी गोपनीय बैठक

की कार्यवाही के बारे में गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता नहीं रही है तो अध्यक्ष की सहमति के अधीन रहते हुए, सदन-नेता या इस प्रकार प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि गोपनीय बैठक के दौरान हुई सभा की कार्यवाही को अब गोपनीय न समझा जाए।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत प्रस्ताव के सभा द्वारा स्वीकार होने पर, महासचिव द्वारा गोपनीय बैठक की कार्यवाही का वृत्तांत तैयार कराया जाएगा और उसे, यथासाध्य शीघ्र, ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति से प्रकाशित कराया जाएगा, जैसे कि अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया जाए।

252. कार्यवाही या विनिश्चयों का प्रकट किया जाना.—

नियम 251 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी गोपनीय बैठक की कार्यवाही या विनिश्चयों का किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी रीति से प्रकट किया जाना सभा के विशेषाधिकार का घोर हनन समझा जाएगा।

अध्याय 26

संसदीय समितियां

सामान्य नियम

253. संसदीय समिति.—इस अध्याय में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो “समिति” का तात्पर्य है और उसके अंतर्गत है नियम 2 के उपनियम (1) में परिभाषित ‘संसदीय समिति’।

254. समिति की नियुक्ति(1).—समिति के सदस्य, प्रस्ताव किए जाने पर सभा द्वारा, यथास्थिति, नियुक्त या निर्वाचित अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किए जाएंगे।

(2) यदि कोई सदस्य संसदीय समिति में काम करने के लिए राजी न हो तो उसे समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा। प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि जिस सदस्य का नाम प्रस्तावित किया जा रहा है, वह समिति में सेवा करने के लिए राजी है या नहीं।

(3) समिति में आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति, यथास्थिति, प्रस्ताव किए जाने पर सभा द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचन से अथवा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशन से की जाएगी, और ऐसी रिक्तता की पूर्ति के लिए नियुक्त या निर्वाचित या नामनिर्देशित कोई सदस्य उस कालावधि तक पद धारण करेगा/करेगी जिसके लिए सदस्य को, जिसके स्थान पर नैमित्तिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित या नामनिर्देशित किया गया है, सामान्यतया पद धारण करता/करती।

255. समिति की सदस्यता पर आपत्ति.—जब किसी सदस्य के किसी समिति में सम्मिलित किए जाने पर इस आधार पर आपत्ति की जाए कि उस सदस्य का इतना अधिक वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित है कि उससे समिति द्वारा विचारणीय विषयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:

(क) ऐसे सदस्य द्वारा जिसने ऐसी आपत्ति की हो ऐसी आपत्ति का आधार तथा समिति के सामने आने वाले विनयों में प्रस्तावित सदस्य के आरोपित हित के स्वरूप को, चाहे वह वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हो सुतथ्यता कथित किया जाएगा;

(ख) आपत्ति का कथन किए जाने के बाद अध्यक्ष द्वारा समिति के लिए प्रस्तावित सदस्य को, जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई हो, स्थिति बताने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा;

(ग) यदि तथ्यों के संबंध में विवाद हो तो अध्यक्ष द्वारा आपत्ति करने वाले सदस्य से तथा उस सदस्य से जिसकी समिति में नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गई हो अपने-अपने मामले के समर्थन में लिखित या अन्य साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा की जा सकेगी;

(घ) अध्यक्ष द्वारा इस तरह दिये गये साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् विनिश्चय किया जाएगा, जो अंतिम होगा;

(ङ) जब तक अध्यक्ष द्वारा खण्ड (घ) के अधीन अपना विनिश्चय न किया गया हो तब तक ऐसा सदस्य, जिसकी समिति में नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गई हो, यदि निर्वाचित या नामनिर्देशित हो गया हो, तो समिति का सदस्य बना रहेगा/रहेगी और चर्चा में भाग लेगा/लेगी, किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा; और

(च) यदि अध्यक्ष द्वारा यह ठहराया जाए कि जिस सदस्य की नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गई है उसका समिति के समक्ष विचाराधीन विनय में कोई वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित है, तो सदस्य की समिति की सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाएगी:

परंतु समिति की जिन बैठकों में ऐसा सदस्य उपस्थित था उनकी कार्यवाही अध्यक्ष के विनिश्चय द्वारा किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगी।

व्याख्या—इस नियम के प्रयोजनों के लिए सदस्य का हित प्रत्यक्ष, वैयक्तिक या आर्थिक होना चाहिए और वह हित जनसाधारण या उसके किसी वर्ग या भाग के साथ सम्मिलित रूप में या राज्य की नीति के किसी विनय में न होकर उस व्यक्ति का, जिसके समिति में सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति की जाये, पृथक् रूप से होना चाहिए।

256. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित समिति की पदावधि.—अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित कोई समिति, जब तक इस अध्याय में निहित नियमों में अन्यथा निर्दिष्ट न हो अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट कालावधि के लिए या जब तक कोई नई समिति नामनिर्देशित न हो जाये, पद धारण करेगी।

257. समिति से पदत्याग(1).—किसी भी सदस्य द्वारा निम्नलिखित प्रपत्र में अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर

सहित लेख द्वारा समिति से अपने स्थान का त्याग किया जा सकेगा:

‘सेवा में,

अध्यक्ष महोदय/महोदया,

लोक सभा

नई दिल्ली ।

महोदय/महोदय,

मैं एतद्द्वारा समिति की सदस्यता से तारीख से पदत्याग करता/करती हूँ, जो (दिनांक) से प्रभावी होगा ।

भवदीय,

स्थान . . . दिनांक

(सदस्य का नाम)'

(2) यह पदत्याग त्यागपत्र में उल्लिखित तिथि से प्रभावी होगा।

(3) यदि त्यागपत्र में पदत्याग के प्रभावी होने की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह पदत्याग की तिथि से प्रभावी होगा।

(4) यदि त्यागपत्र पर कोई तिथि नहीं है, तो यह पदत्याग लोक सभा सचिवालय में त्यागपत्र की प्राप्ति से प्रभावी होगा।¹

258. समिति का सभापति(1).—समिति के सभापति को अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु उपाध्यक्ष यदि समिति का सदस्य/की सदस्य हो तो समिति का सभापति नियुक्त किया जायेगा/की जाएगी।

(2) यदि सभापति किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो अध्यक्ष द्वारा उसके स्थान पर अन्य सभापति नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) यदि सभापति किसी बैठक से अनुपस्थित हो तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में सभापति का कार्य करने के लिए चुनेगी।

259. समिति में गणपूर्ति(1).—समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का, यथासम्भव एक तिहाई के निकट होगी।

(2) यदि समिति की किसी बैठक के लिए निश्चित समय पर, या यदि बैठक के दौरान किसी समय गणपूर्ति न हो तो समिति के सभापति द्वारा या तो उस बैठक को गणपूर्ति होने तक निलम्बित रखा जाएगा या उस बैठक को किसी आगामी दिन के लिए स्थगित किया जाएगा।

(3) जब समिति उपनियम (2) के अनुसरण में, समिति की बैठकों के लिए निश्चित की गई लगातार दो तिथियों को स्थगित की जा चुकी हो, तो सभापति द्वारा उस तथ्य की सूचना सभा को दी जाएगी:

परन्तु जब समिति अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की गई हो तो सभापति द्वारा ऐसे स्थगन के तथ्य की सूचना अध्यक्ष को दी जाएगी ।

260. समिति की बैठकों से अनुपस्थित सदस्यों को हटाया जाना.—यदि कोई सदस्य समिति की लगातार दो या अधिक बैठकों से सभापति की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहे तो ऐसे सदस्य को समिति से हटाने के लिए सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा:

परन्तु जब समिति के सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएं तो सदस्य को अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकेगा।

261. समिति में निर्णय.—समिति की किसी बैठक में सब प्रश्न उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्धारित किए जाएंगे।

262. सभापति का निर्णायक मत.—किसी विनय पर मत समता की अवस्था में सभापति सभापतित्व करने वाले व्यक्ति का दूसरा या निर्णायक मत होगा।

263. उपसमितियां नियुक्त करने की शक्ति(1).—समिति किन्हीं ऐसे विनयों की, जो उसे निर्दिष्ट किये जाएं, जांच करने के लिये एक या अधिक उपसमितियां नियुक्त कर सकेगी, जिनमें से प्रत्येक को अविभक्त समिति की शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसी उपसमितियों के प्रतिवेदन संपूर्ण समिति के प्रतिवेदन समझे जाएंगे, यदि वे संपूर्ण समिति की किसी बैठक में अनुमोदित हो जाएं।

(2) उपसमिति को निर्देश के आदेश में अनुसंधान के विनय या विनयों का स्पष्ट-तया उल्लेख किया जाएगा। उपसमिति के प्रतिवेदन पर संपूर्ण समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

264. समिति की बैठकें.—समिति की बैठकें ऐसे दिन और ऐसे समय पर होंगी जो समिति के सभापति द्वारा निश्चित किया जाए:

परन्तु यदि समिति का सभापति तत्काल उपलब्ध न हो, तो महासचिव द्वारा बैठक की तिथि और समय निश्चित किया जा सकेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि विधेयक संबंधी प्रवर समिति या संयुक्त समिति के मामले में समिति का सभापति तत्काल उपलब्ध नहीं हो, तो महासचिव द्वारा उस मंत्री के परामर्श से, जिसके मंत्रालय का विधेयक से संबंध हो, बैठक की तिथि और समय निश्चित किया जा सकेगा।

265. जिस समय सभा की बैठक हो रही हो उस समय भी समिति की बैठक हो सकेगी.—जिस समय सभा की बैठक

¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.05.2014, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित ।

हो रही हो उस समय भी समिति की बैठक हो सकेगी, परंतु सभा में विभाजन की मांग की जाने पर समिति के सभापति द्वारा समिति की कार्यवाही को ऐसे समय के लिए निलम्बित किया जाएगा जिसके भीतर, सभापति की राय में, सदस्य विभाजन में मत दे सकें।

266. समिति की गुप्त रूप में बैठकें.—समिति की बैठकें गुप्त रूप से होगी।

267. बैठकों का स्थल.—समिति की बैठकें संसद भवन के परिसर में होंगी और यदि बैठक या स्थान संसद भवन के बाहर बदलना आवश्यक हो जाए तो यह विनय अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

268. जब समिति पर्यालोचन कर रही हो तो अजनबी बाहर चले जाएंगे .—जब कभी समिति पर्यालोचन कर रही हो तो समिति के सदस्यों तथा लोक सभा सचिवालय के पदाधिकारियों के अतिरिक्त सब व्यक्ति बाहर चले जाएंगे।

269. साक्ष्य लेने अथवा दस्तावेज मंगाने की शक्ति (1) .—कोई साक्षी महासचिव के हस्ताक्षरित आदेश द्वारा आहूत किया जा सकेगा और वह ऐसे दस्तावेज पेश करेगा जो समिति के उपयोग के लिए आवश्यक हों।

(2) यह समिति के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि उसके सामने दिए गए साक्ष्य को वह गोपनीय या गुप्त समझे।

(3) समिति के समक्ष रखा गया कोई दस्तावेज समिति के ज्ञान और अनुमोदन के बिना न तो वापस लिया जाएगा और न उसमें फेरबदल किया जाएगा।

270. व्यक्तियों को बुलाने तथा पत्रों और अभिलेखों को मंगाने की शक्ति.—समिति को व्यक्तियों को बुलाने तथा पत्रों और अभिलेखों को मंगाने की शक्ति होगी:

परंतु यदि कोई प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति या साक्ष्य या किसी दस्तावेज का पेश किया जाना समिति के प्रयोजनों के लिए संगत है या नहीं, तो वह प्रश्न अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परंतु यह और भी कि सरकार किसी दस्तावेज को पेश करने से इस आधार पर इंकार कर सकेगी कि उसका प्रकट किया जाना राज्य की सुरक्षा या हित के प्रतिकूल होगा।

271. साक्षी के लिए वकील.—कोई समिति, अध्यक्ष के निदेश के अंतर्गत, किसी साक्षी को अपनी बात किसी ऐसे वकील द्वारा कहलवाने की अनुज्ञा दे सकेगी जो उसके द्वारा नियुक्त तथा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

272. शपथ पर साक्ष्य(1).—कोई समिति अपने समक्ष परीक्षित साक्षी को शपथ या प्रतिज्ञान करा सकेगी।

(2) शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप निम्नलिखित होगा

“ मैं, अमुक

ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूँ

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ

कि मैं इस मामले में जो साक्ष्य दूंगा/दूंगी वह सच्चा होगा, मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा/छिपाऊंगी और मेरे साक्ष्य का कोई अंश झूठा नहीं होगा।”

273. साक्षियों की जांच.—समिति के सामने साक्षियों की जांच निम्न प्रकार से की जाएगी:

(एक) समिति, किसी साक्षी को जांच के लिए बुलाए जाने से पूर्व प्रक्रिया की रीति को तथा ऐसे प्रश्नों के स्वरूप को विनिश्चित करेगी जो साक्षी से पूछे जा सकेंगे।

(दो) समिति के सभापति द्वारा इस नियम के खंड (1) में उल्लिखित प्रक्रिया की रीति के अनुसार साक्षी से पहले ऐसा प्रश्न या ऐसे प्रश्न पूछे जा सकेंगे जो विचाराधीन विनय या तत्संबंधी किसी विनय के संबंध में आवश्यक समझे जाएं।

(तीन) सभापति द्वारा एक-एक करके समिति के अन्य सदस्यों से कोई अन्य प्रश्न पूछने के लिए कहा जा सकेगा।

(चार) साक्षी से समिति के सामने कोई ऐसी अन्य संगत बातें रखने के लिए कहा जा सकेगा जो पहले न आ चुकी हों और जिन्हें साक्षी समिति के सामने रखना आवश्यक समझता हो।

(पांच) जब किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिए आहूत किया जाए तो समिति की कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा जाएगा।

(छह) समिति के सामने दिया गया साक्ष्य समिति के सब सदस्यों को उपलब्ध किया जा सकेगा।

274. विनिश्चयों का अभिलेख.—समिति के विनिश्चयों का अभिलेख रखा जाएगा और सभापति के निदेश के अधीन समिति के सदस्यों में परिचालित किया जाएगा।

275. साक्ष्य, प्रतिवेदन तथा कार्यवाही का गोपनीय समझा जाना(1) .—समिति निदेश दे सकेगी कि संपूर्ण साक्ष्य या उसका कोई अंश अथवा उसका सारांश पटल पर रख दिया जाए।

(2) कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष द्वारा दिए गए प्राधिकार के सिवाय मौखिक या लिखित साक्ष्य के किसी अंश का, अथवा समिति के प्रतिवेदन या उसकी कार्यवाही का, जो पटल पर न रखी गई हो, निरीक्षण नहीं कर सकेगा।

(3) किसी संसदीय समिति के सामने दिया गया साक्ष्य संसदीय समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक प्रकाशित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह पटल पर न रख दिया गया हो:

परंतु अध्यक्ष द्वारा अपने स्वविवेक का उपयोग करते समय निदेश दिया जा सकेगा कि उसे सभा पटल पर औपचारिक रूप से रखे जाने से पहले सदस्यों को गुप्त रूप से उपलब्ध कर दिया जाये।

276. विशेष प्रतिवेदन.—कोई संसदीय समिति, यदि वह ठीक समझे, किसी ऐसे विषय पर, जो उसके कार्य के दौरान उत्पन्न हो या प्रकाश में आये और जिसे समिति अध्यक्ष या सभा के ध्यान में लाना आवश्यक समझे, विशेष प्रतिवेदन दे सकेगी, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा विनय समिति के निदेश पदों से प्रत्यक्षतया सम्बन्धित नहीं है या उनके भीतर नहीं आता या उनसे आनुगंगिक नहीं है।

277. समिति का प्रतिवेदन(1).—जब सभा ने प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए कोई समय, निश्चित न किया हो तो प्रतिवेदन उस तिथि से एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जिस तिथि को समिति को निर्देश किया गया था:

परंतु सभा किसी भी समय, प्रस्ताव किए जाने पर निदेश दे सकेगी कि समिति द्वारा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाए।

(2) प्रतिवेदन या तो प्रारम्भिक हो सकेंगे या अंतिम।

(3) समिति के प्रतिवेदन पर समिति की ओर से सभापति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे:

परंतु यदि सभापति अनुपस्थित हो या तत्काल उपलब्ध न हो तो समिति द्वारा प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए समिति का कोई अन्य सदस्य चुना जाएगा/चुनी जाएगी।

278. प्रस्तुतीकरण से पहले प्रतिवेदन का सरकार को उपलब्ध कराना.—समिति, यदि वह ठीक समझे, अपने प्रतिवेदन के किसी पूरे भाग को सभा में प्रस्तुत करने से पहले सरकार को उपलब्ध करा सकेगी। ऐसे प्रतिवेदन, जब तक कि वे सभा में प्रस्तुत न किए जाएं, गुप्त समझे जाएंगे।

279. प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण(1).—समिति का प्रतिवेदन सभा में सभापति द्वारा या सभापति की अनुपस्थिति में समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय सभापति की अनुपस्थिति में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले सदस्य द्वारा यदि कोई अभ्युक्ति की जाए तो संक्षिप्त तथ्य कथन किए जाने तक सीमित रखा जाएगा, किंतु उस कथन पर कोई वाद-विवाद इस अवसर पर नहीं किया जाएगा।

280. प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण से पहले मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन.—अध्यक्ष द्वारा प्रार्थना किए जाने पर और जब सभा सत्र में न हो तो किसी समिति के प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन का आदेश दिया जाएगा यदि वह सभा में प्रस्तुत न किया गया हो। उस अवस्था में प्रतिवेदन सभा में उसके आगामी सत्र के दौरान प्रथम सुविधाजनक अवसर पर प्रस्तुत किया जाएगा।

281. प्रक्रिया पर सुझाव देने की शक्ति.—किसी समिति को उस समिति से संबंधित प्रक्रिया के विनयों पर अध्यक्ष के विचारार्थ संकल्प पारित करने की शक्ति होगी, जो प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जिन्हें अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझा जाए।

282. विस्तृत नियम बनाने की शक्ति.—कोई समिति अध्यक्ष के अनुमोदन से इस अध्याय के नियमों में निहित उपबंधों को पूरा करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया के नियम बना सकेगी।

283. अध्यक्ष की निदेश देने की शक्ति(1).—अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर समिति के सभापति को ऐसे निदेश दिए जा सकेंगे जो अध्यक्ष द्वारा उसकी प्रक्रिया के विनियमन तथा उसके कार्य संगठन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(2) यदि प्रक्रिया के किसी प्रश्न पर या अन्य प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न हो तो सभापति द्वारा यदि ठीक समझा जाए, उस प्रश्न को अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जा सकेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

284. सभा के सत्रावसान पर समिति के समक्ष लम्बित कार्य व्यपगत नहीं होगा.—किसी समिति के समक्ष लम्बित कोई कार्य केवल सभा के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा और इस प्रकार सत्रावसान होने पर भी समिति कार्य करती रहेगी।

285. समितियों का असमाप्त काम.—कोई समिति जो अपना कार्यकाल पूरा होने या सभा के विघटन से पहले अपना काम पूरा न कर सके, सभा को सूचित कर सकेगी कि समिति अपना काम पूरा नहीं कर सकी है। कोई प्रारम्भिक प्रतिवेदन, ज्ञापन या टिप्पणी जो समिति ने तैयार की हो या कोई साक्ष्य जो समिति ने लिया हो, नई समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।

286. सामान्य नियमों का समितियों पर लागू होना.—उन विनयों को छोड़कर जिनके लिए किसी विशेष समिति से सम्बन्धित नियमों में विशेष उपबंध किया जाए, इस अध्याय के सामान्य नियम सभी समितियों पर लागू होंगे; और यदि जहां तक किसी समिति से सम्बन्धित विशिष्ट नियमों में कोई उपबन्ध सामान्य नियमों से असंगत हों तो पूर्वोक्त नियम लागू होंगे।

कार्य-मंत्रणा समिति

287. गठन.—अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, सभा के प्रारम्भ पर या समय-समय पर कार्य-मंत्रणा समिति नामक एक समिति नामनिर्देशित की जा सकेगी जिसमें अध्यक्ष को मिलाकर, जो समिति का सभापति होगा/होगी, पंद्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

288. कृत्य.—(1) समिति का यह कृत्य होगा कि वह ऐसे सरकारी विधेयकों के प्रक्रम या प्रक्रमों तथा अन्य कार्य पर चर्चा के लिए समय के बंटवारे की सिफारिशें करे जिन्हें अध्यक्ष द्वारा सदन नेता के परामर्श से समिति को सौंपे जाने का निदेश दिया जाए।

(2) समिति को प्रस्तावित समय-सूची में यह दर्शाने की शक्ति होगी कि विधेयक के विभिन्न प्रक्रम तथा अन्य कार्य किस-किस समय पूरे होंगे।

(3) समिति ऐसे अन्य कृत्य करेगी जो अध्यक्ष द्वारा उसे समय-समय पर सौंपे जाएं।

व्याख्या— इस नियम तथा नियम 290 क और 291 में उल्लिखित “अन्य कार्य” शब्द से तात्पर्य नियम 65 के अंतर्गत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और नियम 170 के अंतर्गत गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों को छोड़कर अन्य कार्य से है।

289. प्रतिवेदन.—समिति की सिफारिशें सभा को प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत की जाएंगी।

290. सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रस्ताव.—प्रतिवेदन के सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद किसी भी समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि सभा प्रतिवेदन को स्वीकार करती है या संशोधनों के साथ स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है:

परंतु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विनय के संबंध में समिति को वापस भेज दिया जाए:

परंतु यह और भी कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आधे घंटे से अधिक समय नियत नहीं किया जाएगा और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा/बोलेगी।

290क. समय के नियतन के आदेश की अधिसूचना.—विधेयकों तथा अन्य कार्य के विनय में सभा द्वारा अनुमोदित समय का बंटवारा ऐसे लागू होगा जैसे कि वह सभा का आदेश हो और वह लोक सभा समाचार में अधिसूचित कर दिया जाएगा।

291. निश्चित समय पर अवशिष्ट विनयों का निपटारा.—अध्यक्ष द्वारा विधेयक के किसी विशेष प्रक्रम या अन्य कार्य को पूरा करने के लिए समय के नियतन के आदेश के अनुसार निश्चित समय पर विधेयक के उस प्रक्रम या अन्य कार्य के सम्बन्ध में सभी अवशिष्ट विनयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखा जाएगा।

292. समय के नियतन के आदेश में परिवर्तन.—समय के नियतन के आदेश में कोई परिवर्तन अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव किए जाने और उसके सभा द्वारा स्वीकार किए जाने के अतिरिक्त नहीं किया जाएगा:

परंतु यह कि अध्यक्ष द्वारा सभा का अभिप्राय जानकर, कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए बिना, समय को एक घंटे से अनधिक बढ़ाया जा सकेगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

293. गठन.—(1) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी एक समिति होगी जिसमें पंद्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) समिति अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित की जाएगी और एक वर्ष तक पद धारण करेगी।

294. कृत्य.—(1) समिति के ये कृत्य होंगे—

(क) विधेयक के पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव को कार्य सूची में सम्मिलित करने से पूर्व प्रत्येक ऐसे विधेयक की जांच करना जो संविधान में संशोधन करने वाला हो और जिसकी सूचना गैर-सरकारी सदस्य द्वारा दी गई हो;

(ख) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की, उन्हें पुरःस्थापित किए जाने के बाद तथा सभा में उन पर विचार किए जाने से पूर्व जांच करना और उन्हें उनके स्वरूप, अविलम्बनीयता तथा महत्व के अनुसार दो वर्गों अर्थात् वर्ग “क” तथा वर्ग “ख” में वर्गीकृत करना;

(ग) यह सिफारिश करना कि गैर-सरकारी सदस्यों के प्रत्येक विधेयक के प्रक्रम या प्रक्रमों पर चर्चा के लिए कितना समय नियत किया जाना चाहिए और इस प्रकार तैयार की गई समय-सूची में यह भी दर्शाना कि दिन में किस-किस समय पर विधेयक के विभिन्न प्रक्रम पूरे होंगे;

(घ) गैर-सरकारी सदस्यों के प्रत्येक विधेयक की जांच करना जिसका सभा में इस आधार पर विरोध किया जाए कि विधेयक द्वारा ऐसे विधान का सूत्रपात होता है जो सभा की विधायिनी सक्षमता से परे है और अध्यक्ष द्वारा ऐसी आपत्ति को ऊपरी दृष्टि से ठीक समझा जाए;

(ङ.) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों और सहायक विनयों की चर्चा के लिए समय-सीमा की सिफारिश करना।

(2) समिति गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों के सम्बन्ध में अन्य ऐसे कृत्य करेगी जो उसे अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।

295. सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रस्ताव.—प्रतिवेदन के सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद किसी समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि सभा प्रतिवेदन को स्वीकार करती है या संशोधनों के साथ स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है:

परंतु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विनय के संबंध में समिति को वापस भेज दिया जाए:

परंतु यह और भी कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आधे घंटे से अधिक समय नियत नहीं किया जाएगा और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा/बोलेगी।

296. वर्गीकरण और समय का नियतन.—विधेयकों का सभा द्वारा अनुमोदित वर्गीकरण और विधेयकों तथा संकल्पों के संबंध में समय का नियतन ऐसे लागू होगा जैसे कि वह सभा का आदेश हो।

297. निश्चित समय पर अवशिष्ट विनयों का निपटारा.—अध्यक्ष द्वारा समय नियतन के आदेश के अनुसार निश्चित समय पर विधेयक या संकल्प के किसी खास प्रक्रम की समाप्ति के संबंध में सभी अवशिष्ट विनयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरंत रखा जाएगा।

विधेयकों पर प्रवर समितियां

298. गठन.—किसी विधेयक की प्रवर समिति के सदस्य, सभा द्वारा तब नियुक्त किए जाएंगे जब यह प्रस्ताव किया जाए कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए।

299. बैठकों में अन्य सदस्यों की उपस्थिति.—जो सदस्य प्रवर समिति के सदस्य नहीं हैं वे समिति के पर्यालोचन के दौरान उपस्थित रह सकेंगे किंतु वे न तो समिति को सम्बोधित करेंगे और न समिति के सदस्यों में बैठेंगे:

परंतु सभापति की अनुज्ञा से मंत्री द्वारा उस समिति को सम्बोधित किया जा सकेगा जिसका कि वह मंत्री सदस्य न हो।

300. संशोधन की सूचना और सामान्य रूप में प्रक्रिया.—(1) यदि प्रस्तावित संशोधन की सूचना प्रवर समिति द्वारा विधेयक लिए जाने के दिन से पूर्व न दी गई हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि सभापति द्वारा संशोधन के प्रस्तुत किए जाने की अनुमति न दे दी जाए, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी।

(2) अन्य प्रकरणों में, प्रवर समिति में प्रक्रिया ऐसे अनुकूलनों के साथ जो चाहे रूपभेद के हों, अथवा कोई अंश जोड़कर या निकालकर किए गए हों, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा आवश्यक या सुविधाजनक समझा जाए, यथासाध्य वही होगी जिसका सभा में विधेयक के विचार प्रक्रम के दौरान अनुसरण किया जाता है।

301. अन्य सदस्यों द्वारा संशोधनों की सूचना.—जब कोई विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा चुका हो तो विधेयक के किसी खंड के संशोधन की किसी सदस्य द्वारा दी गई सूचना समिति को सौंपी गई समझी जाएगी, परंतु यदि संशोधन की सूचना किसी ऐसे सदस्य से प्राप्त हुई हो जो प्रवर समिति का सदस्य नहीं है तो ऐसे संशोधन समिति द्वारा तब तक नहीं लिए जाएंगे जब तक कि वे समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत न किए गए हों।

302. साक्ष्य लेने की शक्ति.—प्रवर समिति विशेष-ज्ञी साक्ष्य को और उन विशेष हितों के प्रतिनिधियों के बयान सुन सकेगी जिन पर उसके समक्ष विद्यमान विधान का प्रभाव पड़ता हो।

303. प्रतिवेदन.—(1) किसी विधेयक के प्रवर समिति को सौंपे जाने के बाद यथासम्भव शीघ्र प्रवर समिति विधेयक पर विचार करने के लिए नियम 264 के अनुसार समय-समय पर समवेत होगी और सभा द्वारा निश्चित समय के भीतर उस पर प्रतिवेदन देगी:

परंतु जब सभा ने प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए कोई समय निश्चित न किया हो तो प्रतिवेदन उस तिथि से तीन मास की समाप्ति से पहले प्रस्तुत कर दिया जाएगा जिस तिथि को सभा ने प्रवर समिति को विधेयक सौंपे जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था:

परंतु यह और कि सभा किसी भी समय, प्रस्ताव किए जाने पर, निदेश दे सकेगी कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिए समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाए।

(2) प्रवर समिति अपने प्रतिवेदन में यह बताएगी कि इन नियमों के निदेश के अनुसार विधेयक का प्रकाशन हो गया है या नहीं और प्रकाशन किस तिथि को हुआ है।

(3) जब विधेयक में फेरबदल की गई हो, तो प्रवर समिति, यदि ठीक समझे, अपने प्रतिवेदन में विधेयक के प्रभारी सदस्य के लिए यह सिफारिश सम्मिलित कर सकेगी कि ऐसे सदस्य का अगला प्रस्ताव परिचालन का प्रस्ताव होना चाहिए अथवा जब विधेयक पहले ही परिचालित किया जा चुका हो तो पुनः परिचालन का।

(4) प्रवर समिति के किसी भी सदस्य द्वारा विधेयक से सम्बन्धित या प्रतिवेदन में दिये गये किसी विनय या विनयों पर विमत टिप्पण अभिलिखित की जा सकेगी।

(5) विमत टिप्पण संयत और शिष्ट भाषा में लिखा जाएगा और उसमें न तो प्रवर समिति में की गई चर्चा का उल्लेख किया जाएगा और न ही समिति पर आक्षेप किया जाएगा।

(6) यदि अध्यक्ष की राय में किसी विमत टिप्पण में ऐसे शब्द, वाक्यांश या पदावलियां हों जो असंसदीय या अन्यथा अनुपयुक्त हों, तो अध्यक्ष द्वारा ऐसे शब्दों, वाक्यांशों या पदावलियों को विमत टिप्पण में से निकाल दिए जाने का आदेश दिया जा सकेगा।

304. प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण.—किसी विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन, विमत टिप्पण सहित, यदि कोई हो, सभा में सभापति द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

305. प्रतिवेदन का मुद्रण तथा प्रकाशन.—महासचिव द्वारा प्रवर समिति के प्रत्येक प्रतिवेदन को मुद्रित कराया जाएगा और प्रतिवेदन की एक प्रति सभा के प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जायेगी। प्रतिवेदन तथा विधेयक प्रवर समिति द्वारा, प्रतिवेदित रूप में, गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

305क. गठन.—(1) सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी एक समिति होगी जिसमें 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) समिति अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित की जाएगी और अधिक से अधिक एक वर्ष तक पद धारण करेगी।

305ख. कृत्य.—(1) समिति के कृत्य यह होंगे कि वह मंत्रियों द्वारा सभा पटल पर रखे गए सभी पत्रों की जांच करेगी और सभा को इन बातों के बारे में प्रतिवेदन देगी:—

(क) क्या संविधान, अधिनियम, नियम या विनियम के उन उपबंधों का पालन किया गया है, जिसके अंतर्गत पत्र सभा पटल पर रखा गया है;

(ख) क्या पत्रों को सभा पटल पर रखने में कुछ अनुचित विलंब हुआ है;

(ग) यदि ऐसा विलंब हुआ है तो क्या विलंब के कारण बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है और क्या वे कारण संतोषजनक हैं;

(घ) क्या पत्र के हिन्दी और अंग्रेजी दोनों संस्करण सभा पटल पर रखे गए हैं; और

(ङ) क्या हिन्दी संस्करण के सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों के बारे में विवरण दिया गया है और क्या वे कारण संतोषजनक हैं?

(2) समिति सभा पटल पर रखे गये पत्रों के संबंध में अन्य ऐसे कृत्य करेगी जो उसे अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।

305ग. सभा पटल पर रखे गये पत्रों के बारे में सदन में चर्चा उठाने पर प्रतिबंध—यदि कोई सदस्य नियम 305ख के उपनियम (1) में उल्लिखित किसी विषय पर कोई चर्चा उठाना चाहे तो वह उसके द्वारा समिति के पास भेजा जाएगा और ऐसा मामला सदन में नहीं उठाया जाएगा।

याचिका समिति

306. गठन.—अध्यक्ष द्वारा यथास्थिति, सभा के प्रारम्भ पर, या समय-समय पर, एक याचिका समिति नामनिर्देशित की जाएगी जिसमें पन्द्रह से कम सदस्य नहीं होंगे:

परंतु किसी मंत्री को समिति का सदस्य नामनिर्देशित नहीं किया जाएगा और जहां किसी सदस्य को समिति में नामनिर्देशन के पश्चात् मंत्री नियुक्त कर दिया जाए, तो ऐसा

सदस्य ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

307. कृत्य.—(1) समिति, उसे सौंपी गई प्रत्येक याचिका की जांच करेगी और यदि याचिका में इन नियमों का पालन किया गया हो, तो समिति निदेश दे सकेगी कि उसे परिचालित किया जाए। यदि याचिका के परिचालित किए जाने का निदेश न दिया गया हो तो अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय यह निदेश दिया जा सकेगा कि याचिका को परिचालित किया जाए।

(2) याचिका उसके विस्तृत अथवा संक्षिप्त रूप में परिचालित की जाएगी जैसा कि यथास्थिति, समिति या अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया जाए।

(3) समिति का यह भी कर्तव्य होगा कि वह ऐसा साक्ष्य प्राप्त करने के बाद, जैसा कि वह ठीक समझे, उसे सौंपी गई याचिका में की गई विशिष्ट शिकायतें सभा को प्रतिवेदित करे और विचाराधीन मामले से संबंधित, ठोस रूप में या भविष्य में ऐसे मामले रोकने के लिए, प्रतिकारक उपायों का सुझाव दे।

लोक लेखा समिति

308. कृत्य.—(1) भारत सरकार के व्यय के लिए सभा द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखों, भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखों और सभा के सामने रखे गए ऐसे अन्य लेखों की जांच के लिए, जो समिति ठीक समझे, एक लोक लेखा समिति होगी।

(2) भारत सरकार के विनियोग लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन की छानबीन करते समय समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान कर ले:—

(क) कि लेखों में व्यय के रूप में दिखाया गया धन उस सेवा या प्रयोजन के लिए विधिवत उपलब्ध और लगाए जाने योग्य था, जिसमें वह लगाया गया है या भारित किया गया है;

(ख) कि व्यय उस प्राधिकार के अनुसार है जिसके वह अधीन है; और

(ग) कि प्रत्येक पुनर्विनियोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत इस संबंध में किए गए उपबंधों के अनुसार किया गया है।

(3) समिति का यह भी कर्तव्य होगा:—

(क) राज्य निगमों, व्यापार तथा निर्माण योजनाओं, संस्थाओं और परियोजनाओं की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा-विवरणों की तथा संतुलन-पत्रों और लाभ तथा हानि के लेखों के ऐसे विवरणों की जांच करना जिन्हें तैयार करने की रा-ट्रपति द्वारा अपेक्षा की गई हो या जो किसी विशेष निगम, व्यापार या निर्माण-योजना या संस्था या परियोजना के लिए

वित्त-व्यवस्था विनियमित करने वाले सांविधिक नियमों के उपबंधों के अंतर्गत तैयार किए गए हों और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना;

(ख) स्वायत्तशासी तथा अर्द्ध-स्वायत्तशासी निकायों की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा विवरण की जांच करना, जिसकी लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक द्वारा रा-द्रूपति के निदेशों के अंतर्गत या संसद की किसी संविधि के अनुसार की जा सके; और

(ग) उन मामलों में नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना जिसके संबंध में रा-द्रूपति द्वारा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से किन्हीं प्राप्तिओं की लेखा-परीक्षा करने की या भंडार के और स्कंध के लेखों की परीक्षा करने की अपेक्षा की गई हो।

(4) यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उसके प्रयोजन के लिए सभा द्वारा अनुदत्त राशि से कुछ अधिक धन व्यय किया गया हो, तो समिति प्रत्येक मामले के तथ्यों के संबंध में उन परिस्थितियों की जांच करेगी, जिसके कारण अधिक व्यय हुआ और ऐसी सिफारिशें करेगी जो वह ठीक समझे; परंतु समिति ऐसे सरकारी उपक्रमों के संबंध में, जो सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति को इन नियमों द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हों, अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगी।

309. गठन.—(1) समिति में [बाइस से अनधिक सदस्य होंगे जिनमें से पन्द्रह सदस्य]² सभा द्वारा प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे [और समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा द्वारा उस सभा से सात से अनधिक सदस्य नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे]:^{2क}

परंतु कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाएगा या, यदि किसी सदस्य को समिति के लिए निर्वाचित होने के बाद मंत्री नियुक्त किया जाए तो ऐसा सदस्य ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्राक्कलन समिति

310. कृत्य.—ऐसे प्राक्कलनों की परीक्षा के लिए, जो समिति को ठीक प्रतीत हों या जो उसे सभा या अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाएं, एक प्राक्कलन समिति होगी। समिति के कृत्य ये होंगे:

(क) प्राक्कलनों से संबंधित नीति से संगत क्या मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यपटुता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं इस संबंध में प्रतिवेदित करना;

(ख) प्रशासन में कार्यपटुता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना;

(ग) प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं इसकी जांच करना; और

(घ) प्राक्कलन जिस रूप में संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे इसका सुझाव देना:

परंतु समिति ऐसे सरकारी उपक्रमों के संबंध में, जो सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति को इन नियमों द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हों, अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगी।

311. गठन.—(1) समिति में तीस से अनधिक सदस्य होंगे, जो सभा द्वारा प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे:

परंतु कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाएगा और यदि किसी सदस्य को समिति के लिए निर्वाचित होने के बाद, मंत्री नियुक्त किया जाए तो, ऐसा सदस्य ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

312. प्राक्कलनों की जांच.—समिति प्राक्कलनों की जांच वित्तीय वर्ष भर समय-समय पर जारी रख सकेगी और जैसे-जैसे वह जांच करती जाए सभा को प्रतिवेदित कर सकेगी। समिति के लिए वह अनिवार्य न होगा कि वह किसी एक वर्ष के सब प्राक्कलन की जांच करे। इस बात के होते हुए भी कि समिति ने कोई प्रतिवेदन नहीं किया है, अनुदानों की मांगों पर अंतिम रूप से मतदान हो सकेगा।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

312क. कृत्य.—(1) चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के कार्य-संचालन की जांच करने के लिए एक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति होगी। समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—

(क) चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखों की जांच करना;

(ख) सरकारी उपक्रमों के वि-य में नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदनों की यदि कोई हो, जांच करना;

² लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

^{2क} वही, जोड़ा गया।

(ग) सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में यह जांच करना कि क्या सरकारी उपक्रमों के कार्य समुचित व्यापार सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुरूप चल रहे हैं; और

(घ) चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के संबंध में लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में निहित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उपरोक्त खंड (क), (ख) और (ग) के अंतर्गत न आते हों और जो समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे जाएं:

परंतु समिति निम्नलिखित में से किसी के बारे में भी जांच और छानबीन नहीं करेगी, अर्थात्:—

(एक) प्रमुख सरकारी नीति संबंधी मामले जो सरकारी उपक्रमों के व्यापार अथवा वाणिज्यिक कृत्यों से भिन्न हैं;

(दो) दिन-प्रतिदिन के प्रशासन संबंधी मामले;

(तीन) ऐसे मामले जिन पर विचार के लिए उस विशेष-संविधि में व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत कोई सरकारी उपक्रम विशेष-स्थापित किया गया है।

312ख. गठन.—(1) समिति में [बाइस से अनधिक सदस्य होंगे, जिनमें से पन्द्रह]³ सभा द्वारा प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे [और समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा द्वारा उस सभा से सात से अनधिक सदस्य नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे]⁴:

परंतु कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाएगा और यदि किसी सदस्य को, समिति के लिए निर्वाचित होने के बाद मंत्री नियुक्त किया जाए, तो ऐसा सदस्य ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी:

⁵[** ** **]

विशे-ाधिकार समिति

313. गठन.—यथास्थिति, सभा के प्रारंभ पर या समय-समय पर, अध्यक्ष द्वारा एक विशेष-ाधिकार समिति नामनिर्देशित की जाएगी जिसमें पन्द्रह से अनधिक सदस्य होंगे।

314. कृत्य.—(1) समिति उसे सौंपे गए प्रत्येक प्रश्न की जांच करेगी और प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार यह निर्धारित करेगी कि किसी विशेष-ाधिकार का भंग अंतर्ग्रस्त है या नहीं और यदि है, तो किस स्वरूप का है और किन

परिस्थितियों में हुआ है और ऐसी सिफारिशें करेगी जो वह ठीक समझे।

(2) प्रतिवेदन में यह भी बताया जा सकेगा कि सभा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने में किस प्रक्रिया का अनुसरण करे।

315. सभा द्वारा प्रतिवेदन पर विचार.—(1) प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के बाद, सभापति या समिति का कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाए, जिसके बाद अध्यक्ष द्वारा प्रश्न को सभा के सामने रखा जा सकेगा।

(2) प्रश्न को सभा के सामने रखने से पूर्व अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव पर वाद-विवाद की अनुज्ञा दी जा सकेगी जिसकी अवधि आधे घंटे से अधिक नहीं होगी और ऐसे वाद-विवाद में प्रतिवेदन के ब्यौरे का उससे अग्रेतर निर्देश नहीं किया जाएगा जितना यह सिद्ध करने के लिए आवश्यक हो कि सभा द्वारा प्रतिवेदन पर विचार किया जाए।

(3) उपनियम (1) के अंतर्गत किए गए प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद, यथास्थिति, सभापति या समिति का कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य द्वारा, प्रस्ताव किया जा सकेगा कि सभा प्रतिवेदन में अंतर्वि-ट सिफारिशों को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है या संशोधनों के साथ स्वीकार करती है।

316. सभा द्वारा प्रतिवेदन पर विचार के लिए पूर्ववर्तिता.—ऐसे प्रस्ताव को कि विशेष-ाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाए, जब तक कि उसे लाने में अनुचित विलंब न हो गया हो, पूर्ववर्तिता प्रदान की जाएगी जो नियम 225 के उपनियम (1) के अंतर्गत किसी विशेष-ाधिकार वि-य के लिए नियत है:

परंतु जब प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए पहले ही कोई तिथि निश्चित की जा चुकी हो, तो विशेष-ाधिकार वि-य की पूर्ववर्तिता इस तरह निश्चित दिन को दी जाएगी।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

317. कृत्य.—एक अधीनस्थ विधान संबंधी समिति इस बात की छानबीन करने और सभा को प्रतिवेदित करने के लिए होगी कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियों का प्रयोग ऐसे प्रत्यायोजन के अंतर्गत उचित रूप से किया जा रहा है।

318. गठन (1).—समिति में पन्द्रह से अनधिक सदस्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे:

परंतु कोई मंत्री समिति का सदस्य नामनिर्देशित नहीं किया जाएगा और यदि किसी सदस्य को, समिति के लिए

³ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁴ वही, जोड़ा गया।

⁵ वही, लोप किया गया।

नामनिर्देशित किए जाने के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाए तो ऐसा सदस्य ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी ।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

319. आदेशों का संख्यांकन और प्रकाशन.—संविधान के उपबंधों या संसद द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी की प्रत्यायोजित वैधानिक कृत्यों के अनुसरण में बनाए गए प्रत्येक विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि, जिसको सभा के समक्ष रखा जाना अपेक्षित हो और जिसको इसके पश्चात् "आदेश" कहा गया है, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो अध्यक्ष द्वारा सदन के नेता के परामर्श से विहित किए जाए, प्रख्यापित होने के तुरंत बाद केंद्रीय स्थान में संख्यांकित किया जाएगा और गजट में प्रकाशित किया जाएगा ।

320. आदेशों की जांच.—नियम 319 में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसे आदेश के सभा के समक्ष रखे जाने के बाद, समिति विशेष-रूप से इस बात पर विचार करेगी कि:—

(एक) वह संविधान अथवा उस अधिनियम के सामान्य उद्देश्यों के अनुकूल है या नहीं जिसके अनुसरण में वह बनाया गया है;

(दो) उसमें ऐसा वि-अंतर्वि-ट है या नहीं जिसको अधिक समुचित ढंग से निपटाने के लिए समिति की राय में संसद का अधिनियम होना चाहिए;

(तीन) उसमें कोई करारोपण अंतर्वि-ट है या नहीं;

(चार) उसमें न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूकावट होती है या नहीं;

(पांच) वह उन उपबंधों में से किसी को भूललक्षी प्रभाव देता है या नहीं जिनके संबंध में संविधान या अधिनियम स्पष्ट रूप से ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता;

(छह) उसमें भारत की संचित निधि या लोक राजस्व में से व्यय अंतर्ग्रस्त है या नहीं;

(सात) उसमें संविधान या उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का असामान्य अथवा अप्रत्याशित उपयोग किया गया प्रतीत होता है या नहीं, जिसके अनुसरण में यह बनाया गया है;

(आठ) उसके प्रकाशन में या संसद के समक्ष रखे जाने में अनुचित विलंब हुआ प्रतीत होता है या नहीं; और

(नौ) किसी कारण से उसके रूप या अभिप्राय के लिए किसी विशुद्धिकरण की आवश्यकता है या नहीं।

321. प्रतिवेदन (1).—यदि समिति की राय हो कि कोई आदेश पूर्णतः या अंशतः रद्द कर दिया जाना चाहिए या उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए जो वह उक्त राय तथा उसके कारण सभा को प्रतिवेदित करेगी।

(2) यदि समिति की राय हो कि किन्हीं आदेशों से संबंधित कोई अन्य वि-अय सभा के ध्यान में लाया जाना चाहिए तो वह उक्त राय तथा वि-अय सभा को प्रतिवेदित कर सकेगी ।

322. अध्यक्ष की निदेश देने की शक्ति.—अध्यक्ष द्वारा समिति में या सभा में अधीनस्थ विधान के किसी प्रश्न पर विचार से संबंधित सब वि-अयों के बारे में प्रक्रिया के विनियमन के लिए ऐसे निदेश दिए जा सकेंगे जिन्हें आवश्यक समझा जाए।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

323. कृत्य.—मंत्रियों द्वारा समय-समय पर सभा के अंदर दिए गए आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि की छानबीन करने के लिए और निम्न बातों पर प्रतिवेदन करने के लिए सरकारी आश्वासनों संबंधी एक समिति होगी:—

(क) ऐसे आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि का कहां तक परिपालन किया गया है; तथा

(ख) जहां परिपालन किया गया हो तो ऐसा परिपालन उस प्रयोजन के लिए आवश्यक न्यूनतम समय के भीतर हुआ है या नहीं।

324. गठन (1).—समिति में पन्द्रह से अनधिक सदस्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे:

परंतु किसी मंत्री को समिति का सदस्य नामनिर्देशित नहीं किया जाएगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिए नामनिर्देशित किए जाने के पश्चात् मंत्री नियुक्त हो जाए, तो ऐसा सदस्य ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

325. गठन.—सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित पन्द्रह सदस्यों से गठित होगी और उसकी पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

326. कृत्य (1).—समिति के ये कृत्य होंगे:—

(एक) सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति के लिए सदस्यों के सब आवेदन-पत्रों पर विचार करना; और

(दो) ऐसे प्रत्येक मामले की जांच करना जिसमें कोई सदस्य अनुज्ञा के बिना सभा की बैठकों से साठ दिन या अधिक की कालावधि तक अनुपस्थित रहा हो और प्रतिवेदित करना कि अनुपस्थिति माफ की जानी चाहिए या नहीं अथवा

मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उचित है कि सभा को सदस्य का स्थान रिक्त घोषित करना चाहिए।

(2) समिति, सदस्यों की सभा में उपस्थिति के बारे में ऐसे अन्य कृत्य करेगी जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।

327. जब अनुपस्थिति की अनुमति की सिफारिश की जाए तो सभा की इच्छा मालूम करना.—जब समिति सिफारिश करे कि किसी सदस्य को, यथास्थिति, अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए अथवा अनुपस्थिति माफ की जाए तो अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित रूप में प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के यथासंभव शीघ्र पश्चात् किसी दिन सभा की इच्छा मालूम की जाएगी:—

“सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने अपने.....प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि श्रीमती/कुमारी/श्री.....को प्रतिवेदन में दर्शायी गयी कालावधि के लिए (यथास्थिति) अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए या उसकी अनुपस्थिति माफ की जाए।

सदस्य को तदनुसार सूचित किया जा रहा है”।

328. जब अनुपस्थिति की अनुमति की सिफारिश न की जाए तो सभा की इच्छा मालूम करना.—जब किसी आवेदन-पत्र के बारे में समिति द्वारा अनुपस्थिति की अनुमति की सिफारिश न की जाए तो किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि सभा उस आवेदन-पत्र के संबंध में समिति की सिफारिश से सहमत है या संशोधन सहित सहमत है या असहमत है।

नियम समिति

329. कृत्य.—सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के वि-याँ पर विचार करने और इन नियमों में ऐसे संशोधनों तथा वृद्धियों की सिफारिश करने के लिए, जो आवश्यक समझी जाएं, एक नियम समिति होगी।

330. गठन.—नियम समिति अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित की जाएगी और उसमें समिति के सभापति को मिला कर पन्द्रह सदस्य होंगे। अध्यक्ष समिति का पदेन सभापति होगा/होगी।

331. प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना (1).—समिति की सिफारिशें पटल पर रखी जाएंगी और जिस दिन वे इस तरह रखी जाएं, उससे प्रारंभ होकर सात दिनों की कालावधि के भीतर, कोई सदस्य ऐसी सिफारिशों में किसी संशोधन की सूचना दे सकेगा/सकेगी।

(2) समिति की सिफारिशों में किसी सदस्य द्वारा की गई किसी संशोधन की सूचना समिति को निर्दिष्ट होगी, जो उस पर विचार करेगी तथा अपनी सिफारिशों में ऐसे परिवर्तन कर सकेगी जो समिति उचित समझे। समिति का अंतिम

प्रतिवेदन सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधनों पर विचार करने के पश्चात् पटल पर रख दिया जाएगा। तत्पश्चात् समिति के सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव पर प्रतिवेदन से सभा के सहमत हो जाने पर नियमों के संशोधन, सभा द्वारा अनुमोदित किए गए रूप में, अध्यक्ष द्वारा लोक सभा समाचार में प्रख्यापित कर दिए जाएंगे।

(3) यदि ऐसे संशोधन की सूचना सात दिन के भीतर न दी गई हो तो समिति की सिफारिशें सभा द्वारा अनुमोदित की गई समझी जाएंगी और उक्त कालावधि की समाप्ति पर अध्यक्ष द्वारा समिति द्वारा सिफारिश किए गए नियमों में संशोधनों को लोक सभा समाचार में प्रख्यापित करवाया जाएगा।

(4) जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, नियमों के संशोधन, बुलेटिन (समाचार) में उनके प्रकाशन पर प्रवृत्त होंगे।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

331क. कृत्य.—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी एक समिति होगी। समिति के कृत्य ये होंगे:—

(क) संविधान के अनुच्छेद 338(5)(घ) के अंतर्गत [रा-ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग]^{5क} द्वारा पेश किए गए प्रतिवेदनों पर विचार करना और संघ सरकार, जिसमें संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन भी शामिल हैं, के क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाले मामलों के बारे में संघ सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों को प्रतिवेदित करना;

(ख) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर संघ सरकार और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदित करना;

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का विधिवत् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 335 के उपबंधों को दृष्टि में रखते हुए संघ सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं तथा पदों में (जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, संविहित और अर्द्ध सरकारी निकायों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में नियुक्तियां भी शामिल हैं) संघ सरकार द्वारा किए गए उपायों पर विचार करना;

(घ) संघ राज्यक्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवेदन देना; और

(ङ) ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो समिति उचित समझे या जो सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे विशेष रूप से निर्दिष्ट किए जाएं।

^{5क} लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 3.3.1997, के पैरा संख्या 1996 द्वारा अन्तःस्थापित।

331ख. गठन.—समिति में [तीस से अनधिक सदस्य होंगे जिनमें से बीस सदस्य]⁶ एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार सदन द्वारा प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे [और समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा द्वारा उस सभा से दस से अनधिक सदस्य नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे];⁷

परंतु किसी मंत्री को समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाएगा और यदि सदस्य को, समिति में निर्वाचन के पश्चात् मंत्री नियुक्त हो जाए, तो ऐसा सदस्य ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी:

⁸[** ** **]

9[विभागों के संबद्ध स्थायी समितियां]

331ग. विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां (1).—सदनों की विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां होंगी (जिन्हें स्थायी समितियां कहा जाएगा)।

(2) प्रत्येक स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय/विभाग पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे:

परंतु यह कि सभापति, राज्य सभा तथा अध्यक्ष समय-समय पर एक दूसरे के परामर्श से उक्त अनुसूची में परिवर्तन कर सकेंगे।

331घ. गठन (1).—नियम 331ग के अंतर्गत गठित प्रत्येक स्थायी समिति में ¹⁰(31 से अनधिक सदस्य होंगे, 21 सदस्यों को लोक सभा के सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और (10) सदस्यों को राज्य सभा के सदस्यों में से सभापति, राज्य सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा और यदि सदस्य को समिति के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने के बाद मंत्री नियुक्त किया जाए, तो ऐसा सदस्य ऐसी नियुक्ति की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(3) पांचवीं अनुसूची के भाग-एक में विनिर्दिष्ट समितियों के सभापतियों की नियुक्ति सभापति, राज्य सभा द्वारा की जाएगी तथा उक्त अनुसूची के भाग-दो में विनिर्दिष्ट समितियों के सभापतियों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाएगी।

(4) समिति के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

331ङ. कृत्य (1).—प्रत्येक स्थायी समिति के कृत्य इस प्रकार होंगे:—

(क) संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करना और उनके संबंध में सभाओं को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। प्रतिवेदन में किसी भी प्रकार के कटौती प्रस्तावों का सुझाव नहीं दिया जाएगा;

(ख) संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना जो सभापति, राज्य सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, सौंपे गए हैं और उनके संबंध में सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(ग) मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना; और

(घ) दोनों सदनों में प्रस्तुत रा-द्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति संबंधी दस्तावेजों, जो राज्य सभा के सभापति या अध्यक्ष, यथास्थिति, द्वारा समिति को सौंपे गए हों, पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(2) स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों पर विचार नहीं करेंगी।

331च. कृत्यों से संबंधित उपबंधों की प्रयोज्यता.—नियम 331ङ के उपनियम (1) के खंड (क) से (घ) में यथाउपबंधित इन समितियों के प्रत्येक कृत्य, सभापति राज्य सभा और अध्यक्ष द्वारा किसी कृत्य विशेष की प्रयोज्यता के संबंध में अधिसूचित तारीख से इन समितियों के लिए लागू होंगे।

331छ. अनुदानों की मांगों से संबंधित प्रक्रिया.—प्रत्येक स्थायी समिति द्वारा अनुदानों की मांगों पर विचार करने और उन पर सदनों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:—

(क) सभा में बजट पर सामान्य चर्चा हो चुकने के पश्चात् सभा एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दी जाएगी;

(ख) समितियां उपर्युक्त अवधि के दौरान संबंधित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर विचार करेंगी;

(ग) समितियां उपर्युक्त अवधि के दौरान अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी और इससे अधिक समय दिए जाने का अनुरोध नहीं करेंगी;

(घ) सभा द्वारा अनुदानों की मांगों पर इन समितियों के प्रतिवेदनों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा और तदन्तर उन्हें पारित किया जाएगा; और

⁶ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁷ वही, जोड़ा गया।

⁸ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁹ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 29.3.1989 पैरा संख्या 1921 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹⁰ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 20.7.2004 पैरा संख्या 253 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ड) प्रत्येक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर पृथक प्रतिवेदन होगा।

331ज. विधेयकों से संबंधित प्रक्रिया.—प्रत्येक स्थायी समिति द्वारा विधेयकों की जांच तथा उनके संबंध में सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:—

(क) समितियां, उन्हें सौंपे गए विधेयकों के सामान्य सिद्धांतों तथा खंडों पर विचार करेंगी और उन पर संबंधित सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी;

(ख) समिति किसी भी सभा में पुरःस्थापित केवल ऐसे विधेयकों पर विचार करेगी जिन्हें, यथास्थिति, सभापति, राज्य सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपा जाए; और

(ग) समिति दिए गए समय में विधेयकों पर अपना प्रतिवेदन देगी।

331झ. समिति के प्रतिवेदन (1).—समितियों के प्रतिवेदन व्यापक आम सहमति पर आधारित होंगे।

(2) समिति का कोई भी सदस्य समिति के प्रतिवेदन पर विमत टिप्पण दे सकेगा/दे सकेगी ।

(3) विमत टिप्पण दोनों सभाओं के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

331ज. सामान्य नियमों की प्रयोज्यता.—उन मामलों के सिवाय, जिनके लिए स्थायी समितियों से संबंधित नियमों में विशेष उपबंध किया जाए, राज्य सभा में अन्य संसदीय समितियों के लिए लागू सामान्य नियम, आवश्यक परिवर्तनों के साथ पांचवीं अनुसूची के भाग-एक में यथाविनिर्दिष्ट स्थायी समितियों पर लागू होंगे और लोक सभा में अन्य संसदीय समितियों पर लागू होने वाले आम नियम अनुसूची के भाग-दो में यथाविनिर्दिष्ट स्थायी समितियों पर लागू होंगे।

331ट. बैठकों का स्थल.—स्थायी समितियां, जब तक यथास्थिति सभापति, राज्य सभा अथवा अध्यक्ष अन्यथा विशिष्ट अनुमति न दे, संसद के परिसर को छोड़कर अन्यत्र बैठक नहीं करेंगी ।

331ठ. विशेषज्ञ राय लेने का अधिकार.—स्थायी समितियां प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों की राय अथवा जनमत प्राप्त कर सकेंगी।

331ड. विचार न किए जाने वाले विषय.—स्थायी समितियां उन मामलों पर सामान्यतः विचार नहीं करेंगी जिन पर अन्य संसदीय समितियों द्वारा विचार किया जाता है।

331ढ. प्रतिवेदनों का स्वरूप प्रत्ययकारी होगा.—स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों का स्वरूप प्रत्ययकारी होगा

और उन्हें समितियों के सुविचारित परामर्श के रूप में माना जाएगा ।]

11[महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

331त. (1).—महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी एक समिति होगी—

(2) समिति में 30 से अनधिक सदस्य होंगे जिनमें से 20 सदस्य अध्यक्ष द्वारा लोक सभा के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और 10 सदस्य राज्य सभा के सभापति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं होगा और यदि किसी सदस्य को समिति के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाए, तो ऐसा सदस्य ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी ।

(4) समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाएगी ।

(5) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

331त. कृत्य.—समिति के कृत्य इस प्रकार होंगे:

(1) रा-द्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करना और इस बात की सूचना देना कि संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन सहित केंद्रीय सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में महिलाओं की स्थिति/दशा सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने चाहिएं;

(2) महिलाओं को सभी मामलों में समानता, प्रति-ठा और उचित दर्जा दिलाने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों की जांच करना;

(3) महिलाओं के लिए व्यापक शिक्षा तथा विधायी निकायों/सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों की जांच करना;

(4) महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रमों के कार्यकरण के बारे में सूचित करना;

(5) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर केंद्रीय सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सूचित करना; और

(6) ऐसे अन्य मामलों की जांच करना, जो समिति को उपयुक्त लगे अथवा जो इसे सभा या अध्यक्ष द्वारा तथा राज्य सभा या राज्य सभा के सभापति द्वारा विशेष रूप से भेजे जाएं।

¹¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 6.3.1997, के पैरा संख्या 1003 द्वारा जोड़ा गया।

331थ. अन्य समितियों द्वारा विचार न किए जाने वाले वि-य.—विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों सहित अन्य संसदीय समितियां, यथासंभव उन मामलों पर विचार नहीं करेंगी, जो नियमों के अंतर्गत विशेष-रूप से इस समिति को सौंपे गए हों।]

अध्याय 27

प्रक्रिया के सामान्य नियम

सूचनाएं

332. सूचनाएं देने की रीति (1).—इन नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना महासचिव को संबोधित करके लिखित रूप में दी जाएगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और संसदीय सूचनालय में छोड़ दी जाएगी जो कि इस प्रयोजन के लिए रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिन को छोड़कर प्रत्येक दिन समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले समय के लिए खुला रहेगा।

(2) संसदीय सूचनालय में उपनियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद छोड़ी गई सूचनाएं अगले खुलने वाले दिन की गई समझी जाएंगी।

333. संभाव्य सूचना (1).—ऐसे किसी भी सदस्य द्वारा ऐसे प्रस्ताव या संकल्प या विधेयक की सूचना दी जा सकेगी, जिसे वह चाहता/चाहती हो कि ऐसे अन्य कार्य की समाप्ति पर लिया जाए जिस पर यह प्रस्ताव संभाव्य हो और यदि ऐसी सूचना अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य कर ली जाए तो उसे कार्य-सूची में, यथास्थिति, प्रस्ताव या संकल्प या विधेयक की संभाव्य सूचना शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकेगा।

(2) संभाव्य सूचना ऐसे रूप में होगी जो अध्यक्ष द्वारा विहित की जाए और सभा में उस कार्य के निपटाए जाने के बाद ही ली जाएगी जिस पर कि सूचना संभाव्य हो।

334. सूचनाओं तथा पत्रों का सदस्यों में परिचालन.—महासचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक सूचना या पत्र की एक प्रति, जिसकी इन नियमों के अनुसार सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है, परिचालित करने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा।

(2) कोई सूचना या अन्य पत्र प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया समझा जाएगा यदि उसकी एक प्रति ऐसी रीति से और ऐसे स्थान में रख दी जाए जैसा कि अध्यक्ष द्वारा, समय-समय पर निदेश दिया जाए।

334क. सूचनाओं के पहले से विख्यापन पर प्रतिबंध.—किसी सूचना का विख्यापन किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह अध्यक्ष द्वारा गृहीत न कर ली गई हो और सदस्यों में परिचालित न कर दी गई हो:

परंतु किसी प्रश्न की सूचना का, उस दिन तक कोई विख्यापन नहीं किया जाएगा जिस दिन उस प्रश्न का सभा में उत्तर दिया जाए।

335. सत्रावसान होने पर लंबित सूचनाओं का व्यपगमन.—सत्रावसान होने पर किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करने के विचार की सूचनाओं के अतिरिक्त सब लंबित सूचनाएं व्यपगत हो जाएंगी और अगले सत्र के लिए नई सूचनाएं देनी पड़ेंगी:

परंतु किसी ऐसे विधेयक को, जिसके संबंध में संविधान के अंतर्गत मंजूरी या सिफारिश प्रदान की गई हो, पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करने के विचार की नई सूचना का दिया जाना आवश्यक होगा यदि, यथास्थिति, मंजूरी या सिफारिश प्रवर्तित नहीं रही हो।

336. प्रस्तुत प्रस्ताव, संकल्प या संशोधन सत्रावसान पर व्यपगत नहीं होंगे.—कोई प्रस्ताव, संकल्प अथवा संशोधन जो प्रस्तुत किया गया है और सभा में लंबित है केवल सत्रावसान होने के कारण ही व्यपगत नहीं होगा।

337. सूचनाओं का संशोधन करने संबंधी अध्यक्ष का अधिकार.—यदि अध्यक्ष की राय में किसी सूचना में ऐसे शब्द, वाक्यांश या पत्र हैं जो प्रतीकात्मक, असंसदीय, व्यंग्यात्मक, असंगत, आडम्बरपूर्ण या अन्यथा अनुचित हों, तो अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक का प्रयोग करते हुए ऐसी सूचना में परिचालन से पूर्व संशोधन किया जा सकेगा।

प्रस्ताव

338. किसी प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए जो सारवान रूप में उस प्रश्न के समान हो जिस पर सभा उसी सत्र में विनिश्चय कर चुकी है।

339. प्रस्ताव की वापसी (1).—जिस सदस्य द्वारा कोई प्रस्ताव किया गया है वह उसे सभा की अनुमति से वापस ले सकेगा/सकेगी।

(2) अनुमति, प्रश्न पर नहीं अपितु अध्यक्ष द्वारा सभा की इच्छा जानकर व्यक्त की जाएगी। अध्यक्ष द्वारा यह पूछा जाएगा: “क्या यह आपकी इच्छा है कि प्रस्ताव वापस लिया जाए?” यदि कोई विमत में न हो तो अध्यक्ष द्वारा कथन किया जाएगा: “प्रस्ताव अनुमति से वापस लिया गया।” किंतु यदि कोई विमत ध्वनि सुनाई दे या कोई सदस्य वाद-विवाद जारी रखने के लिए उठे, तो अध्यक्ष द्वारा तुरंत प्रस्ताव रखा जाएगा:

परंतु यदि किसी प्रस्ताव पर कोई संशोधन प्रस्तावित किया गया हो तो मूल प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाएगा जब तक कि संशोधन न निपटा दिया गया हो।

340. प्रस्ताव पर वाद-विवाद का स्थगन.—किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने के बाद किसी समय किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रस्ताव पर वाद-विवाद को स्थगित कर दिया जाए।

341. प्रस्ताव जिससे सभा के नियमों का दुरुपयोग होता हो अथवा विलम्बकारी प्रस्ताव (1).—यदि अध्यक्ष की राय हो

कि वाद-विवाद के स्थगन का कोई प्रस्ताव सभा के नियमों का दुरुपयोग है तो अध्यक्ष द्वारा उस पर या तो तुरंत प्रश्न रखा जा सकेगा या प्रश्न प्रस्तुत करने से इंकार किया जा सकेगा।

(2) यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि किसी विधेयक पर अग्रेतर राय जानने के लिए उसे पुनः परिचालन का प्रस्ताव ऐसे विलंबकारी प्रस्ताव के स्वरूप का है, जिससे सभा के नियमों का दुरुपयोग होगा क्योंकि मूल परिचालन ही पर्याप्त या व्यापक था या यह कि पूर्व परिचालन के बाद विधेयक को पुनः परिचालन की आवश्यकता हेतु कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, तो अध्यक्ष द्वारा उस पर या तो तुरंत प्रश्न रखा जा सकेगा या प्रश्न प्रस्तुत करने से इंकार किया जा सकेगा।

(3) यदि अध्यक्ष की राय यह हो कि किसी विधेयक पर सभा की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन दिए जाने के बाद विधेयक के सभा की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति को फिर से सौंपे जाने या उसके परिचालन या पुनः परिचालन का प्रस्ताव ऐसे विलंबकारी प्रस्ताव के स्वरूप का है जिससे सभा के नियमों का दुरुपयोग होगा क्योंकि यथास्थिति, सभा की प्रवर समिति या सदनों की संयुक्त समिति विधेयक पर उचित रीति से विचार कर चुकी है, या यह कि विधेयक के किसी समिति से आने के बाद कोई अप्रत्याशित या नई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है तो अध्यक्ष द्वारा उस पर या तो तुरंत प्रश्न रखा जा सकेगा या प्रश्न प्रस्तुत करने से इंकार किया जा सकेगा।

342. नीति, स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य वि-य पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव.—यह प्रस्ताव कि नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य वि-य पर विचार किया जाए, सभा के मत के लिए नहीं रखा जाएगा, किंतु सभा ऐसे वि-य पर प्रस्तावक का भा-गण समाप्त होने के बाद तुरंत चर्चा करेगी और निश्चित समय पर वाद-विवाद की समाप्ति पर कोई अग्रेतर प्रश्न नहीं रखा जाएगा जब तक कि कोई सदस्य, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले उचित रूप में मूल प्रस्ताव न रखे और ऐसे प्रस्ताव पर सभा का मत लिया जाएगा।

चर्चा की प्रत्याशा

343. चर्चा की प्रत्याशा.—कोई सदस्य किसी ऐसे वि-य की चर्चा की प्रत्याशा नहीं करेगा जिसकी सूचना दी जा चुकी हो परंतु यह निर्धारित करने के लिए कि चर्चा की प्रत्याशा के आधार पर नियमबाह्य है या नहीं अध्यक्ष द्वारा प्रत्याशित वि-य के सभा के सामने उचित समय के भीतर लाए जाने की संभावना को ध्यान में रखा जाएगा।

संशोधन

344. संशोधनों की व्याप्ति.—संशोधन उस प्रस्ताव से सुसंगत तथा उसकी व्याप्ति के भीतर होगा जिस पर वह प्रस्तुत किया जाए।

(2) ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जिसका प्रभाव केवल नकारात्मक मत हो।

(3) किसी प्रश्न पर कोई संशोधन उसी प्रश्न पर किए गए पूर्व विनिश्चय से असंगत नहीं होगा।

345. संशोधनों की सूचना.—किसी प्रस्ताव में संशोधन की सूचना जिस दिन प्रस्ताव पर विचार किया जाना है उससे एक दिन पहले दी जाएगी यदि अध्यक्ष द्वारा ऐसी सूचना के बिना संशोधन के प्रस्तुत किए जाने की अनुमति न दे दी जाए।

346. संशोधनों का संवरण.—किसी प्रस्ताव के संबंध में, अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधनों का संवरण करने की शक्ति होगी और यदि वह ठीक समझा जाए तो किसी सदस्य से, जिसने संशोधन की सूचना दी हो, संशोधन के उद्देश्य की ऐसी व्याख्या करने के लिए कहा जा सकेगा जिससे अध्यक्ष उसका निर्णय करने में समर्थ हो सके।

347. संशोधनों का रखा जाना.—अध्यक्ष संशोधनों को उस क्रम में रख सकेगा, जिसे ठीक समझा जाए:

परंतु अध्यक्ष द्वारा किसी ऐसे संशोधन को रखने से इंकार किया जा सकेगा जो अध्यक्ष की राय से तुच्छ हो।

रा-द्रूपति की सिफारिश की संसूचना

348. सिफारिश की संसूचना की रीति.—रा-द्रूपति की प्रत्येक मंजूरी या सिफारिश मंत्री द्वारा महासचिव को निम्न रूप में संसूचित की जाएगी:—

“रा-द्रूपति द्वारा प्रस्तावित विधेयक प्रस्ताव, अनुदान की मांग या संशोधन की वि-य-वस्तु से सूचित किए जाने के बाद विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने या संशोधन के प्रस्तुत किए जाने के लिए अपनी पूर्व मंजूरी प्रदान की जाती है अथवा सभा में विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने या प्रस्ताव, अनुदान की मांग या संशोधन के प्रस्तुत किए जाने की सिफारिश की जाती है अथवा सभा से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश की जाती है।”

यह सभा की कार्यवाही में ऐसी रीति से छापा जाएगा जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया जाए।

सदस्यों द्वारा पालनीय नियम

349. सदस्यों द्वारा सभा में पालनीय नियम.—जब सभा की बैठक हो रही हो तो कोई सदस्य—

(एक) ऐसी पुस्तक, समाचारपत्र या पत्र नहीं पढ़ेगा/पढ़ेगी, जिसका सभा की कार्यवाही से संबंध न हो;

(दो) किसी सदस्य के भा-गण करते समय उसमें अव्यवस्थित बात या शोर या किसी अन्य अव्यवस्थित रीति से बाधा नहीं डालेगा/डालेगी;

(तीन) सदन में प्रवेश करते समय या सदन से बाहर जाते समय और अपने स्थान पर बैठते समय या वहां से उठते समय भी अध्यक्षपीठ के प्रति नमन करेगा/करेगी;

(चार) अध्यक्षपीठ और ऐसे सदस्य के बीच से, जो भा-ण दे रहा/रही हो, नहीं गुजरेगा/गुजरेगी;

(पांच) जब अध्यक्ष द्वारा सभा को संबोधित किया जा रहा हो तो सदन से बाहर नहीं जाएगा/जाएगी;

(छह) सदैव अध्यक्षपीठ को ही सम्बोधित करेगा/करेगी;

(सात) सभा को सम्बोधित करते समय अपने स्वयं के सामान्य स्थान पर ही रहेगा/रहेगी;

(आठ) जब सभा में नहीं बोल रहा/रही हो तो शान्त रहेगा/रहेगी;

(नौ) कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेगा/डालेगी, सीत्कार नहीं करेगा/करेगा, या बाधा नहीं डालेगा/डालेगी और जब [कोई दूसरा सदस्य बोल रहा हो]¹ तो साथ-साथ उनकी टीका नहीं करेगा/करेगी;

(दस) जब किसी दीर्घा में अथवा विशेष-स्थान (बाक्स) में कोई अजनबी प्रवेश करे तो प्रशंसा-घो-न नहीं करेगा/करेगी;

[(ग्यारह) सभा में नारे नहीं लगाएगा/लगाएगी;²

(बारह) अध्यक्षपीठ की ओर पीठ करके नहीं बैठेगा/बैठेगी या खड़ा/खड़ी नहीं होगा/होगी;³

(तेरह) सभा के अध्यक्षपीठ के पास स्वयं नहीं जाएगा/जाएगी। यदि आवश्यक हो तो सदस्य पटल अधिकारी को पर्चियां भेज सकता/सकती है;

(चौदह) सभा में (लैपेलपिन अथवा बिल्ले के रूप में रा-ट्रीय ध्वज के सिवाए) किसी प्रकार के बिल्ले नहीं लगाएगा/लगाएगी या प्रदर्शित नहीं करेगा/करेगी;

(पंद्रह) सभा में शस्त्र नहीं लाएगा/लाएगी या प्रदर्शित नहीं करेगा/करेगी;

(सोलह) सभा में झंडे, प्रतीक या कोई प्रदर्शित वस्तु प्रदर्शित नहीं करेगा/करेगी;

(सत्रह) अपना भा-ण देने के तुरंत बाद सभा से बाहर नहीं जाएगा/जाएगी;

(अठारह) संसद भवन के परिसर में ऐसे साहित्य, प्रश्नावली, पुस्तिकाओं, प्रेस टिप्पणियों, पर्चों इत्यादि का वितरण नहीं करेगा/करेगी जो सभा के कार्य से संबंधित न हों;

(उन्नीस) सभा में डेस्क पर अपना हैट/टोपी नहीं रखेगा/रखेगी, फाइल रखने या लेखन के कार्य के लिए सदन में फलक नहीं लाएगा/ लाएगी, सभा में धूम्रपान नहीं करेगा/

करेगी या बांह पर कोट लटकाकर सभा में प्रवेश नहीं करेगा/करेगी;

(बीस) जब तक स्वास्थ्य के आधार पर अध्यक्ष की अनुमति न दी गई हो, सभा भवन में छड़ी नहीं लाएगा/लाएगी ;

(इक्कीस) सभा में अभ्यापत्तिपूर्वक दस्तावेजों को नहीं फाड़ेगा/फाड़ेगी;

(बाइस) सभा में कैसेट या टेप रिकार्डर नहीं लाएगा/लाएगी या बजाएगा/बजाएगी;

(तेइस) लॉबी में इतनी जोर से बात नहीं करेगा/करेगी अथवा हंसेगा/हंसेगी जो सभा में सुनाई दे।]

350. अध्यक्ष द्वारा पुकारे गए सदस्य को ही बोलने का हक.—जब कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा हो तो अध्यक्ष द्वारा ऐसे सदस्य का नाम पुकारा जाएगा। यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हों तो जिस सदस्य का नाम इस तरह पुकारा जाए उसी को बोलने का हक होगा।

351. सभा को सम्बोधित करने की रीति.—सभा के समक्ष किसी वि-य पर कुछ चर्चा करने का इच्छुक सदस्य अपने स्वयं के स्थान से बोलेगा/बोलेगी, बोलते समय खड़ा होगा/खड़ी होगी और अध्यक्ष को सम्बोधित करेगा/करेगी:

परंतु रोग या दुर्बलता के कारण असमर्थ किसी सदस्य को बैठ कर बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

352. बोलते समय पालनीय नियम.—बोलते समय कोई सदस्य—

(एक) किसी ऐसे तथ्य, वि-य का निर्देश नहीं करेगा/करेगी जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो;

(दो) [सभा के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा/करेगी या उसकी सद्भावना पर आपत्ति करके उसका वैयक्तिक निर्देश नहीं करेगा/करेगी जब तक कि ऐसा निर्देश विचाराधीन प्रश्न या सुसंगत होने के कारण वाद-विवाद के प्रयोजनों के लिए अनिवार्यतः आवश्यक न हो;]⁴

(तीन) संसद या किसी राज्य विधान मंडल के व्यवहार या कार्यवाही के वि-य में आपत्तिजनक पदावलि का उपयोग नहीं करेगा/करेगी;

(चार) सभा के किसी निर्धारण पर, उसे रद्द करने के प्रस्ताव को छोड़कर आक्षेप नहीं करेगा/करेगी;

(पांच) उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा/करेगी जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो;

¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

² लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

³ वही, प्रतिस्थापित।

⁴ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

व्याख्या—शब्द “उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियाँ” का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा संविधान के अंतर्गत केवल उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर की जा सकती है या ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा अध्यक्ष की राय में, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर की जानी चाहिए।

(छह) वाद-विवाद पर प्रभाव डालने के प्रयोजन के लिए रा-द्रुपति के नाम का उपयोग नहीं करेगा/करेगी;

(सात) अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्द नहीं कहेगा/कहेगी;

⁵ [***]

(आठ) अपने भा-ण के अधिकार का उपयोग सभा के कार्य में बाधा डालने के प्रयोजन के लिए नहीं करेगा/करेगी;

⁶ [(नौ) किसी भी दीर्घा में बैठे हुए अजनबियों के प्रति कोई निर्देश नहीं करेगा/करेगी;

(दस) सरकारी अधिकारियों का नाम लेकर उल्लेख नहीं करेगा/करेगी;

(ग्यारह) अध्यक्षपीठ की पूर्व अनुमति के बिना लिखित भा-ण नहीं पढ़ेगा/पढ़ेगी।]

353. किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया.—किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी ⁷ [पर्याप्त अग्रिम सूचना] न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए वि-य की जांच कर सके:

परंतु अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिनिद्ध किया जा सकेगा यदि अध्यक्ष की राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता।

354. राज्य सभा में दिए गए भा-णों के उद्धृत किए जाने पर निर्बन्धन.—राज्य सभा में दिया गया कोई भा-ण सभा में उद्धृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किसी मंत्री द्वारा दिया गया कोई नीति संबंधी निश्चित वक्तव्य न हो।

परंतु अध्यक्ष द्वारा उससे पहले से प्रार्थना किए जाने पर, किसी सदस्य को राज्य सभा में दिए गए किसी भा-ण को उद्धृत करने या राज्य सभा की कार्यवाही का निर्देश करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी यदि अध्यक्ष यह समझे कि ऐसा करना किसी सदस्य के लिए किसी विशेष-ाधिकार या प्रक्रिया के प्रश्न को स्प-ट करने के लिए आवश्यक है।

355. प्रश्नों का अध्यक्ष के माध्यम से पूछा जाना.—जब चर्चा के दौरान स्प-टीकरण के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, किसी सदस्य को उस समय सभा के विचाराधीन किसी वि-य पर किसी अन्य सदस्य से कोई प्रश्न पूछना हो तो वह सदस्य अध्यक्ष के माध्यम से प्रश्न पूछेगा/पूछेगी।

356. असंगति या पुनरुक्ति.—अध्यक्ष द्वारा ऐसे सदस्य के आचरण की ओर, जो वाद विवाद में बार-बार असंगत बातें करे या जो स्वयं अपने प्रतर्कों की या अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त प्रतर्कों की उकता देने वाली पुनरुक्ति करता रहे, सभा का ध्यान दिला देने के बाद उस सदस्य को भा-ण बंद करने का निदेश दिया जा सकेगा।

357. वैयक्तिक स्प-टीकरण.—कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुज्ञा से, वैयक्तिक स्प-टीकरण कर सकेगा/सकेगी यद्यपि सभा के सामने कोई प्रश्न न हो किंतु उस अवस्था में कोई विवादास्पद वि-य नहीं उठाया जाएगा और कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

भा-णों का क्रम, उत्तर देने का अधिकार और वाद-विवाद का समापन

358. भा-णों का क्रम और उत्तर देने का अधिकार(1).—प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य के बोल चुकने के बाद अन्य सदस्य प्रस्ताव पर ऐसे क्रम में बोल सकेंगे जिसमें कि अध्यक्ष द्वारा उनको पुकारा जाए। यदि कोई सदस्य इस प्रकार पुकारे जाने पर न बोले तो फिर ऐसे सदस्य को अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, वाद-विवाद के किसी आगे के प्रक्रम में प्रस्ताव पर बोलने का हक नहीं होगा।

(2) उत्तर देने के अधिकार के प्रयोग को छोड़कर या इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर कोई सदस्य किसी प्रस्ताव पर, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, एक बार से अधिक नहीं बोलेगा/बोलेगी।

(3) कोई सदस्य, जिसने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो, उत्तर के रूप में पुनः बोल सकेगा/सकेगी और यदि प्रस्ताव किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो संबंधित मंत्री, (चाहे वाद-विवाद में पहले बोल चुका हो या नहीं), अध्यक्ष की अनुमति से, प्रस्ताव के उत्तर देने के बाद बोल सकेगा/सकेगी:

परंतु इस उप-नियम की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि किसी विधेयक या संकल्प में संशोधन के प्रस्तावक को अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना उत्तर देने का कोई अधिकार मिलता है।

359. वाद-विवाद का समापन.—नियम 358 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए वाद-विवाद सब अवस्थाओं में मूल प्रस्ताव के प्रस्तावक के उत्तर देने पर समाप्त हो जाएगा।

⁵ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 9.5.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा लोप किया गया।

⁶ वही, जोड़ा गया।

⁷ वही, प्रतिस्थापित किया गया।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

360. अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन.—अध्यक्ष द्वारा स्वयं ही या किसी सदस्य द्वारा प्रश्न उठाए जाने पर या प्रार्थना किए जाने पर, किसी भी समय सभा में विचाराधीन वि-य पर सदस्यों का उनके पर्यालोचन में सहायता करने की दृष्टि से सभा को सम्बोधित किया जा सकेगा और इस प्रकार व्यक्त किए गए मत को किसी प्रकार के विनिश्चय के स्वरूप में नहीं समझा जाएगा।

अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया

361. अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया(1).—अध्यक्ष को जब कभी खड़े हों शांतिपूर्वक सुना जाएगा और कोई सदस्य, जो उस समय बोल रहा/रही हो या बोलने वाला/वाली हो, तुरंत अपना स्थान ग्रहण कर लेगा/लेगी।

(2) जब अध्यक्ष द्वारा सभा को सम्बोधित किया जा रहा हो तो कोई सदस्य अपने के स्थान को नहीं छोड़ेगा/छोड़ेगी।

समापन और वाद-विवाद की परिसीमा

362. समापन(1).—किसी प्रस्ताव के किये जाने के बाद किसी समय कोई भी सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी “कि अब प्रश्न रखा जाए” और, “जब तक अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग है या उचित वाद-विवाद अधिकार का उल्लंघन करता है, तब अध्यक्ष द्वारा यह प्रस्ताव रखा जाएगा। “कि अब प्रश्न रखा जाएगा”।

(2) जब यह प्रस्ताव “कि अब प्रश्न रखा जाए स्वीकृत हो जाए” स्वीकृत हो जाए तो उससे आनु-गिक प्रश्न या प्रश्नों को, अग्रेतर वाद-विवाद के बिना तुरंत रख दिया जाएगा:

परंतु अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य को कोई उत्तर देने का अधिकार दिया जा सकेगा जो सदस्य को इन नियमों के अंतर्गत प्राप्त हो।

363. वाद-विवाद की परिसीमा(1).—जब कभी विधेयक के संबंध में किसी प्रस्ताव पर या किसी अन्य प्रस्ताव पर वाद-विवाद अनुचित रूप से लंबा हो जाए तो अध्यक्ष द्वारा सभा का अभिप्राय जानने के बाद, यथास्थिति, विधेयक या प्रस्ताव के किसी प्रक्रम या सब प्रक्रमों पर चर्चा की समाप्ति के लिए समय-सीमा निश्चित की जा सकेगी।

(2) विधेयक या प्रस्ताव के किसी खास प्रक्रम को पूरा करने के लिए निश्चित समय-सीमा के अनुसार नियत समय पर यदि वाद-विवाद उससे पूर्व समाप्त न हो गया हो, तो अध्यक्ष द्वारा विधेयक या प्रस्ताव के उस प्रक्रम के संबंध में सभी अवशिष्ट वि-यों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरंत रखा जाएगा।

सभा का विनिश्चय

364. प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर प्रश्न.—जिस वि-य पर सभा का विनिश्चय अपेक्षित हो वह सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव पर अध्यक्ष द्वारा रखे गए प्रश्न के द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

365. प्रस्ताव तथा प्रश्न का रखा जाना.—जब कोई प्रस्ताव किया गया हो तो अध्यक्ष द्वारा प्रश्न को विचार के लिए प्रस्तुत किया जाए और उसे सभा के विनिश्चय के लिए रखा जाए। यदि कोई प्रस्ताव में दो या अधिक अलग-अलग प्रस्थापनाएं शामिल हों तो वे प्रस्थापनाएं अध्यक्ष द्वारा अलग-अलग प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत की जा सकेंगी।

366. आवाजें संग्रहीत होने के बाद किसी भा-गण का न होना.— किसी प्रश्न पर अध्यक्ष “हां” वालों और “ना” वालों, दोनों की आवाजें संग्रहीत कर ले तो उसके बाद कोई सदस्य उस प्रश्न पर नहीं बोलेगा।

विभाजन

367. विभाजन संबंधी प्रक्रिया(1).—किसी वाद-विवाद की समाप्ति पर अध्यक्ष द्वारा प्रश्न रखा जाएगा और जो प्रस्ताव के पक्ष में हों उनसे “हां” और जो प्रस्ताव के विरुद्ध हों उनसे “ना” कहने के लिए कहा जाएगा।

(2) अध्यक्ष द्वारा तब यह कथन किया जाएगा : “मैं समझता/समझती हूं कि ‘हां’ (या यथास्थिति ‘ना’) वाले जीत गए हैं”। यदि किसी प्रश्न के विनिश्चय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आक्षेप नहीं किया जाता है, तो अध्यक्ष द्वारा दो बार यह कथन किया जाएगा: “हां” (या यथास्थिति ‘ना’) वाले जीत गए” और सभा के समक्ष प्रश्न तदनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(3) (क) यदि किसी प्रश्न के विनिश्चय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आक्षेप किया जाता है, तो अध्यक्ष “सभाकक्ष” खाली किए जाने का आदेश देगा।

(ख) [3 मिनट और 30 सैकेंड]⁸ बीतने पर अध्यक्ष द्वारा प्रश्न को दूसरी बार रखा जाएगा और घोषित किया जाएगा कि अध्यक्ष की राय में ‘हां’ वाले जीत गये या ‘ना’ वाले।

(ग) यदि इस तरह घोषित राय पर फिर आपत्ति की जाये तो अध्यक्ष निदेश देगा कि स्वचालित मतदान-यंत्र को चलाकर अथवा सभा में ‘हां’ और ‘ना’ वाली पर्चियों का प्रयोग करके अथवा सदस्यों द्वारा सभाकक्ष में जाकर मतदान किया जाये:

परंतु यदि अध्यक्ष की यह राय है कि विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की गई है, तो अध्यक्ष द्वारा क्रमशः ‘हां’ तथा ‘ना’ वाले सदस्यों से अपने अपने स्थान पर खड़े होने के

⁸ लोक सभा समाचार भाग-दो दिनांक 9.5.1989 पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित।

लिए कहा जा सकेगा और गणना हो जाने के बाद सभा का निश्चय विधो-नित किया जा सकेगा। ऐसी दशा में मत देने वालों के नाम अभिलिखित नहीं किए जायेंगे।

367क. स्वचालित मतदान-यंत्र द्वारा विभाजन(1).—अध्यक्ष द्वारा जब नियम 367 के उप-नियम (3) के खण्ड (ग) के अंतर्गत यह निदेश दिया जाए कि स्वचालित मतदान-यंत्र चलाकर मत अभिलिखित किए जायें तो मतदान यंत्र चलाया जाएगा और सदस्य अपने नियत स्थान से मतदान के लिए लगाये गए बटन दबाकर अपने मत देंगे।

(2) परिणाम-सूचक बोर्ड पर मतदान का परिणाम आ जाने पर, विभाजन का परिणाम अध्यक्ष द्वारा विधो-नित किया जाएगा और उस पर आपत्ति नहीं की जायेगी।

(3) जो सदस्य मतदान के लिए लगाए गए बटन को, किसी ऐसे कारण से जो अध्यक्ष के विचार में पर्याप्त हो, दबाकर अपना मत न दे सका/सकी हो, वह विभाजन का परिणाम घो-नित किए जाने से पहले अध्यक्ष की अनुज्ञा से [यह कह कर कि वह] प्रस्ताव के पक्ष में अथवा विपक्ष में अपना मत मौखिक रूप से अभिलिखित करा सकेगा/सकेगी।

(4) यदि किसी सदस्य को पता चले कि उसने भूल से गलत बटन दबा कर मत दे दिया तो ऐसे सदस्य को अपनी भूल सुधारने की अनुमति दी जा सकेगी यदि वह सदस्य उसे अध्यक्ष की जानकारी में विभाजन का परिणाम घो-नित किए जाने से पहले लाए।

367कक. ‘हां’ और ‘ना’ वाली पर्चियों का वितरण करके मत विभाजन(1).—जहाँ अध्यक्ष द्वारा नियम 367 के उप-नियम (3) के खण्ड (ग) के अंतर्गत यही निदेश दिया जाए कि सदस्यों द्वारा मत ‘हां’ और ‘ना’ वाली पर्चियों पर अभिलिखित किए जाएंगे, मत विभाजन लिपिक ऐसे सदस्यों को उनके स्थानों पर उनके द्वारा दर्शाई गई इच्छानुसार ‘हां’ अथवा ‘ना’ वाली एक पर्ची देंगे। सदस्य द्वारा इस पर्ची पर हस्ताक्षर करके तथा स्वयं की विभाजन संख्या लिखकर अपना मत अभिलिखित किया जाएगा।

(2) जब सदस्य अपना मत अभिलिखित कर लेंगे तो उसके पश्चात् मत विभाजन लिपिक ‘हां’ वाली तथा ‘ना’ वाली पर्चियां इकट्ठी करेंगे और उन्हें सभा पटल पर लाएंगे जहां पर सभा पटल के निकट बैठे अधिकारियों द्वारा मतों की गणना की जाएगी तथा ‘हां’ और ‘ना’ वालों के योग अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

(3) मत विभाजन का परिणाम अध्यक्ष द्वारा विधो-नित किया जाएगा और उस पर आपत्ति नहीं की जाएगी।

367 ख. लॉबी में जाकर विभाजन(1).—अध्यक्ष द्वारा जब नियम 367 के उप नियम (3) के खण्ड (ग) के अंतर्गत यह निदेश दिया जाए कि सदस्यों द्वारा सभा-कक्ष में जाकर

मत अभिलिखित करवाये जाएंगे तो वह ‘हां’ वालों से दाएं लॉबी में जाने के लिए कहेगा और ‘ना’ वालों से बायें लॉबी में। यथास्थिति ‘हां’ या ‘ना’ वाले लॉबी में प्रत्येक सदस्य द्वारा अपनी विभाजन संख्या बतायी जाएगी और विभाजन लिपिक विभाजन सूची में उसकी संख्या पर निशान लगाते हुए साथ-साथ सदस्य का नाम पुकारेगा।

(2) लॉबी में मतदान पूर्ण हो जाने के बाद विभाजन लिपिक विभाजन सूचियां पटल पर ले आयेंगे और तब पटल पर बैठे हुए पदाधिकारियों द्वारा मतों की गणना की जाएगी और ‘हां’ वालों और ‘ना’ वालों के योग अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किए जायेंगे।

(3) विभाजन का परिणाम अध्यक्ष द्वारा विधो-नित किया जाएगा और उस पर आपत्ति नहीं की जाएगी।

(4) जो सदस्य बीमारी या दौर्बल्य के कारण विभाजन लॉबी तक जाने में असमर्थ हो, वह विभाजन का परिणाम विधो-नित किए जाने से पहले अध्यक्ष की अनुज्ञा से या तो उस सदस्य को आबंटित स्थान पर या लॉबी में मत अभिलिखित करा सकेगा।

(5) यदि किसी सदस्य को यह पता चले कि भूल से गलत लॉबी में मत दे दिया गया है तो ऐसे सदस्य को भूल सुधारने की अनुमति दी जा सकेगी यदि उस सदस्य द्वारा इस बात की जानकारी विभाजन का परिणाम विधो-नित किए जाने से पहले अध्यक्ष के ध्यान में लाई जाए।

(6) जब विभाजन लिपिक विभाजन सूचियां पटल पर ला चुके हों तो कोई सदस्य, जिसने उस समय तक अपना मत अभिलिखित न कराया हो, किंतु जो तब अपना मत अभिलिखित कराना चाहता/चाहती हो, विभाजन का परिणाम विधो-नित किए जाने से पहले, अध्यक्ष की अनुज्ञा से ऐसा कर सकेगा/सकेगी।

पत्रों का पटल पर रखा जाना

368. उद्धृत पत्रों का पटल पर रखा जाना.—यदि किसी मंत्री द्वारा सभा में किसी ऐसे प्रे-ण पत्र या अन्य राजपत्र को उद्धृत किया जाए जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो, तो मंत्री द्वारा संगत पत्र को पटल पर रखा जाएगा:

परंतु यह नियम ऐसे किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होगा जिसे मंत्री द्वारा ऐसे स्वरूप का बताये कि उसका पेश किया जाना लोकहित के प्रतिकूल होगा:

परंतु यह और भी कि जब मंत्री द्वारा ऐसे प्रे-ण पत्र या राजपत्र का अपने शब्दों में संक्षेप या सारांश बता दिया जाए तो संगत पत्रों को पटल पर रखना आवश्यक नहीं होगा।

369. पटल पर रखे गये पत्रों पर कार्यवाही और उनका प्रमाणीकरण(1).—पटल पर रखा गया पत्र या दस्तावेज, उसे प्रस्तुत करने वाले सदस्य द्वारा उचित प्रकार से प्रमाणित किया जायेगा।

(2) पटल पर रखे गये सब पत्र और दस्तावेज सार्वजनिक समझे जायेंगे।

370. दिए गए परामर्श या राय को प्रकट करने संबंधी दस्तावेजों का सभा पटल पर रखा जाना.—किसी मंत्री द्वारा किसी प्रश्न के उत्तर में या वाद-विवाद के दौरान कोई ऐसा परामर्श या राय प्रकट की जाए जो मंत्री को सरकार के किसी पदाधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दी गई हो तो मंत्री द्वारा साधारणतया उस राय या परामर्श वाला संगत दस्तावेज या दस्तावेज का भाग या उसका संक्षेप पटल पर रखा जाएगा।

[सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति विनियमों के लिए इस नियमावली का अध्याय 26 देखिए]

वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित के आधार पर किसी सदस्य के मत पर आपत्ति

371. किसी सदस्य के मत पर आपत्ति.—यदि सभा के किसी विभाजन में किसी सदस्य के मत का विनिश्चय किए जाने वाले विनियमों में उस सदस्य के वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित होने के आधार पर आपत्ति की जाए तो अध्यक्ष द्वारा, यदि आवश्यक समझे, आपत्ति करने वाले सदस्य से अपनी आपत्ति के आधारों को सुतथ्यतः कहने के लिए और जिस सदस्य के मत पर आपत्ति की गई हो उससे अपना मामला बताने के लिए कहा जा सकेगा और यह विनिश्चित किया जाएगा कि उस सदस्य का मत अस्वीकृत किया जाना चाहिए या नहीं और अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा:

परंतु किसी सदस्य या सदस्यों के मत पर आपत्ति मत विभाजन समाप्त होने के तुरन्त बाद और अध्यक्ष द्वारा परिणाम विधो-नित किए जाने से पहले की जाए।

व्याख्या—इस नियम के प्रयोजनों के लिए सदस्य का हित प्रत्यक्ष, वैयक्तिक या आर्थिक होना चाहिए और वह हित जन साधारण या उसके किसी वर्ग या भाग के साथ सम्मिलित रूप में राज्य की नीति के किसी विनियम में न होकर उस व्यक्ति का, जिसके मत पर आपत्ति की जाए, पृथक रूप से होना चाहिए।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

372. मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य.—लोक-महत्व के किसी विनियम पर अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जाएगा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।

सदस्यों का बाहर चला जाना या निलम्बन

373. सदस्यों का बाहर चला जाना.—यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि किसी सदस्य का व्यवहार अव्यवस्थापूर्ण है तो अध्यक्ष द्वारा उस सदस्य को, तत्काल सभा से बाहर चले जाने का निदेश दिया जा सकेगा और जिस सदस्य को इस

तरह बाहर चले जाने का आदेश दिया जा सकेगा वह तुरन्त सभा से बाहर चला जाएगा/चली जाएगी और उस दिन की अवशिष्ट बैठक के समय तक अनुपस्थित रहेगा/रहेगी।

374. सदस्य का निलम्बन(1).—अध्यक्ष द्वारा, यदि आवश्यक समझा जाए उस सदस्य का नाम लिया जा सकेगा जो अध्यक्ष-पीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करे या जो हठपूर्वक और जानबूझकर सभा के कार्य में बाधा डालकर सभा के नियमों का दुरुपयोग करे।

(2) यदि किसी सदस्य का अध्यक्ष द्वारा इस तरह नाम लिया जाए तो अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव किए जाने पर, तुरन्त यह प्रश्न रखा जाए कि सदस्य (उस सदस्य का नाम लेकर) को सत्र के अवशिष्ट काल तक सभा की सेवा से निलंबित किया जाए:

परंतु सभा किसी भी समय प्रस्ताव किए जाने पर संकल्प कर सकेगी कि ऐसा निलंबन समाप्त किया जाए।

(3) इस नियम के अंतर्गत निलम्बित सदस्य तुरन्त सभा के परिसर के बाहर चला जाएगा/चली जाएगी।

⁹**[374क. सदस्य का स्वतः निलंबन(1).**—नियम 373 और 374 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष के आसन के निकट आकर अथवा सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से सभा की कार्यवाही में बाधा डालकर लगातार और जानबूझकर सभा के नियमों का दुरुपयोग करते हुए घोर अव्यवस्था उत्पन्न किए जाने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा सदस्य का नाम लिए जाने पर वह सभा की सेवा से लगातार पाँच बैठकों के लिए या सत्र की शेष अवधि के लिए, जो भी कम हो, स्वतः निलंबित हो जाएगा/जाएगी:

परंतु सभा किसी भी समय प्रस्ताव किए जाने पर, संकल्प कर सकेगी कि ऐसा निलंबन समाप्त किया जाए।

(2) अध्यक्ष द्वारा इस नियम के अंतर्गत निलंबन किए जाने की घोषणा के बाद निलंबित सदस्य सभा के परिसर से तुरन्त बाहर चला जाएगा/चली जाएगी।]

घोर अव्यवस्था के कारण सभा का स्थगन या बैठक का निलम्बन

375. अध्यक्ष की सभा को स्थगित करने या बैठक को निलंबित करने की शक्ति.—सभा में घोर अव्यवस्था उत्पन्न होने की दशा में अध्यक्ष द्वारा यदि ऐसा करना आवश्यक समझा जाए अध्यक्ष द्वारा उसके बताए गए समय के लिए सभा को स्थगित किया जा सकेगा या किसी बैठक को निलंबित किया जा सकेगा।

औचित्य प्रश्न

376. औचित्य प्रश्न और उन पर विनिश्चय(1).—औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सभा का कार्य विनियमित होता है, निर्वाचन या

⁹ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 06.12.2001, पैरा संख्या 2430 द्वारा जोड़ा गया।

प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसके द्वारा ऐसा प्रश्न उठाया जाएगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।

(2) औचित्य प्रश्न तत्समय सभा के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा:

परंतु अध्यक्ष द्वारा सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारंभ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दी जा सकेगी यदि वह सभा में व्यवस्था बनाए रखने या सभा के समक्ष कार्य विन्यास के संबंध में हो।

(3) उपनियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी सदस्य द्वारा औचित्य प्रश्न उठाया जा सकेगा और अध्यक्ष द्वारा यह विनिश्चय किया जाएगा कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) किसी औचित्य प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुमति नहीं होगी, किन्तु अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बात सुनी जा सकेगी।

(5) औचित्य प्रश्न विशेष-अधिकार का प्रश्न नहीं है।

(6) किसी सदस्य द्वारा—

(क) जानकारी मांगने के लिए, या

(ख) अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए, या

(ग) जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सभा के सामने रखा जा रहा हो, या

(घ) काल्पनिक, या

(ङ) विभाजन की घंटियां नहीं बजें या सुनाई नहीं पड़ें, ऐसा औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जाए।

377. ¹⁰[ऐसा वि-अय उठाना जो औचित्य प्रश्न न हो.]—ऐसे किसी सदस्य द्वारा जो सभा की जानकारी में कोई ऐसा वि-अय लाना चाहे जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह उठाए जाने वाले वि-अय के पाठ की सूचना स्पष्ट तथा सही रूप से लिखित रूप में महासचिव को दी जाएगी। सदस्य को ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सहमति दिए जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिए दी जाएगी जो अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाए।

377क. ¹¹[ग्राह्यता की शर्त.]—सूचना को ग्राह्य बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:—

(एक) वह उस वि-अय से संबंधित नहीं होगी जो मुख्यतया भारत सरकार से संबंधित नहीं है;

(दो) वह उस वि-अय के संबंध में नहीं होगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो अथवा सत्र के दौरान इस नियम के अंतर्गत सदस्य द्वारा उठाए गए वि-अय के समान हो;

(तीन) उसमें 250 से अधिक शब्द नहीं होंगे;

(चार) उसमें एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे;

(पाँच) उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मकपद, अभ्यारोप, विशेष-अय या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे; और

(छह) उसमें संसदीय/सलाहकार समिति की कार्यवाही वृत्तांतों का उल्लेख नहीं किया जाएगा।

377ख. सूचनाएं देने के लिए समय और उनकी वैधता.—

(एक) सप्ताह के दौरान पहली बैठक प्रारंभ होने के समय से सप्ताह के अंतिम दिन, जब सभा की बैठक हो, 10.00 बजे तक प्राप्त होने वाली सूचनाएं उस सप्ताह के लिए वैध होंगी।

(दो) सप्ताह के अंतिम दिन, जिस दिन सभा की बैठक हो, 10.00 बजे के बाद प्राप्त होने वाली सूचनाएं अगले सप्ताह के लिए वैध होंगी। उस दिन 10.00 बजे के बाद 10.30 बजे तक प्राप्त सूचनाएं उसी समय दी गई सूचनाएं समझी जाएंगी तथा सदस्यों की पारस्परिक प्राथमिकता निश्चित करने के लिए इनका बैलट किया जाएगा। बाद में प्राप्त होने वाली सूचनाएं उनके प्राप्त होने की तिथि तथा समय के अनुसार क्रमबद्ध की जाएंगी।

(तीन) उस सप्ताह के दौरान, जिसके लिए उन्हें दिया गया है, न चुनी गई सूचनाएं, सप्ताह के अंत में व्यपगत हो जाएंगी:

परंतु अध्यक्ष के आदेश के अधीन तथ्यों के लिए निर्दिष्ट कोई सूचना उसके अंतिम रूप से निपटाए जाने तक व्यपगत नहीं होगी।

377ग. विषय उठाने पर प्रतिबंध.—(एक) किसी भी सदस्य द्वारा सप्ताह के दौरान एक से अधिक वि-अय नहीं उठाए जाएंगे।

(दो) केवल अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित पाठ ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

व्यवस्था बनाए रखना

378. अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था बनाए रखा जाना और विनिश्चयों का प्रवर्तन किया जाना.—अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था बनाए रखी जाएगी और अपने विनिश्चयों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष को सब आवश्यक शक्तियां होंगी।

सभा की कार्यवाही, संसदीय पत्र और पत्रों की अभिरक्षा

379. कार्यवाही वृत्तांत का तैयार किया जाना और उसका प्रकाशन.—महासचिव द्वारा सभा की प्रत्येक बैठक

¹⁰ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 09.05.1989, पैरा संख्या 2930 द्वारा

¹¹ वही, जोड़ा गया।

प्रतिस्थापित किया गया।

की कार्यवाही का पूरा वृत्तांत तैयार करवाया जाएगा और उसे यथासाध्य शीघ्र ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति से प्रकाशित कराया जाएगा जैसा कि अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निदेश दिया जाए।

380. शब्दों का निकाला जाना.—यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किए गए हैं जो मानहानिकारक या अशि-ट या असंसदीय या अभद्र हैं, तो अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया जा सकेगा कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही में से निकाल दिए जाएं।

381. निकाले गए शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत में दर्शाना.—सभा की कार्यवाही में से इस तरह निकाले गए अंश पर तारांक लगाया जाएगा और कार्यवाही में निम्नलिखित व्याख्यात्मक टिप्पणी समाविष्ट की जाएगी:

अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया

382. संसदीय पत्रों का मुद्रण तथा प्रकाशन.—(1) अध्यक्ष द्वारा सभा के कार्य के संबंध में किसी पत्र, दस्तावेज या प्रतिवेदन अथवा पटल पर रखे गए या सभा या उसकी किसी समिति के सामने प्रस्तुत किए गए किसी पत्र, दस्तावेज या प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन, वितरण या विक्रय का प्राधिकार दिया जा सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अनुसरण में मुद्रित, प्रकाशित, वितरित या विक्रीत कोई पत्र, दस्तावेज या प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 105 के खण्ड (2) के अर्थ में सभा के प्राधिकार के अंतर्गत मुद्रित, प्रकाशित, वितरित या विक्रीत समझा जाएगा।

(3) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई पत्र, दस्तावेज या प्रतिवेदन सभा के कार्य से संबंधित है या नहीं, तो उस प्रश्न को अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

383. पत्रों की अभिरक्षा.—सभा या उसकी किसी समिति के अथवा लोक सभा सचिवालयों के सब अभिलेख, दस्तावेज और पत्र महासचिव की अभिरक्षा में रहेंगे और महासचिव द्वारा किन्हीं ऐसे अभिलेखों, दस्तावेजों या पत्रों को, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, संसद भवन से बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा।

सभा का भवन

384. सभा के भवन के उपयोग पर निर्बन्धन.—सभा के भवन का उपयोग सभा की बैठकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

सभा में राज्य सभा के पदाधिकारी का प्रवेश

385. राज्य सभा के पदाधिकारियों को सभा की बैठक में प्रवेश का हक.—राज्य सभा के साचिविक कर्मचारीवृन्द के किसी भी पदाधिकारी को सभा की किसी बैठक के दौरान सदन में प्रवेश करने का हक होगा।

अजनबियों का प्रवेश, उनको बाहर जाने का आदेश हटाया जाना

386. अजनबियों का प्रवेश.—सभा की बैठकों के दौरान सदन के उन भागों में जो सदस्यों के अनन्य उपयोग के लिए रक्षित न हो, अजनबियों का प्रवेश अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

387. अजनबियों का बाहर चला जाना.—अध्यक्ष द्वारा जब कभी ठीक समझा जाए अजनबियों को सदन के किसी भाग से बाहर चले जाने का आदेश दिया जा सकेगा।

387क. अजनबियों का हटाया जाना और अभिरक्षा में लिया जाना.—अध्यक्ष द्वारा इस वि-य में प्राधिकृत सचिवालय का किसी पदाधिकारी द्वारा सभा के परिसर के किसी भाग में, जो सदस्यों के अनन्य उपयोग के लिए रक्षित है, देखे गए किसी अजनबी को या जिसका वहाँ होना ऐसे पदाधिकारी को बताया जाए और ऐसे किसी अजनबी को भी, जो सभा के परिसर के किसी भाग में प्रविष्ट हो गया हो, जो स्वयं दुर्व्यवहार करे अथवा अध्यक्ष द्वारा नियम 386 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों का जान-बूझकर उल्लंघन करे या सभा की बैठक के समय नियम 387 के अंतर्गत जब अजनबियों से बाहर जाने को कहा जाए, बाहर न जाए, सभा के परिसर से हटा दिया जाएगा अथवा अभिरक्षा में ले लिया जाएगा।

रा-ट्रपति के शासनाधीन राज्य का कार्य

387ख. रा-ट्रपति के शासनाधीन राज्य से संबंधित कार्यवाही पर नियमों का लागू किया जाना.—ये नियम, ऐसे परिवर्तनों या रूप भेदों के साथ जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर किए जाएं ऐसे राज्य से संबंधित कार्यवाही पर लागू होंगे जिनके विधानमंडल की शक्तियाँ रा-ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घो-णा की सामर्थ्य से, संसद द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य हों।

नियमों का निलंबन

388. नियमों का निलंबन.—किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की सम्मति से यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलंबित कर दिया जाए और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

अवशि-ट शक्तियाँ

389. अवशि-ट शक्तियाँ.—ऐसे सब वि-य जिनका इन नियमों में विशि-ट रूप से उपबन्धन न किया गया हो और इन नियमों की विस्तृत क्रियान्विति से संबंधित सब प्रश्न ऐसी रीति से विनियमित किए जाएंगे जैसा कि अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निदेश दिया जाए।

प्रथम अनुसूची
(देखिए नियम 161)
याचिका का प्रपत्र

द्वितीय अनुसूची
¹[*** **]

सेवा में

लोक सभा

(यहां संक्षिप्त रूप में याचिका देने वाले/वाली या देने वालों के नाम तथा पद या विवरण, यथा "क, ख तथा अन्य" "या..... के/की निवासी" की नगरपालिका" आदि समावि-ट कीजिए) की विनम्र याचिका दर्शाती है।

(यहां मामले का संक्षिप्त विवरण लिखिए)

और तदनुसार आपको याचिका देने वाला/वाली (या याचिका देने वाले) प्रार्थना करता है (करते हैं) कि

(यहां समावि-ट कीजिए " कि विधेयक के संबंध में आगे कार्यवाही की जाये या न की जाये " या "कि आपको याचिका देने वाले/वाली (वालों) के मामले के लिए विधेयक में विशेष-उपबंध किया जाए" या सभा के समक्ष विधेयक या वि-य अथवा सामान्य लोक हित के वि-य के संबंध में कोई अन्य समुचित प्रार्थना)

और आपको याचिका देने वाला/वाली (वाले) कर्तव्यबद्ध होकर सदा प्रार्थना करेगा/करेगी (करेंगे)।

याचिका देने वाले/वाली का नाम	पता	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्रस्तुत करने वाले सदस्य के प्रतिहस्ताक्षर ।

¹लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 17.02.2014, पैरा संख्या 6174 द्वारा लोप किया गया।

तृतीय अनुसूची
(देखिए नियम 229 और 230)

किसी सदस्य के, यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध,
दो-गिराई या रिहाई के बारे में सूचना का प्रपत्र

स्थान

दिनांक

सेवा में,
अध्यक्ष,
लोक सभा,
नई दिल्ली।

प्रिय अध्यक्ष महोदय/महोदय,

क

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि
(अधिनियम) की धारा के अंतर्गत अपनी
शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना
कर्तव्य समझा कि लोक सभा के सदस्य, श्रीमती/कुमारी/श्री
..... को (यथास्थिति बन्दीकरण
या निरोध के कारण) के लिए बन्दी/निरुद्ध कर लिया जाए।

तदनुसार श्रीमती/कुमारी/श्री, संसद सदस्य
को.....(तिथि) पर (समय) बन्दी
बना लिया गया है।

हवालात में रखा गया है।

और उसे इस समय जेल
(स्थान) में रखा गया है।

ख

मुझे आपको सूचना देनी है कि लोक सभा के सदस्य
श्रीमती/कुमारी/श्रीपर (दो-गिराई
के कारण) के दो-गिराई (या दो-गिराई के लिए).....
न्यायालय में मेरे सामने मुकदमा चलाया गया।

..... दिन तक मुकदमा चलने के बाद
..... (तिथि) को मैंने उसे का
अपराधी पाया और उसे (कालावधि) के
कारावास का दंडादेश दिया।

(..... * को अपील करने की अनुमति के
लिए उसका प्रार्थनापत्र विचारार्थ लंबित है)।

*न्यायालय का नाम।

ग

मुझे आपको सूचना देनी है कि लोक सभा के सदस्य
श्रीमती/कुमारी/श्री को, जिसे.....
(तिथि) को (बन्दीकरण/निरोध/दो-गिराई) के
कारण बन्दी बनाया गया/निरुद्ध किया गया/सिद्धदो-गिराई
गया था, (तिथि) को (रिहाई
के कारण) रिहा कर दिया गया था।

भवनि-ठ,
(न्यायाधीश, दण्डाधिकारी,
या कार्यपालिका प्राधिकारी)

चतुर्थ अनुसूची

(देखिए नियम 312क)

सरकारी उपक्रमों की सूची

भाग 1

(केन्द्रीय अधिनियमों द्वारा स्थापित किए गए सरकारी
उपक्रम)

1. दामोदर घाटी निगम।
2. भारतीय औद्योगिक वित्त आयोग।
3. इंडियन एयरलाइन्स। ¹[***]
4. एयर इंडिया। ²[***]
5. भारतीय जीवन बीमा निगम।
6. सेन्ट्रल वेअरहाउसिंग कारपोरेशन।
7. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग।
8. भारतीय खाद्य निगम।
9. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण।
10. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ³[***]
11. दिल्ली परिवहन निगम।⁴

भाग 2

(सरकारी उपक्रम जो कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत
बनाई गई सरकारी कम्पनियां हैं)

प्रत्येक सरकारी कम्पनी जिसका वार्षिक प्रतिवेदन
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा
(1) के अन्तर्गत संसद के सदनों के समक्ष रखा जाता
है।

¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 09.05.1989, के पैरा संख्या 2930 द्वारा जोड़ा गया।

² वही, लोप किया गया।

³ वही, प्रविन्टि 11 का लोप किया गया।

⁴ वही, प्रविन्टि 12 को पुनर्संख्यांकित करके 11 किया गया।

भाग 3

1

2

3

1. हिन्दुस्तान ⁵[एयरोनोटिक्स] लिमिटेड, बंगलौर।
2. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर।
3. मझगांव डाक्स लिमिटेड, मुम्बई।
4. गार्डनरीच ⁶[शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स] लिमिटेड, कलकत्ता।

पांचवीं अनुसूची¹

(देखिए नियम 331ग)

**स्थायी समितियों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
आने वाले मंत्रालय/विभाग**

क्रमांक	समिति का नाम	मंत्रालय/विभाग
1	2	3
भाग एक		
1.	वाणिज्य संबंधी समिति	वाणिज्य और उद्योग
2.	गृह कार्य संबंधी समिति	(1) गृह (2) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास
3.	मानव संसाधन विकास संबंधी समिति	(1) मानव संसाधन विकास (2) युवा मामले और खेल (3) महिला और बाल विकास
4.	उद्योग संबंधी समिति	(1) भारी उद्योग और सरकारी उद्यम (2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
5.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति	(1) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (2) अंतरिक्ष (3) पृथ्वी विज्ञान (4) परमाणु ऊर्जा (5) पर्यावरण और वन
6.	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति	(1) नागर विमानन (2) सड़क परिवहन और राजमार्ग (3) पोत परिवहन (4) संस्कृति (5) पर्यटन
7.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
8.	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति	(1) विधि और न्याय (2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन

भाग दो

9. कृषि संबंधी समिति (1) कृषि
(2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
10. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति (1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी
(2) सूचना और प्रसारण
11. रक्षा संबंधी समिति रक्षा
12. ऊर्जा संबंधी समिति (1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा
(2) विद्युत
13. विदेशी मामलों संबंधी समिति (1) विदेश
(2) प्रवासी भारतीय कार्य
14. वित्त संबंधी समिति (1) वित्त
(2) कारपोरेट मामले
(3) योजना
(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
15. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
16. श्रम संबंधी समिति (1) श्रम और रोजगार
(2) वस्त्र
17. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
18. रेल संबंधी समिति रेल
19. शहरी विकास संबंधी समिति (1) शहरी विकास
(2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन
20. जल संसाधन संबंधी समिति जल संसाधन
21. रसायन और उर्वरक संबंधी समिति रसायन और उर्वरक
22. ग्रामीण विकास संबंधी समिति (1) ग्रामीण विकास
(2) पेयजल और स्वच्छता
(3) पंचायती राज
23. कोयला और इस्पात संबंधी समिति (1) कोयला
(2) खान
(3) इस्पात
24. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता
(2) जनजातीय कार्य
(3) अल्पसंख्यक मामले

⁵ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 09.05.1989, के पैरा संख्या 2930 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

⁶ वही, प्रतिस्थापित किया गया।

¹ लोक सभा समाचार भाग-दो, दिनांक 20.07.2004 (पैरा 253) द्वारा 17 समितियों की वर्तमान अनुसूची को 24 समितियों की संशोधित अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और इसे समाचार भाग-दो दिनांक 05.05.2006 (पैरा 2367), दिनांक 10.04.2007 (पैरा 3493), दिनांक 10.09.2008 (पैरा 6008) 10.11.2009 (पैरा 675) और 01.11.2011 (पैरा 3223) द्वारा स्वीकार किया गया।

परिशिष्ट 1**संसद के सदनों (संयुक्त बैठकें तथा संवाद) संबंधी नियम*****अध्याय 1****प्रारम्भिक**

1. संक्षिप्त नाम.—ये नियम संसद के सदनों (संयुक्त बैठक तथा संवाद) संबंधी नियम कहलाएंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

- (क) "परि-द्" का तात्पर्य राज्य सभा से है;
- (ख) "सभा" का तात्पर्य लोक सभा से है;
- (ग) "सदनों" का तात्पर्य राज्य सभा तथा लोक सभा से है;
- (घ) "संयुक्त बैठक" का तात्पर्य सदनों की किसी संयुक्त बैठक से है;
- (ङ.) "सदस्य" का तात्पर्य राज्य सभा या लोक सभा के सदस्य से है;
- (च) "महासचिव" का तात्पर्य लोक सभा के महासचिव से और किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो उस समय महासचिव का कार्य कर रहा हो/रही हो; और
- (छ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य सभा के अध्यक्ष से है;

अध्याय 2**सदनों की संयुक्त बैठकें**

3. सदस्यों को आमंत्रण.—महासचिव द्वारा संयुक्त बैठक के लिए समय तथा स्थान का उल्लेख करते हुए प्रत्येक सदस्य को आमंत्रण भेजा जाएगा।

4. बैठक का समय.—अध्यक्ष द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि संयुक्त बैठक किस समय स्थगित की जायेगी तथा किस दिन और किस समय अथवा उसी दिन के किस भाग तक के लिए स्थगित की जायेगी।

5. पीठासीन अधिकारी.—किसी संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान, सभा का उपाध्यक्ष या, यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो, तो राज्य सभा का उप-चेयरपर्सन

या, यदि उप-चेयरपर्सन भी अनुपस्थित हो तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाये, पीठासीन होगा।

6. गणपूर्ति.—संयुक्त बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति सदनों के सदस्यों की समस्त संख्या का दसवां भाग होगी।

7. प्रक्रिया.—किसी संयुक्त बैठक में सभा की प्रक्रिया ऐसे रूपभेदों तथा परिवर्तनों के साथ लागू होगी जिन्हें अध्यक्ष आवश्यक या उचित समझे।

8. संयुक्त बैठकों की कार्यवाही का वृत्तांत.—महासचिव द्वारा प्रत्येक संयुक्त बैठक की कार्यवाही का पूरा वृत्तान्त तैयार करवाया जाएगा और उसे यथासाध्य शीघ्र ऐसे रूप में तथा ऐसी नीति से प्रकाशित करवाया जाएगा, जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश दें।

अध्याय 3**सदनों के बीच संवाद**

9. संदेशों द्वारा संवाद.—सदनों के बीच संवाद संदेशों द्वारा होगा।

10. संदेशों के भेजने की रीति.—सभा से राज्य सभा को या राज्य सभा से सभा को प्रत्येक संदेश लिखा हुआ या छपा हुआ या आंशिक रूप में लिखा हुआ और आंशिक रूप में छपा हुआ होगा तथा उस पर, यथास्थिति सभा या राज्य सभा के महासचिव के हस्ताक्षर होंगे और वह यथास्थिति राज्य सभा या सभा के महासचिव को भेजा जाएगा।

11. सदस्यों को संदेशों की सूचना (1).—सभा या राज्य सभा जबकि वह सत्र में हो, से किसी संदेश के प्राप्त होने पर महासचिव द्वारा यथास्थिति, सभा या राज्य सभा को, संदेश प्राप्त होने के बाद प्रथम सुविधाजनक अवसर पर, उनकी सूचना दी जाएगी।

(2) जब कभी, यथास्थिति सभा या राज्य सभा, जिसे संदेश भेजा जाए, सत्र में न हो तो संदेश की प्रति सभा या राज्य सभा के महासचिव को जैसे ही प्राप्त हो उसके द्वारा सभा या राज्य सभा के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी।

12. संदेश के वि-य के संबंध में कार्यवाही करने की प्रक्रिया.—यथास्थिति, सभा या राज्य सभा जिसे कोई संदेश भेजा जाए उसके द्वारा संदेश के वि-य के संबंध में कार्यवाही उसकी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार की जाएगी।

*रा-द्रूपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 118 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सभा के सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् बनाये गये नियम। [संसदीय कार्य विभाग अधिसूचना संख्या 5(1) पी.ए. 52, दिनांक 16.5.1952, राजपत्र असाधारण (I-1) 20.05.1952]

परिशिष्ट 2**प्रक्रिया नियमों में जिन समितियों का उल्लेख****नहीं है उनके बारे में नियम*****सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति**

1. गठन.—एक सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति होगी जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरपर्सन तालिका के सदस्य, लोक सभा की सब स्थायी संसदीय समितियों के चेयरपर्सन, लोक सभा के मान्यताप्राप्त दलों और गुटों के नेता और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाए। अध्यक्ष, समिति का पदेन सभापति होगा।

2. कृत्य.—समिति का कृत्य, सभा के मामलों से संबंधित ऐसे विषयों पर जो उसे अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं, विचार करना और उनके संबंध में मंत्रणा देना होगा।

3. अन्य प्रकरणों में लागू होने वाले उपबंध.—अन्य प्रकरणों में, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (चौदहवां संस्करण) के अध्याय 26 में दिए गए संसदीय समितियों को लागू होने वाले सामान्य नियम ऐसे परिवर्तनों के साथ, चाहे वे रूपभेद, वृद्धि अथवा लोप द्वारा हों, लागू होंगे जैसे कि अध्यक्ष आवश्यक अथवा सुविधाजनक समझे।

आवास समिति

1. गठन (1).—एक आवास समिति होगी, जिसमें सभापति को मिलाकर बारह से अनधिक सदस्य होंगे।

(2) समिति, अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित की जाएगी और उसकी पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। कोई सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नई आवास समिति के लिए पुनः नामनिर्देशित किया जा सकेगा।

2. गणपूर्ति.—समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति पांच होगी।

3. कृत्य (1).—आवास समिति के कृत्य ये होंगे:—

(एक) लोक सभा के सदस्यों के निवास-स्थान संबंधी प्रश्नों के बारे में कार्यवाही करना; और

(दो) सदस्यों को दिल्ली में उनके निवास-स्थानों और होस्टलों में दी गई आवास, भोजन, चिकित्सा सहायता संबंधी और अन्य सुविधाओं की देखभाल करना।

(2) समिति के कृत्य मंत्रणात्मक होंगे।

4. आवास स्थान उप-समिति (1).—एक आवास-स्थान उप-समिति होगी, जिसमें आवास समिति के सभापति सहित, जो उप-समिति का पदेन चेयरपर्सन होगा, चार से अनधिक सदस्य होंगे।

(2) उप-समिति के सदस्य, आवास समिति के सभापति द्वारा आवास समिति के सदस्यों में से नामनिर्देशित किए जाएंगे।

(3) उप-समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति दो होगी।

(4) उप-समिति का कृत्य सदस्यों को निवास-स्थान देने के संबंध में मंत्रणा देना होगा।

5. उप-समिति को नियुक्त करने की शक्ति (1).—समिति, आवास-स्थान, भोजन, चिकित्सा सहायता और सदस्यों के निवास-स्थानों में अन्य सुविधाओं के संबंध में किसी विशेष बात की जांच करने के लिए एक या अधिक उप-समितियां नियुक्त कर सकेंगी, जिनमें से प्रत्येक को अविभक्त समिति की शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसी उप-समितियों के प्रतिवेदन संपूर्ण समिति के प्रतिवेदन समझे जाएंगे, यदि वे संपूर्ण समिति की किसी बैठक में अनुमोदित हो जाएं।

(2) किसी उप-समिति को निर्देश के आदेश में जांच की बात या बातें स्पष्टतया लिखी होंगी। उप-समिति के प्रतिवेदन पर संपूर्ण समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

6. समिति के लिए सचिवालय.—आवास समिति अथवा इसकी उप-समिति के लिए सचिवालय की व्यवस्था लोक सभा सचिवालय द्वारा की जाएगी। लोक सभा के महासचिव द्वारा इस विषय में नामनिर्देशित लोक सभा सचिवालय का एक पदाधिकारी आवास समिति तथा आवास स्थान उप-समिति का सचिव होगा।

7. समिति की कार्यवाही और कार्यवाही के सारांश का अभिलेख (1).—आवास समिति और आवास स्थान उप-समिति की बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखा जाएगा।

(2) कार्यवाही के सारांश का प्रारूप समिति के सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा और सभापति द्वारा अनुमोदित होगा।

(3) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का सारांश, यथास्थिति, समिति या उप-समिति के सदस्यों को परिचालित किया जाएगा। उसमें से संगत उद्धरण संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजे जा सकेंगे।

8. अपील.—आवास समिति अथवा आवास स्थान उप-समिति के विनिश्चय के विरुद्ध अपील अध्यक्ष से की जाएगी जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

9. अन्य प्रकरणों में लागू होने वाले उपबंध.—अन्य प्रकरणों में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (चौदहवां संस्करण) के अध्याय 26 में दिए गए संसदीय समितियों को लागू होने वाले सामान्य नियम ऐसे परिवर्तनों के साथ, चाहे वे रूपभेद, वृद्धि अथवा लोप द्वारा हों, लागू होंगे जैसे कि अध्यक्ष आवश्यक तथा सुविधाजनक समझे।

ग्रंथालय समिति

1. गठन (1).—एक ग्रंथालय समिति होगी जिसमें—

(क) उपाध्यक्ष और अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट लोक सभा के पांच अन्य सदस्य;

* अध्यक्ष द्वारा बनाये गये नियम।

(ख) राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य सभा के तीन सदस्य होंगे।

(2) समिति एक वर्ग से अनधिक अवधि के लिए पदधारण करेगी।

(3) उपाध्यक्ष, समिति का पदेन सभापति होगा।

(4) समिति में आकस्मिक रिक्त स्थानों को, लोक सभा के सदस्यों के संबंध में अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशन से और राज्य सभा के सदस्यों के संबंध में राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्देशन से भरा जाएगा।

2. कृत्य.—सभापति के कृत्य ये होंगे—

(क) ग्रंथालय से संबंधित ऐसे वि-ियों पर विचार करना और मंत्रणा देना जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएं;

(ख) ग्रंथालय की उन्नति के लिए सुझावों पर विचार करना; और

(ग) ग्रंथालय द्वारा दी गई सेवाओं से पूरा-पूरा लाभ उठाने में संसद सदस्यों की सहायता करना।

3. समिति से त्यागपत्र.—कोई सदस्य अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा समिति से अपने स्थान का त्याग कर सकेगा/सकेगी।

4. समिति की बैठकों से अनुपस्थित सदस्यों को हटाना.—यदि कोई सदस्य समिति की लगातार दो या अधिक बैठकों से समिति के सभापति की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहे तो ऐसे सदस्य को, यथास्थिति, लोक सभा का अध्यक्ष अथवा राज्य सभा का सभापति समिति से हटा सकेगा/सकेगी।

5. सदनों की बैठक के समय समिति की बैठक हो सकेगी.—जिस समय लोक सभा अथवा राज्य सभा की बैठक हो रही हो उस समय भी समिति की बैठक हो सकेगी परंतु किसी भी सदन में विभाजन की मांग की जाने पर समिति का सभापति समिति की कार्यवाही ऐसे समय के लिए निलंबित कर देगा जिसके भीतर, सभापति की राय में, सदस्य, विभाजन में मत दे सकें।

6. अन्य प्रकरणों में लागू होने वाले उपबंध.—अन्य प्रकरणों में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (चौदहवां संस्करण) के अध्याय 26 में दिए गए संसदीय समितियों को लागू होने वाले सामान्य नियम ऐसे परिवर्तनों के साथ, चाहे वे रूपभेद, वृद्धि अथवा लोप द्वारा हों, लागू होंगे जैसे कि अध्यक्ष आवश्यक अथवा सुविधाजनक समझे।

परिशिष्ट 3

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रावधान

संसद सदस्य वेतन, भत्ते तथा पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 के उद्धरण:

9. नियम बनाने की शक्ति (1).—इस धारा के अधीन नियम बनाने के प्रयोजन से संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी जिसमें राज्य सभा के पांच सदस्य, जो सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे और लोक सभा के दस सदस्य होंगे जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति अपना सभापति निर्वाचित करेगी और उसे अपनी प्रक्रिया के विनियमन की शक्ति होगी।

¹[(2क) संयुक्त समिति का एक सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से एक वर्ग तक इस प्रकार के सदस्य के रूप में पदधारण करेगा और संयुक्त समिति में कोई आकस्मिक रिक्ति, यथास्थिति, राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशन द्वारा भरी जा सकेगी।

स्प-टीकरण—संसद सदस्य वेतन भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 1958 के प्रारंभ से तुरंत पूर्व इस प्रकार के पदधारण करने वाले संयुक्त समिति के सदस्य की अवस्था में एक वर्ग की अवधि इस प्रकार के प्रारंभ की तारीख से गिनी जाएगी।]

(3) उप-धारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति² [केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के बाद] निम्न वि-ियों में से सब या किसी की व्यवस्था के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्—

(क) किसी यात्रा के करने के लिए प्रयाणमार्ग;

³[(कक) वे व्यक्ति जो धारा 2 के खंड (कक) के उपखंड (छ) के अधीन आश्रित के रूप में विनिर्दिष्ट किए जाएं;]

(ख) रीति, जिसमें दिन के भागों को उस दिन के लिए समनुज्ञेय दैनिक भत्ते का अवधारण/करने के प्रयोजन से गिनती में लिया जाएगा;

(ग) जहां किसी सदस्य के किसी पूरी यात्रा या उसके या उसके किसी भाग के लिए निःशुल्क आने-जाने की व्यवस्था की गई है, वहां देय यात्रा भत्ता और ⁴[जहां किसी सदस्य के लिए सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार के खर्च पर निःशुल्क भोजन या निवास की व्यवस्था की गई है, वहां दैनिक भत्ते में कमी]

¹1958 के अधिनियम 55 द्वारा प्रतिस्थापित 30.12.1958 से लागू।

²तदेव।

³2004 के अधिनियम 9 द्वारा अंतःस्थापित 9.1.2004 से लागू।

⁴1958 के अधिनियम 55 द्वारा अंतःस्थापित 30.12.1958 से लागू।

⁵ [(गग) वह दर, जिस पर धारा 4 की उप धारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (दो) के अधीन सड़क मील भत्ता दिया जाएगा।]

⁶ [(गगग) वह मार्गस्थ वास-सुविधा और अवधि जिसके लिए धारा 5 क के अधीन ऐसी वास सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी]

(घ) जहां वह स्थान जिससे कोई सदस्य अपनी यात्रा प्रारंभ करता है या जहां वह वापस लौट आता है, ऐसा स्थान नहीं है, जहां वह प्रायः निवास करता हो, वहां देय यात्रा-भत्ता ;

⁷ [(घघ) जहां कोई नियमित स्टीमर सेवा न हो वहां किसी जहाज द्वारा की गई यात्रा के संबंध में देय यात्रा भत्ता ;

(घघघ) किसी सदस्य द्वारा सदस्य के नाते अपने कर्तव्य से संबद्ध भारत से बाहर के दौरे में की गई यात्राओं के लिए देय यात्रा और दैनिक भत्ते];

(ङ) प्रपत्र, जिसमें प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, तो सदस्य द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी भत्ते का दावा करने के लिए दिए जाएंगे;

⁸ [(ङ-ङ) प्रपत्र, जिसमें प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, तो किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी पेंशन के दावे के प्रयोजन के लिए दिए जाएंगे;]

⁹ [(च) धारा 8 में उल्लिखित निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता तथा चिकित्सीय और अन्य सुविधाएं तथा ऐसे भत्तों और सुविधाओं के बदले में नकद संदत्त की जाने वाली रकम;

(चच) वह रकम जिसका वाहन क्रय करने के लिए प्रतिसंदेय अग्रिम के रूप में संदाय किया जा सकेगा, उस पर ब्याज की दर तथा ऐसी रकम और उस ब्याज की वसूली का ढंग;]

¹⁰ [(चचच) 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी वर्ग से संबंधित अनुपयोजित निःशुल्क टेलीफोन काल किसी पश्चात्पूर्वी वर्ग के लिए अग्रेनीत होने के संबंध में उपबंध करना] ; और

(छ) साधारणतया इस अधिनियम के अधीन दैनिक तथा यात्रा भत्तों और पेंशन के संदाय के विनियमन के लिए।

(4) उप-धारा (3) के अधीन बनाए गए कोई नियम तब तक प्रभावशील न होंगे, जब तक कि राज्य सभा के सभापति

और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन और पु-ट न कर दिए गए हों और राजकीय गजट में प्रकाशित न कर दिए गए हों और नियमों का ऐसा प्रकाशन निश्चायक प्रमाण होगा कि वे विधिवत् बनाए गए हैं ।

परिशिष्ट 4

लोक सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता)

नियम, 1985

लोक सभा के अध्यक्ष भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम, लोक सभा सदस्य (दल- परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 है।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "समाचार " से लोक सभा समाचार अभिप्रेत है;

(ख) "समिति " से लोक सभा की विशेष-ाधिकार समिति अभिप्रेत है;

(ग) "प्ररूप " से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) इन नियमों के संबंध में "प्रारंभ की तारीख " से वह तारीख अभिप्रेत है, जिस तारीख को ये नियम दसवीं अनुसूची, के पैरा 8 के उप-पैरा (2) के अधीन प्रभावी होंगे;

(ङ) "सदन " से लोक सभा अभिप्रेत है;

(च) किसी विधानमंडलीय पार्टी के संबंध में "नेता " से उस दल का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जिसे उस दल ने अपना नेता चुना है और इसके अंतर्गत उस दल का कोई ऐसा अन्य सदस्य भी है जो उसकी अनुपस्थिति में नियमों के प्रयोजनार्थ उस दल के नेता के रूप में कार्य करने, उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उस दल द्वारा प्राधिकृत किया गया है;

(छ) "सदस्य " से लोक सभा का सदस्य अभिप्रेत है;

(ज) "दसवीं अनुसूची " से भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची अभिप्रेत है;

(झ) "महासचिव " से लोक सभा का महासचिव अभिप्रेत है, और उसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो महासचिव के कर्तव्यों का तत्समय निर्वहन कर रहा है।

⁵1982 के अधिनियम 61 द्वारा अंतःस्थापित 6.11.1982 से लागू ।

⁶2004 के अधिनियम 9 द्वारा अंतःस्थापित 9.1.2004 से लागू ।

⁷1958 के अधिनियम 55 द्वारा प्रतिस्थापित 30.12.1958 से लागू।

⁸1976 के अधिनियम 105 द्वारा अंतःस्थापित 9.9.1976 से लागू ।

⁹1975 के अधिनियम 48 द्वारा प्रतिस्थापित 16.8.1975 से लागू ।

¹⁰2004 के अधिनियम 9 द्वारा अंतःस्थापित 9.1.2004 से लागू ।

3. विधान दल के नेता द्वारा जानकारी का दिया जाना.—

(1) प्रत्येक विधानमंडल पार्टी का नेता (ऐसे विधान-दल से भिन्न जिसमें केवल एक सदस्य हो) सभा की पहली बैठक की तारीख से तीस दिन के भीतर या जहां ऐसे विधान-दल का गठन ऐसी तारीख के बाद किया गया है, वहां उसके गठन की तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा प्रत्येक स्थिति में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :—

(क) एक विवरण (लिखित रूप में) जिसमें ऐसे विधान दल के सदस्यों के नाम और उसके साथ ऐसे सदस्यों से संबंधित अन्य विवरण होंगे जैसे कि प्ररूप 1 में हैं और ऐसे दल के उन सदस्यों के नाम और पदनाम होंगे, जिन्हें उस दल ने इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष से पत्र व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया है;

(ख) संबंधित राजनीतिक दल के नियमों और विनियमों की एक प्रति (चाहे उन्हें इस नाम से या संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो); और

(ग) जहां ऐसे विधानमंडलीय पार्टी के कोई पृथक नियम और विनियम हैं (चाहे उन्हें इस नाम से अथवा संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो) वहां ऐसे नियमों और विनियमों की एक प्रति ।

(2) जहां किसी विधानमंडलीय पार्टी में केवल एक सदस्य है वहां ऐसा सदस्य सदन की पहली बैठक की तारीख से तीस दिन के भीतर या जहां वह ऐसी तारीख के बाद सदन का सदस्य बना है वहां सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा प्रत्येक स्थिति में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को उपनियम (1) के खंड (ख) में उल्लिखित नियमों और विनियमों की एक प्रति भेजेगा/ भेजेगी।

(3) ऐसे किसी विधान दल की संख्या में, जिसमें केवल एक सदस्य है, वृद्धि होने पर, उपनियम (1) के उपबंध ऐसे विधान दल के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, मानो वह विधान दल उस तारीख को बनाया गया है, जिसको उसकी संख्या में वृद्धि हुई है।

(4) जब कभी किसी विधान-दल के नेता द्वारा उपनियम (1) के अंतर्गत या किसी सदस्य द्वारा उपनियम (2) के अंतर्गत दी गई सूचना में कोई परिवर्तन होता है तो संबंधित सदस्य उसके पश्चात् 30 दिन के भीतर अथवा ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को ऐसे परिवर्तन की लिखित सूचना देगा ।

(5) इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख को विद्यमान सदन की दशा में उपनियम (1) और उपनियम (2) में सदन की पहली बैठक की तारीख के प्रति निर्देश का यह अर्थ

लगाया जाएगा कि वह इन नियमों के आरंभ की तारीख के प्रति निर्देश है ।

(6) जहां किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य, ऐसे राजनीतिक दल द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है, तो संबंधित विधान-दल का नेता या जहां ऐसा सदस्य ऐसे विधान-दल का, यथास्थिति, नेता या एकमात्र सदस्य है तो ऐसा सदस्य ऐसा मतदान करने या मतदान से विरत रहने की तारीख से पंद्रह दिन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, और किसी भी स्थिति में ऐसे मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के तीस दिन के भीतर, प्ररूप 2 के अनुसार, अध्यक्ष को यह संसूचित करेगा कि ऐसा मतदान करने या मतदान से विरत रहने के लिए ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने माफ किया है या नहीं।

स्प-टीकरण—किसी सदस्य का मतदान से विरत रहना तभी माना जाएगा जब ऐसा सदस्य मतदान करने के लिए अधिकृत किए जाने पर स्वेच्छा से मतदान से विरत रहेगा ।

4. सदस्यों द्वारा सूचना आदि का दिया जाना.—(1)

ऐसा प्रत्येक सदस्य जिसने इन नियमों के आरंभ होने की तारीख से पूर्व सदन में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, ऐसी तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा ऐसी आगे की अवधि के भीतर जिसकी अनुमति अध्यक्ष पर्याप्त कारण से दे, प्ररूप 3 में विशिष्टियों का एक विवरण और घो-णा महासचिव को भेजेगा।

(2) प्रत्येक सदस्य द्वारा जो इन नियमों के आरंभ के पश्चात् सदन में अपना स्थान ग्रहण करता है, संविधान के अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, महासचिव के पास, यथास्थिति, अपना निर्वाचन प्रमाणपत्र या उसे सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना की प्रमाणित प्रति जमा करायी जाएगी और प्ररूप 3 में विशिष्टियों का एक विवरण और घो-णा महासचिव को दिया जाएगा ।

स्प-टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "निर्वाचन प्रमाणपत्र" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया निर्वाचन प्रमाणपत्र है।

(3) इस नियम के अधीन सदस्य जो जानकारी देंगे उसका संक्षेप समाचार में प्रकाशित किया जाएगा और यदि अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में उसमें कोई विसंगति बताई जाती है तो समाचार में आवश्यक शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जाएगा।

5. सदस्यों के बारे में जानकारी का रजिस्टर.—(1) महासचिव द्वारा प्ररूप 4 में एक रजिस्टर रखा जाएगा जो सदस्यों के संबंध में नियम 3 और नियम 4 के अधीन जानकारी पर आधारित होगा।

(2) प्रत्येक सदस्य के संबंध में जानकारी रजिस्टर में पृथक पृष्ठ पर अभिलिखित की जाएगी।

6. निर्देश का अर्जी द्वारा किया जाना.—(1) कोई सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, या नहीं इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के संबंध में इस नियम के उपबंधों के अनुसार दी गई अर्जी द्वारा ही किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(2) किसी सदस्य के संबंध में कोई अर्जी किसी अन्य सदस्य द्वारा अध्यक्ष को लिखित रूप में दी जा सकेगी:

परंतु अध्यक्ष के संबंध में कोई अर्जी महासचिव को संबोधित की जाएगी:

(3) महासचिव द्वारा,—

(क) उप-नियम (2) के परंतुक के अधीन दी गई अर्जी की प्राप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र, उसके बारे में सदन को एक रिपोर्ट दी जाएगी; और

(ख) दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (1) के परंतुक के अनुसरण में सदन द्वारा किसी सदस्य के निर्वाचित किए जाने के पश्चात् अर्जी को यथाशीघ्र उस सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) किसी सदस्य के संबंध में कोई अर्जी देने से पूर्व अर्जीदार अपना यह समाधान करेगा कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं।

(5) प्रत्येक अर्जी:—

(क) अर्जी में उन तात्त्विक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा, जिन पर अर्जीदार निर्भर करता है; और

(ख) अर्जी के साथ ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की, यदि कोई हो, प्रतियां संलग्न होंगी, जिस पर अर्जीदार निर्भर करता है और जहां अर्जीदार किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गई किसी जानकारी पर निर्भर करता है, वहां उन व्यक्तियों के नाम और पते सहित विवरण और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गई ऐसी जानकारी का सारांश संलग्न होगा।

(6) प्रत्येक अर्जी पर अर्जीदार के हस्ताक्षर होंगे और उसे, अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित रीति से सत्यापित किया जाएगा।

(7) अर्जी के प्रत्येक उपाबंध पर भी अर्जीदार के हस्ताक्षर होंगे और उसे अर्जी के समान रीति से ही सत्यापित किया जाएगा।

7. प्रक्रिया.—(1) नियम 6 के अधीन अर्जी प्राप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या अर्जी उक्त नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है।

(2) यदि अर्जी नियम 6 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है तो अध्यक्ष द्वारा अर्जी को रद्द किया जाएगा और अर्जीदार को तदनुसार संसूचित किया जाएगा।

(3) यदि अर्जी नियम 6 की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है तो अध्यक्ष द्वारा अर्जी और उसके उपाबंधों की प्रतियां—

(क) उस सदस्य को भिजवाई जाएंगी, जिसके संबंध में अर्जी दी गई है; और

(ख) जहां ऐसा सदस्य किसी विधानमंडलीय पार्टी का है और ऐसी अर्जी उस दल के नेता ने नहीं दी है वहां ऐसे नेता को भी भिजवाई जाएगी और ऐसे सदस्य या नेता द्वारा, ऐसी प्रतियों की प्राप्ति से सात दिन के भीतर, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, उस पर अपनी लिखित टिप्पणियां अध्यक्ष को भिजवाई जाएंगी।

(4) अर्जी के संबंध में अनुज्ञात अवधि (चाहे मूलतः या उक्त उप-नियम के अधीन विस्तारित) के भीतर उप-नियम (3) के अधीन प्राप्त टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष या तो प्रश्न का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा/होगी या यदि अध्यक्ष का उस मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो अध्यक्ष अर्जी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उसे समिति को निर्दिष्ट करेगा/करेगी।

(5) अध्यक्ष उप-नियम (4) के अधीन समिति को अर्जी निर्दिष्ट करने के पश्चात् यथाशीघ्र अर्जीदार को तदनुसार संसूचित करेगा और ऐसे निर्देश के संबंध में सदन में घोषणा करेगा/करेगी या यदि सदन या सत्र उस समय नहीं चल रहा है तो उस निर्देश की सूचना समाचार में प्रकाशित कराएगा/कराएगी।

(6) जहां अध्यक्ष समिति को उप-नियम (4) के अधीन निर्देश करता/करती है, वहां अध्यक्ष समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र उस प्रश्न का अवधारण करेगा/करेगी।

(7) वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण अध्यक्ष उप-नियम (4) के अधीन किसी प्रश्न के अवधारणा के लिए करेगा/

करेगी और वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण समिति प्रारंभिक जांच के प्रयोजन के लिए करेगी, यथासंभव, वही प्रक्रिया होगी जिसका समिति किसी सदस्य द्वारा सदन के विशेषाधिकार का भंग किए जाने के किसी प्रश्न का अवधारण करने के लिए अनुसरण करती है और अध्यक्ष या समिति इस निष्कर्ष पर कि वह सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, तभी पहुंचेगी जबकि उस सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का और व्यक्तिगत रूप से और यदि वह चाहता/चाहती है तो उसकी इच्छानुसार परामर्शों की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

(8) उप-नियम (1) से (7) तक के उपबंध अध्यक्ष के संबंध में दी गई अर्जी के बारे में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी अन्य सदस्य के संबंध में दी गई अर्जी के बारे में लागू होते हैं तथा इस प्रयोजनार्थ, इन उप-नियमों में अध्यक्ष के प्रति निर्देश का अर्थ दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (1) के परन्तुक के अंतर्गत सदन द्वारा निर्वाचित सदस्य के प्रति निर्देश सहित लगाया जाएगा।

8. अर्जी पर विनिश्चय.—(1) अर्जी पर विचार पूरा होने के पश्चात् यथास्थिति, अध्यक्ष या दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (1) परन्तुक के अधीन निर्वाचित सदस्य लिखित आदेश द्वारा:—

(क) अर्जी को खारिज करेगा; या

(ख) यह घोषणा करेगा कि वह सदस्य जिसके संबंध में अर्जी दी गई है, दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, और उस आदेश की प्रतियां अर्जीदार को, उस सदस्य को, जिसके संबंध में अर्जी दी गई है और संबंधित विधानमंडलीय पार्टी के नेता को, यदि कोई हो, परिदत्त या अग्रेणित करवाएगा।

(2) ऐसा प्रत्येक विनिश्चय, जिसमें किसी सदस्य को दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त घोषित किया गया है सदन को, यदि वह सत्र में है, तुरंत रिपोर्ट किया जाएगा और यदि सदन सत्र में नहीं है तो सदन के पुनः समवेत होने के तुरंत पश्चात् रिपोर्ट किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक विनिश्चय समाचार में प्रकाशित किया जाएगा और राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा तथा महासचिव उस विनिश्चय की प्रतियां भारत के निर्वाचन आयोग को और केन्द्रीय सरकार को अग्रेणित करेगा/करेगी।

9. इन नियमों के विस्तृत कार्यकरण के संबंध में निदेश.— अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर ऐसे निदेश जारी किए जा सकेंगे जो, अध्यक्ष इन नियमों के विस्तृत कार्यकरण के बारे में आवश्यक समझे।

प्ररूप 1

[देखिए नियम (3)(क)]

विधान-दल का नाम:			तत्स्थानी राजनीतिक दल का नाम		
क्रम सं.	सदस्य का नाम (स्प-ट अक्षरों में)	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	राज्य का नाम जहां से निर्वाचित हुए	निर्वाचन क्षेत्र का नाम जहां से निर्वाचित हुए
1	2	3	4	5	6

तारीख

विधानमंडलीय पार्टी के नेता के हस्ताक्षर

प्ररूप 2

[देखिए नियम (3)(6)]

सेवा में,
अध्यक्ष,
लोक सभा।

महोदया/महोदय,

सदन की..... (तारीख) को हुई बैठक में
..... वि-य पर हुए मतदान में

श्रीमती/कुमारी/श्री,
*मैंने/मैंसदस्य का नाम, संसद सदस्य ने
(विभाजन संख्या) जो संसद सदस्य (विभाजन
संख्या),(राजनीतिक
दल का नाम) के(राजनीतिक दल का नाम)
सदस्य तथा जो(विधानमंडलीय का सदस्य
और(विधानमंडलीय पार्टी का नाम) के
सदस्य हैं,..... पार्टी का नाम) का नेता/एकमात्र सदस्य,

.....(व्यक्ति/प्राधिकारी/दल द्वारा दिए गए निदेशों
के विरुद्ध उक्त व्यक्ति/प्राधिकारी/दल की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त
किए बिना मतदान किया है/मतदान करने से विरत रहा है/रहा
हूँ।

2.(तारीख) को पूर्वोक्त मामले पर
.....*(व्यक्ति/प्राधिकारी/दल) द्वारा विचार किया
गया और उक्त मतदान करने/मतदान करने से विरत* रहने को,
उसके *द्वारा माफ* किया गया/माफ नहीं किया गया।

तारीख

भवदीय,
(हस्ताक्षर)

प्ररूप 3

(देखिए नियम 4)

1. सदस्य का नाम (स्प-ट अक्षरों में):

2. पिता/पति का नाम:

3. स्थायी पता:

4. दिल्ली का पता:

5. निर्वाचन/नामनिर्देशन की तारीख:

6. जिस दल से संबद्ध है/हैं—

(1) निर्वाचन/नामनिर्देशन की तारीख को:

(2) *28 फरवरी, 1985 को:

(3) इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने की तारीख:

घो-णा

मैं;यह घो-णा करता/करती हूँ
कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है। ऊपर दी गई
जानकारी में कोई परिवर्तन होने पर मैं अध्यक्ष महोदय को
तत्काल सूचित करने का वचन देता/देती हूँ।

तारीख

सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

* अनुपयुक्त शब्दों/अंशों को काट दें।

* (यहां पर, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति, प्राधिकारी, दल का नाम लिखें जिसने
निदेश जारी किया है)।

* 1 मार्च, 1985 अर्थात् संविधान (52वां संशोधन) अधिनियम, 1985 के
प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व निर्वाचित या नाम-निर्देशित सदस्यों द्वारा ही
भरा जाएगा।

प्ररूप 4

[देखिए नियम 5(1)]

सदस्य का नाम (स्प-ट अक्षरों में)	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	दिल्ली का पता	राज्य जिससे निर्वाचित	निर्वाचन/नाम- निर्देशन की तारीख	उस राजनीतिक दल का नाम जिससे वह संबद्ध है	उस विधान-मंडलीय पार्टी का नाम जिससे वह संबद्ध है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

पी. श्रीधरण, महासचिव

LOK SABHA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th March, 2014

No. 29/2/CI/2014.—The following paragraphs published in the Lok Sabha Bulletin-Part II dated 5th March, 2014, are hereby published for general information :—

“No. 6211

**MAKING RULES OF PROCEDURE AND
CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA AS
GENDER NEUTRAL**

The Gender Neutral Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha as approved by Lok Sabha are hereby published in pursuance of sub-rule (3) of rule 331 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fourteenth Edition). These Rules shall be deemed to have come into force on the 13th day of February, 2014.

CHAPTER I**SHORT TITLE AND DEFINITIONS**

1. Short title.—These rules may be called “the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha”.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

“Bulletin” means the Bulletin of the House containing (a) a brief record of the proceedings of the House at each of its sittings; (b) information on any matter relating to or connected with the business of the House or other matter which in the opinion of the Speaker may be included therein; and (c) information regarding Parliamentary Committees;

“Constitution” means the Constitution of India;

“Council” means the Council of States (Rajya Sabha);

“Finance Minister” includes any Minister;

“Gazette” means the Gazette of India;

“House” means the House of the People (Lok Sabha);

“Houses” means the Council of States (Rajya Sabha) and the House of the People (Lok Sabha);

“Leader of the House” means the Prime Minister, if Prime Minister is a member of the House, or a Minister who is a member of the House and is nominated by the Prime Minister to function as the Leader of the House;

“Lobby” means the covered corridor immediately adjoining the Chamber and coterminous with it;

“Lok Sabha Secretariat/Sekretariat” means and includes the Lok Sabha Secretariat at Delhi and any Camp Office set up outside Delhi for the time being for, or under the authority of, the Speaker;

“member” means a member of the House of the People (Lok Sabha);

“member in charge of the Bill” means the member who has introduced the Bill and any Minister in the case of a Government Bill;

“Minister” means a member of the Council of Ministers ¹[and includes a member of the Cabinet], a Minister of State, a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary;

²[*Explanation.*:—A Parliamentary Secretary who is not a member of the House, is not entitled to attend its sitting.]

“Parliamentary Committee” means a Committee which is appointed or elected by the House or nominated by the Speaker and which works under the direction of the Speaker and presents its report to the House or to the Speaker and the Sekretariat for which is provided by the Lok Sabha Sekretariat;

“precincts of the House” means and includes the Chamber, the Lobbies, the Galleries and such other places as the Speaker may from time to time specify;

“private member” means a member other than a Minister;

“Secretary-General” means the Secretary-General to the House of the People (Lok Sabha) and includes any person for the time being performing the duties of the Secretary-General; and

“Table” means the Table of the House.

(2) Words and expressions used in the Constitution and also in these rules shall, unless the context otherwise requires, have the meanings assigned to them in the Constitution.

CHAPTER II**SUMMONS TO MEMBERS, SEATING, OATH
OR AFFIRMATION AND ROLL OF MEMBERS**

3. Summons.—The Secretary-General shall issue a summons to each member specifying the date and place for a session of the House:

Provided that when a session is called at short notice or emergently, summons may not be issued to each member separately but an announcement of the date and place of the session shall be published in the Gazette and made in the press, and members may be informed by telegram.

¹Ins. by L.S. Bn. (II) 9.5.1989, para 2930.

²Added *ibid*.

4. Seating.—The members shall sit in such order as the Speaker may determine.

5. Oath or affirmation.—A member who has not already made and subscribed an oath or affirmation, in pursuance of article 99 of the Constitution, may do so at the commencement of a sitting of the House, or at any other time of the sitting of the House, as the Speaker may direct, on any day after giving previous notice in writing to the Secretary-General.

6. Roll of Members.— There shall be a Roll of Members of the House which shall be signed in the presence of the Secretary-General by every member, before taking one's own seat.

CHAPTER III

ELECTION OF SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER AND NOMINATION OF PANEL OF CHAIRPERSONS

7. Election of Speaker.—(1) The election of a Speaker shall be held on such date as the President may fix, and the Secretary-General shall send to every member notice of this date.

(2) At any time before noon on the day preceding the date so fixed, any member may give notice in writing, addressed to the Secretary-General, of a motion that another member be chosen as the Speaker of the House, and the notice shall be seconded by a third member and shall be accompanied by a statement by the member whose name is proposed in the notice that the member proposed is willing to serve as Speaker, if elected:

Provided that a member shall not propose one's own name, or second a motion proposing the member's own name, or propose or second more than one motion.

¹[(3) A member in whose name a motion stands on the list of business, unless makes a statement conveying unwillingness to move the motion, move the motion when called upon to do so.]

Provided that such statement shall be confined to, conveying the unwillingness, or moving the motion for decision of the House under sub-rule (4).

(4) The motions which have been moved and duly seconded shall be put one by one in the order in which they have been moved, and decided, if necessary, by division. If any motion is carried, the person presiding shall, without putting later motions, declare that the member proposed in the motion which has been carried, has been chosen as the Speaker of the House.

8. Election of Deputy Speaker.—(1) The election of a Deputy Speaker shall be held on such date as the

Speaker may fix, and the Secretary-General shall send to every member notice of this date.

(2) At any time before noon on the day preceding the date so fixed, any member may give notice in writing, addressed to the Secretary-General, of a motion that another member be chosen as the Deputy Speaker of the House and the notice shall be seconded by a third member and shall be accompanied by a statement by the member whose name is proposed in the notice that the member proposed is willing to serve as Deputy Speaker, if elected:

Provided that a member shall not propose one's own name, or second a motion proposing the member's own name, or propose or second more than one motion.

²[(3) A member in whose name a motion stands on the list of business shall, unless makes a statement conveying unwillingness to move the motion, move the motion when called upon to do so. In either case the member shall confine to making of a statement conveying the intention to move or not to move the motion.]

(4) The motions which have been moved and duly seconded shall be put one by one in the order in which they have been moved, and decided, if necessary, by division. If any motion is carried, the person presiding shall, without putting later motions, declare that the member proposed in the motion which has been carried, has been chosen as the Deputy Speaker of the House.

9. Nomination of Panel of Chairpersons.—(1) At the commencement of the House or from time to time, as the case may be, the Speaker shall nominate from amongst the members a panel of not more than ten³ Chairpersons, anyone of whom may preside over the House in the absence of the Speaker and the Deputy Speaker when so requested by the Speaker or, in the absence of the Speaker, by the Deputy Speaker.

(2) A Chairperson nominated under sub-rule (1) shall hold office until a new panel of Chairpersons is nominated.

10. Powers of Deputy Speaker or other member presiding.—The Deputy Speaker or any other member competent to preside over a sitting of the House under the Constitution or these rules shall, when so presiding, have the same powers as the Speaker when so presiding and all references to the Speaker in these rules shall in these circumstances be deemed to be references to any such person so presiding.

CHAPTER IV

SITTINGS OF THE HOUSE

11. Duly constituted sitting.—A sitting of the House is duly constituted when it is presided over by

¹Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

²Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

³Sub. by L.S. Bn. (II) dated 4.8.1993, para 2298.

the Speaker or any other member competent to preside over a sitting of the House under the Constitution or these rules.

¹[**12. Commencement and conclusion of sitting.**—

Unless the Speaker otherwise directs, sitting of the House on any day shall ordinarily commence at 11.00 hours and conclude at 18.00 hours with a lunch break for one hour which may ordinarily be from 13.00 hours to 14.00 hours.]

13. Days of sittings.—The House shall sit on such days as the Speaker, having regard to the state of business of the House, may from time to time direct.

²[**14. *** ****]

15. Adjournment of House ³[**and procedure for reconvening.**].—(1) The Speaker shall determine the time when a sitting of the House shall be adjourned *sine die* or to a particular day, or to an hour or part of the same day:

Provided that the Speaker, if thinks fit, may call a sitting of the House before the date or time to which it has been adjourned or at any time after the House has been adjourned *sine die*.

⁴[(2) In case the House, after being adjourned is reconvened under proviso to sub-rule (1), the Secretary-General shall communicate to each member the date, time, place and duration of the next part of the session.]

CHAPTER V

PRESIDENT'S ADDRESS AND MESSAGES TO THE HOUSE

16. Allotment of time for discussion of the Address.—The Speaker shall, in consultation with the Leader of the House, allot time for the discussion of the matters referred to in the President's Address to the Houses under article 87(1) of the Constitution.

17. Scope of Discussion.—On such day or days or part of any day, the House shall be at liberty to discuss the matters referred to in such Address on a Motion of Thanks moved by a member and seconded by another member.

18. Amendments.—Amendments may be moved to such Motion of Thanks in such form as may be considered appropriate by the Speaker.

19. Other business that may be taken up.—Notwithstanding that a day has been allotted for discussion on the President's Address,—

(a) a motion or motions for leave to introduce a Bill or Bills may be made and a Bill or Bills may be introduced on such day; and

(b) other business of a formal character may be transacted on such day before the House commences or continues the discussion on the Address.

(2) The discussion on the Address may be postponed in favour of a Government Bill or other Government business on a motion being made that the discussion on the Address be adjourned to a subsequent day to be appointed by the Speaker. The Speaker shall forthwith put the question, no amendment or debate being allowed.

(3) The discussion on the Address shall be interrupted in the course of a sitting by an adjournment motion under rule 61.

20. ¹[Right of reply].—(1) The Prime Minister or any other Minister shall, whether previously taken part in the discussion or not, have on behalf of the Government a general right of explaining the position of the Government at the end of the discussion and the Speaker may enquire how much time will be required for the speech so that the Speaker may fix the hour by which the discussion shall conclude.

²[(2) The mover or the seconder shall not have any right of reply after the Prime Minister or any other Minister has explained the position of the Government at the end of the discussion.]

21. Time limit for speeches.—The Speaker, if thinks fit, may prescribe a time-limit for speeches after taking the sense of the House.

22. President's Address under art. 86(1).—The Speaker may allot time for the discussion of the matters referred to in the President's Address under article 86(1) of the Constitution.

23. Messages from President.—The Speaker shall, on receiving a message from the President for the House under clause (2) of article 86 of the Constitution, read such message to the House and give necessary directions in regard to the procedure that shall be followed for the consideration of matters referred to in the message. In giving these directions, the Speaker shall be empowered to suspend or vary the rules to such extent as may be necessary.

24. President's Address on prorogation.—The President, on proroguing the House or Houses, may address the House or Houses, as the case may be.

¹Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

²Omitted *ibid*.

³Added *ibid*.

⁴Added by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

¹Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

²Added *ibid*.

CHAPTER VI

ARRANGEMENT OF BUSINESS
AND LIST OF BUSINESS

25. Arrangement of Government business.—On days allotted for the transaction of Government business, such business shall have precedence and the Secretary-General, shall arrange that business in such order as the Speaker may, after consultation with the Leader of the House, determine:

Provided that such order of business shall not be varied on the day that business is set down for disposal unless the Speaker is satisfied that there is sufficient ground for such variation.

26. Allotment of time for Private members' business.—The last two and a half hours of a sitting on Friday shall be allotted for the transaction of private members' business:

Provided that the Speaker may allot different Fridays for the disposal of different classes of such business and on Fridays so allotted for any particular class of business, business of that class shall have precedence:

Provided further that the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, allot any day other than a Friday for the transaction of private members' business:

Provided further that if there is no sitting of the House on a Friday, the Speaker may direct that two and a half hours on any other day in the week may be allotted for private members' business.

27. Precedence of Private members' Bills.—(1) On a day allotted for the disposal of private members' Bills, such Bills shall have relative precedence in the following order, namely:—

(a) Bills in respect of which the motion is that leave be granted to introduce the Bill;

(b) Bills returned by the President with a message under article 111 of the Constitution;

(c) Bills which have been passed by the House and returned by the Council with amendments;

(d) Bills which have been passed by the Council and transmitted to the House;

(e) Bills in respect of which a motion has been carried that the Bill be taken into consideration;

(f) Bills in respect of which the report of a Joint or Select Committee has been presented;

(g) Bills which have been circulated for the purpose of eliciting opinion thereon;

(h) Bills introduced and in respect of which no further motion has been made or carried; and

(i) other Bills.

(2) The relative precedence of Bills falling under the same clause of sub-rule (1) shall be determined by ballot to be held in accordance with the orders made by the Speaker and on such day and in such manner as the Speaker may direct:

Provided that the motion in respect of Bills falling under clause (a) of sub-rule (1) shall be entered in the list of business in the order in which notices of such motions have been received in point of time:

Provided further that Bills falling under clause (h) of sub-rule (1) which are classified by the Committee on Private Members' Bills and Resolutions as category A shall have precedence over Bills classified as category B, and that the relative precedence of Bills falling under each of these categories shall be determined by ballot separately:

¹[Provided further that where the Committee on Private Members' Bills and Resolutions has classified the Bills falling under clause (h) of sub-rule (1) as category A and number thereof is twenty or more, ballot of category B Bills may not be held]:

Provided further that where the Committee has not classified the Bills falling under clause (h) of sub-rule (1) as category A and category B, the order in which such Bills shall be put down in the list of business shall be determined by ballot in accordance with such directions as the Speaker may give.

(3) The Speaker may, by special order to be announced in the House, make such variations in the relative precedences of Bills set out in sub-rule (1) as the Speaker may consider necessary or convenient.

28. Precedence of Private members' Resolutions.—

²[A ballot of names of members desiring to move a resolution shall be held in accordance with orders made by the Speaker, on such day as the Speaker may direct.]

29. Private members' business outstanding at end of day.—Private members' business set down for the day allotted for that class of business and not disposed of on that day shall not be set down for any subsequent day, unless it has gained priority at the ballot held with reference to that day:

Provided that notwithstanding anything contained in rules 27 and 28 any such business which is under discussion at the end of that day shall be set down for the next day allotted to business of that class, and shall have precedence over all other business set down for that day.

¹Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

²Sub. by L.S. Bn. (II), dated 9.5.1989, para 2930.

30. Resumption of adjourned debate on Private members' Bill or Resolution.—(1) When on a motion being carried the debate on a private member's Bill or resolution is adjourned to the next day allotted for private members' business in the same or next session, it shall not be set down for further discussion unless it has gained priority at the ballot.

(2) When the debate on a private member's Bill or resolution is adjourned *sine die* and if the member in charge of the Bill or as the case may be the mover of the resolution, wishes to proceed with such Bill or resolution on a subsequent day allotted for private members' business, may give notice for resumption of the adjourned debate and on receipt of such notice the relative precedence of such Bill or resolution shall be determined by ballot.

31. List of Business.—(1) A list of business for the day shall be prepared by the Secretary-General, and a copy thereof shall be made available for the use of every member.

(2) Save as otherwise provided in these rules, no business not included in the list of business for the day shall be transacted at any sitting without the permission of the Speaker.

(3) Save as otherwise provided in these rules, no business requiring notice shall be set down for a day earlier than the day after that on which the period of the notice necessary for that class of business expires.

(4) Unless the Speaker otherwise directs, not more than three resolutions (in addition to any resolution which is outstanding under the proviso to rule 29) shall be set down in the list of business for any day allotted for the disposal of private members' resolutions.

[For rules relating to Business Advisory Committee and Committee on Private Members' Bills and Resolutions, see Chapter XXVI of these rules.]

CHAPTER VII

QUESTIONS

32. Question hour.—Unless the Speaker otherwise directs, the first hour of every sitting shall be available for the asking and answering of questions.

33. Period of notice.—Unless the Speaker otherwise directs, ¹[not less than fifteen clear days'] notice of a question shall be given.

34. Form of notice.—Notice of a question shall be given in writing to the Secretary-General and shall specify—

²[(a) the text of the question;]

³[(b) the official designation of the Minister to whom the question is addressed;

(c) the date on which answer to the question is desired; and]

⁴[(d) the order of preference, if any, for its being placed on the list of questions, where a member tables more than one notice of questions for the same day.]

Where a notice is signed by more than one member, it shall be deemed to have been given by the first signatory only.

35. Notice of admitted questions to Minister.—

Unless the Speaker otherwise directs, no question shall be placed on the list of questions for answer until five days have expired from the day when notice of such question was given by the Secretary-General to the Minister to whom it was addressed.

36. Starred question.—A member who desires an oral answer to one's question shall distinguish it by an asterisk. If the member does not distinguish it by an asterisk, the question shall be placed on the list of questions for written answer.

37. Limit of number of Starred questions.—(1)

Not more than one question distinguished by ⁵[an] asterisk by the same member and not more than twenty questions in all shall be placed on the list of questions for oral answer on any one day:

Provided that when a question is postponed or transferred from one list of questions for oral answer to another, more than one question may stand in the name of one member and the total number of questions may exceed by such postponed or transferred question.

⁶[(2) Unless the Speaker otherwise directs, where a member has given more than one notice of questions distinguished by an asterisk for same day, the member's question for the list of questions for oral answer shall be selected in the order indicated by the member and if no such order is indicated, any of these questions shall be placed on the list of questions for oral answer in the order in which notices are received in point of time.]

38. Rotational allotment of days for questions.—

The time available for answering questions shall be allotted on different days in rotation for the answering of questions relating to such Ministry or Ministries as the Speaker may, from time to time, provide, and on each such day, unless the Speaker with the consent of the Minister concerned otherwise directs, only questions relating to the Ministry or Ministries for which time has

¹Sub. by L.S. Bn. (II) dated 19.3.2010, para 1265.

²Ins. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

³Clauses (a) and (b) relettered as (b) and (c) and clause (c) so relettered sub. *ibid.*

⁴Added by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

⁵Ins. *ibid.*

⁶Sub. *ibid.*

been allotted on that day shall be placed on the list of questions for oral answer.

39. Unstarred questions.—(1) If a question is not distinguished by an asterisk or if a question placed on the list of questions for oral answer on any day is not called for answer within the time available for answering questions on that day, ⁷[* * *] a written answer to such question shall be deemed to have been laid on the Table at the end of the Question Hour or as soon as the questions for oral answer have been disposed of, as the case may be, by the Minister to whom the question is addressed.

⁸[***]

⁹[(2) If there is no Question Hour owing to the cancellation of a sitting or its adjournment without transacting any business, the answers to questions included in the lists of questions for oral as well as written answer shall be deemed to have been laid on the Table by the Ministers to whom such questions are addressed at the next sitting of the House after the Question Hour and form part of the proceedings of that day.]

(3) If the Question Hour on any day is dispensed with ¹⁰[* * *] for any ¹¹[* * *] reason, the answers to questions included in the lists of questions for oral as well as written answers for that day shall be deemed to have been laid on the Table by the Ministers to whom such questions are addressed and shall form part of the proceedings of the day:

Provided that if the House does not continue with its sitting after dispensing with ¹²[* * *] the Question Hour, the answers to questions included in the lists of questions for oral as well as written answer for that day shall be deemed to have been laid on the Table after the Question Hour at the next sitting of the House and shall form part of the proceedings of that day:

Provided further that if the Question Hour is interrupted after having taken up the list of questions for oral answer and the list is partly disposed of and the sitting continues, answers to remaining questions in the list of questions for oral answer and answers to questions in the list of questions for written answer shall be deemed to have been laid on the Table after 12 O'clock and form part of the proceedings of the day.

¹³[(4) If the last sitting of a session is cancelled, the questions in the lists of questions for oral as well as written answer for that day shall lapse.]

40. Question to private members.—A question may be addressed to a private member provided the

subject matter of the question relates to some Bill, resolution or other matter connected with the business of the House for which that member is responsible; and the procedure in regard to such questions shall, as far as may be, be the same as that followed in the case of questions addressed to a Minister with such variations as the Speaker may consider necessary or convenient.

41. Admissibility of questions.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a question may be asked for the purpose of obtaining information on a matter of public importance within the special cognizance of the Minister to whom it is addressed.

(2) The right to ask a question is governed by the following conditions, namely:—

¹⁴[(i) it shall be clearly and precisely expressed and shall not be too general incapable of any specific answer or in the nature of a leading question;]

¹⁵[(ii) it shall not bring in any name or statement not strictly necessary to make the question intelligible;

(iii) if it contains a statement the member shall make oneself responsible for the accuracy of the statement;

(iv) it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations, epithets or defamatory statements;

(v) it shall not ask for an expression of opinion or the solution of an abstract legal question or of a hypothetical proposition;

(vi) it shall not ask as to the character or conduct of any person except in that person's official or public capacity;

(vii) it shall not ordinarily exceed 150 words;

(viii) it shall not relate to a matter which is not primarily the concern of the Government of India;

(ix) it shall not ask about proceedings in the Committee which have not been placed before the House by a report from the Committee.

(x)) it shall not reflect on the character or conduct of any person whose conduct can only be challenged on a substantive motion;

(xi) it shall not make or imply a charge of a personal character;

(xii) it shall not raise questions of policy too large to be dealt with within the limits of an answer to a question;

⁷Omitted by L.S. Bn. (II) dated 19.3.2010, para 1265.

⁹Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

^{8, 10 & 11}Omitted by L.S. Bn. (II) dated 19.3.2010, para 1265.

¹²Omitted by L.S. Bn. (II) dated 19.3.2010, para 1265.

¹³Added by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

¹⁴Ins. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

¹⁵Renumbered *ibid*.

(xiii) it shall not repeat in substance questions already answered or to which an answer has been refused;

(xiv) it shall not ask for information on trivial matters;

(xv) it shall not ordinarily ask for information on matters of past history;

(xvi) it shall not ask for information set forth in accessible documents or in ordinary works of reference;

(xvii) it shall not raise matters under the control of bodies or persons not primarily responsible to the Government of India;

(xviii) it shall not ask for information on matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India;

(xix) it shall not relate to a matter with which a Minister is not officially ¹⁶{concerned};

(xx) it shall not refer discourteously to a friendly foreign country;

¹⁷{(xxi) it shall not seek information about matters which are in their nature secret, such as composition of Cabinet Committees, Cabinet discussions, or advice given to the President in relation to any matter in respect of which there is a constitutional, statutory or conventional obligation not to disclose information;}

(xxii) it shall not ordinarily ask for information on matters which are under consideration of a Parliamentary Committee; and

(xxiii) it shall not ordinarily ask about matters pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into, or investigate, any matter but may refer to matters concerned with procedure or subject or stage of enquiry, if it is not likely to prejudice the consideration of the matter by the tribunal or commission or court of enquiry.]

42. Questions on matters of correspondence between Government of India and State Governments.—In matters which are or have been the subject of correspondence between the Government of India and the Government of a State, no question shall be asked except as to matters of fact, and the answer shall be confined to a statement of fact.

43. Speaker to decide admissibility.—(1) The Speaker shall decide whether a question, or a part thereof, is or is not admissible under these rules and may disallow any question, or a part thereof, when in the opinion of

the Speaker, it is an abuse of the right of questioning or is calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules.

(2) Subject to the provisions of rule 38, the Speaker may direct that a question be placed on the list of questions for answer on a date later than that specified by a member in the notice if the Speaker is of the opinion that a longer period is necessary to decide whether the question is or is not admissible.

44. Speaker to decide if a question is to be treated as starred or unstarred.—If in the opinion of the Speaker any question put down for oral answer is of such a nature that a written reply would be more appropriate, the Speaker may direct that such question be placed on the list of questions for written answer:

Provided that the Speaker, if thinks fit, may call upon the member who has given notice of a question for oral answer to state in brief the reasons for desiring an oral answer and, after considering the same, may direct that the question be included in the list of questions for written answer.

45. ¹⁸[Limit of number of unstarred question.—(1) Questions which have been admitted and not included in the list of questions for oral answer shall be included in the list of questions for written answer, in accordance with the orders of the Speaker.

(2) In the list of questions for written answer on any one day, not more than four questions by the same member if she or he has one question in the list of questions for oral answer, and not more than five questions if that member has none in the list of questions for oral answer, and not more than 230 questions in all, shall be included:

Provided that these limits may be exceeded by the number of questions transferred or postponed from one list of questions for written answer to another:

Provided further that the overall limit of 230 questions in the list of questions for written answer on any one day may exceed by the number of questions pertaining to a State or States under President's Rule subject to the maximum limit of 25.]

46. Order in which starred questions to be called.—Questions for oral answers shall be called ¹⁹[* * *] in the order in which they stand on the list ²⁰[* * *]:

Provided that a question not reached for oral answer may be answered after the end of the Question Hour with the permission of the Speaker if the Minister

¹⁶Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

¹⁷Sub. *ibid.*

¹⁸Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

^{19&20}Omitted by L.S. Bn. (II) dated 19.03.2010, Para 1265.

represents to the Speaker that the question is one of special public interest to which the Minister desired to give a reply.

47. Withdrawal or postponement of questions.—

A member may, by notice given at any time before the sitting for which such member's question has been placed on the list, withdraw the question, or postpone it to a later day to be specified in the notice and on such later day the question shall, subject to the provisions of rule 38, be placed on the list after all questions which have not been so postponed:

Provided that a postponed question shall not be placed on the list until two clear days have expired from the day when the notice of postponement has been received by the Secretary-General.

48. Mode of asking questions.—(1) When the time for asking questions arrives, the Speaker shall call successively each member in whose name a question appears on the list of question.

(2) The member so called shall rise in one's own place and, unless the member expresses unwillingness to ask the question standing in the name of such member, ask the question by reference to its number on the list of questions.

(3) If on a question being called it is not asked ²¹[or] the member in whose name it stands is absent, the Speaker may ²²[* * *] direct that the answer to it be given.

49. ²³[* * *]

50. Supplementary questions.—²⁴(1) The member in whose name a question is listed for oral answer or any other member, when called by the Speaker, may ask a supplementary question for the purpose of further elucidating any matter of fact regarding which an answer has been given.

(2) A supplementary question, shall be held out of order by the Speaker if, in the opinion of the Speaker : —

(i) it does not arise from the main question or its answer;

(ii) instead of seeking information, it gives information;

(iii) it involves more than one separate issues;

(iv) it seeks confirmation or denial of an opinion; and

(v) it infringes any of the rules regarding questions.

(3) No discussion shall be permitted during the time for questions under rule 32 in respect of any question or of any answer given to a question].

51. Answers not to refer to procedings in Council.— An answer to question in the House shall not refer to the answer to a question or proceedings in the Council during a current session.

52. Lapse of pending questions referred to members.—Where a reference is made to a member in connection with the notice of a question and no reply is received or a reply received from such member is too late for the consideration of the Speaker and the placing of the question, if admitted, on the list of questions for an appropriate date, such notice shall be deemed to have lapsed.

53. Prohibition of advance publicity of answers.— Answers to questions which Ministers propose to give in the House shall not be released for publication until the answers have actually been given on the floor of the House or laid on the Table.

54. Short notice questions.—(1) A question relating to a matter of public importance may be asked with notice shorter than ten clear days and the Speaker, if, is of the opinion that the question is of an urgent character, may direct that an enquiry may be made from the Minister concerned if such Minister is in a position to reply and, if so, on what date.

(2) If the Minister concerned agrees to reply, such question shall be answered on a day to be indicated by the Minister and shall be called immediately after the questions which have appeared on the list of questions for oral answer have been disposed of.

(3) If the Minister is unable to answer the question at short notice and the Speaker is of the opinion that the question is of sufficient public importance to be orally answered in the House, the Speaker may direct that the question be placed as the first question on the list of questions for the day on which it would be due for answer under rule 33:

Provided that not more than one such question shall be accorded first priority on the list of questions for any one day.

(3A) Where a notice of a short notice question is signed by more than one member, it shall be deemed to have been given by the first signatory only.

(4) Where two or more members give short notice questions on the same subject and one of the questions is accepted for answer at short notice, names of not more than four members, other than the one whose notice has been admitted, as determined by ballot, shall be shown against the admitted question:

Provided that the Speaker may direct that all the notices be consolidated into a single notice, if in the

²¹Sub. by L.S. Bn. (II) dated 19.3.2010, para 1265.

^{22&23}Omitted by L.S. Bn. (II) dated 19.3.2010, para 1265.

²⁴Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

opinion of the Speaker, it is desirable to have a single self-contained question covering all the important points raised by members, and the Minister shall then give reply to the consolidated question:

Provided further that in the case of consolidated question, names of not more than four members, other than the one whose notice has been admitted, as determined by ballot, shall be shown against the question.

(5) Where a member desires an oral answer to a question at a shorter notice, such Member shall briefly state the reasons for asking the question with short notice. Where no reasons have been assigned in the notice of the question, the question shall be returned to the member.

(6) The member who has given notice of the question shall be in one's own seat to ask the question by reference to its number on the list of questions when called by the Speaker and the Minister concerned shall give a reply immediately:

Provided that when a question is shown in the names of more than one member the Speaker shall call the name of the first member or, in the absence of that member, any other name.

(7) In other respects, the procedure for short notice questions shall be the same as for ordinary questions for oral answer with such modifications as the Speaker may consider necessary or convenient.

CHAPTER VIII

HALF-AN-HOUR DISCUSSIONS

55. Discussion on matter arising out of answer to question.—(1) The Speaker may allot half an hour on three sittings in a week, for raising discussion on a matter of sufficient public importance which has been the subject of a recent question, oral or written, and the answer to which needs elucidation on a matter of fact.

(2) A member wishing to raise a matter shall give notice in writing to the Secretary-General three days in advance of the day on which the matter is desired to be raised, and shall shortly specify the point or points such member wishes to raise:

Provided that the notice shall be accompanied by an explanatory note stating the reasons for raising discussion on the matter in question:

Provided further that if a notice is signed by more than one member it shall be deemed to have been given by the first signatory only:

Provided further that the Speaker may with the consent of the Minister concerned waive the requirement concerning the period of notice.

(3) The Speaker shall decide whether the matter is of sufficient public importance to be put down for discussion, and may not admit a notice which, in the opinion of the Speaker seeks to revise the policy of Government.

(4) If more than two notices have been received and admitted by the Speaker, the Secretary-General shall hold a ballot with a view to draw two notices and the notices shall be put down in the order in which they were received in point of time:

Provided that if any matter put down for discussion on a particular day is not disposed of on that day it shall not be set down for any other day, unless the member so desires, in which case it shall be included in the ballot for the next available day.

(5) There shall be no formal motion before the House nor voting. The member who has given notice may make a short statement and the ¹[members who have previously intimated to the Speaker may ask a question for the purpose of further elucidating any matter of fact. Thereafter, the Minister shall reply shortly]:

Provided that not more than four members who have previously intimated to the Secretary-General may be permitted to ask a question each for the purpose of further elucidating any matter of fact.

Explanation.—A member wishing to ask a question shall make such request in writing before the commencement of the sitting at which the discussion is to take place. If such requests are received from more than four members, a ballot shall be held to determine the names of first four members who may be permitted to ask a question each.

CHAPTER IX

ADJOURNMENT MOTIONS

56. Speaker's consent.—Subject to the provisions of these rules, a motion for an adjournment of the business of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker.

57. Notice.—¹[Notice of an adjournment motion shall be given by 10.00 hours on the day on which the motion is proposed to be made to the Secretary-General and copies thereof shall be endorsed to:—

- (i) the Speaker;
- (ii) the Minister concerned;
- (iii) the Minister of Parliamentary Affairs:

Provided that notices, received after 10.00 hours shall be deemed to have been received at 10.00 hours on the next day on which the House sits:

¹Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

¹Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

Provided further that no member shall give more than one such notice for any one sitting.

Explanation.—(i) Where a notice is signed by more than one member, it shall be deemed to have been given by the first signatory only.

(ii) A ballot shall be held to determine the relative priority of all notices on the same subject for the sitting for which they are valid.]

58. Restrictions on right to move motion.—The right to move the adjournment of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance shall be subject to the following restrictions, namely:—

(i) not more than one such motion shall be made at the same sitting;

(ii) not more than one matter shall be discussed on the same motion;

(iii) the motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence ²[involving responsibility of the Government of India];

(iv) the motion shall not raise a question of privilege;

(v) the motion shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session;

(vi) the motion shall not anticipate a matter, which has been previously appointed for consideration. In determining whether a discussion is out of order on the ground of anticipation, regard shall be had by the Speaker to the probability of the matter anticipated being brought before the House within a reasonable time;

(vii) the motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India; and

(viii) the motion shall not raise any question which under the Constitution or these rules can only be raised on a distinct motion by a notice given in writing to the Secretary-General.

59. Matters before tribunals, commissions, etc.—

No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into, or investigate, any matter shall ordinarily be permitted to be moved:

Provided that the Speaker may while exercising discretion allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory tribunal, statutory authority, commission or court of enquiry.

60. Leave to move adjournment motion.—(1) The Speaker, if gives consent under rule 56 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall call the member concerned who shall rise in one's own place and ask for leave to move the adjournment of the House:

Provided that where the Speaker has refused consent under rule 56 or is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, the Speaker may, if thinks it necessary, read the notice of motion and state the reasons for refusing consent or holding the motion as being not in order:

Provided further that where the Speaker is not in possession of full facts about the matter mentioned therein, the Speaker may before giving or refusing consent read the notice of the motion and hear from the Minister, or members concerned, a brief statement on facts and then give decision on the admissibility of the motion.

(2) If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than fifty members rise accordingly, the Speaker shall intimate that leave is granted. If less than fifty members rise, the Speaker shall inform that the member has not the leave of the House.

61. Time for taking up motion.—The motion 'that the House do now adjourn' shall be taken up at 16.00 hours or at an earlier hour if the Speaker, after considering the state of business in the House, so directs.

62. Closure of debate.—The Speaker may, on being satisfied that there has been adequate debate, put the question at 18.30 hours or at such other hour not being less than two hours and thirty minutes from the time of commencement of the debate.

63. Time limit for speeches.—The Speaker shall prescribe a time limit for speeches.

CHAPTER X

LEGISLATION

I. Bills originating in the House

INTRODUCTION AND PUBLICATION OF BILLS

64. Publication of Bill in Gazette before introduction.—The Speaker, on request being made, may order the publication of any Bill (together with the Statement of Objects and Reasons, the memorandum regarding delegation of legislative power and the financial memorandum accompanying it) in the Gazette, although no motion has been made for leave to introduce the Bill. In that case, it shall not be necessary to move for leave to introduce the Bill, and, if the Bill is afterwards introduced, it shall not be necessary to publish it again.

²Added by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

65. Notice for leave to introduce private members'

Bills.—(1) Any member, other than a Minister, desiring to move for leave to introduce a Bill, shall give notice of one's intention, and shall, together with the notice, submit a copy of the Bill and an explanatory Statement of Objects and Reasons which shall not contain arguments:

Provided that the Speaker, if thinks fit, may revise the Statement of Objects and Reasons.

(2) If the Bill is a Bill which under the Constitution cannot be introduced without the previous sanction or recommendation of the President, the member shall annex to the notice such sanction or recommendation conveyed through a Minister, and the notice shall not be valid until this requirement is complied with.

(3) The period of notice of a motion for leave to introduce a Bill under this rule shall be one month unless the Speaker allows the motion to be made at shorter notice.

(4) The Speaker may disallow a notice of a Bill in case the Bill does not comply with the requirement of sub-rule (2) of this rule, or rule 69 or 70.

66. Bill dependent on another pending Bill.—A Bill, which is dependent wholly or partly upon another Bill pending before the House, may be introduced in the House in anticipation of the passing of the Bill on which it is dependent:

Provided that the second Bill shall be taken up for consideration and passing in the House only after the first Bill has been passed by the Houses and assented to by the President.

67. Identical Bills.—When a Bill is pending before the House, notice of an identical Bill, whether received before or after the introduction of the pending Bill, shall be removed from, or not entered in, the list of pending notices, as the case may be, unless the Speaker otherwise directs.

68. Communication of President's recommendation regarding Bill.—The order of the President granting or withholding the sanction or recommendation to the introduction or consideration of a Bill shall be communicated to the Secretary-General by the Minister concerned in writing.

69. Financial memorandum and clauses involving expenditure.—(1) A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law.

(2) Clauses or provisions in Bills involving expenditure from the Consolidated Fund of India shall be printed in thick type or in italics:

¹[Provided that where a clause in a Bill involving expenditure is inadvertently not printed in thick type or in italics, the member in charge of the Bill shall, with the permission of the Speaker, bring such clauses to the notice of the House.]

70. Memorandum regarding delegated legislation.—A Bill involving proposals for the delegation of legislative power shall further be accompanied by a memorandum explaining such proposals and drawing attention to their scope and stating also whether they are of normal or exceptional character.

71. Statement regarding Ordinances.—(1) Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is introduced in the House, shall be placed before the House along with the Bill a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance.

(2) Whenever an Ordinance, which embodies wholly or partly or with modification the provisions of a Bill pending before the House is promulgated a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance shall be laid on the Table at the commencement of the session following the promulgation of the Ordinance.

72. Procedure when introduction of Bill opposed.—(1) If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, if thinks fit, after permitting, brief statements from the member who opposes the motion and the member who moved the motion, may, without further debate, put the question:

Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon:

Provided further that the Speaker shall forthwith put to vote the motion for leave to introduce a Finance Bill or an Appropriation Bill.

²(2) Notice to oppose introduction of a Bill shall be addressed to the Secretary-General ³{specifying clearly and precisely the objections to be raised} and given by 10.00 hours on the day on which the motion for leave to introduce the Bill is included in the list of business.]

73. Publication of Bill in Gazette after introduction.—As soon as may be after a Bill has been introduced, the Bill, unless it has already been published, shall be published in the Gazette.

¹Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

²Added by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

³Ins. By L.S. Bn. (II) dated 10.12.2004, para 710.

MOTIONS AFTER INTRODUCTION OF BILLS AND SCOPE
OF DEBATE

74. Motions after introduction of Bills.—When a Bill is introduced or on some subsequent occasion, the member in charge may make one of the following motions in regard to one's own Bill, namely:—

- (i) that it be taken into consideration; or
- (ii) that it be referred to a Select Committee of the House; or
- (iii) that it be referred to a Joint Committee of the Houses with the concurrence of the Council; or
- (iv) that it be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon:

Provided that no such motion as is referred to in clause (iii) shall be made with reference to a Bill ⁴[if it contains only provisions dealing with all or any of the matters specified in sub-clauses (a) to (g) of clause (1) of article 110 of the Constitution]:

Provided further that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of members, and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for two days before the day on which the motion is made and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made.

75. Discussion of principle of Bills.—(1) On a motion referred to in rule 74 being made, the principle of the Bill and its provisions may be discussed generally, but the details of the Bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principles.

(2) At this stage no amendments to the Bill may be moved, but—

- (a) if the member in charge moves that the Bill be taken into consideration any member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee of the House, or a Joint Committee of the Houses with the concurrence of the Council, or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion;
- (b) if the member in charge moves that the Bill be referred to a Select Committee of the House, or a Joint Committee of the Houses with the concurrence of the Council, any member may move as an amendment that the Bill be referred to a Joint Committee of the Houses with the concurrence of the Council or a Select Committee, as the case may be, or that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion.

(3) Where a motion that a Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon is carried, and the Bill is circulated in accordance with that direction and opinions are received thereon, the member in charge, if so wishes to proceed with the Bill thereafter, shall move that the Bill be referred to a Select Committee of the House or a Joint Committee of the Houses with the concurrence of the Council, unless the Speaker allows a motion to be made that the Bill be taken into consideration:

Provided that if an amendment or a motion for appointment of a Select Committee or a Joint Committee has been moved under this Rule, any member may move that the House give instructions to the Select Committee or to the Joint Committee to which the Bill is proposed to be referred to make some particular or additional provision in the Bill and if necessary or convenient to consider and report on amendments which may be proposed to the original Act which the Bill seeks to amend:

Provided further that no amendment or a motion for appointment of a Joint Committee under this rule shall be moved with reference to a Bill ⁵[if it contains only provisions dealing with all or any of the matters specified in sub-clauses (a) to (g) of clause (1) of article 110 of the Constitution.]

76. Members entitled to move motions in respect of Bills.—No motion that a Bill be taken into consideration or be passed shall be made by any member other than the member in charge of the Bill and no motion that a Bill be referred to a Select Committee of the House, or a Joint Committee of the Houses with the concurrence of the Council, or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon shall be made by any member other than the member in charge except by way of amendment to a motion made by the member in charge:

Provided that if the member in charge of a Bill is unable, for reasons which the Speaker considers adequate, to move the next motion in regard to that Bill at any subsequent stage after introduction, the member may authorise another member to move that particular motion with the approval of the Speaker.

Explanation—Notwithstanding the provisions contained in the proviso the member who introduced the Bill shall continue to be the member in charge.

[For rules relating to selected committees on Bills, *See* Chapter XXVI of these rules.]

⁴Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

⁵Added by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

MOTIONS AFTER PRESENTATION OF SELECT/JOINT
COMMITTEE REPORTS AND SCOPE OF DEBATE

77. Motions after presentation of Select/Joint Committee reports.—After the presentation of the final report of a Select Committee of the House or a Joint Committee of the Houses, as the case may be, on a Bill, the member in charge may move—

(a) that the Bill as reported by the Select Committee of the House or the Joint Committee of the Houses, as the case may be, be taken into consideration; or

(b) that the Bill as reported by the Select Committee of the House or the Joint Committee of the Houses, as the case may be, be re-committed to the same Select Committee or to a new Select Committee, or to the same Joint Committee or to a new Joint Committee with the concurrence of the Council, either—

(i) without limitation, or

(ii) with respect to particular clauses or amendments only, or

(iii) with instructions to the Committee to make some particular or additional provision in the Bill, or

(c) that the Bill as reported by the Select Committee of the House or the Joint Committee of the Houses, be circulated or recirculated, as the case may be, for the purpose of eliciting opinion or further opinion thereon:

Provided that any member may object to any such motion being made if a copy of the report has not been made available for the use of members for two days before the day on which the motion is made and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made.

(2) If the member in charge moves that the Bill as reported by the Select Committee of the House or the Joint Committee of the Houses, as the case may be, be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be re-committed or be circulated or recirculated for the purpose of eliciting opinion or further opinion thereon.

78. Scope of debate on Select/Joint Committee reports.—The debate on a motion that the Bill as reported by the Select Committee of the House or the Joint Committee of the Houses, as the case may be, be taken into consideration shall be confined to consideration of the report of the Committee and the matters referred to in that report or any alternative suggestions consistent with the principle of the Bill.

AMENDMENTS TO CLAUSES ETC. AND CLAUSE BY
CLAUSE CONSIDERATION OF BILLS

79. Notice of amendments to clauses or schedules.—(1) If notice of an amendment to a clause or schedule of the Bill has not been given one day before that day on which the Bill is to be considered any

member may object to the moving of the amendment, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the amendment to be moved:

Provided that, in the case of a Government Bill, an amendment, of which notice has been received from the member in charge, shall not lapse by reason of the fact that the member in charge has ceased to be a Minister or a member and such amendment shall be printed in the name of the new member in charge of the Bill.

(2) The Secretary-General shall, if time permits, make available to the members from time to time lists of amendments of which notices have been received.

80. Admissibility of amendments.—The following conditions shall govern the admissibility of amendments to clauses or schedules of a Bill:—

(i) An amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject-matter of the clause to which it relates.

(ii) An amendment shall not be inconsistent with any previous decision of the House on the same question.

(iii) An amendment shall not be such as to make the clause which it proposes to amend unintelligible or ungrammatical.

(iv) If an amendment refers to, or is not intelligible without a subsequent amendment or schedule, notice of the subsequent amendment or schedule shall be given before the first amendment is moved, so as to make the series of amendments intelligible as a whole.

(v) The Speaker shall determine the place at which an amendment shall be moved.

(vi) The Speaker may refuse to propose an amendment which is, in the opinion of the Speaker, frivolous or meaningless.

(vii) An amendment may be moved to an amendment which has already been proposed by the Speaker.

81. President's recommendation regarding amendments.—If any member desires to move an amendment which under the Constitution cannot be moved without the previous sanction or recommendation of the President, that member shall annex to the notice required by these rules such sanction or recommendation conveyed through a Minister and the notice shall not be valid until this requirement is complied with:

Provided that no previous sanction or recommendation of the President shall be required, if an amendment seeks to—

(a) abolish or reduce the limits of the tax proposed in the Bill or amendment, or

(b) increase such tax upto the limits of an existing tax.

82. Communicaton of President's recommendation.—The order of the President, granting or withholding the sanction or recommendation to an amendment to a Bill, shall be communicated to the Secretary-General by the Minister concerned in writing.

83. Selection of new clauses or amendments.—The Speaker shall have power to select the new clauses or amendments to be proposed, and, if thinks fit, may call upon any member who has given notice of an amendment to give such explanation of the object of the amendment as may enable the member to form a judgment upon it.

84. Arrangement of amendments.—Amendments of which notice has been given shall, as far as practicable, be arranged in the list of amendments, issued from time to time, in the order in which they may be called. In arranging amendments raising the same question at the same point of a clause, precedence may be given to an amendment ⁶[proposed] by the member in charge of the Bill. Subject as aforesaid, amendments may be arranged in the order in which notices thereof are received.

85. Order of amendments.—(1) Amendments shall ordinarily be considered in the order of the clauses of the Bill to which they respectively relate; and in respect of any such clause a motion shall be deemed to have been made: "That this clause do stand part of the Bill."

(2) The Speaker, if thinks fit, may put as one question similar amendments to a clause:

Provided that if a member requests that any amendment be put separately, the Speaker shall put that amendment separately.

86. Moving of amendments.—When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried, any member may, when called upon by the Speaker, move an amendment to the Bill of which that Member has previously given notice:

Provided that in order to save time and repetition of arguments, a single discussion may be allowed to cover a series of inter-dependent amendments.

87. Withdrawal of amendments.—An amendment moved may, by leave of the House, but not otherwise be withdrawn on the request of the member moving it. If an amendment has been proposed to an amendment; the original amendment shall not be withdrawn until the amendment proposed to it has been disposed of.

88. Submission of Bill clause by clause.—Notwithstanding anything contained in these rules, the Speaker may, when a motion that a Bill be taken into consideration has been carried, submit the Bill, or any part of the Bill to the House clause by clause. The Speaker may call each clause separately, and, when the

amendments relating to it have been dealt with, shall put the question: "That this clause (or, that this clause as amended, as the case may be) do stand part of the Bill."

89. Postponement of clause.—The Speaker, if thinks fit, may postpone the consideration of a clause.

90. Consideration of schedules.—The consideration of the schedule or schedules, if any, shall follow the consideration of clauses. Schedules shall be put from the Chair, and may be amended, in the same manner as clauses, and the consideration of new schedules shall follow the consideration of the original schedules. The question shall then be put: "That this schedule (or, that this schedule as amended, as the case may be) do stand part of the Bill":

Provided that the Speaker may allow the schedule or schedules, if any, being considered before the clauses are disposed of or along with a clause or otherwise as the Speaker may think fit.

91. Voting on group of clauses and schedules.—The Speaker, if thinks fit, may put as one question clauses and or schedules, or clauses and or schedules as amended, as the case may be, together to the vote of the House:

Provided that if a member requests that any clause or schedule, or any clause or schedule as amended, as the case may be, be put separately, the Speaker shall put that clause or schedule, or clause or schedule as amended, as the case may be, separately.

92. Clause one, Enacting Formula, Preamble and Title.—Clause one, the Enacting Formula, the Preamble, if any, and the Title of a Bill shall stand postponed until the other clauses and schedules (including new clauses and new schedules) have been disposed of and the Speaker shall then put the question: "That clause one, or the Enacting Formula, or the Preamble or the Title (or, that clause one Enacting Formula, Preamble or Title as amended, as the case may be) do stand part of the Bill."

PASSING OF BILLS

93. Motion for passing of Bill.—(1) When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the Bill is made, the member in charge may at once move that the Bill be passed.

(2) Where a Bill has undergone amendments the motion that the Bill as amended be passed shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded, unless the Speaker allows the motion to be made.

(3) To such a motion no amendment may be moved which is not either formal, verbal or consequential upon an amendment made after the Bill was taken into consideration.

⁶Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

94. Scope of debate on motion for passing of Bill.—

The discussion on a motion that the Bill or as the case may be, the Bill as amended, be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill. The member while making the speech shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of arguments which shall be of a general character.

95. Correction of patent errors.—Where a Bill is passed by the House, the Speaker shall have power to correct patent errors and make such other changes in the Bill as are consequential upon the amendments accepted by the House.

96. Transmission of Bills to Council.—(1) When a Bill is passed by the House, it shall be transmitted to the Council for concurrence with a message to that effect.

(2) The Secretary-General shall certify, on top of the first page of the Bill so transmitted to the Council, in the following form:—

‘This Bill has been passed by the House of the People on the20

Dated on 20 Secretary-General:’

Provided that if it is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution the certificate by the Speaker shall be endorsed at the end of the Bill in the following form:

‘I hereby certify that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India.

Dated the 20 Speaker.’

97. Council’s message regarding Bills other than Money Bills.—If a Bill other than a Money Bill passed by the House and transmitted to the Council is passed by the Council without amendment, the message received from the Council to that effect shall be reported by the Secretary-General to the House if in session or published in the Bulletin for the information of the members if the House is not in session.

BILLS OTHER THAN MONEY BILLS RETURNED BY
THE COUNCIL

98. Bill returned with amendments.—If a Bill other than Money Bill passed by the House and transmitted to the Council is returned to the House with amendments, it shall on receipt be laid on the Table.

99. Notice for consideration of amendments.—After the amended Bill has been laid on the Table, any Minister in the case of a Government Bill, or in any other case any member may, after giving two days’ notice, or with the consent of the Speaker without notice move that the amendments be taken into consideration.

100. Consideration of amendments.—(1) If a motion that the amendments be taken into consideration is carried, the Speaker shall put the amendments to the House in such manner as the Speaker thinks most convenient for their consideration.

(2) An amendment relevant to the subject-matter of an amendment made by the Council may be moved, but no further amendment shall be moved to the Bill unless it is consequential upon, or an alternative to, an amendment made by the Council.

101. Disposal of amendments made by Council.—The House, if it agrees to the amendment made by the Council, shall send a message to the Council to that effect, but if it disagrees with that amendment or proposes further amendment or an alternative amendment, the House shall return the Bill or the Bill as further amended to the Council with a message to that effect.

102. Disagreement between Houses as to amendments.—If the Bill is returned to the House with a message that the Council insists on an amendment or amendments to which the House has disagreed, the Houses shall be deemed to have finally disagreed as to the amendment or amendments.

MONEY BILLS RETURNED BY THE COUNCIL

103. Money Bill returned without recommendation.—If a Money Bill passed by the House and transmitted to the Council is returned to the House without recommendation, the message to that effect shall be reported by the Secretary-General to the House if in session or published in the Bulletin for the information of the members if the House is not in session. The Bill shall then be presented to the President for her/his assent.

104. Money Bill returned with recommendation.—If a Money Bill passed by the House and transmitted to the Council is returned to the House with amendments recommended by the Council, it shall on receipt be laid on the Table.

105. Notices for consideration of amendments recommended by Council.—After the Bill with amendments as recommended by the Council has been laid on the Table, any Minister in the case of a Government Bill, or in any other case any member may, after giving two days’ notice, or with the consent of the Speaker without notice, move that the amendments recommended by the Council be taken into consideration.

106. Consideration of amendments recommended by Council.—If a motion that the amendments as recommended by the Council be taken into consideration is carried, the Speaker shall put the amendments as recommended by the Council to the House in such manner as the Speaker thinks most convenient for their consideration.

107. Disposal of amendments recommended by Council.—If the House accepts any amendment or amendments as recommended by the Council, the Bill shall be deemed to have been passed by both the Houses with the amendment or amendments recommended by the Council and accepted by the House and a message to that effect shall be sent to the Council.

108. Bill deemed passed on House not accepting Council's recommendations.—If the House does not accept any of the recommendations of the Council, the Bill shall be deemed to have been passed by both the Houses in the form in which it was passed by the House without any of the amendments recommended by the Council and a message to that effect shall be sent to the Council.

ADJOURNMENT OF DEBATE, WITHDRAWAL AND REMOVAL OF BILLS

109. Adjournment of debate on Bill.—At any stage of a Bill which is under discussion in the House, a motion that the debate on the Bill be adjourned may be moved with the consent of the Speaker.

110. Withdrawal of Bill.—The member in charge of a Bill may at any stage of the Bill move for leave to withdraw the Bill on the ground that—

(a) the legislative proposal contained in the Bill is to be dropped; or

(b) the Bill is to be replaced subsequently by a new Bill which substantially alters the provisions contained therein; or

(c) the Bill is to be replaced subsequently by another Bill which includes all or any of its provisions in addition to other provisions; and if such leave is granted no further motion shall be made with reference to the Bill:

Provided that where a Bill is under consideration by a Select Committee of the House or a Joint Committee of the Houses, as the case may be, notice of any motion for the withdrawal of the Bill shall automatically stand referred to the Committee and after the Committee has expressed its opinion in a report to the House, the motion shall be set down in the list of business:

Provided further that where a Bill has originated in the Council and is pending before the House, the member in charge shall move a motion in the House recommending to the Council that the Council do agree to leave being granted by the House to withdraw the Bill and after the motion is adopted by the House and concurred in by the Council, the member in charge shall move for leave to withdraw the Bill.

111. Procedure when withdrawal of Bill opposed.—If a motion for leave to withdraw a Bill is opposed, the

Speaker, if thinks fit, may permit the member who ⁷[opposes the motion and the member who moved] the motion to make brief explanatory statements and may thereafter, without further debate, put the question.

112. Removal of Bill from Register of Bills.—(1) Where any of the following motions made by the member in charge under these rules in regard to a Bill is rejected by the House, no further motion shall be made with reference to the Bill and such Bill shall be removed from the Register of Bills pending in the House:—

(i) that leave be granted to introduce the Bill;

(ii) that the Bill be referred to a Select Committee;

(iii) that the Bill be referred to a Joint Committee of the Houses with the concurrence of the Council;

(iv) that the Bill, be taken into consideration;

(v) that the Bill as reported by Select Committee of the House or Joint Committee of the Houses, as the case may be, be taken into consideration; and

(vi) that the Bill (or, that the Bill as amended, as the case may be) be passed.

(2) A Bill pending before the House shall also be removed from the Register of Bills pending in the House in case a Bill substantially identical is passed by the House or the Bill is withdrawn under rule 110.

Explanation.—A Bill pending before the House shall include—

(i) a Bill introduced in the House which does not fall within the categories of Bills mentioned in this rule or rule 113;

(ii) a Bill transmitted to the Council and returned by the Council with amendment, or recommendation, as the case may be, and laid on the Table under rule 98 or 104;

(iii) a Bill originating in the Council and transmitted to the House and laid on the Table under rule 114 or 122; and

(iv) a Bill returned by the President with a message under article 111 of the Constitution.

113. Additional provision for removal of private member's Bill from Register of Bills.—A private member's Bill pending before the House shall also be removed from the Register of Bills pending in the House in case—

(a) the member in charge ceases to be a member of the House;

(b) the member in charge is appointed a Minister.

II. Bills originating in the Council and transmitted to the House

114. Laying of Bills on Table.—When a Bill originating in the Council has been passed by the Council and is transmitted to the House the Bill shall, as soon as may be, be laid on the Table.

⁷Sub by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

115. Notice for consideration.—At any time after the Bill has been so laid on the Table, any Minister in the case of a Government Bill, or, in any other case, any member may give notice of one's intention to move that the Bill be taken into consideration.

116. Motion for consideration.—On the day on which the motion for consideration is set down in the list of business which shall, unless the Speaker otherwise directs, be not less than two days from the receipt of the notice, the member giving notice may move that the Bill be taken into consideration.

117. Discussion of principle of Bill.—On the day on which such motion is made or on any subsequent day to which the discussion is postponed, the principle of the Bill and its general provisions may be discussed, but the details of the Bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principle.

118. Reference to Select Committee.—Any member may, if the Bill has not already been referred to a Joint Committee of both the Houses, move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee and, if such motion is carried, the Bill shall be referred to a Select Committee, and the rules regarding Select Committees on Bills originating in the House shall then apply.

119. Consideration and passing of Bills.—If the motion that the Bill be taken into consideration is carried, the Bill shall be taken into consideration clause by clause and the provisions of the rules of the House regarding consideration of amendments to Bills and the subsequent procedure in regard to the passing of Bills shall apply.

120. Bill passed without amendment.—If the Bill is passed without amendment, a message shall be sent to the Council intimating that the House has agreed to the Bill without any amendment.

121. Bill passed with amendments.—(1) If the Bill is passed with amendments, the Bill shall be returned with a message asking the concurrence of the Council in the amendments.

(2) The Secretary-General shall certify, on top of the first page of the Bill so returned to the Council, in the following form:—

‘This Bill has been passed as amended by the House of the People on the.....’

Dated...20.....

Secretary-General’.

122. Procedure consequent on disposal of amendments by Council.—If the Council disagrees with the amendments made by the House or any of them, or agrees to any of the amendments made by the House with further amendments, or proposes further amendments in place of amendments made by the House, the Bill as further amended shall on receipt by the House be laid on the Table.

123. Consideration of amendments made by Council.—After the amended Bill has been laid on the Table, any Minister in the case of a Government Bill, or in any other case, any member may, after giving two days' notice or with the consent of the Speaker without notice, move that the amendments be taken into consideration.

124. Procedure on consideration of amendments.—(1) If a motion that the amendments be taken into consideration is carried, the Speaker shall put the amendments to the House in such manner as the Speaker thinks most convenient for their consideration.

(2) An amendment relevant to the subject-matter of an amendment made by the Council may be moved, but no further amendment shall be moved to the Bill, unless it is consequential upon, or an alternative to, an amendment made by the Council.

125. Disposal of Bills and amendments.—The House may either agree to the Bill as originally passed by the Council or as further amended by the Council, as the case may be, or may return the Bill with a message that it insists on an amendment or amendments to which the Council has disagreed.

126. Disagreement between Houses as to amendments.—If a Bill is returned with a message intimating that the House insists on amendments to which the Council is unable to agree, the Houses shall be deemed to have finally disagreed as to the amendments.

127. Rejection of Bill.—When any of the following motions moved in the House with reference to a Bill originating in the Council and transmitted to the House is negatived by the House, the Bill shall be deemed to have been rejected by the House:

- (i) that the Bill be taken into consideration;
- (ii) that the Bill be referred to a Select Committee;
- (iii) that the Bill as reported by Select Committee be taken into consideration; and
- (iv) that the Bill (or, that the Bill as amended, as the case may be) be passed.

III. Authentication and Assent of Bills passed

128. Authentication and assent.—(1) When a Bill is passed by the Houses and is in possession of the House, the Bill shall be signed in duplicate by the Speaker and presented to the President:

Provided that in the absence of the Speaker from New Delhi, the Secretary-General may, in case of urgency, authenticate the Bill on behalf of the Speaker.

(2) One copy of the Bill so assented to by the President shall be preserved for verification and record and shall not be allowed to pass out of the custody of

the House without the permission of the Speaker.

IV. Reconsideration of Bills returned by President

BILLS ORIGINATING IN THE HOUSE

129. Message of President.—(1) When a Bill passed by the Houses is returned to the House by the President with a message requesting that the House should reconsider the Bill or any specified provisions thereof or any such amendments are recommended in the message, the Speaker shall read the message of the President in the House if in session, or if the House is not in session, direct that it may be published in the Bulletin for the information of the members.

(2) The Bill as passed by the Houses and returned by the President for reconsideration shall thereafter be laid on the Table.

130. Notice for consideration of amendments.—At any time after the Bill has been so laid on the Table, any Minister in the case of a Government Bill, or, in any other case, any member may give notice of one's intention to move that the amendments recommended by the President be taken into consideration.

131. Motion for consideration.—On the day on which the motion for consideration is set down in the list of business which shall, unless the Speaker otherwise directs, be not less than two days from the receipt of the notice, the member giving notice may move that the amendments be taken into consideration.

132. Scope of debate.—The debate on such a motion shall be confined to consideration of matters referred to in the message of the President or to any suggestion relevant to the subject-matter of the amendments recommended by the President.

133. Procedure on motion for consideration of amendments being carried.—If the motion that the amendments recommended by the President be taken into consideration is carried, the Speaker shall put the amendments to the House in such manner as the Speaker thinks most convenient for their consideration.

134. Amendment to amendment.—An amendment relevant to the subject-matter of an amendment recommended by the President may be moved, but no further amendment shall be moved to the Bill unless it is consequential upon, incidental or alternative to, an amendment recommended by the President.

135. Passing again of Bill.—When all the amendments have been disposed of, the member giving notice of the motion under rule 130 may move that the Bill as originally passed by the Houses be passed again, or passed again as amended, as the case may be.

136. Procedure on motion for consideration of amendments not being carried.—If the motion that the amendments recommended by the President be taken

into consideration is not carried, the member giving notice of the motion under rule 130 may at once move that the Bill as originally passed by the Houses be passed again without amendment.

137. Transmission to Council of Bill passed again.—(1) When the Bill is passed again by the House with or without amendment, as the case may be, it shall be transmitted to the Council for concurrence with a message to that effect.

(2) The Secretary-General shall certify, on the top of the first page of the Bill so transmitted to the Council, in the following form:—

‘This Bill which was passed by the Houses of Parliament and returned by the President for reconsideration has been passed again with/without amendment by the House of the People on, the20

Dated the...20

Secretary-General’.

138. Message from Council regarding passing again of Bill.—If the Bill passed again by the House and transmitted to the Council is passed again by the Council without amendment, the message received from the Council to that effect shall be reported by the Secretary-General to the House if in session or published in the Bulletin for the information of the members if the House is not in session.

139. Bill returned by Council with amendments.—If the Bill passed again by the House and transmitted to the Council is returned to the House with amendments it shall on receipt be laid on the Table.

140. Consideration of amendments made by Council.—After the amended Bill has been laid on the Table, any Minister in the case of a Government Bill, or, in any other case any member may, after giving two days' notice, or with the consent of the Speaker without notice, move that the amendments be taken into consideration.

141. Procedure on consideration of amendments.—(1) If a motion that the amendments be taken into consideration is carried, the Speaker shall put the amendments to the House in such manner as the Speaker thinks most convenient for their consideration.

(2) An amendment relevant to the subject-matter of an amendment made by the Council may be moved, but no further amendment shall be moved to the Bill unless it is consequential upon, incidental or alternative to, an amendment made by the Council.

142. Disposal of amendments made by Council.—The House, if it agrees to the amendment made by the Council, shall send a message to the Council to that effect, but if it disagrees with that amendment or proposes further amendment or an alternative amendment, the House shall return the Bill or the Bills as further amended to the Council with a message to that effect.

143. Disagreement between Houses.—If the Bill is returned to the House with a message that the Council insists on an amendment or amendments to which the House has disagreed, the Houses shall be deemed to have finally disagreed as to the amendment or amendments.

BILLS ORIGINATING IN THE COUNCIL

144. Laying of Bill on Table.—When a Bill passed by the Houses which has been returned by the President to the Council for reconsideration, has been passed again with or without amendments by the Council and transmitted to the House, the Bill together with the President's message shall, as soon as may be, be laid on the Table.

145. Motion for consideration.—At any time after the Bill together with the President's message has been so laid on the Table, any Minister in the case of a Government Bill, or, in any other case, any member, may, after giving two days' notice, or with the consent of the Speaker without notice, move that the Bill as passed again by the Council be taken into consideration.

146. Procedure on motion for consideration being carried.—(1) If the motion that the Bill as passed again by the Council be taken into consideration is carried, the Speaker shall put to the House the amendments, if any, made to the Bill by the Council in such manner as the Speaker thinks most convenient for their consideration.

(2) An amendment relevant to the subject-matter of an amendment made by the Council may be moved, but no further amendment shall be moved unless it is consequential upon, incidental or alternative to, an amendment made by the Council:

Provided that if the Council has not agreed to an amendment recommended by the President any member may move an amendment relevant to the subject-matter of the amendment recommended by the President.

147. Bill passed again without amendment.—If the Bill passed again by the Council is passed again by the House without amendment, a message shall be sent to the Council to that effect.

148. Bill passed again with amendments.—If the Bill is passed again by the House with amendments, the Bill shall be returned to the Council with a message asking the concurrence of the Council in such amendments.

149. Procedure consequent on disposal of amendments by Council.—If the Council disagrees with the amendments made by the House or any of them, or agrees to any of the amendments made by the House with further amendments, or proposes further amendments in place of amendments made by the House, the Bill as further amended shall on receipt by the House be laid on the Table.

150. Consideration of amendments made by Council.—After the amended Bill has been so laid on the Table, any Minister in the case of a Government Bill, or, in any other case, any member may, after giving two days' notice, or with the consent of the Speaker without notice, move that the amendments be taken into consideration.

151. Procedure on consideration of amendments.—(1) If a motion that the amendments be taken into consideration is carried, the Speaker shall put the amendments to the House in such manner as the Speaker thinks most convenient for their consideration.

(2) An amendment relevant to the subject-matter of the amendments made by the Council may be moved but no further amendment shall be moved to the Bill, unless it is consequential upon, incidental or alternative to, an amendment made by the Council.

152. Disposal of Bill and amendments.—The House may agree to the Bill as passed again by the Council or as further amended by the Council, as the case may be, or may return the Bill with a message that it insists on an amendment or amendments to which the Council has disagreed.

153. Disagreement between Houses as to amendments.—If the Bill is returned with a message that the House insists on an amendment or amendments to which the Council is unable to agree, the Houses shall be deemed to have finally disagreed as to the amendment or amendments.

AUTHENTICATION OF BILLS PASSED AGAIN BY THE HOUSES

154. Authentication.—When a Bill is passed again by the Houses and is in possession of the House, the Bill shall be signed in duplicate by the Speaker and presented to the President in the following form:

'The above Bill has been passed again by the Houses of Parliament in pursuance of the proviso to article 111 of the Constitution.

Dated.....20

Speaker':

Provided that in the absence of the Speaker from New Delhi, the Secretary-General may, in case of urgency, authenticate the Bill on behalf of the Speaker.

CHAPTER XI

BILLS SEEKING TO AMEND THE CONSTITUTION

155. Voting on clauses and schedules.—Each clause or schedule or clause, or schedule as amended, as the case may be, of a Bill seeking to amend the Constitution shall be put to the vote of the House separately and shall form part of the Bill if it is passed by a majority of the total membership of the House and

by a majority of not less than two thirds of the members present and voting:

Provided that the Speaker may, with concurrence of the House, put clauses and/or schedules, or clauses and/or schedules as amended, as the case may be, together to the vote of the House in which case the result of the voting shall be taken as applicable to each clause or schedule separately and so indicated in the proceedings:

Provided further that if a member requests that any clause or schedule, or any clause or schedule as amended, as the case may be, be put separately, the Speaker shall put that clause or schedule, or clause or schedule as amended, as the case may be, separately:

Provided further that the Short Title, the Enacting Formula and the Long Title may be adopted by a simple majority.

156. Voting on amendments.—Amendments to clauses or schedules shall be decided by a majority of members present and voting in the same manner as in the case of any other Bill.

157. Voting on motions.—If the motion in respect of such Bill is that:

- (i) the Bill be taken into consideration; or
- (ii) the Bill as reported by the Select Committee of the House or the Joint Committee of the Houses, as the case may be, be taken into consideration; or
- (iii) the Bill, or the Bill as amended, as the case may be, be passed;

then the motion shall be deemed to have been carried if it is passed by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

158. Voting by division(1) Voting shall be by division whenever a motion has to be carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

(2) If the result of the voting shows that the majority of the total membership of the House and the majority of not less than two-thirds of the members present and voting are in favour of the motion, the Speaker shall, while announcing the result, say that the motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

159. Residuary procedure.—In all other respects, the procedure laid down in these rules with respect to other Bills shall apply.

Explanation.—The expression “total membership” referred to in these rules means the total number of

members comprising the House irrespective of the fact whether there are vacancies or absentees on any account.

CHAPTER XII

PETITIONS

160. Scope of petitions.—¹[Petitions may be presented by a Member to the House with the consent of the Speaker on—

(i) a Bill which has been published under rule 64 or which has been introduced in the House;

(ii) any matter connected with the business pending before the House; and

(iii) any matter of general public interest provided that it is not one:—

(a) which falls within the cognizance of a court of law having jurisdiction in any part of India or a court of enquiry or a statutory tribunal or authority or a *quasi-judicial* body, or a commission;

(b) which should ordinarily be raised in a State Legislature;

(c) which can be raised on a substantive motion or resolution; or

(d) for which remedy is available under the law, including rules, regulations, bye-laws made by the Government of India or an authority to whom power to make such rules, regulations, etc. is delegated.]

160A. Petitions dealing with financial matters.—A petition, dealing with any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 110 or involving expenditure from the Consolidated Fund of India, shall not be presented to the House unless recommended by the President.

161. General form of petition.—(1) The general form of petition set out in the First Schedule, with such variations as the circumstances of each case require, may be used, and, if used, shall be sufficient.

(2) Every petition shall be couched in respectful, decorous and temperate language.

(3) Every petition shall be either in Hindi or in English. If any petition in any other Indian language is made, it shall be accompanied by a translation either in Hindi or in English, and signed by the petitioner.

162. Authentication of petition.—(1) The full name and address of every signatory to a petition shall be set out therein and shall be authenticated by the petitioner's signature, and if illiterate by the petitioner's thumb impression.

(2) Where there is more than one signatory to a petition, at least one person shall sign, or affix thumb impression if such person is illiterate, on the sheet on

¹Sub. by L.S. Bn. (II) dated 17.2.2014, para 6174.

which the petition is inscribed. If signatures or thumb impressions are affixed to more than one sheet, the prayer of the petition shall be repeated at the head of each sheet.

163. Documents not be attached.—Letters, affidavits or other documents shall not be attached to any petition.

164. Counter signature.—(1)² [Every petition shall be countersigned by a member presenting it]. If a petition is made in any Indian language other than Hindi or English, its translation in Hindi or English shall also be countersigned by the member presenting it.

(2) A member shall not present one's own petition.

165. Petition to be addressed to House.—Every petition shall be addressed to the House and shall conclude with a prayer reciting the definite object of the petitioner in regard to the matter to which it relates.

166. Notice of presentation.—A member shall give advance intimation to the Secretary-General of one's intention to present a petition.

167. Presentation of petition.—³ [A petition may be presented by a member to the House. No debate shall be permitted on the presentation of a petition.]

168. Form of presentation.—A member presenting a petition shall confine to making of a statement in the following form:—

Madam/Sir, I beg to present a petition signed by...petitioner(s) regarding...

and no debate shall be permitted on this statement.

169. Reference to Committee on Petitions.—⁴ [Every petition shall, after presentation by a member stand referred to the Committee on Petitions.]

[For rules relating to Committee on Petitions, See Chapter XXVI of these rules.]

CHAPTER XIII

RESOLUTIONS

170. Notice of resolution.—A member other than a Minister who wishes to move a resolution on a day allotted for private members' resolutions, shall give a notice to that effect at least two days before the date of ballot. The names of all members from whom such notices are received shall be balloted and those members who secure the first three places in the ballot for the day allotted for private members' resolutions shall be eligible to give notice of one resolution each within two days after the date of the ballot.

171. Form of resolution.—A resolution may be in the

form of a declaration of opinion, or a recommendation; or may be in the form so as to record either approval or disapproval by the House of an act or policy of Government, or convey a message; or commend, urge or request an action; or call attention to a matter or situation for consideration by Government; or in such other form as the Speaker may consider appropriate.

172. Subject-matter of resolution.—Subject to the provisions of these rules, a member or a Minister may move a resolution relating to a matter of general public interest.

173. Admissibility of resolution.—In order that a resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely:—

- (i) it shall be clearly and precisely expressed;
- (ii) it shall raise substantially one definite issue;
- (iii) it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements;
- (iv) it shall not refer to the conduct or character of persons except in their official or public capacity; and
- (v) it shall not relate to any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India.

174. Speaker to decide admissibility.—The Speaker shall decide whether resolution or a part thereof is or is not admissible under these rules and may disallow any resolution or a part thereof when the Speaker is of the opinion that it is an abuse of the right of moving a resolution or calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules.

175. Matters before tribunals, commissions, etc..—No resolution which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or *quasi-judicial* functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into, or investigate any matter shall ordinarily be permitted to be moved:

Provided that the Speaker may, in own discretion, allow such matter being raised in the House as if concerned with the procedure or subject or stage of enquiry, if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory tribunal, statutory authority, commission or court of enquiry.

176. Moving of resolution.—(1) A member in whose name a resolution stands on the list of business shall, except when that member wishes to withdraw it, when called upon, move the resolution, and shall commence

²Sub. by L.S. Bn. (II) dated 17.2.2014, para 6174.

^{3&4}Sub. by L.S. Bn. (II) dated 17.2.2014, para 6174.

one's own speech by a formal motion in the terms appearing in the list of business.

(2) A member may, with the permission of the Speaker, authorise any other member, in whose name the same resolution stands lower in the list of business, to move it on her or his behalf and the member so authorised may move it accordingly.

(3) If a member other than a Minister when called on is absent, any other member authorised by that member in writing in her or his behalf may, with the permission of the Speaker, move the resolution standing in the name of such member.

177. Amendments.—(1) After a resolution has been moved any member may, subject to the rules relating to resolutions, move an amendment to the resolution.

(2) If notice of such amendment has not been given one day previous to the day on which the resolution is moved, any member may object to the moving of the amendment, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the amendment to be moved.

(3) The Secretary-General shall, if time permits, make available to members from time to time lists of amendments of which notices have been received.

178. Time limit for speeches.—No speech on a resolution shall, except with the permission of the Speaker, exceed fifteen minutes in duration:

Provided that the mover of a resolution, when moving the same and the Minister concerned when speaking for the first time, may speak for thirty minutes or for such longer time as the Speaker may permit.

179. Scope of discussion.—The discussion on a resolution shall be strictly relevant to and within the scope of the resolution.

180. Withdrawal of resolution and amendment.—(1) A member in whose name a resolution stands on the list of business may, when called upon, withdraw the resolution, and shall confine to making of a mere statement to the effect.

(2) A member who has moved a resolution or amendment to a resolution shall not withdraw the same except by leave of the House.

181. Splitting of resolution.—When any resolution involving several points has been discussed, the Speaker, may divide the resolution, and put each or any point separately to the vote, as the Speaker may think fit.

182. Repetition of resolution.—When a resolution has been moved no resolution or amendment raising substantially the same question shall be moved within one year from the date of the moving of the earlier resolution:

Provided that when a resolution has been withdrawn with the leave of the House, no resolution raising substantially the same question shall be moved during the same session.

183. Resolution passed to be sent to Minister.—A copy of every resolution which has been passed by the House shall be forwarded to the Minister concerned.

CHAPTER XIV

MOTIONS

184. Discussion on matter of public interest.—Save in so far as is otherwise provided in the Constitution or in these rules, no discussion of a matter of general public interest shall take place except on a motion made with the consent of the Speaker.

185. Notice of motion.—Notice of a motion shall be given in writing addressed to the Secretary-General.

186. Admissibility of motions.—In order that a motion may be admissible it shall satisfy the following conditions, namely:—

- (i) it shall raise substantially one definite issue;
- (ii) it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements;
- (iii) it shall not refer to the conduct or character of persons except in their public capacity;
- (iv) it shall be restricted to a matter of recent occurrence;
- (v) it shall not raise a question of privilege;
- (vi) it shall not revive discussion of a matter which has been discussed in the same session;
- (vii) it shall not anticipate discussion of a matter which is likely to be discussed in the same session;
¹[XXX]
- (viii) it shall not relate to any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India;
- ²[(ix) if it contains a statement the member shall take the responsibility for the accuracy of the statement;
- (x) it shall not seek discussion on a paper or document laid on the Table by a private member;
- (xi) it shall not ordinarily relate to matters which are under consideration of a Parliamentary Committee;
- (xii) it shall not ask for an expression of opinion or the solution of an abstract legal question or of a hypothetical proposition;

¹Omitted by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

²Added by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

- (xiii) it shall not relate to a matter which is not primarily the concern of the Government of India;
- (xiv) it shall not raise matter under the control of bodies or persons not primarily responsible to the Government of India;
- (xv) it shall not relate to a matter with which a Minister is not officially concerned;
- (xvi) it shall not refer discourteously to a friendly foreign country;
- (xvii) it shall not refer to or seek disclosure of information about matters which are in their nature secret such as Cabinet discussions or advice given to the President in relation to any matter in respect of which there is a constitutional, statutory or conventional obligation not to disclose information; and
- (xviii) it shall not relate to a trivial matter.]

187. Speaker to decide admissibility.—The Speaker shall decide whether a motion or a part thereof is or is not admissible under these rules and disallow any motion or a part thereof when the Speaker is of the opinion that it is an abuse of the right of moving a motion or is calculated to obstruct or prejudicially affects the procedure of the House or is in contravention of these rules.

188. Matters before tribunals, commissions etc..—No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or *quasi-judicial* functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into or investigate, any matter shall ordinarily be permitted to be moved:

Provided that the Speaker may, in own discretion, allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory tribunal, statutory authority, commission or court of enquiry.

189. Publication of admitted motions.—If the Speaker admits notice of a motion and no date is fixed for the discussion of such motion, it shall be ³[***] notified in the Bulletin with the heading:

‘No-Day-Yet-Named Motions’.

190. Allotment of time for discussion.—The Speaker may, after considering the state of business in the House and in consultation with the Leader of the House ⁴[or on the recommendation of the Business Advisory Committee] allot a day or days or part of a day for the discussion of any such motion.

191. Putting of question at appointed time.—The Speaker shall, at the appointed hour on the allotted day or the last of the allotted days, as the case may be, forthwith put every question necessary to determine the decision of the House on the original question.

192. Time limit for speeches.—The Speaker, if thinks fit, may prescribe a time-limit for speeches.

CHAPTER XV

SHORT DURATION DISCUSSIONS

193. Notice for raising discussion.—Any member desirous of raising discussion on a matter of urgent public importance may give notice in writing to the Secretary-General specifying clearly and precisely the matter to be raised:

Provided that the notice shall be accompanied by an explanatory note stating reasons for raising discussion on the matter in question:

Provided further that the notice shall be supported by the signatures of at least two other members.

194. Speaker to decide admissibility and allotment of time.—(1) If the Speaker is satisfied, after calling for such information from the member who has given notice and from the Minister as the Speaker may consider necessary, that the matter is urgent and is of sufficient importance to be raised in the House at an early date, the Speaker may admit the notice:

Provided that if an early opportunity is otherwise available for the discussion of the matter the Speaker may refuse to admit the notice.

(2) The Speaker may allot two sittings in a week on which such matters may be taken up for discussion and allow such time for discussion not exceeding '[two] hours at or before the end of the sitting, as the Speaker may consider appropriate in the circumstances.

195. No formal motion.—There shall be no formal motion before the House nor voting. The member who has given notice may make a short statement and the Minister shall reply shortly. Any member who has previously intimated to the Speaker may be permitted to take part in the discussion.

196. Time limit for speeches.—The Speaker, if thinks fit, may prescribe a time-limit for the speeches.

CHAPTER XVI

CALLING ATTENTION

197. Procedure regarding Calling Attention.—(1) A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent

³Omitted by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

⁴Added *ibid*.

¹Sub. by L.S. Bn. (II) dated 30.4.1987, para 1639.

public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date:

Provided that no member shall give more than two such notices for any one sitting.

¹[(2) There shall be no debate on such statement at the time it is made but each member in whose name the item stands in the list of business may, with the permission of the Speaker, ask a clarificatory question and the Minister shall reply at the end to all such questions:

Provided that names of not more than five members shall be shown in the list of business.]

Explanation.—(i) Where a notice is signed by more than one member, it shall be deemed to have been given by the first signatory only.

(ii) Notices for a sitting received upto 10.00 hours shall be deemed to have been received at 10.00 hours on that day and a ballot shall be held to determine the relative priority of each such notice on the same subject. Notices received after 10.00 hours shall be deemed to have been given for the next sitting.

²[(iii) Notices received during a week commencing from its first sitting till 10.00 hours on the last day of the week on which the House sits, shall be valid for that week. Notices received after 10.00 hours on the last day of the week on which the House sits, shall be valid for the following week.

(iv) In case the number of members giving notices on a subject that is admitted by the Speaker, is ³{five or less}, their *inter-se* priority shall be determined with reference to the date and time of receipt of Notices.]

(3) Not more than two such matters shall be raised at the same sitting:

Provided that the second matter shall not be raised by the same members who have raised the first matter and it shall be raised at ⁴[such time] as the Speaker may fix.

(4) In the event of more than one matter being presented for the same day, priority shall be given to the matter which is, in the opinion of the Speaker, more urgent and important.

⁵[(5) All the notices which have not been taken up during the week for which they have been given, shall lapse at the end of the week unless the Speaker has admitted any of them for a subsequent sitting:

Provided that a notice referred for facts to a Minister shall not lapse till it is finally disposed of by the Speaker.]

¹Sub. by L.S. Bn. (II) dated 30.4.1987, para 1639.

²Added *ibid.*

³Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

⁴Sub. *ibid.*

⁵Sub. by L.S. Bn. (II) dated 30.4.1987, para 1639.

CHAPTER XVII

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN COUNCIL OF MINISTERS AND STATEMENT BY MINISTER WHO HAS RESIGNED

198. Procedure regarding motion of no-confidence in Council of Ministers.—(1) A motion expressing want of confidence in the Council of Ministers may be made subject to the following restrictions, namely:—

- (a) leave to make the motion shall be asked for by the member when called by the Speaker;
- (b) the member asking for leave shall, ¹[by 10.00 hours on] that day give to the Secretary-General a written notice of the motion which such member proposes to move.

²[Provided that notices, received after 10.00 hours, shall be deemed to have been received at 10.00 hours on the next day on which the House sits.]

(2) If the Speaker is of opinion that the motion is in order, the Speaker shall read the motion to the House and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than fifty members rise accordingly, the Speaker shall declare that leave is granted and that the motion will be taken up on such day, not being more than ten days from the date on which the leave is asked for as the Speaker may appoint. If less than fifty members rise, the Speaker shall inform that the member has not the leave of the House.

(3) If leave is granted under sub-rule (2), the Speaker may, after considering the state of business in the House, allot a day or days or part of a day for the discussion of the motion.

(4) The Speaker shall, at the appointed hour on the allotted day or the last of the allotted days, as the case may be, forthwith put every question necessary to determine the decision of the House on the motion.

(5) The Speaker, if thinks fit, may prescribe a time limit for speeches.

199. Statement by Minister who has resigned.—(1) A member who has resigned the office of Minister may, with the consent of the Speaker, make a personal statement in explanation of her or his resignation ³[on any day during the session in which the resignation has been accepted by the President:

Provided that a member may make such a statement at the earliest opportunity on a day not being more than seven days from the date of commencement of the session if the resignation was accepted by the President when the House was not in session.]

¹Sub. by L.S. Bn. (II) dated 1.8.1989, para 3091.

²Added *ibid.*

³Added by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

(2) A copy of the statement shall be forwarded to the Speaker and the Leader of the House⁴ [at least] one day in advance of the day on which it is made.

$$5 \left[\begin{array}{ccc} *** & & \end{array} \right]$$

(3) There shall be no debate on such statement, but after it has been made, a Minister may make a statement pertinent thereto.

CHAPTER XVIII

RESOLUTION FOR REMOVAL OF SPEAKER OR DEPUTY SPEAKER FROM OFFICE

200. Notice of Resolution for removal of Speaker or Deputy Speaker.—(1) A member wishing to give notice of a resolution, under clause (c) of article 94 of the Constitution, for the removal of the Speaker or the Deputy Speaker shall do so in writing to the Secretary-General¹ and shall furnish the full text of such resolution.]

(2) On receipt of a notice under sub-rule (1) a motion for leave to move the resolution shall be entered in the list of business in the name of the member concerned, on a day fixed by the Speaker, provided that the day so fixed shall be any day after fourteen days from the date of the receipt of notice of the resolution.

200A. ²[Admissibility of Resolution.— In order that such a resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely:—

- (i) it shall be specific with respect to charges;
- (ii) it shall be clearly and precisely expressed; and
- (iii) it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements.]

201. Leave of House to move resolution.—(1) Subject to the provisions of article 96 of the Constitution, the Speaker or the Deputy Speaker or such other person as is referred to in clause (2) of article 95 of the Constitution shall preside when a motion under sub-rule (2) of rule 200 is taken up for consideration.

(2) The member in whose name the motion stands on the list of business shall, ³[unless makes a statement conveying unwillingness to move the motion, move the motion when called upon to do so, but in either case] no speech shall be permitted at this stage.

(3) The Speaker or the Deputy Speaker or the person presiding, as the case may be, shall thereupon place the motion before the House and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places. If not less than fifty members rise accordingly, the Speaker or the Deputy Speaker or the person presiding, as

the case may be, shall declare that leave has been granted and that the resolution will be taken up on such day, not being more than ten days from the date on which leave is asked for, as the Speaker or the Deputy Speaker or the person presiding, as the case may be, may appoint. If less than fifty members rise, the Speaker or the Deputy Speaker or the person presiding, as the case may be, shall inform that the member has not the leave of the House.

202. Inclusion of resolution in list of business.—On the appointed day the resolution shall be included in the list of business.

202A. ⁴[Scope of discussion.—The discussion on the resolution shall be strictly confined to the charges preferred in the resolution.]

203. Time limit for speeches.—Except with the permission of the Speaker or the person presiding, a speech on the resolution shall not exceed fifteen minutes in duration:

Provided that the mover of the resolution when moving the same may speak for such longer time as the Speaker or the person presiding may permit.

CHAPTER XIX

FINANCIAL BUSINESS

BUDGET

204. Presentation of budget.—(1) The Annual Financial Statement or the Statement of the Estimated Receipts and Expenditure of the Government of India in respect of each financial year (hereinafter referred to as ‘the Budget’) shall be presented to the House on such day as the President may direct.

(2) The Budget shall be presented to the House in such form as the Finance Minister may, after considering the suggestions, if any, of the Estimates Committee, settle.

205. No discussion on day of presentation.—There shall be no discussion of the Budget on the day on which it is presented to the House.

DEMANDS FOR GRANTS

206. Demands for Grants.—(1) A separate demand shall ordinarily be made in respect of the grant proposed for each Ministry, provided that the Finance Minister may include in one demand grants proposed for two or more Ministries or Departments or make a demand in respect of expenditure which cannot readily be classified under particular Ministries.

(2) Each demand shall contain first statement of the total grant proposed and then a statement of the detailed estimate under each grant divided into items.

207. General discussion on Budget.—(1) On a day to be appointed by the Speaker subsequent to the day on

⁴Inserted *ibid.*

⁵Omitted *ibid.*

¹Added by L.S. Bn. (II) dated 1.8.1989, para 3091.

²Ins. *ibid.*

³Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

⁴Ins. by L.S. Bn. (II) dated 1.8.1989, para 3091.

which the Budget is presented and for such time as the Speaker may allot for this purpose, the House shall be at liberty to discuss the Budget as a whole or any question of principle involved therein, but no motion shall be moved nor shall the Budget be submitted to the vote of the House.

(2) The Finance Minister shall have a general right of reply at the end of the discussion.

(3) The Speaker, if thinks fit, may prescribe a time limit for speeches.

208. Voting of demands for grants.—(1) The Speaker shall, in consultation with the Leader of the House, allot so many days as may be compatible with the public interest for the discussion and voting of demands for grants.

(2) On the last day of the allotted days at 17.00 hours or at such other hour as the Speaker may fix in advance, the Speaker shall forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the demands for grants.

(3) Motions may be moved to reduce any demand for grant.

(4) No amendments to motions to reduce any demand for grant shall be permissible.

(5) When several motions relating to the same demand for grant are offered, they shall be discussed in the order in which the heads to which they relate appear in the Budget.

209. Cut motions.—A motion may be moved to reduce the amount of a demand in any of the following ways:—

(a) ‘that the amount of the demand be reduced to Re. 1’ representing disapproval of the policy underlying the demand. Such a motion shall be known as ‘Disapproval of Policy Cut’. A member giving notice of such a motion shall indicate in precise terms the particulars of the policy which the member proposes to discuss. The discussion shall be confined to the specific point or points mentioned in the notice and it shall be open to members to advocate an alternative policy;

(b) ‘that the amount of the demand be reduced by a specified amount’ representing the economy that can be effected. Such specified amount may be either a lump sum reduction in the demand or omission or reduction of an item in the demand. The motion shall be known as ‘Economy Cut’. The notice shall indicate briefly and precisely the particular matter on which discussion is sought to be raised and speeches shall be confined to the discussion as to how economy can be effected;

(c) ‘that the amount of the demand be reduced by Rs. 100’ in order to ventilate a specific grievance which is within the sphere of the responsibility of the Government of India. Such a motion shall be known as ‘Token Cut’ and

the discussion thereon shall be confined to the particular grievance specified in the motion.

210. Admissibility of cut motions.—In order that notice of motion for reduction of the amount of demand may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely:—

- (i) it shall relate to one demand only;
- (ii) it shall be clearly expressed and shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations, epithets or defamatory statements;
- (iii) it shall be confined to one specific matter which shall be stated in precise terms;
- (iv) it shall not reflect on the character or conduct of any person whose conduct can only be challenged on a substantive motion;
- (v) it shall not make suggestions for the amendment or repeal of existing laws;
- (vi) it shall not refer to a matter which is not primarily the concern of the Government of India;
- (vii) it shall not relate to expenditure charged on the Consolidated Fund of India;
- (viii) it shall not relate to a matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India;
- (ix) it shall not raise a question of privilege;
- (x) it shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session and on which a decision has been taken;
- (xi) it shall not anticipate a matter which has been previously appointed for consideration in the same session;
- (xii) it shall not ordinarily seek to raise a discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into, or investigate any matter:

Provided that the Speaker may in own discretion allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or stage of enquiry, if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory tribunal, statutory authority, commission or court of enquiry; and

- (xiii) it shall not relate to a trivial matter.

211. Speaker to decide admissibility.—The Speaker shall decide whether a cut motion is or is not admissible under these rules and may disallow any cut motion when the Speaker is of the opinion that it is an abuse of the right of moving cut motions or is calculated to obstruct or

prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules.

212. Notice of cut motions.—If notice of a motion to reduce any demand for grant has not been given one day previous to the day on which the demand is under consideration, any member may object to the moving of the motion, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made.

213. Presentation of Budget in parts.—Nothing hereinbefore contained shall be deemed to prevent the presentation of the Budget to the House in two or more parts and when such presentation takes place, each part shall be dealt with in accordance with these rules as if it were the Budget.

214. Vote on Account.—(1) A motion for vote on account shall state the total sum required and the various amounts needed for each Ministry, Department or item of expenditure which compose that sum shall be stated in a schedule appended to the motion.

(2) Amendments may be moved for the reduction of the whole grant or for the reduction or omission of the items whereof the grant is composed.

(3) Discussion of a general character may be allowed on the motion or any amendments moved thereto, but the details of the grant shall not be discussed further than is necessary to develop the general points.

(4) In other respects, a motion for vote on account shall be dealt with in the same way as if it were a demand for grant.

215. Supplementary etc. grants and votes of credit.—Supplementary, additional, excess and exceptional grants and votes of credit shall be regulated by the same procedure as is applicable in the case of demands for grants subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as the Speaker may deem to be necessary or expedient.

216. Scope of debate on supplementary grants.—The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion.

217. Token grants.—When funds to meet proposed expenditure on a new service can be made available by reappropriation, a demand for the grant of a token sum may be submitted to the vote of the House and, if the

House assents to the demand, funds may be so made available.

APPROPRIATION BILL

218. Procedure regarding Appropriation Bill.—(1) Subject to the provision of the Constitution, the procedure in regard to an Appropriation Bill shall be the same as for Bills generally with such modifications as the Speaker may consider necessary.

¹[(2) *** ***)]

²[The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration.

(3) The Speaker may, in order to avoid repetition of debate, require members desiring to take part in discussion on an Appropriation Bill to give advance intimation of the specific points they intend to raise, and the Speaker may withhold permission for raising such of the points, as in the opinion of the Speaker appear to be repetitions of the matters discussed on a demand for grant or as may not be of sufficient public importance.

(4) If an Appropriation Bill is in pursuance of a supplementary grant in respect of an existing service, the discussion shall be confined to the items constituting the same, and no discussion shall be raised on the original grant nor the policy underlying it save in so far as it may be necessary to explain or illustrate a particular item under discussion.]

(5) The Speaker, if thinks fit, may prescribe a time-limit for speeches. ³[***]

FINANCE BILL

219. Procedure regarding Finance Bill.—(1) In this rule “Finance Bill” means the Bill ordinarily introduced in each year to give effect to the financial proposals of the Government of India for the next following financial year and includes a Bill to give effect to supplementary financial proposals for any period.

(2) At any time after the introduction in the House of a Finance Bill, the Speaker may allot a day or days, jointly or severally, for the completion of all or any of the stages involved in the passage of the Bill by the House, and when such allotment has been made, the Speaker ⁴[may, at the specified hour] on the allotted day or the last of the allotted days, as the case may be, forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the stage or stages for which the day or days have been allotted:

¹Omitted by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

²Renumbered *ibid*.

³Omitted by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

⁴Sub. *ibid*.

Provided that if a Minister has a right of reply to the debate on the motion which is under discussion ⁵[an hour before the specified hour] and has not commenced reply at that hour, the Speaker shall inquire how much time not exceeding one hour the Minister requires for the reply, and shall call upon any member for the time being addressing the House to resume seat at such time as will leave available before ⁶[the specified hour] the amount of time which the Minister has stated to require for the reply.

(3) Where the question or one of the questions required by sub-rule (2) to be put at ⁷[the specified hour] on the allotted day or the last of the allotted days is that the Bill be passed, sub-rule (2) shall have effect notwithstanding that amendments to the Bill have been made.

(4) Subject to the provision to sub-rule (2), the Speaker, if thinks fit, may prescribe a time-limit for speeches at all or any of the stages for which a day or days have been allotted under that sub-rule.

(5) On a motion that the Finance Bill be taken into consideration, a member may discuss matters relating to general administration, local grievances within the sphere of the responsibility of Government of India or monetary or financial policy of Government.

(6) In other respects the rules applicable to Bills in Chapter X of these rules shall apply.

GENERAL PROVISIONS REGARDING FINANCIAL BUSINESS

220. Business that can be taken up on day allotted for financial business.—Notwithstanding that a day has been allotted for financial business under rules 207, 208, 218 or 219, a motion or motions for leave to introduce a Bill or Bills may be made and a Bill or Bills may be introduced on such day before the House enters on the business for which the day has been allotted.

221. Timely completion of financial business.—In addition to the powers exercisable under these rules, the Speaker may exercise all such powers as are necessary for the purpose of the timely completion of all financial business including allotment of time for the disposal of various kinds of such business, and where time is so allotted, the Speaker shall, at the appointed hour, put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the stage or stages for which time has been allotted.

Explanation.—Financial business includes any business which the Speaker holds as coming within this category under the Constitution.

[For rules relating to Committees on Public Accounts, Estimates and Public Undertakings, *see* Chapter XXVI of these rules.]

CHAPTER XX

PRIVILEGES

QUESTIONS OF PRIVILEGE

222. Consent of Speaker.—A member may, with the consent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a Committee thereof.

223. Notice of question of privilege.—A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary-General ¹[by 10.00 hours] on the day the question is proposed to be raised. If the question raised is based on a document, the notice shall be accompanied by the document:

²[Provided that notices received after 10.00 hours shall be deemed to have been received at 10.00 hours on the next day on which the House sits.]

224. Admissibility of questions of privilege.—The right to raise a question of privilege shall be governed by the following conditions, namely:—

- (i) not more than one question shall be raised at the same sitting;
- (ii) the question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence; and
- (iii) the matter requires the intervention of the House.

225. Mode of raising questions of privilege.—(1) The Speaker, if gives consent under rule 222 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall call the member concerned, who shall rise in one's own place and, while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto:

Provided that where the Speaker has refused to give consent under rule 222 or is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, the Speaker, if thinks necessary, may read the notice of question of privilege and state that the consent is refused or the notice of question of privilege is not in order:

Provided further that the Speaker may, on being satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised at any time during the course of a sitting after the disposal of questions.

(2) If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than twenty-five members rise accordingly, the Speaker shall declare that leave is granted. If less than twenty-five members rise, the Speaker shall inform the member that such member has not the leave of the House.

⁵⁻⁷Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

¹Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

²Added *ibid.*

226. Questions of privilege to be considered by House or Committee.—If leave under rule 225 is granted, the House may consider the question and come to a decision or refer it to a Committee of Privileges on a motion made either by the member who has raised the question of privilege or by any other member.

227. Reference of questions of privilege to Committee by Speaker.—Notwithstanding anything contained in these rules, the Speaker may refer any question of privilege to the Committee of Privileges for examination, investigation or report.

228. Power of Speaker to give directions.—The Speaker may issue such directions as may be necessary for regulating the procedure in connection with all matters connected with the consideration of the question of privilege either in the Committee of Privileges or in the House.

INTIMATION TO SPEAKER REGARDING ARREST, DETENTION
ETC. AND RELEASE OF MEMBER

229. Intimation regarding arrest, detention etc. of member.—When a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or is sentenced to imprisonment by a court or is detained under an executive order, the committing judge, magistrate or executive authority, as the case may be, shall immediately intimate such fact to the Speaker indicating the reasons for the arrest, detention or conviction, as the case may be, as also the place of detention or imprisonment of the member in the appropriate form set out in the Third Schedule.

230. Intimation regarding release of member.—When a member is arrested and after conviction released on bail pending an appeal or otherwise released, such fact shall also be intimated to the Speaker by the authority concerned in the appropriate form set out in the Third Schedule.

231. Treatment of communications regarding arrest, detention, release etc.—As soon as may be, the Speaker shall, after receiving a communication referred to in rule 229 or rule 230, read it out in the House if in session, or if the House is not in session, direct that it may be published in the Bulletin for the information of the members:

Provided that if the intimation of the release of a member either on bail or by discharge on appeal is received before the House has been informed of the original arrest, the fact of her or his arrest, or her or his subsequent release or discharge may not be intimated to the House by the Speaker.

PROCEDURE REGARDING ARREST AND SERVICE OF LEGAL
PROCESS WITHIN PRECINCTS OF THE HOUSE

232. Arrest within precincts of House.—No arrest shall be made within the precincts of the House without obtaining the permission of the Speaker.

233. Service of legal process.—A legal process, civil

or criminal, shall not be served within the precincts of the House without obtaining the permission of Speaker.

[For rules relating to Committee of Privileges, see Chapter XXVI of these rules.]

CHAPTER XXI

SUBORDINATE LEGISLATION

234. Laying of Regulation rule etc. on Table.—(1) Where a regulation, rule, sub-rule, byelaw etc. framed in pursuance of the Constitution or of the legislative functions delegated by Parliament to a subordinate authority is laid before the House, the period specified in the Constitution or the relevant Act for which it is required to be laid shall be completed before the House is adjourned *sine die* and later prorogued, unless otherwise provided in the Constitution or the relevant Act.

(2) Where the specified period is not so completed the regulation, rule, sub-rule, bye-law etc. shall be relaid in the succeeding session or sessions until the said period is completed in one session.

235. Allotment of time for consideration of amendments to regulation, rule etc.—The Speaker shall, in consultation with the Leader of the House, fix a day or days or part of a day as the Speaker may think fit for the consideration and passing of an amendment to such regulation, rule, sub-rule, bye-law, etc., of which notice may be given by a member.

Provided that notice of the amendment shall be in such form as the Speaker may consider appropriate and shall comply with these rules.

236. Transmission of amendment to Council.—After an amendment is passed by the House, it shall be transmitted to the Council for its concurrence and on receipt of a message from the Council agreeing to the amendment, it shall be forwarded by the Secretary-General to the Minister concerned.

237. Amendment returned by Council.—If the Council disagrees with the amendment passed by the House or agrees subject to a further amendment thereof or proposes an amendment in substitution thereof, the House may either drop the amendment or agree with the Council in the proposed amendment or insist on the original amendment passed by the House. A message in either case shall be sent to the Council. In case the House agrees to the amendment as further amended by the Council, the amended amendment shall be forwarded by the Secretary-General to the Minister concerned.

238. Disagreement between Houses.—If the Council agrees to the original amendment passed by the House, it shall be sent by the Secretary-General to the Minister concerned, but if the Council disagrees or insists on an amendment to which the House has not agreed, the Houses shall be deemed to have finally disagreed, and all further proceedings thereon shall be dropped.

239. Laying of regulation rule etc. as amended on Table.—If a regulation, rule, sub-rule, bye-law etc. is modified in accordance with the amendment passed by the Houses, the amended regulation, rule, sub-rule, bye-law etc. shall be laid on the Table.

[For rules relating to Committee on Subordinate Legislation, *see* Chapter XXVI of these rules.]

CHAPTER XXII

RESIGNATION AND VACATION OF SEATS IN THE HOUSE

240. Resignation of seats in House.—(1) A member who desires to resign one's seat in the House shall intimate in writing under one's own hand addressed to the Speaker, such intention to resign the seat in the following form and shall not give any reason for the resignation:

'To

The Speaker,

Lok Sabha,

New Delhi.

Madam/Sir,

I hereby tender my resignation of my seat in the House with effect from.....

Yours faithfully,

Place..... Date..... Member of the House:'

Provided that where any member gives any reason or introduces any extraneous matter the Speaker may while exercising discretion omit such words, phrases or matter and the same shall not be read out in the House.

(1A) If a member hands over the letter of resignation to the Speaker personally and informs that the resignation is voluntary and genuine and the Speaker has no information or knowledge to the contrary, the Speaker may accept the resignation immediately.

(1B) If the Speaker receives the letter of resignation either by post or through someone else, the Speaker may make such inquiry as is considered necessary to get satisfied that the resignation is voluntary and genuine. If the Speaker, after making a summary enquiry either by oneself or through the agency of Lok Sabha Secretariat or through such other agency, as the Speaker may deem fit, is satisfied that the resignation is not voluntary or genuine, the Speaker shall not accept the resignation.

(1C) A member may withdraw the letter of resignation at any time before it is accepted by the Speaker.

(2) The Speaker shall, as soon as may be, after accepting the resignation of a member, inform the House about resignation of seat by the member and acceptance of such resignation.

Explanation.—When the House is not in session, the Speaker shall inform the House immediately after the House reassembles.

(3) The Secretary-General shall, as soon as may be, after the Speaker has accepted the resignation of a member, cause the information to be published in the Bulletin and the Gazette and forward a copy of the notification to the Election Commission for taking steps to fill the vacancy thus caused:

Provided that where the resignation is to take effect from a future date, the information shall be published in the Bulletin and the Gazette not earlier than the date from which it is to take effect.

241. Vacation of seats in House.—(1) The seat of a member shall be declared vacant under clause (4) of article 101 of the Constitution on a motion by the Leader of the House or by such other member to whom the functions are delegated in this behalf by the Leader of the House.

(2) If the motion referred to in sub-rule (1) is carried, the Secretary-General shall cause the information to be published in the Gazette and forward a copy of the notification to the Election Commission for taking steps to fill the vacancy thus caused.

CHAPTER XXIII

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

242. Application for leave of absence.—(1) A member desiring permission of the House to remain absent from the sittings thereof under clause (4) of article 101 of the Constitution shall make an application in writing to the Speaker.

(2) An application under sub-rule (1) shall specify the period for which leave of absence is required, indicating also the date of commencement and of termination of such leave of absence and the grounds for it:

Provided that leave of absence applied for at any one time shall not exceed a period of sixty days.

243. Reference of applications to Committee.—All applications under rule 242 shall stand referred to the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

244. Communication of decision of House to member.—The Secretary-General shall, as soon as may be, after a decision has been signified by the House on the recommendations of the Committee in respect of an application for leave of absence, communicate it to the member.

245. Lapse of unexpired portion of leave.—If a member who has been granted leave of absence under these rules attends the session of the House during the period for which the leave of absence has been granted to such member, the unexpired portion of the leave from the date on which the member resumed attendance shall lapse.

[For rules relating to Committee on Absence of Members from the Sittings of the House, *see* Chapter XXVI of these rules.]

CHAPTER XXIV COMMUNICATIONS BETWEEN PRESIDENT AND THE HOUSE

246. Communications from President to House.—

Communications from the President to the House shall be made to the Speaker by written message signed by the President or, if the President is absent from the place of sitting of the House, the message shall be conveyed to the Speaker through a Minister.

247. Communications from House to President.—

Communications from the House to the President shall be made—

- (i) by formal address, after motion made and carried in the House; and
- (ii) through the Speaker.

CHAPTER XXV SECRET SITTING OF THE HOUSE

248. Secret Sitting.—(1) On a request made by the Leader of the House, the Speaker shall fix a day or part thereof for sitting of the House in secret.

(2) When the House sits in secret no stranger shall be permitted to be present in the Chamber, Lobby or Galleries:

Provided that members of the Council may be present in their Gallery:

Provided further that persons authorised by the Speaker may be present in the Chamber, Lobby or Galleries.

249. Report of proceedings.—The Speaker may cause a report of the proceedings of a secret sitting to be issued in such manner as the Speaker thinks fit, but no other person present shall keep a note or record of any proceedings or decisions of a secret sitting, whether in part or full, or issue any report of, or purport to describe, such proceedings.

250. Procedure in other respects.—The procedure in all other respects in connection with a secret sitting shall be in accordance with such directions as the Speaker may give.

251. Lifting of ban on publication of proceedings.—

(1) When it is considered that the necessity for maintaining secrecy in regard to the proceedings of a secret sitting has ceased to exist and subject to the consent of the Speaker, the Leader of the House or any member so authorized may move a motion that the proceedings in the House during a secret sitting be no longer treated as secret.

(2) On adoption by the House of the motion under sub-rule (1), the Secretary-General shall cause to be prepared a report of the proceedings of the secret sitting, and shall, as soon as practicable, publish it in such form and manner as the Speaker may direct.

252. Disclosure of proceedings or decisions.—

Subject to the provisions of rule 251, disclosure of proceedings or decisions of a secret sitting by any person in any manner shall be treated as a gross breach of privilege of the House.

CHAPTER XXVI PARLIAMENTARY COMMITTEES

GENERAL RULES

253. Parliamentary Committee.—In this Chapter, unless the context otherwise requires, ‘Committee’ means and includes ‘Parliamentary Committee’ as defined in sub-rule (1) of rule 2.

254. Appointment of Committee.—(1) The members of a Committee shall be appointed or elected by the House on a motion made, or nominated by the Speaker as the case may be.

(2) No member shall be appointed to a Committee if unwilling to serve on it. The proposer shall ascertain whether the member whose name is being proposed is willing to serve on the Committee.

(3) Casual vacancies in a Committee shall be filled by appointment or election by the House on a motion made, or nomination by the Speaker, as the case may be, and any member appointed, elected or nominated to fill such vacancy shall hold office for the unexpired portion of the term for which the member in whose place, a member to fill the casual vacancy is appointed, elected or nominated would have normally held office.

255. Objection to membership of Committee.—

Where an objection is taken to the inclusion of a member in a Committee on the ground that the member has a personal, pecuniary or direct interest of such an intimate character that it may prejudicially affect the consideration of any matters to be considered by the Committee, the procedure shall be as follows:

(a) The member who has taken objection shall precisely state the ground of such objection and the nature of the alleged interest, whether personal, pecuniary or direct, of the proposed member in the matters coming up before the Committee;

(b) After the objection has been stated, the Speaker shall give an opportunity to the member proposed on the Committee against whom the objection has been taken to state the position;

(c) if there is dispute on facts, the Speaker may call upon the member taking objection and the member against whose appointment on the Committee objection has been taken, to produce documentary or other evidence in support of their respective cases;

(d) The Speaker, shall, after considering the evidence so tendered, give decision which shall be final;

(e) Until the Speaker has given the decision under clause (d), the member against whose appointment on the Committee objection has been taken shall continue to be a member thereof if elected or nominated and take part in discussion, but shall not be entitled to vote; and

(f) if the Speaker holds that the member against whose appointment objection has been taken has a personal, pecuniary or direct interest in the matter before the Committee, that member shall cease to be a member thereof forthwith:

Provided that the proceedings of the sitting of the Committee at which such member was present shall not in any way be affected by the decision of the Speaker.

Explanation.—For the purpose of this rule the interest of the member should be direct, personal or pecuniary and separately belong to the person whose inclusion in the Committee is objected to and not in common with the public in general or with any class or section thereof or on a matter of State policy.

256. Term of office of Committee nominated by Speaker.—A Committee nominated by the Speaker shall, unless otherwise specified in the rules contained in this Chapter, hold office for the period specified by the Speaker or until a new Committee is nominated.

257. ¹[Resignation from Committee.]—(1) A member may resign one's seat from a Committee by writing under own hand addressed to the Speaker, in the following form:

'To

The Speaker,

Lok Sabha,

New Delhi.

Madam/Sir,

I hereby tender my resignation from the membership of the Committee on..... with effect from.....

Yours faithfully,

Place..... Date..... (Name of the Member).'

(2) The resignation shall take effect from the date of resignation specified in the letter of resignation.

(3) If the date from which the resignation should take effect is not specified in the letter, the resignation shall take effect from the date of the letter.

(4) If the letter of resignation does not bear any date, the resignation shall take effect from the date of receipt of the letter in the Lok Sabha Secretariat.]

258. Chairperson of Committee.—(1) The Chairperson of a Committee shall be appointed by the Speaker from amongst members of the Committee:

Provided that the Deputy Speaker, in case is a member of the Committee, shall be appointed as Chairperson of the Committee.

(2) If the Chairperson is for any reason unable to act, the Speaker may appoint another Chairperson in her or his place.

(3) If the Chairperson is absent from any sitting, the Committee shall choose another member to act as Chairperson for that sitting.

259. Quorum in Committee.—(1) The quorum to constitute a sitting of a Committee shall be, as near as may be, one-third of the total number of members of the Committee.

(2) If at any time fixed for any sitting of the Committee, or if at any time during any such sitting, there is no quorum, the Chairperson of the Committee shall either suspend the sitting until there is a quorum or adjourn the sitting to some future day.

(3) When the Committee has been adjourned in pursuance of sub-rule (2) on two successive dates fixed for sittings of the Committee, the Chairperson shall report the fact to the House:

Provided that where the Committee has been appointed by the Speaker, the Chairperson shall report the fact of such adjournment to the Speaker.

260. Discharge of member absent from sittings of Committee.—If a member is absent from two or more consecutive sittings of a Committee without the permission of the Chairperson, a motion may be moved in the House for the discharge of such member from the Committee:

Provided that where the members of the Committee are nominated by the Speaker such member may be discharged by the Speaker.

261. Decisions in Committee.—All questions at any sitting of a Committee shall be determined by a majority of votes of the members present and voting.

262. Casting vote of Chairperson.—In the case of an equality of votes on any matter, the Chairperson or the person acting as such, shall have a second or casting vote.

263. Power to appoint sub-Committees.—(1) A Committee may appoint one or more sub-Committees, each having the powers of the undivided Committee, to examine any matters that may be referred to them and the reports of

¹Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

such sub-Committees shall be deemed to be the reports of the whole Committee, if they are approved at a sitting of the whole Committee.

(2) The order of reference to a sub-Committee shall clearly state the point or points for investigation. The report of the sub-Committee shall be considered by the whole Committee.

264. Sittings of Committee.—The sittings of a Committee shall be held on such days and at such hour as the Chairperson of the Committee may fix:

Provided that if the Chairperson of the Committee is not readily available, the Secretary-General may fix the date and time of a sitting:

Provided further that in the case of Select or Joint Committee on a Bill, if the Chairperson of the Committee is not readily available, the Secretary-General may, in consultation with the Minister concerned with the Bill, fix the date and time of a sitting.

265. Committee may sit whilst House sitting.—A Committee may sit whilst the House is sitting provided that on a division being called in the House, the Chairperson of the Committee shall suspend the proceedings in the Committee for such time as will in the opinion of the Chairperson, enable the members to vote in a division.

266. Sittings in private.—The sittings of a Committee shall be held in private.

267. Venue of Sittings.—The sittings of a Committee shall be held within the precincts of the Parliament House, and if it becomes necessary to change the place of sitting outside the Parliament House, the matter shall be referred to the Speaker whose decision shall be final.

268. Strangers to withdraw when Committee deliberates.—All persons other than members of the Committee and officers of the Lok Sabha Secretariat shall withdraw whenever the Committee is deliberating.

269. Power to take evidence or call for documents.—(1) A witness may be summoned by an order signed by the Secretary-General and shall produce such documents as are required for the use of a Committee.

(2) It shall be in the discretion of the Committee to treat any evidence given before it as secret or confidential.

(3) No document submitted to the Committee shall be withdrawn or altered without the knowledge and approval of the Committee.

270. Power to send for persons, papers and records.—A Committee shall have power to send for persons, papers and records:

Provided that if any question arises whether the evidence of a person or the production of a document is relevant for the purposes of the Committee, the question shall be referred to the Speaker whose decision shall be final:

Provided further that Government may decline to produce a document on the ground that its disclosure would be prejudicial to the safety or interest of the State.

271. Counsel for witness.—A Committee may, under the direction of the Speaker, permit a witness to be heard by a counsel appointed by the witness and approved by the Committee.

272. Evidence on oath.—(1) A Committee may administer oath or affirmation to a witness examined before it.

(2) The form of the oath or affirmation shall be as follows:

‘I, A.B., swear in the name of God that the
Solemnly affirm

evidence which I shall give in this case shall be true, that I will conceal nothing, and that no part of my evidence shall be false.’

273. Examination of witnesses.—The examination of witnesses before a Committee shall be conducted as follows:—

(i) The Committee shall, before a witness is called for examination, decide the mode of procedure and the nature of question that may be asked of the witness.

(ii) The Chairperson of the Committee may first ask the witness such question or questions, as is considered necessary by the Chairperson, with reference to the subject matter under consideration or any subject connected therewith according to the mode of procedure mentioned in clause (i) of this rule.

(iii) The Chairperson may call other members of the Committee one by one to ask any other questions.

(iv) A witness may be asked to place before the Committee any other relevant points that have not been covered and which a witness thinks are essential to be placed before the Committee.

(v) A verbatim record of proceedings of the Committee shall, when a witness is summoned to give evidence, be kept.

(vi) The evidence given before the Committee may be made available to all members of the Committee.

274. Record of decisions.—A record of the decisions of a Committee shall be maintained and circulated to members of the Committee under the direction of the Chairperson.

275. Evidence, report and proceedings treated as confidential.—(1) A Committee may direct that the whole or a part of the evidence or a summary thereof may be laid on the Table.

(2) No part of the evidence, oral or written, report or proceedings of the Committee which has not been laid on the Table shall be open to inspection by any one except under the authority of the Speaker.

(3) The evidence given before a Committee shall not be published by any member of the Committee or by any other person until it has been laid on the Table:

Provided that the Speaker may, while exercising discretion direct that such evidence be confidentially made available to members before it is formally laid on the Table.

276. Special Report.—A Committee may, if it thinks fit, make a special report on any matter that arises or comes to light in the course of its work which it may consider necessary to bring to the notice of the Speaker or the House, notwithstanding that such matter is not directly connected with, or does not fall within or is not incidental to, its terms of reference.

277. Report.—(1) Where the House has not fixed any time for the presentation of a report by a Committee the report shall be presented within one month of the date on which reference to the Committee was made:

Provided that the House may at any time, on a motion being made, direct that the time for the presentation of the report by the Committee be extended to a date specified in the motion.

(2) Reports may be either preliminary or final.

(3) The report of the Committee shall be signed by the Chairperson on behalf of the Committee:

Provided that in case the Chairperson is absent or is not readily available the Committee shall choose another member to sign the report on behalf of the Committee.

278. Availability of report to Government before presentation.—A Committee may, if it thinks fit, make available to Government any completed part of its report before presentation to the House. Such reports shall be treated as confidential until presented to the House.

279. Presentation of report.—(1) The report of a Committee shall be presented to the House by the Chairperson or in the absence of the Chairperson by any member of the Committee.

(2) In presenting the report the Chairperson or, in the absence of the Chairperson, the member presenting the report shall, if makes any remarks, confine to a brief statement of fact, but there shall be no debate on that statement at this stage.

280. Printing publication or circulation of report before presentation.—On a request being made and when the House is not in session, the Speaker may, order the printing, publication or circulation of a report of a Committee although it has not been presented to the House. In that case the report shall be presented to the House during its next session at the first convenient opportunity.

281. Power to make suggestions on procedure.—A Committee shall have power to pass resolutions on matters of procedure relating to that Committee for the consideration of the Speaker, who may make such variations in procedure as the Speaker may consider necessary.

282. Power to make detailed rules.—A Committee may with the approval of the Speaker make detailed rules of procedure to supplement the provisions contained in the rules in this Chapter.

283. Power of Speaker to give directions.—(1) The Speaker may from time to time issue such directions to the Chairperson of a Committee, as the Speaker considers necessary, for regulating its procedure and the organisation of its work.

(2) If any doubt arises on any point of procedure or otherwise, the Chairperson may if thinks fit, refer the point to the Speaker whose decision shall be final.

284. Business before Committee not to lapse on prorogation on House.—Any business pending before a Committee shall not lapse by reason only of the prorogation of the House and the Committee shall continue to function notwithstanding such prorogation.

285. Unfinished work of Committee.—A Committee which is unable to complete its work before the expiration of its term or before the dissolution of the House may report to the House that the Committee has not been able to complete its work. Any preliminary report, memorandum or note that the Committee may have prepared or any evidence that the Committee may have taken shall be made available to the new Committee.

286. Applicability of general rules to Committees.—Except for matters for which special provision is made in the rules relating to any particular Committee, the general rules in this Chapter shall apply to all Committees; and if and so far as any provision in the special rules relating to a Committee is inconsistent with the general rules, the former rules shall prevail.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

287. Constitution.—At the commencement of the House or from time to time, as the case may be, the Speaker may nominate a Committee called the Business Advisory Committee consisting of not more than fifteen members including the Speaker who shall be the Chairperson of the Committee.

288. Functions.—(1) It shall be the function of the Committee to recommend the time that should be allocated for the discussion of the stage or stages of such Government Bills and other business as the Speaker, in consultation with the Leader of the House, may direct for being referred to the Committee.

(2) The Committee shall have the power to indicate in the proposed time-table the different hours at which the various stages of the Bill or other business shall be completed.

(3) The Committee shall have such other functions as may be assigned to it by the Speaker from time to time.

Explanation.—The expression other business referred to in this rule and rules 290A and 291 means business, other than private members' Bills under rule 65 and private members' resolutions under rule 170.

289. Report.—The recommendations of the Committee shall be presented to the House in the form of a report.

290. Motion in House after presentation of report.—At any time after the report has been presented to the House a motion may be moved that the House agrees or agrees with amendments or disagrees with the report:

Provided that an amendment may be moved that the report be referred back to the Committee either without limitation or with reference to any particular matter:

Provided further that not more than half an hour shall be allotted for the discussion of the motion and no member shall speak for more than five minutes on such motion.

290A. Notification of Allocation of Time Order.—The allocation of time in respect of Bills and other business as approved by the House shall take effect as if it were an order of the House and shall be notified in the Bulletin.

291. Disposal of outstanding matters at appointed hour.—At the appointed hour, in accordance with the Allocation of Time Order for the completion of a particular stage of a Bill or other business, the Speaker shall forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with that stage of the Bill or other business.

292. Variation in Allocation of Time Order.—No variation in the Allocation of Time Order shall be made except on a motion made, with the consent of the Speaker, and accepted by the House:

Provided that the Speaker may, after taking the sense of the House, increase the time, not exceeding one hour, without any motion being moved.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

293. Consitution.—(1) There shall be a Committee on Private Members' Bills and Resolutions consisting of not more than fifteen members.

(2) The Committee shall be nominated by the Speaker and shall hold office for a term not exceeding one year.

294. Function.—(1) The functions of the Committee shall be—

(a) to examine every Bill seeking to amend the Constitution notice of which has been given by a private member, before a motion for leave to introduce the Bill is included in the list of business;

(b) to examine all private members' Bills after they are introduced and before they are taken up for consideration in the House and to classify them according to their nature, urgency and importance into two categories namely, category A and category B;

(c) to recommend the time that should be allocated for the discussion of the stage or stages of each private member's Bill and also to indicate in the time-table so drawn up the different hours at which various stages of the Bill in a day shall be completed;

(d) to examine every private member's Bill which is opposed in the House on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, and the Speaker considers such objection *prima facie* tenable;

(e) to recommend time-limit for the discussion of private members' resolutions and other ancillary matters.

(2) The Committee shall perform such other functions in respect of private members' Bills and resolutions as may be assigned to it by the Speaker from time to time.

295. Motion in House after presentation of report.—At any time after the report has been presented to the House a motion may be moved that the House agrees or agrees with amendments or disagrees with the report:

Provided that an amendment may be moved that the report be referred back to the Committee either without limitation or with reference to any particular matter:

Provided further that not more than half an hour shall be allotted for discussion of the motion and no member shall speak for more than five minutes on such motion.

296. Classification and Allocation of Time.—The classification of Bills and the allocation of time in respect of Bills and resolutions as approved by the House shall take effect as if it were an order of the House.

297. Disposal of outstanding matters at appointed hour.—At the appointed hour, in accordance with the Allocation of Time Order, the Speaker shall forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the completion of a particular stage of the Bill or the resolution.

SELECT COMMITTEE ON BILLS

298. Constitution.—The members of a Select Committee on a Bill shall be appointed by the House when a motion that the Bill be referred to a Select Committee is made.

299. Presence of other members at sittings.—Members who are not members of the Select Committee may be present during the deliberations of the Committee but shall not address the Committee or sit in the body of the Committee:

Provided that a Minister may with the permission of the Chairperson address the Committee of which such Minister may not be a member.

300. Notice of amendments and procedure generally.—(1) If notice of a proposed amendment has not been given before the day on which the Bill is taken up by the Select Committee, any member may object to the moving of the amendment and such objection shall prevail unless the Chairperson allows the amendment to be moved.

(2) In other respects, the procedure in a Select Committee shall, as far as practicable, be the same as is followed in the House during the consideration stage of a Bill, with such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as the Speaker may consider necessary or convenient.

301. Notice of amendments by other members.—When a Bill has been referred to a Select Committee any notice given by a member of any amendment to a clause in the Bill shall stand referred to the Committee provided that where notice of amendment is received from a member who is not a member of the Select Committee such amendment shall not be taken up by the Committee unless moved by member of the Committee.

302. Power to take evidence.—A Select Committee may hear expert evidence and representatives of special interests affected by the measure before them.

303. Report.—(1) As soon as may be, after a Bill has been referred to a Select Committee, the Select Committee shall meet from time to time in accordance with rule 264 to consider the Bill and shall make a report thereon within the time fixed by the House:

Provided that where the House has not fixed any time for the presentation of the report by a Select Committee, the report shall be presented before the expiry of three months from the date on which the House adopted the motion for the reference of the Bill to the Select Committee:

Provided further that the House may at any time, on a motion being made, direct that the time for the presentation of the report by the Select Committee be extended to a date specified in the motion.

(2) The Select Committee shall in their report state whether the publication of the Bill directed by these rules has taken place, and the date on which the publication has taken place.

(3) Where a Bill has been altered, the Select Committee may, if they think fit, include in their report a recommendation to the member incharge of the Bill that the next motion of such member should be a motion for circulation, or, where the Bill has already been circulated, for recirculation.

(4) Any member of the Select Committee may record a minute of dissent on any matter or matters connected with the Bill or dealt with in the report.

(5) A minute of dissent shall be couched in temperate and decorous language and shall not refer to any discussion in the Select Committee nor cast aspersion on the Committee.

(6) If in the opinion of the Speaker a minute of dissent contains words, phrases or expressions which are unparliamentary or otherwise inappropriate, the Speaker may order such words, phrases or expressions to be expunged from the minute of dissent.

304. Presentation of report.—The report of the Select Committee on a Bill together with the minutes of dissent, if any, shall be presented to the House by the Chairperson or in the absence of the Chairperson, by any member of the Committee.

305. Printing and publication of reports.—The Secretary-General shall cause every report of a Select Committee to be printed, and a copy of the report shall be made available for the use of every member of the House. The report, and the Bill, as reported by the Select Committee, shall be published in the Gazette.

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

305A. Constitution.—(1) There shall be a Committee on Papers Laid on the Table consisting of not more than 15 members.

(2) The Committee shall be nominated by the Speaker and shall hold office for a term not exceeding one year.

305B. Functions.—(1) The functions of the Committee shall be to examine all papers laid on the Table of the House by Ministers and to report to the House on—

(a) whether there has been compliance of the provisions of the Constitution, Act, rule or regulation under which the paper has been laid;

(b) whether there has been any unreasonable delay in laying the paper;

(c) if there has been such delay, whether a statement explaining the reasons for delay has been laid on the Table of the House and whether those reasons are satisfactory;

(d) whether both the Hindi and English versions of the paper have been laid on the Table; and

(e) whether a statement explaining the reason for not laying the Hindi version has been given and whether such reasons are satisfactory.

(2) The Committee shall perform such other functions in respect of the papers laid on the Table as may be assigned to it by the Speaker from time to time.

305C. Restriction on raising matters in House about papers laid.—A member wishing to raise any of the matters referred to in sub-rule (1) of rule 305B shall refer it to the Committee and not raise it in the House.

COMMITTEE ON PETITIONS

306. Constitution.—At the commencement of the House, or from time to time, as the case may be, the Speaker shall nominate a Committee on Petitions consisting of not less than fifteen members:

Provided that a Minister shall not be nominated a member of the Committee, and where a member, after nomination to the Committee is appointed a Minister, such member shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

307. Functions.—(1) The Committee shall examine every petition referred to it, and if the petition complies with these rules, the Committee may direct that it be circulated. Where circulation of the petition has not been directed, the Speaker may at any time direct that the petition be circulated.

(2) Circulation of the petition shall be *in extenso* or in summary form as the Committee or the Speaker, as the case may be, may direct.

(3) It shall also be the duty of the Committee to report to the House on specific complaints made in the petition referred to it after taking such evidence as it deems fit and to suggest remedial measures either in a concrete form applicable to the case under review or to prevent such cases in future.

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

308. Functions.—(1) There shall be a Committee on Public Accounts for the examination of accounts showing the appropriation of sums granted by the House for the expenditure of the Government of India, the annual finance accounts of the Government of India and such other accounts laid before the House as the Committee may think fit.

(2) In scrutinising the Appropriation Accounts of the Government of India and the report of the Comptroller and Auditor-General thereon, it shall be the duty of the Committee to satisfy itself—

(a) that the moneys shown in the accounts as having been disbursed were legally available for, and applicable to, the service or purpose to which they have been applied or charged;

(b) that the expenditure conforms to the authority which governs it; and

(c) that every re-appropriation has been made in accordance with the provisions made in this behalf under rules framed by competent authority.

(3) It shall also be the duty of the Committee—

(a) to examine the statement of accounts showing the income and expenditure of State corporations, trading

and manufacturing schemes, concerns and projects together with the balance sheets and statements of profit and loss accounts which the President may have required to be prepared or are prepared under provisions of the statutory rules regulating the financing of a particular corporation, trading or manufacturing scheme or concern or project and the report of the Comptroller and Auditor-General thereon;

(b) to examine the statement of accounts showing the income and expenditure of autonomous and semi-autonomous bodies, the audit of which may be conducted by the Comptroller and Auditor-General of India either under the directions of the President or by a statute of Parliament; and

(c) to consider the report of the Comptroller and Auditor-General in cases where the President may have required the Comptroller and Auditor-General to conduct an audit of any receipts or to examine the accounts of stores and stocks.

(4) If any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted by the House for that purpose, the Committee shall examine with reference to the facts of each case the circumstances leading to such an excess and make such recommendation as it may deem fit:

Provided that the Committee shall not exercise its functions in relation to such public undertakings as are allotted to the Committee on Public Undertakings by these rules or by the Speaker.

309. Constitution.—(1) The Committee shall consist of not more than ²[22 members comprising 15 members who shall be elected by the House every year from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote ^{2A}[and not more than 7 members of Rajya Sabha to be nominated by that House for being associated with the Committee:]

Provided that a Minister shall not be elected a member of the Committee, and if a member, after election to the Committee, is appointed a Minister, such member shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(2) The term of office of members of the Committee shall not exceed one year.

COMMITTEE ON ESTIMATES

310. Functions.—There shall be a Committee on Estimates for the examination of such of the estimates as may seem fit to the Committee or are specifically referred to it by the House or the Speaker. The functions of the Committee shall be—

²Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

^{2A}Added *ibid*.

(a) to report what economies, improvements in organisation, efficiency or administrative reform, consistent with the policy underlying the estimates, may be effected;

(b) to suggest alternative policies in order to bring about efficiency and economy in administration;

(c) to examine whether the money is well laid out within the limits of the policy implied in the estimates; and

(d) to suggest the form in which the estimates shall be presented to Parliament:

Provided that the Committee shall not exercise its functions in relation to such public undertakings as are allotted to the Committee on Public Undertakings by these rules or by the Speaker.

311. Constitution.—(1) The Committee shall consist of not more than thirty members who shall be elected by the House every year from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote:

Provided that a Minister shall not be elected a member of the Committee, and if a member, after election to the Committee, is appointed a Minister, such member shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(2) The term of office of members of the Committee shall not exceed one year.

312. Examination of estimates.—The Committee may continue the examination of the estimates from time to time throughout the financial year and report to the House as its examination proceeds. It shall not be incumbent on the Committee to examine the entire estimates of any one year. The Demands for Grants may be finally voted notwithstanding the fact that the Committee has made no report.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

312A. Functions.—There shall be a Committee on Public Undertakings for the examination of the working of the public undertakings specified in the Fourth Schedule. The functions of the Committee shall be—

(a) to examine the reports and accounts of the public undertakings specified in the Fourth Schedule;

(b) to examine the reports, if any, of the Comptroller and Auditor-General on the public undertakings;

(c) to examine, in the context of the autonomy and efficiency of the public undertakings, whether the affairs of the public undertakings are being managed in accordance with sound business principles and prudent commercial practices; and

(d) to exercise such other functions vested in the Committee on Public Accounts and the Committee on Estimates in relation to the public undertakings specified in the Fourth Schedule as are not covered by clauses (a), (b) and (c) above and as may be allotted to the Committee by the Speaker from time to time:

Provided that the Committee shall not examine and investigate any of the following, namely:—

(i) matters of major Government policy as distinct from business or commercial functions of the public undertakings;

(ii) matters of day-to-day administration; and

(iii) matters for the consideration of which machinery is established by any special statute under which a particular public undertaking is established.

312B. Constitution.—(1) The Committee shall consist of not more than ³[22 members comprising 15 members] who shall be elected by the House every year from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote ⁴[and not more than 7 members of Rajya Sabha to be nominated by that House for being associated with the Committee]:

Provided that a Minister shall not be elected a member of the Committee, and if a member, after election to the Committee, is appointed a Minister, such member shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(2) The term of office of members of the Committee shall not exceed one year.

⁵[*** *** ***]

COMMITTEE OF PRIVILEGES

313. Constitution.—At the commencement of the House or from time to time, as the case may be, the Speaker shall nominate a Committee of Privileges consisting of not more than fifteen members.

314. Functions.—(1) The Committee shall examine every question referred to it and determine with reference to the facts of each case whether a breach of privilege is involved and, if so, the nature of the breach, the circumstances leading to it and make such recommendations as it may deem fit.

(2) The report may also state the procedure to be followed by the House in giving effect to the recommendations made by the Committee.

315. Consideration of report by House.—(1) After the report has been presented, the Chairperson or any

³Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

⁴Added *ibid*.

⁵Omitted by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

member of the Committee or any other member may move that the report be taken into consideration whereupon the Speaker may put the question to the House.

(2) Before putting the question to the House, the Speaker may permit a debate on the motion, not exceeding half an hour in duration, and such debate shall not refer to the details of the report further than is necessary to make out a case for the consideration of the report by the House.

(3) After the motion made under sub-rule (1) is agreed to, the Chairperson or any member of the Committee or any other member, as the case may be, may move that the House agrees, or disagrees or agrees with amendments, with the recommendations contained in the report.

316. Priority for consideration of report by House.—

A motion that the report of the Committee be taken into consideration shall be accorded the priority assigned to a matter of privilege under sub-rule (1) of rule 225, unless there has been undue delay in bringing it forward:

Provided that when a date has already been fixed for the consideration of the report, it shall be given priority as a matter of privilege on the day so appointed.

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

317. Functions.—There shall be a Committee on Subordinate Legislation to scrutinize and report to the House whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, bye-laws etc., conferred by the Constitution or delegated by Parliament are being properly exercised within such delegation.

318. Consitution.—(1) The Committee shall consist of not more than fifteen members who shall be nominated by the Speaker:

Provided that a Minister shall not be nominated a member of the Committee, and if a member, after nomination to the Committee is appointed a Minister, such member shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(2) The term of office of members of the Committee shall not exceed one year.

319. Numbering and publication of Orders.—Each regulation, rule, sub-rule, bye-law etc. framed in pursuance of the provisions of the Constitution or the legislative functions delegated by Parliament to a subordinate authority, and which is required to be laid before the House, hereinafter referred to as “Order”, shall, subject to such rules as the Speaker may in consultation with the Leader of the House prescribe, be numbered centrally and published in the Gazette immediately after it is promulgated.

320. Examination of Orders.—After each such Order referred to in rule 319 is laid before the House, the Committee shall, in particular, consider—

(i) whether it is in accord with the general objects of the Constitution or the Act pursuant to which it is made;

(ii) whether it contains matter which in the opinion of the Committee should more properly be dealt with in an Act of Parliament.

(iii) whether it contains imposition of any tax;

(iv) whether it directly or indirectly bars the jurisdiction of the courts;

(v) whether it gives retrospective effect to any of the provisions in respect of which the Constitution or the Act does not expressly give any such power;

(vi) whether it involves expenditure from the Consolidated Fund of India or the public revenues;

(vii) whether it appears to make some unusual or unexpected use of the powers conferred by the Constitution or the Act pursuant to which it is made;

(viii) whether there appears to have been unjustifiable delay in its publication or in laying it before Parliament; and

(ix) whether for any reason its form or purport calls for any elucidation.

321. Report.—(1) If the Committee is of opinion that any Order should be annulled wholly or in part, or should be amended in any respect, it shall report that opinion and the grounds thereof to the House.

(2) If the Committee is of opinion that any other matter relating to any Orders should be brought to the notice of the House, it may report that opinion and matter to the House.

322. Power of Speaker to give directions.—The Speaker may issue such directions as may be considered necessary for regulating the procedure in connection with all matters connected with the consideration of any question of Subordinate Legislation either in the Committee or in the House.

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

323. Functions.—There shall be a Committee on Government Assurances to scrutinise the assurances, promises, undertakings, etc., given by Ministers, from time to time, on the floor of the House and to report on—

(a) the extent to which such assurances, promises, undertakings, etc. have been implemented; and

(b) where implemented whether such implementation has taken place within the minimum time necessary for the purpose.

324. Constitution.—(1) The Committee shall consist of not more than fifteen members who shall be nominated by the Speaker:

Provided that a Minister shall not be nominated a member of the Committee, and if a member, after nomination to the Committee is appointed a Minister, such member shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(2) The term of office of members of the Committee shall not exceed one year.

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE
SITTINGS OF THE HOUSE

325. Constitution.—The Committee on Absence of Members from the sittings of the House shall consist of fifteen members nominated by the Speaker and shall hold office for a term not exceeding one year.

326. Functions.—(1) The functions of the Committee shall be:—

(i) to consider all applications from members for leave of absence from the sittings of the House; and

(ii) to examine every case where a member has been absent for a period of sixty days or more, without permission, from the sittings of the House and to report whether the absence should be condoned or circumstances of the case justify that the House should declare the seat of the member vacant.

(2) The Committee shall perform such other functions in respect of attendance of members in the House as may be assigned to it by the Speaker from time to time.

327. Pleasure of House taken where leave of absence recommended.—Where the Committee recommends that leave of absence be granted to a member or the absence be condoned, as the case may be, the pleasure of the House shall be taken by the Speaker in the following terms on a day as soon as may be after the presentation of the report:—

‘The Committee on Absence of Members from the Sittings of the House in its...report has recommended that leave of absence be granted or absence be condoned (as the case may be) in respect of Smt./ Kumari/ Shri..... for the period indicated in the report.

The member is being informed accordingly.’

328. Motion where leave of absence not recommended.—Where leave of absence is not recommended by the Committee in respect of any application, a motion may be moved by any member that the House agrees or agrees with amendment or disagrees with the recommendations of the Committee in respect of that application.

RULES COMMITTEE

329. Functions.—There shall be a Committee on Rules to consider matters of procedure and conduct of business in the House and to recommend any amendments or additions to these rules that may be deemed necessary.

330. Constitution.—The Committee on Rules shall be nominated by the Speaker and shall consist of fifteen members including the Chairperson of the Committee. The

Speaker shall be the *ex-officio* Chairperson of the Committee.

331. Laying of report on Table.—(1) The recommendations of the Committee shall be laid on the Table and within a period of seven days, beginning with the day on which they are so laid, any member may give notice of any amendment to such recommendations.

(2) Any notice given by a member of any amendment to the recommendations of the Committee shall stand referred to the Committee who shall consider it and make such changes in their recommendations as the Committee may consider fit. The final report of the Committee after taking into consideration the amendments suggested by the members shall be laid on the Table. Thereafter, on the House agreeing to the report on a motion made by a member of the Committee, the amendments to the rules as approved by the House, shall be promulgated by the Speaker in the Bulletin.

(3) If notice of such amendment has not been given within seven days, the recommendations of the Committee shall be deemed to have been approved by the House and on the expiry of the said period the Speaker shall promulgate in the Bulletin the amendments to the rules as recommended by the Committee.

(4) The amendments to the rules shall come into force on their publication in the Bulletin unless otherwise specified.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES
AND SCHEDULED TRIBES

331A. Functions.—There shall be a Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The functions of the Committee shall be:—

(a) to consider the reports submitted by the National Commission for the Scheduled Castes under article 338(5)(d) and the ^{5A}[National Commission for the Scheduled Tribes under article 338A(5)(d)] of the Constitution and to report as to the measures that should be taken by the Union Government in respect of matters within the purview of the Union Government including the Administrations of the Union Territories;

(b) to report on the action taken by the Union Government and the Administrations of the Union Territories on the measures proposed by the Committee;

(c) to examine the measures taken by the Union Government to secure due representation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services and posts under its control (including appointments in the Public Sector Undertakings, Statutory and Semi-Government Bodies and in the Union Territories) having regard to the provisions of article 335;

^{5A}Sub. by L.S. Bn. (II) dated 19.3.2010, para 1265.

(d) to report on the working of the welfare programmes for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Union Territories; and

(e) to examine such other matters as may seem fit to the Committee or are specifically referred to it by the House or the Speaker.

331B. Constitution.—(1) The Committee shall consist of not more than ⁶[30 members, comprising 20 members] who shall be elected by the House every year from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote ⁷[and not more than 10 members of Rajya Sabha to be nominated by that House for being associated with the Committee];

Provided that a Minister shall not be elected a member of the Committee, and if a member, after election to the Committee, is appointed a Minister, such member shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(2) The term of office of members of the Committee shall not exceed one year.

⁸[*** *** ***]

⁹[DEPARTMENTALLY RELATED STANDING COMMITTEE]

331C. Departmentally related Standing Committees.—(1) There shall be Departmentally Related Standing Committees of the Houses (to be called the Standing Committees).

(2) The Ministries/Departments covered under the jurisdiction of each of the Standing Committees shall be as specified in the Fifth Schedule:

Provided that the Chairperson, Rajya Sabha and the Speaker may alter the said Schedule from time to time in consultation with each other.

331D. Constitution.—(1) Each of the Standing Committees constituted under Rule 331C shall consist of not more than ¹⁰[31 members, 21 members to be nominated by the Speaker from amongst the members of Lok Sabha and 10] members to be nominated by the Chairperson, Rajya Sabha, from amongst the members of Rajya Sabha.

(2) A Minister shall not be nominated as a member of the Committee, and if a member after nomination to the Committee is appointed a Minister, such member shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(3) The Chairperson of Committees as specified in Part I of Fifth Schedule shall be appointed by the Chairperson, Rajya Sabha and Chairperson of Committees as specified in Part II of the said Schedule shall be appointed

by the Speaker, from amongst the members of the Committees.

(4) The term of office of the members of the Committees shall not exceed one year.

331E. Functions.—(1) The functions of each of the Standing Committees shall be:—

(a) to consider the Demands for Grants of the concerned Ministries/ Departments and make a report on the same to the Houses. The report shall not suggest anything of the nature of cut motions;

(b) to examine such Bills pertaining to the concerned Ministries/Departments as are referred to the Committee by the Chairperson, Rajya Sabha or the Speaker, as the case may be, and make report thereon;

(c) to consider annual reports of Ministries/ Departments and make reports thereon;

(d) to consider national basic long term policy documents presented to the Houses, if referred to the Committee by the Chairperson, Rajya Sabha or the Speaker, as the case may be, and make reports thereon.

(2) The Standing Committees shall not consider the matters of day to day administration of the concerned Ministries/Departments.

331F. Applicability of provisions relating to functions.—Each of the functions of these Committees as provided in clauses (a) to (d) of sub-rule(1) of rule 331E shall be applicable to the Committees from the date as may be notified by the Chairperson, Rajya Sabha and the Speaker in respect of applicability of particular function.

331G. Procedure relating to Demands for Grants.—The following procedure shall be followed by each of the Standing Committees in their consideration of the Demands for Grants and making a report thereon to the Houses:—

(a) after the general discussion on the Budget in the Houses is over, the Houses shall be adjourned for a fixed period;

(b) the Committees shall consider the Demands for Grants of the concerned Ministries during the aforesaid period;

(c) the Committees shall make their report within the period and shall not ask for more time;

(d) the Demands for Grants shall be considered by the House in the light of the reports of the Committees; and

(e) there shall be a separate report on the Demands for Grants of each Ministry.

⁶Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

⁷Added *ibid*.

⁸Omitted by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

⁹Sub. by L.S. Bn. (II) dated 29.3.1993, para 1921.

¹⁰Sub. by L.S. Bn. (II) dated 20.7.2004, para 253.

331H. Procedure relating to Bills.—The following procedure shall be followed by each of the Standing Committees in examining the Bills and making report thereon:—

(a) the Committee shall consider the general principles and clauses of the Bills referred to them and make report thereon;

(b) the Committee shall consider only such Bills introduced in either of the Houses as are referred to them by the Chairperson, Rajya Sabha or the Speaker, as the case may be; and

(c) the Committee shall make report on the Bills in the given time.

331I. Reports of the Committees.—(1) The Reports of the Committees shall be based on broad consensus.

(2) A Member of a Standing Committee may give note of dissent on the report of the Committee.

(3) The note of dissent shall be presented to the House along with the report.

331J. Applicability of General Rules.—Except for matters for which special provision is made in the rule relating to the Standing Committees, the general rules applicable to other Parliamentary Committees in Rajya Sabha shall apply *mutatis mutandis* to the Standing Committees specified in Part-I of the Fifth Schedule and the general rules applicable to other Parliamentary Committees in Lok Sabha shall apply to Standing Committees as specified in Part-II of the Schedule.

331K. Venue of sittings.—The Standing Committees shall not work in any other place except the precincts of Parliament House, unless otherwise specifically permitted by the Chairperson, Rajya Sabha or the Speaker, as the case may be.

331L. Power to have expert opinion.—The Committee may avail of the expert opinion or the public opinion to make the report.

331M. Matters not to be considered.—The Standing Committees shall not generally consider the matters which are considered by the other Parliamentary Committees.

331N. Reports to have persuasive value.—The report of the Standing Committees shall have persuasive value and shall be treated as considered advice given by the Committees.]

¹¹[COMMITTEE ON THE EMPOWERMENT OF WOMEN

331 O. Constitution.—(1) There shall be a Committee on the Empowerment of Women—

(2) The Committee shall consist of not more than 30 Members, 20 Members to be nominated by the Speaker from amongst the Members of Lok Sabha and 10 Members to be nominated by the Chairperson, Rajya Sabha, from amongst the Members of Rajya Sabha.

(3) A Minister shall not be a Member of the Committee, and if a Member, after nomination to the Committee is appointed as Minister, such member shall cease to be a Member of the Committee from the date of such appointment.

(4) The Chairperson of the Committee shall be appointed by the Speaker from amongst the Members of the Committee.

(5) The term of office of Members of the Committee shall not exceed one year.

331P. Functions.—The functions of the Committee shall be—

(1) to consider the reports submitted by the National Commission for Women and to report on the measures that should be taken by the Union Government for improving the status/conditions of women in respect of matters within the purview of the Union Government including the Administrations of the Union Territories;

(2) to examine the measures taken by the Union Government to secure for women equality, status and dignity in all matters;

(3) to examine the measures taken by the Union Government for comprehensive education and adequate representation of women in Legislative bodies/services and other fields;

(4) to report on the working of the welfare programmes for the women;

(5) to report on the action taken by the Union Government and Administrations of the Union Territories on the measures proposed by the Committee; and

(6) to examine such other matters as may seem fit to the Committee or are specifically referred to it by the House or the Speaker and the Rajya Sabha or the Chairperson, Rajya Sabha.

331Q. Matters not to be considered by other Committees.—The other Parliamentary Committees, including the Departmentally related Standing Committees, shall not, as far as possible, consider the matters which are exclusively assigned to this Committee under the rules.]

¹¹Added by L.S. Bn. (II) dated 6.3.1997, para 1003.

CHAPTER XXVII

GENERAL RULES OF PROCEDURE

NOTICES

332. Mode of giving notice.—(1) Every notice required by these rules shall be given in writing addressed to the Secretary-General and signed by the member giving notice, and shall be left at the Parliamentary Notice Office which shall be kept open for this purpose between the hours to be notified from time to time on every day except Sunday or a public holiday.

(2) Notices left at the Parliamentary Notice Office after the hours notified under sub-rule (1) shall be treated as given on the next day.

333. Contingent Notice.—(1) A member may give notice of a motion or resolution or Bill which the member may desire to be taken up on the conclusion of other business on which that motion is contingent and if such a notice is admitted by the Speaker it may be included in the list of business under the heading; contingent notice of motion or resolution or Bill, as the case may be.

(2) A contingent notice shall be in such form as the Speaker may prescribe and shall be taken up in the House only after the business on which the notice is contingent is disposed of.

334. Circulation of notices and papers to members.—(1) The Secretary-General shall make every effort to circulate to each member a copy of every notice or other paper which is required by these rules to be made available for the use of members.

(2) A notice or other paper shall be deemed to have been made available for the use of every member if a copy thereof is deposited in such manner and in such places as the Speaker may, from time to time, direct.

334A. Prohibition of advance publicity of notices.—A notice shall not be given publicity by any member or other person until it has been admitted by the Speaker and circulated to member:

Provided that a notice of a question shall not be given any publicity until the day on which the question is answered in the House.

335. Lapse of pending notices on prorogation of House.—On the prorogation of the House, all pending notices, other than notices of intention to move for leave to introduce a Bill, shall lapse and fresh notices shall be given for the next session:

Provided that a fresh notice shall be necessary of intention to move for leave to introduce any Bill in respect of which sanction or recommendation has been granted under the Constitution if the sanction or recommendation, as the case may be, has ceased to be operative.

336. Motion, resolution or amendment moved not to lapse.—A motion, resolution or an amendment, which has

been moved and is pending in the House, shall not lapse by reason only of the prorogation of the House.

337. Power of Speaker to amend notices.—If in the opinion of the Speaker, any notice contains words, phrases or expressions which are argumentative, unparliamentary, ironical, irrelevant, verbose, or otherwise inappropriate, the Speaker may, while exercising discretion, amend such notice before it is circulated.

MOTIONS

338. Repetition of motion.—A motion shall not raise a question substantially identical with one on which the House has given a decision in the same session.

339. Withdrawal of motion.—(1) A member who has made a motion may withdraw the same by leave of the House.

(2) The leave shall be signified not upon question but by the Speaker taking the pleasure of the House. The Speaker shall ask: 'Is it your pleasure that the motion be withdrawn?' If no one dissents, the Speaker shall say: The motion is by leave withdrawn. But if any dissentient voice be heard or a member rises to continue the debate the Speaker shall forthwith put the motion:

Provided that if an amendment has been proposed to a motion, the original motion shall not be withdrawn until the amendment has been disposed of.

340. Adjournment of debate on motion.—At any time after a motion has been made, a member may move that the debate on the motion be adjourned.

341. Motion in abuse of rules or dilatory motion.—(1) If the Speaker is of opinion that a motion for the adjournment of a debate is an abuse of the rules of the House, the Speaker may either forthwith put the question thereon or decline to propose the question.

(2) If the Speaker is of opinion that a motion for recirculation of a Bill to elicit further opinion thereon is in the nature of a dilatory motion in abuse of the rules of the House in as much as the original circulation was adequate or comprehensive or that no circumstance has arisen since the previous circulation to warrant the recirculation of the Bill, the Speaker may, forthwith put the question thereon or decline to propose the question.

(3) If the Speaker is of opinion that a motion for recommittal of a Bill to a Select Committee of the House or a Joint Committee of the Houses or circulation or recirculation of the Bill after the Select Committee of the House or the Joint Committee of the Houses has reported thereon, is in the nature of a dilatory motion in abuse of the rules of the House inasmuch as the Select Committee of the House or the Joint Committee of the Houses, as the case may be, has dealt with the Bill in a proper manner or that no unforeseen or new circumstance has arisen since the Bill emerged from such Committee, the Speaker may forthwith put the question thereon or decline to propose the question.

342. Motion to consider policy, situation, statement or any other matter.—A motion that the policy or situation or statement or any other matter be taken into consideration shall not be put to the vote of the House, but the House shall proceed to discuss such matter immediately on conclusion of the speech of the mover and no further question shall be put at the conclusion of the debate at the appointed hour unless a member moves a substantive motion in appropriate terms to be approved by the Speaker and the vote of the House shall be taken on such motion.

ANTICIPATING DISCUSSION

343. Anticipating discussion.—No member shall anticipate the discussion of any subject of which notice has been given provided that in determining whether a discussion is out of order on the ground of anticipation, regard shall be had by the Speaker to the probability of the matter anticipated being brought before the House within a reasonable time.

AMENDMENTS

344. Scope of amendments.—(1) An amendment shall be relevant to, and within the scope of, the motion to which it is proposed.

(2) An amendment shall not be moved which has merely the effect of a negative vote.

(3) An amendment on a question shall not be inconsistent with a previous decision on the same question.

345. Notice of amendments.—Notice of an amendment to a motion shall be given one day before the day on which the motion is to be considered, unless the Speaker allows the amendment to be moved without such notice.

346. Selection of amendments.—The Speaker shall have power to select the amendments to be proposed in respect of any motion, and if thinks fit, may call upon any member who has given notice of an amendment to give such explanation of the object of the amendment as may enable the Speaker to form a judgment upon it.

347. Putting of amendments.—The Speaker may put amendments in such order as may be considered appropriate:

Provided that the Speaker may refuse to put an amendment which in the opinion of the Speaker is frivolous.

COMMUNICATION OF PRESIDENT'S RECOMMENDATION

348. Mode of Communication of recommendation.—Every sanction or recommendation by the President shall be communicated to the Secretary-General by a Minister in the following terms:—

‘The President, having been informed of the subject matter of the proposed Bill, motion, demand for grant or

amendment, accords the previous sanction to the introduction of the Bill or the moving of the amendment or, recommends the introduction of the Bill or the moving of the motion, demand for grant or amendment in the House or recommends to the House the consideration of the Bill.’

It shall be printed in the proceedings of the House in such manner as the Speaker may direct.

RULES TO BE OBSERVED BY MEMBERS

349. Rules to be observed by Members in House.—Whilst the House is sitting, a member—

(i) shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the House;

(ii) shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner;

(iii) shall bow to the Chair while entering or leaving the House, and also when taking or leaving one's own seat;

(iv) shall not pass between the Chair and any member who is speaking;

(v) shall not leave the House when the Speaker is addressing the House;

(vi) shall always address the Chair;

(vii) shall keep to one's own usual seat while addressing the House;

(viii) shall maintain silence when not speaking in the House;

(ix) shall not obstruct proceedings, hiss or interrupt and shall avoid making running commentaries when ¹[another member is speaking];

(x) shall not applaud when a stranger enters any of the Galleries, or the Special Box;

²[(xi) shall not shout slogans in the House;

(xii) shall not sit or stand with his back towards the Chair;

(xiii) shall not approach the Chair personally in the House. The member may send chits to the officers at the Table, if necessary;

(xiv) shall not wear to display badges of any kind in the House ³{except the National Flag in the form of a lapel pin or a badge};

(xv) shall not bring or display arms in the House;

(xvi) shall not display flags, emblems or any exhibits in the House;

¹Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

²Subs. *Ibid.*

³Added by L.S. Bn. (II) dated 19.3.2010, para 1265.

(xvii) shall not leave the House immediately after delivering the speech;

(xviii) shall not distribute within the precincts of Parliament House any literature, questionnaire, pamphlets, press notes, leaflets, etc. not connected with the business of the House;

(xix) shall not place one's hat/cap on the desk in the House, bring boards in the Chamber for keeping files or for writing purposes, smoke or enter the House with the coat hanging on the arms;

(xx) shall not carry walking stick into the House unless permitted by the Speaker on health grounds;

(xxi) shall not tear off documents in the House in protest;

(xxii) shall not bring or play cassette or tape recorder in the House; and

(xxiii) shall avoid talking or laughing in Lobby loud enough to be heard in the House.]

350. Only member called by Speaker entitled to speak.—When a member rises to speak, the name of such member shall be called by the Speaker. If more members than one rise at the same time, the member whose name is so called shall be entitled to speak.

351. Mode of addressing House.—A member desiring to make any observations on any matter before the House shall speak from one's own place, shall rise when speaking and shall address the Speaker:

Provided that a member disabled by sickness or infirmity may be permitted to speak sitting.

352. Rules to be observed while speaking.—A member while speaking shall not—

(i) refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending;

(ii) ⁴[make personal reference by way of making an allegation imputing a motive to or questioning the *bona fides* of any other member of the House unless it be imperatively necessary for the purpose of the debate being itself a matter in issue or relevant thereto;]

(iii) use offensive expressions about the conduct or proceedings of Parliament or any State Legislature;

(iv) reflect on any determination of the House except on a motion for rescinding it;

(v) reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms;

Explanations.—The words 'persons in high authority' mean persons whose conduct can only be

discussed on a substantive motion drawn in proper terms under the Constitution or such other persons whose conduct, in the opinion of the Speaker, should be discussed on a substantive motion drawn up in terms approved by the Speaker;

(vi) use the President's name for the purpose of influencing the debate;

(vii) utter treasonable, seditious or defamatory words;
⁵[***]

(viii) use the right of speech for the purpose of obstructing the business of the House;

⁶[(ix) make any reference to the strangers in any of the galleries;

(x) refer to Government officials by name; and

(xi) read a written speech except with the previous permission of the Chair.]

353. Procedure regarding allegation against any person.—No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given ⁷[adequate advance notice] to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply:

Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if the Speaker is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation.

354. Restriction on quoting speeches made in Council.—No speech made in the Council shall be quoted in the House unless it is a definite statement of policy by a Minister:

Provided that the Speaker, on a request being made in advance, may give permission to a member to quote a speech or make reference to the proceedings in the Council, if the Speaker thinks that such a course is necessary in order to enable the member to develop a point of privilege or procedure.

355. Questions to be asked through Speaker.—When, for the purposes of explanation during discussion or for any other sufficient reason, any member has occasion to ask a question of another member on any matter then under the consideration of the House, the member shall ask such question through the Speaker.

356. Irrelevance or repetition.—The Speaker, after having called the attention of the House to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition

⁴Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

⁵Omitted by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

⁶Added *ibid.*

⁷Sub. *ibid.*

either in one's own arguments or of the arguments used by other members in debate, may direct that member to discontinue the speech.

357. Personal explanation.—A member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House, but in this case no debatable matter may be brought forward, and no debate shall arise.

ORDER OF SPEECHES, RIGHT OF REPLY AND CONCLUSION OF DEBATE

358. Order of speeches and right of reply.—(1) After the member who moves a motion has spoken, other members may speak to the motion in such order as the Speaker may call upon them. If any member who is so called upon does not speak, such member shall not be entitled except with the permission of Speaker, to speak to the motion at any later stage of the debate.

(2) Except in the exercise of right of reply or as otherwise provided by these rules, no member shall speak more than once to any motion, except with the permission of the Speaker.

(3) A member who has moved a motion may speak again by way of reply, and if the motion is moved by a private member, the Minister concerned, whether previously spoken in the debate or not, may with the permission of the Speaker, speak after the mover has replied:

Provided that nothing in this sub-rule shall be deemed to give any right of reply to the mover of an amendment to a Bill or a resolution save with the permission of the Speaker.

359. Conclusion of debate.—Subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 358 the reply of the mover of the original motion shall in all cases conclude the debate.

ADDRESS BY SPEAKER

360. Address by Speaker.—The Speaker may herself/himself, or on a point being raised or on a request made by a member, may address the House at any time on a matter under consideration in the House with a view to aid members in their deliberations, and such expression of views shall not be taken to be in the nature of a decision.

PROCEDURE WHEN SPEAKER RISES

361. Procedure when Speaker rises.—(1) The Speaker shall, whenever rises, be heard in silence and any member who is then speaking or offering to speak shall immediately resume one's own seat.

(2) No member shall leave one's own seat while the Speaker is addressing the House.

CLOSURE AND LIMITATION OF DEBATE

362. Closure.—(1) At any time after a motion has been made, any member may move: 'That the question be now put', and unless it appears to the Speaker that the

motion is an abuse of these rules or an infringement of the right of reasonable debate, the Speaker shall then put the motion 'That the question be now put'.

(2) Where the motion: 'That the question be now put' has been carried, the question or questions consequent thereon shall be put forthwith without further debate:

Provided that the Speaker may allow a member any right of reply which the member may have under these rules.

363. Limitation of debate.—(1) Whenever the debate on any motion in connection with a Bill or on any other motion becomes unduly protracted, the Speaker may, after taking the sense of the House, fix a time limit for the conclusion of discussion on any stage or all stages of the Bill or the motion, as the case may be.

(2) At the appointed hour, in accordance with the time limit fixed for the completion of a particular stage of a Bill or a motion, the Speaker shall, unless the debate is sooner concluded, forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with that stage of the Bill or the motion.

DECISION OF HOUSE

364. Question on motion made.—A matter requiring the decision of the House shall be decided by means of a question put by the Speaker on a motion made by a member.

365. Proposal and putting of question.—When a motion has been made, the Speaker shall propose the question for consideration, and put it for the decision of the House. If a motion embodies two or more separate propositions, those propositions may be proposed by the Speaker as separate questions.

366. No speech after voices collected.—A member shall not speak on a question after the Speaker has collected the voices both of the 'Ayes' and of the 'Noes' on that Question.

DIVISION

367. Procedure regarding division.—(1) On the conclusion of a debate, the Speaker shall put the question and invite those who are in favour of the motion to say 'Aye' and those against the motion to say 'No'.

(2) The Speaker shall then say: 'I think the Ayes (or the Noes, as the case may be) have it. 'If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is not challenged, the Speaker shall say twice: 'The Ayes (or the Noes, as the case may be) have it' and the question before the House shall be determined accordingly.

(3) (a) If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged, the Speaker shall order that the Lobby be cleared.

(b) After the lapse of ⁸[three minutes and thirty seconds], the Speaker shall put the question a second time

⁸Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

and declare whether in opinion of the Speaker the 'Ayes' or the 'Noes' have it.

(c) If the opinion so declared is again challenged, the Speaker shall direct that the votes be recorded either by operating the automatic vote recorder or by using 'Aye' and 'No' Slips in the House or by the Members going into the Lobbies:

Provided that the Speaker may, if is of the opinion that the Division is unnecessarily claimed, ask the members who are for 'Aye' and those for 'No' respectively to rise in their places and, on a count being taken, may declare the determination of the House. In such a case, the names of the voters shall not be recorded.

367A. Division by automatic vote recorder.—(1) Where the Speaker directs under clause (c) of sub-rule (3) of rule 367 that the votes be recorded by operating the automatic vote recorder, it shall be put into operation and the members shall cast their votes from the sets respectively allotted to them by pressing the buttons provided for the purpose.

(2) After the result of the voting appears on the indicator board, the result of the Division shall be announced by the Speaker and it shall not be challenged.

(3) A member who is not able to cast one's own vote by pressing the button provided for the purpose due to any reason considered sufficient by the Speaker, may, with the permission of the Speaker, have the vote recorded verbally by stating whether she or he is in favour of or against the motion, before the result of the Division is announced.

(4) If a member finds having voted by mistake by pressing the wrong button, such member may be allowed to correct the mistake provided it is brought to notice of the Speaker by the member before the result of the Division is announced.

367AA. Division by distribution of 'Aye' and 'No' slips.—(1) Where the Speaker directs under clause (c) of sub-rule (3) of rule 367 that the votes shall be recorded by members on 'Aye' and 'No' slips, the Division Clerks shall supply to such members at their seats, 'Aye' or 'No' slips, according to the choice indicated by a member. A member shall record the vote on the slip by signing and indicating one's own Division Number thereon.

(2) After the members have recorded their votes, the Division Clerks shall collect the 'Aye' and 'No' slips and bring them to the Table where the votes shall be counted by the Officers at the Table and the totals of 'Ayes' and 'Noes' presented to the Speaker.

(3) The result of the Division shall be announced by the Speaker and it shall not be challenged.

367B. Division by going into Lobbies.—(1) Where the Speaker directs under clause (c) of sub-rule (3) of rule 367 that the votes shall be recorded by the members going

into the Lobbies, the Speaker shall direct the 'Ayes' to go into the Right Lobby and the 'Noes' into the Left Lobby. In the 'Ayes' or 'Noes' Lobby, as the case may be, each member shall state one's own Division Number and the Division Clerk, while marking off the number on the Division List, shall simultaneously call out the name of the member.

(2) After voting in the Lobbies is completed, the Division Clerks shall bring the Division Lists to the Table when the votes shall be counted by the officers at the Table and the totals of 'Ayes' and 'Noes' presented to the Speaker.

(3) The result of the Division shall be announced by the Speaker and it shall not be challenged.

(4) A member who is unable to go to the Division Lobby owing to sickness or infirmity may, with the permission of the Speaker, have the vote recorded either at the allotted seat of such member or in the Lobby before the result of the Division is announced.

(5) If a member finds having voted by mistake in the wrong Lobby, such Member may be allowed to correct the mistake, provided it is brought to the notice of the Speaker by the member before the result of the Division is announced.

(6) When the Division Clerks have brought the Division Lists to the Table, a member who has not upto that time recorded one's own vote but who then wishes to have the vote recorded may do so with the permission of the Speaker before the result of the Division is announced.

PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE

368. Papers quoted to be laid.—If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, the Minister shall lay the relevant paper on the Table:

Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest:

Provided further that where a Minister gives in one's own words a summary or gist of such despatch or State paper it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table.

369. Authentication and treatment of papers laid.—(1) A paper or document to be laid on the Table shall be duly authenticated by the member presenting it.

(2) All papers and documents laid on the Table shall be considered public.

370. Document containing advice or opinion disclosed to be laid.—If, in answer to a question or during debate, a Minister discloses the advice or opinion given to the Minister by any officer of the Government or by any other person or authority, the Minister shall ordinarily lay

the relevant document or parts of document containing that opinion or advice, or a summary thereof on the Table.

[For rules relating to Committee on Papers laid on the Table, see Chapter XXVI of these rules.]

OBJECTION TO VOTE OF A MEMBER ON GROUNDS OF
PERSONAL, PECUNIARY OR DIRECT INTEREST

371. Objection to vote of a member.—If the vote of a member in a division in the House is challenged on the ground of personal, pecuniary or direct interest in the matter to be decided, the Speaker, if considers necessary, may call upon the member making the challenge to state precisely the grounds of objection and the member whose vote has been challenged to state one's own case and shall decide whether the vote of the member should be disallowed or not and the decision of the Speaker shall be final:

Provided that the vote of a member or members is challenged immediately after the division is over and before the result is announced by the Speaker.

Explanation.—For the purposes of this rule the interest of the member should be direct, personal or pecuniary and separately belong to the person whose vote is questioned and not in common with the public in general or with any class or section thereof or on a matter of State policy.

STATEMENT BY MINISTER

372. Statement by Minister.—A statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the Speaker but no question shall be asked at the time the statement is made.

WITHDRAWAL AND SUSPENSION OF MEMBERS

373. Withdrawal of Member.—The Speaker, if is of the opinion that the conduct of any member is grossly disorderly, may direct such member to withdraw immediately from the House, and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall remain absent during the remainder of the day's sitting.

374. Suspension of Member.—(1) The Speaker, may, if deems it necessary, name a member who disregards the authority of the Chair or abuses the rules of the House by persistently and wilfully obstructing the business thereof.

(2) If a member is so named by the Speaker, the Speaker shall, on a motion being made forthwith put the question that the member (naming such member) be suspended from the service of the House for a period not exceeding the remainder of the session:

Provided that the House may, at any time, on a motion being made, resolve that such suspension be terminated.

(3) A member suspended under this rule shall forthwith withdraw from the precincts of the House.

***[374A. Automatic Suspension of a Member.**—(1) Notwithstanding anything contained in rules 373 and 374, in the event of grave disorder occasioned by a member coming into the well of the House or abusing the Rules of the House persistently and wilfully obstructing its business by shouting slogans or otherwise, such member shall, on being named by the Speaker, stand automatically suspended from the service of the House for five consecutive sittings or the remainder of the session, whichever is less:

Provided that the House may, at any time, on a motion being made, resolve that such suspension be terminated.

(2) On the Speaker announcing the suspension under this rule, the member shall forthwith withdraw from the precincts of the House.]

ADJOURNMENT OF HOUSE OR SUSPENSION OF SITTING DUE
TO GRAVE DISORDER

375. Power of Speaker to adjourn House or suspend sitting.—In the case of a grave disorder arising in the House, the Speaker, may if thinks it necessary to do so, adjourn the House or suspend any sitting for a time to be named by the Speaker.

POINTS OF ORDER

376. Points of order and decisions thereon.—(1) A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker.

(2) A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment:

Provided that the Speaker may permit a member to raise a point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another if it relates to maintenance of order in, or arrangement of business before, the House.

(3) Subject to conditions referred to in sub-rules (1) and (2) a member may formulate a point of order and the Speaker shall decide whether the point raised is a point of order and if so, the decision of the Speaker thereon, shall be final.

(4) No debate shall be allowed on a point of order, but the Speaker, if thinks fit, may hear members before giving the decision.

(5) A point of order is not point of privilege.

(6) A member shall not raise a point of order—

- (a) to ask for information; or
- (b) to explain one's own position; or
- (c) when a question on any motion is being put to the House; or

(d) which may be hypothetical; or

(e) that Division Bells did not ring or were not heard.

377. ¹⁰[Raising a matter which is not a point of order.]—A member who wishes to bring to the notice of the House a matter which is not a point of order, shall give notice in writing to the Secretary-General specifying clearly and precisely the text of the matter to be raised. The member shall be permitted to raise it only after the Speaker has given the consent and at such time and date as the Speaker may fix.]

377A. ¹¹[Conditions of admissibility.]—In order that a notice may be admissible it shall satisfy the following conditions:—

(i) it shall not refer to a matter which is not primarily the concern of the Government of India;

(ii) it shall not relate to a matter which has been discussed in the same session or which is substantially identical to the matter already raised by a member under this rule during the session;

(iii) it shall not exceed 250 words;

(iv) it shall not raise more than one issue;

(v) it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations, epithets or defamatory statements; and

(vi) it shall not refer to proceedings of a parliamentary/consultative committee.

377B. Time for Tabling notices and their validity.—

(1) Notices received during a week commencing from its first sitting till 10.00 hours on the last day of the week on which the House sits shall be valid for that week.

(2) Notices received after 10.00 hours on the last day of the week on which the House sits shall be valid for the next week. Notices received after 10.00 hours and upto 10.30 hours on that day shall be deemed to have been received at the same point of time and these shall be ballotted to determine the *inter-se* priority of members. Notices received subsequently shall be arranged in accordance with the date and time of their receipt.

(3) Notices not selected during the week for which they have been tabled, shall lapse at the end of the week:

Provided that a notice referred for facts under order of the Speaker shall not lapse till it is finally disposed of.

377C. Restrictions on raising matters.—(1) No member shall raise more than one matter during a week.

(2) Only the text approved by the Speaker shall go on record.]

MAINTENANCE OF ORDER

378. Speaker to preserve order and enforce decisions.—The Speaker shall preserve order and shall have all powers necessary for the purpose of enforcing own decisions.

PROCEEDINGS OF THE HOUSE, PARLIAMENTARY PAPERS AND CUSTODY OF PAPERS

379. Preparation and publication of proceedings.—The Secretary-General shall cause to be prepared a full report of the proceedings of the House at each of its sittings and shall, as soon as practicable, publish it in such form and manner as the Speaker may, from time to time, direct.

380. Expunction.—If the Speaker is of opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, the Speaker may, while exercising discretion order that such words be expunged from the proceedings of the House.

381. Indication in proceedings regarding expunction.—The portion of the proceedings of the House so expunged shall be marked by asterisks and an explanatory footnote shall be inserted in the proceedings as follows:

'EXPUNGED AS ORDERED BY THE CHAIR'

382. Printing and publication of Parliamentary papers.—(1) The Speaker may authorise printing, publication, distribution or sale of any paper, document or report in connection with the business of the House or any paper, document or report laid on the table or presented to the House or a Committee thereof.

(2) A paper, document or report printed, published, distributed or sold in pursuance of sub-rule (1) shall be deemed to have been printed, published, distributed or sold under the authority of the House within the meaning of clause (2) of article 105 of the Constitution.

(3) If a question arises whether a paper, document or report is in connection with the business of the House or not, the question shall be referred to the Speaker whose decision shall be final.

383. Custody of papers.—The Secretary-General shall have custody of all records, documents and papers belonging to the House or any of its Committees or Lok Sabha Secretariat and the Secretary-General shall not permit any such records, documents or papers to be taken from the Parliament House without the permission of the Speaker.

CHAMBER OF THE HOUSE

384. Restriction on use of Chamber of House.—The Chamber of the House shall not be used for any purpose other than the sittings of the House.

ADMISSION OF OFFICERS OF THE COUNCIL

385. Admission of officers of Council to House.—Any officer of the Secretarial staff of the Council shall be

¹⁰Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.

¹¹Added *Ibid*.

THIRD SCHEDULE

(See rules 229 and 230)

Form of communication regarding arrest, detention, conviction or release, as the case may be, of a member

Place

Date

To

The Speaker,
Lok Sabha,
New Delhi.
Dear Madam/Mr. Speaker,

A

I have the honour to inform you that I have found it my duty, in the exercise of my powers under Section of the (Act), to direct that Shrimati/Kumari/Shri..... Members of the Lok Sabha, be arrested for detained

(reasons for the arrest or detention, as the case may be).

Shrimati/Kumari/ShriM.P., was accordingly arrested

taken into custody

at (time) on (date) and is at present lodged in the jail, (Place).

B

I have the honour to inform you that Shrimati/Kumari/Shri., Member of the Lok Sabha, was tried at the Court before me on a charge (or charges) of (reasons for the conviction).

On (date) after a trial lasting for days, I found Shrimati/Kumari/Shri guilty of and sentenced her/him to imprisonment for (period).

(Her/his application for leave to appeal to* is pending consideration).

C

I have the honour to inform you that Shrimati/Kumari/Shri....., Member of the Lok Sabha, who was arrested/detained/convicted on (date), for (reasons for arrest/detention/conviction), was released on (date) on (grounds for release).

Yours faithfully,

(Judge, Magistrate or Executive Authority)

*Name of the Court.

¹Added by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.²Omitted *ibid*.

FOURTH SCHEDULE

(See rule 312A)

List of Public Undertakings**Part I***(Public Undertakings established by Central Acts)*

1. The Damodar Valley Corporation.
2. The Industrial Finance Corporation¹ [of India].
3. The Indian Airlines. ²[***].
4. The Air India ²[***].
5. The Life Insurance Corporation¹ [of India].
6. The Central Warehousing Corporation.
7. Oil and Natural Gas Commission.
8. The Food Corporation of India.
9. The International Airports Authority of India.
10. The Industrial Development Bank of India ³[*** ***].
11. ⁴The Delhi Transport Corporation.

Part II*(Public Undertakings which are Government Companies formed under the Companies Act)*

Every Government Company whose annual report is placed before the Houses of Parliament under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956.

Part III

1. Hindustan ⁵[Aeronautics] Ltd., Bangalore.
2. Bharat Electronics Ltd., Bangalore.
3. Mazagon Docks Ltd., Bombay.
4. Garden Reach ⁶[Ship Builders and Engineers] Ltd., Calcutta.

³Entry 11 omitted *ibid* .⁴Entry 12 renumbered as 11 *ibid* .⁵Sub. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1989, para 2930.⁶Subs. *ibid*.

FIFTH SCHEDULE¹

(See rule 331C)

Ministries/Departments under the Jurisdiction of the Standing Committees

Sl. No.	Names of the Committees	Ministries/Departments
(1)	(2)	(3)
Part I		
1.	Committee on Commerce	Commerce and Industry
2.	Committee on Home Affairs	(1) Home Affairs (2) Development of North-Eastern Region
3.	Committee on Human Resource Development	(1) Human Resource Development (2) Youth Affairs and Sports (3) Women and Child Development
4.	Committee on Industry	(1) Heavy Industries and Public Enterprises (2) Micro, Small and Medium Enterprises
5.	Committee on Science & Technology, Environment & Forests	(1) Science and Technology (2) Space (3) Earth Sciences (4) Atomic Energy (5) Environment and Forests
6.	Committee on Transport, Tourism and Culture	(1) Civil Aviation (2) Road Transport and Highways (3) Shipping (4) Culture (5) Tourism
7.	Committee on Health and Family Welfare	Health and Family Welfare
8.	Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice	(1) Law and Justice (2) Personnel, Public Grievances and Pensions
Part II		
9.	Committee on Agriculture	(1) Agriculture (2) Food Processing Industries
10.	Committee on Information Technology	(1) Communications and Information Technology (2) Information and Broadcasting
11.	Committee on Defence	Defence
12.	Committee on Energy	(1) New and Renewable Energy (2) Power
13.	Committee on External Affairs	(1) External Affairs (2) Overseas Indian Affairs

(1)	(2)	(3)
14.	Committee on Finance	(1) Finance (2) Corporate Affairs (3) Planning (4) Statistics and Programme Implementation
15.	Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution	Consumer Affairs, Food and Public Distribution
16.	Committee on Labour	(1) Labour and Employment (2) Textiles
17.	Committee on Petroleum and Natural Gas	Petroleum and Natural Gas
18.	Committee on Railways	Railways
19.	Committee on Urban Development	(1) Urban Development (2) Housing and Urban Poverty Alleviation
20.	Committee on Water Resources	Water Resources
21.	Committee on Chemicals and Fertilizers	Chemicals and Fertilizers
22.	Committee on Rural Development	(1) Rural Development (2) Drinking Water and Sanitation (3) Panchayati Raj
23.	Committee on Coal and Steel	(1) Coal (2) Mines (3) Steel
24.	Committee on Social Justice and Empowerment	(1) Social Justice and Empowerment (2) Tribal Affairs (3) Minority Affairs

APPENDIX I**THE HOUSES OF PARLIAMENT (JOINT SITTINGS AND COMMUNICATIONS) RULES*****CHAPTER I****PRELIMINARY**

1. Short Title.—These Rules may be called the Houses of Parliament (Joint Sittings and Communications) Rules.

2. Definitions.—In these Rules unless the context otherwise requires,—

- "Council" means the Council of States;
- "House" means the House of the People;
- "Houses" means the Council of States and the House of the People;
- "Joint Sitting" means a joint sitting of the Houses;
- "Member" means a member of the Council or of the House;

¹Extant Schedule of 17 Committees substituted by revised Schedule of 24 Committees by L.S. Bn. (II) dated 20.7.2004 (para 253) and adapted *vide* bn. (Ii) dated 5.5.2006 (para 2367), dated 10.4.2007 (para 3493), 10.9.2008 (para 6008), 10.11.2009 (para 675), 1.11.2011 (para 3223).

*Rules made by the President, after consultation with the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, in exercise of the powers conferred by clause (3) of article 118 of the Constitution of India.

[Department of Parliamentary Affairs Notfn. No. 5(1) PA-52, Dt. 16.5.1952; Gaz. Ex. (I-1), 20.5.1952].

(f) "Secretary-General" means the Secretary-General of the House and includes any person for the time being performing the duties of the Secretary-General of the House;

(g) "Speaker" means the Speaker of the House.

CHAPTER II

JOINT SITTINGS OF HOUSES

3. Summons to members.—The Secretary-General shall issue a summon to each member specifying the time and place for a joint sitting.

4. Time of sittings.—The hour upon which a joint sitting shall adjourn and the day and hour or the part of the same day to which it shall be adjourned shall be determined by the Speaker.

5. Presiding Officers.—During the absence of the Speaker from any joint sitting, the Deputy Speaker of the House or, the Deputy Speaker is also absent, the Deputy Chairman of the Council or, if the Deputy Chairman is also absent such other person as may be determined by the members present at the sitting, shall preside.

6. Quorum.—The quorum to constitute a joint sitting shall be one tenth of the total number of members of the Houses.

7. Procedure.—At any joint sitting the procedure of the House shall apply with such modifications and variations as the Speaker may consider necessary or appropriate.

8. Report of proceedings of joint sittings.—The Secretary-General shall cause to be prepared a full report of the proceedings of every joint sitting, and shall, as soon as practicable, publish it in such form and manner as the Speaker may, from time to time, direct.

CHAPTER III

COMMUNICATIONS BETWEEN HOUSES

9. Communication by message.—Communications between the Houses shall be by messages.

10. Mode of sending messages.—Every message from the House to the Council or from the Council to the House shall be in writing or in print or partly in writing and partly in print and shall be signed by the Secretary-General of the House or the Council and conveyed to the Secretary-General of the Council or the House, as the case may be.

11. Communication of messages to members.—(1) On receipt of any message, from the House or the Council when it is in session, the Secretary-General shall report the message to the House or the Council, as the case may be, at the first convenient opportunity after its receipt.

(2) Whenever the House or the Council to which a message is sent is not in session, a copy of the message

shall, as soon as it is received by the Secretary-General of the House or the Council, it shall be forwarded to every member of the House or the Council, as the case may be.

12. Procedure to deal with the subject matter of the message.—The subject matter of the message shall be dealt with by the House or the Council, as the case may be, to which the message is sent according to the rules regulating its procedure and the conduct of its business.

APPENDIX II

RULES RELATING TO COMMITTEES NOT MENTIONED IN THE RULES OF PROCEDURE*

GENERAL PURPOSES COMMITTEE

1. Constitution.—There shall be a General Purposes Committee consisting of the Speaker, the Deputy Speaker, members of the Panel of Chairpersons, Chairpersons of all Standing Parliamentary Committees of Lok Sabha, Leaders of recognised parties and groups in Lok Sabha and such other members as may be nominated by the Speaker. The Speaker shall be the *ex-officio* Chairperson of the Committee.

2. Functions.—The functions of the Committee shall be to consider and advise on such matters concerning the affairs of the House as may be referred to it by the Speaker from time to time.

3. Provisions applicable in other respects.—In other respects, the general rules applicable to Parliamentary Committees given in Chapter XXVI of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fourteenth Edition) shall apply with such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as the Speaker may consider necessary or convenient.

HOUSE COMMITTEE

1. Constitution.—(1) There shall be a House Committee consisting of not more than twelve members including the Chairperson.

(2) The Committee shall be nominated by the Speaker and shall hold office for a term not exceeding one year. A member may be re-nominated by the Speaker to the new House Committee.

2. Quorum.—The quorum to constitute a sitting of the Committee shall be five.

3. Functions.—(1) The functions of the House Committee shall be—

(i) to deal with all questions relating to residential accommodation for members of Lok Sabha; and

(ii) to exercise supervision over facilities for accommodation, food, medical aid and other amenities accorded to members in members' residences and hostels in Delhi.

*Rules made by the Speaker.

(2) The functions of the Committee shall be advisory.

4. Accommodation sub-Committee.—(1) There shall also be an Accommodation sub-Committee consisting of not more than four members including the Chairperson of the House Committee who shall be the *ex-officio* Chairperson of the sub-Committee.

(2) The members of the sub-Committee shall be nominated by the Chairperson of the House Committee from amongst the members of the House Committee.

(3) The quorum to constitute a sitting of the sub-Committee shall be two.

(4) The function of the sub-Committee shall be to advise on the allotment of residential accommodation to members.

5. Power to appoint sub-Committees.—(1) The Committee may appoint one or more sub-Committees each having the powers of the undivided Committee, to examine any special points relating to residential accommodation, food, medical aid and other amenities in members' residences and the report of such sub-Committees shall be deemed to be the reports of the whole Committee, if they are approved at a sitting of the whole Committee.

(2) The order of reference to a sub-Committee shall clearly state the point or points for investigation. The report of the sub-Committee shall be considered by the whole Committee.

6. Secretariat for Committee.—The Secretariat for the House Committee or its sub-Committees shall be provided by the Lok Sabha Secretariat. An Officer of the Lok Sabha Secretariat nominated in this behalf by the Secretary-General of the Lok Sabha shall be the Secretary to the House Committee and the Accommodation sub-Committee.

7. Record of proceedings and minutes of Committee.—(1) A record of the proceedings of the sittings of the House Committee and the Accommodation sub-Committee shall be maintained.

(2) The draft minutes shall be prepared by the Secretary to the Committee and approved by the Chairman.

(3) The minutes of each sitting shall be circulated to members of the Committee or the sub-Committee, as the case may be. Relevant extracts therefrom may be forwarded to appropriate authorities for necessary action.

8. Appeal.—An appeal against the decision of the House Committee or Accommodation sub-Committee shall lie to the Speaker whose decision shall be final.

9. Provisions applicable in other respects.—In other respects, the general rules applicable to Parliamentary Committees given in Chapter XXVI of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fourteenth Edition) shall apply with such adaptations,

whether by way of modification, addition or omission, as the Speaker may consider necessary or convenient.

LIBRARY COMMITTEE

1. Constitution.—(1) There shall be a Library Committee consisting of—

- (a) the Deputy Speaker and five other members from the Lok Sabha nominated by the Speaker; and
- (b) three members from the Rajya Sabha nominated by the Chairperson of the Rajya Sabha.

(2) The Committee shall hold office for a term not exceeding one year.

(3) The Deputy Speaker shall be the *ex-officio* Chairperson of the Committee.

(4) Casual vacancies in the Committee shall be filled by nomination by the Speaker in respect of members from the Lok Sabha and by the Chairperson of the Rajya Sabha in respect of members from the Rajya Sabha.

2. Functions.—The functions of the Committee shall be—

(a) to consider and advise on such matters concerning the Library as may be referred to it by the Speaker from time to time;

(b) to consider suggestions for the improvement of the Library; and

(c) to assist members of Parliament in fully utilising the services provided by the Library.

3. Resignation from Committee.—A member may resign one's seat from the Committee by writing under one's own hand addressed to the Chairperson of the Committee.

4. Discharge of members absent from sittings of Committee.—The Speaker of the Lok Sabha or the Chairperson of the Rajya Sabha, as the case may be, may discharge a member from the Committee, if such member is absent from two or more consecutive sittings thereof without the permission of the Chairperson of the Committee.

5. Committee may sit whilst Houses sitting.—The Committee may sit whilst the Lok Sabha or the Rajya Sabha is sitting provided that on a division being called in either House, the Chairperson of the Committee shall suspend the proceedings in the Committee for such time as will, in the opinion of the Chairperson, enable the members to vote in a division.

6. Provisions applicable in other respects.—In other respects, the general rules applicable to Parliamentary Committees given in Chapter XXVI of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fourteenth Edition) shall apply with such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as the Speaker may consider necessary or convenient.

APPENDIX III

PROVISIONS RELATING TO THE JOINT COMMITTEE
ON SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS
OF PARLIAMENT

Extract of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954:—

9. Power to make rules.—(1) For the purpose of making rules under this section, there shall be constituted a Joint Committee of both Houses of Parliament consisting of five members from the Council of States nominated by the Chairman and ten members from the House of the People nominated by the Speaker.

(2) The Joint Committee constituted under sub-section (1) shall elect its Chairman and shall have power to regulate its procedure.

¹[(2A) a member of the Joint Committee shall hold office as such member for one year from the date of his nomination and any casual vacancy in the Joint Committee may be filled by nomination by the Chairman of the Council of States, or the Speaker of the House of the People, as the case may be.

Explanation.— In the case of a member of a Joint Committee holding office as such immediately before the commencement of the Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Act, 1958, the period of one year shall be computed from the date of such commencement.]

(3) The Joint Committee constituted under sub-section (1) may ²[after consultation with the Central Government] make rules to provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the routes for performance of any journey;

³[(aa) the person who may be specified as dependent under sub-clause (g) of clause (aa) of section 2;]

(b) the manner in which fractions of a day shall be dealt with for the purpose of determining the daily allowance admissible for that day;

(c) the travelling allowance admissible where a member is provided with free transit for the whole or any part of a journey ⁴[and the reduction of the daily allowance where a member is provided with free board or lodging at the expenses of the Government or a local authority;]

⁵[(cc) the rate at which road mileage shall be paid under sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 4;]

⁶[(ccc) the transit accommodation and the period for which such accommodation may be provided under section 5A];

(d) the travelling allowance admissible where the place from which a member commences his journey or to which he returns is not his usual place of residence;

⁷[(dd) the travelling allowance admissible in respect of journeys performed by any vessel where there is no regular steamer service;

(ddd) the travelling and daily allowances admissible for journeys performed by a member in the course of a tour outside India undertaken in connection with his duties as such member;]

(e) the form in which certificates, if any, shall be furnished by a member for the purpose of claiming any allowance under this Act.

⁸[(ee) the form in which certificates, if any, shall be furnished by any person for the purpose of claiming any pension under this Act;]

⁹[(f) the constituency allowance and medical and other facilities mentioned in section 8 and the amount to be paid in cash in lieu of such facilities;

(ff) the amount which may be paid by way of repayable advance for the purchase of conveyance; the rate of interest thereon and the mode of recovery of such amount and interest thereon;]

¹⁰[(fff) to provide for carry forward of unutilised free telephone calls pertaining to any year beginning on or after the 1st day of April, 2002 to any subsequent year]; and

(g) generally for regulating payment of the daily and travelling allowances and pension under this Act.

(4) Any rules made under sub-section (3) shall not take effect until they are approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People and are published in the Official Gazette, and such publication of the rules shall be conclusive proof that they have been duly made.

¹Ins. by Act 55 of 1958 effective from 30.12.1958.

² *ibid.*

³Ins. by Act 9 of 2004 effective from 9.1.2004.

⁴Ins. by Act 55 of 1958 effective from 30.12.1958.

⁵Ins. by Act 61 of 1982 effective from 6.11.1982.

⁶Ins. by Act 9 of 2004 effective from 9.1.2004.

⁷Sub. by Act 55 of 1958 effective from 30.12.1958.

⁸Ins. by Act 105 of 1976 effective from 9.9.1976.

⁹Sub. by Act 48 of 1975 effective from 16.8.1975.

¹⁰Ins. by Act 9 of 2004 effective from 9.1.2004.

APPENDIX IV

THE MEMBERS OF LOK SABHA
(DISQUALIFICATION ON GROUND
OF DEFECTION) RULES, 1985

In exercise of the powers conferred by paragraph 8 of the Tenth Schedule to the Constitution of India, the Speaker, Lok Sabha, hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Members of Lok Sabha (Disqualification on Ground of Defection) Rules, 1985.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) 'Bulletin' means the Bulletin of the House of the People (Lok Sabha);

(b) 'Committee' means the Committee of Privileges of the House of the People (Lok Sabha);

(c) 'Form' means a form appended to these rules;

(d) 'date of commencement', in relation to these rules means the date on which these rules take effect under sub-paragraph (2) of paragraph 8 of the Tenth Schedule;

(e) 'House' means the House of the People (Lok Sabha);

(f) 'leader' in relation to a legislature party, means a member of the party chosen by it as its leader and includes any other member of the party authorised by the party to act, in the absence of the leader as, or discharge the functions of, the leader of the party for the purposes of these rules;

(g) 'member' means a member of the House of the People (Lok Sabha);

(h) 'Tenth Schedule' means the Tenth Schedule to the Constitution of India;

(i) 'Secretary-General' means the Secretary-General to the House of the People (Lok Sabha) and includes any person for the time being performing the duties of the Secretary-General.

3. Information to be furnished by leader of a legislature party.—(1) The leader of each legislature party (other than legislature party consisting of only one member) shall, within thirty days after the first sitting of the House, or, where such legislature party is formed after the first sitting, within thirty days after its formation, or, in either case within such further period as the Speaker may for sufficient cause allow, furnish the following to the Speaker, namely:—

(a) a statement (in writing) containing the names of members of such legislature party together with other particulars regarding such members as in Form I and the names and designations of the members of such party who have been authorised by it for communicating with the Speaker for purposes of these rules;

(b) a copy of the rules and regulations (whether known as such or as constitution or by any other name) of the political party concerned; and

(c) where such legislature party has any separate set of rules and regulations (whether known as such or as constitution or by any other name), also a copy of such rules and regulations.

(2) Where a legislature party consists of only one member, such member shall furnish a copy of the rules and regulations mentioned in clause (b) of sub-rule (1) to the Speaker, within thirty days after the first sitting of the House or, where one has become a member of the House after the first sitting, within thirty days after taking one's seat in the House, or, in either case within such further period as the Speaker may for sufficient cause allow.

(3) In the event of any increase in the strength of a legislature party consisting of only one member, the provisions of sub-rule (1) shall apply in relation to such legislature party as if such legislature party had been formed on the first date on which its strength increased.

(4) Whenever any change takes place in the information furnished by the leader of a legislature party under sub-rule (1) or by a member under sub-rule (2), the member concerned, within thirty days thereafter, or, within such further period as the Speaker may for sufficient cause allow, furnish in writing information to the Speaker with respect to such change.

(5) In the case of the House in existence on the date of commencement of these rules, the reference in sub-rules (1) and (2) to the date of the first sitting of the House shall be construed as a reference to the date of commencement of these rules.

(6) Where a member belonging to any political party votes or abstains from voting in the House contrary to any direction issued by such political party or by any person or authority authorised by it in this behalf, without obtaining, in either case, the prior permission of such political party, person or authority, the leader of the legislature party concerned or where such member is the leader, or as the case may be, the sole member of such legislature party, such member, shall, as soon as may be after the expiry of fifteen days from the date of such voting or abstention, and in any case within thirty days from the date of such voting or abstention, inform the Speaker as in Form II whether such voting or abstention has or has not been condoned by such political party, person or authority.

Explanation.—A member may be regarded as having abstained from voting only when such member, being entitled to vote, voluntarily refrained from voting.

4. Information etc. to be furnished by members.—

(1) Every member who has taken seat in the House before the date of commencement of these rules shall furnish to the Secretary-General, within thirty days from such date or within such further period as the Speaker may for sufficient cause allow, a statement of particulars and declaration as in Form III.

(2) Every member who takes seat in the House after the commencement of these rules shall, before making and subscribing an oath or affirmation under article 99 of the Constitution and taking seat in the House, deposit with the Secretary-General, the election certificate or, as the case may be, a certified copy of the notification of being nominated as a member and also furnish to the Secretary-General a statement of particulars and declaration as in Form III.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule, "Election Certificate" means the certificate of election issued under the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and the rules made thereunder.

(3) A summary of the information furnished by the members under this rule shall be published in the Bulletin and if any discrepancy therein is pointed out to the satisfaction of the Speaker, necessary corrigendum shall be published in the Bulletin.

5. Register of information as to members.—(1) The Secretary-General shall maintain, as in Form IV, a register based on the information furnished under rules 3 and 4 in relation to the members.

(2) The information in relation to each member shall be recorded on a separate page in the Register.

6. References to be by petitions.—(1) No reference of any question as to whether a member has become subject to disqualification under the Tenth Schedule shall be made except by a petition in relation to such member made in accordance with the provisions of this rule.

(2) A petition in relation to a member may be made in writing to the Speaker by any other member:

Provided that a petition in relation to the Speaker shall be addressed to the Secretary-General.

(3) The Secretary-General shall,—

(a) as soon as may be after the receipt of a petition under the proviso to sub-rule (2) make a report in respect thereof to the House; and

(b) as soon as may be after the House has elected a member in pursuance of the proviso to sub-paragraph (1) of paragraph 6 of the Tenth Schedule place the petition before such member.

(4) Before making any petition in relation to any member, the petitioner shall satisfy oneself that there are reasonable grounds for believing that a question has arisen as to whether such member has become subject to disqualification under the Tenth Schedule.

(5) Every petition,—

(a) shall contain a concise statement of the material facts on which the petitioner relies; and

(b) shall be accompanied by copies of the documentary evidence, if any, on which the petitioner relies

and where the petitioner relies on any information furnished by any person, a statement containing the names and addresses of such persons and the gist of such information as furnished by each such person.

(6) Every petition shall be signed by a petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), for the verification of pleadings.

(7) Every annexure to the petition shall also be signed by the petitioner and verified in the same manner as the petition.

7. Procedure.—(1) On receipt of a petition under rule 6, the Speaker shall consider whether the petition complies with the requirements of that rule.

(2) If the petition does not comply with the requirements of rule 6, the Speaker shall dismiss the petition and intimate the petitioner accordingly.

(3) If the petition complies with the requirements of rule 6, the Speaker shall cause copies of the petition and of the annexures thereto to be forwarded,—

(a) to the member in relation to whom the petition has been made; and

(b) where such member belongs to any legislature party and such petition has not been made by the leader thereof, also to such leader, and such member or leader shall, within seven days of the receipt of such copies, or within such further period as the Speaker may for sufficient cause allow, forward comments in writing thereon to the Speaker.

(4) After considering the comments, if any, in relation to the petition, received under sub-rule (3) within the period allowed (whether originally or on extension under that sub-rule), the Speaker may either proceed to determine the question or, if the Speaker is satisfied, having regard to the nature, and circumstances of the case that it is necessary or expedient so to do, refer the petition to the Committee for making a preliminary inquiry and submitting a report to the Speaker.

(5) The Speaker shall, as soon as may be after referring a petition to the Committee under sub-rule (4), intimate the petitioner accordingly and make an announcement with respect to such reference in the House or, if the House is not then in session, cause the information as to the reference to be published in the Bulletin.

(6) Where the Speaker makes a reference under sub-rule (4) to the Committee, the Speaker shall proceed to determine the question as soon as may be after receipt of the report from the Committee.

(7) The procedure which shall be followed by the Speaker for determining any question and the procedure which shall be followed by the Committee for the purpose of making a preliminary inquiry under sub-rule (4) shall be, so far as may be, the same as the procedure for inquiry and

determination by the Committee of any question as to breach of privilege of the House by a member, and neither the Speaker nor the Committee shall come to any finding that a member has become subject to disqualification under the Tenth Schedule without affording a reasonable opportunity to such member to represent her/his case and to be heard in person.

(8) The provisions of sub-rules (1) to (7) shall apply with respect to a petition in relation to the Speaker as they apply with respect to a petition in relation to any other member and for this purpose, reference to the Speaker in these sub-rules shall be construed as including references to the member elected by the House under the proviso to sub-paragraph (1) of paragraph 6 of the Tenth Schedule.

8. Decision on petitions.—(1) At the conclusion of the consideration of the petition, the Speaker or, as the case may be, the member elected under the proviso to sub-paragraph (1) of paragraph 6 of the Tenth Schedule shall by order in writing,—

(a) dismiss the petition, or

(b) declare that the member in relation to whom the petition has been made has become subject to disqualification under the Tenth Schedule, and cause copies of the order to be delivered or forwarded to the petitioner, the member in relation to whom the petition has been made and to the leader of the legislature party, if any, concerned.

(2) Every decision declaring a member to have become subject to disqualification under the Tenth Schedule shall be reported to the House forthwith if the House is in session, and if the House is not in session, immediately after the House reassembles.

(3) Every decision referred to in sub-rule (1) shall be published in the Bulletin and notified in the Official Gazette and copies of such decision forwarded by the Secretary-General to the Election Commission of India and the Central Government.

9. Directions as to detailed working of these rules.—

The Speaker may, from time to time, issue such directions as the Speaker may consider necessary in regard to the detailed working of these rules.

FORM I

[See Rule 3 (1)(a)]

Name of the Legislature Party:

Name of the Corresponding political party:

Sl. No.	Name of the Member (in block letters)	Father's/ husband's name	Permanent Address	Name of the State from which elected	Name of the Constituency from which elected
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Date:

Signature of the leader
of the legislature party**FORM II**

[See Rule 3(6)]

To

The Speaker,
Lok Sabha

Madam/Sir,

At the sitting of the House held on.....(date) during
voting on.....(subject-matter).....†Shrimati/Kumari/ShriM.P.
(Division No.....)
member of(name of
political party), and member
of(name of
legislature party) had voted/
abstained from voting,†I,
(name of the member)
M.P.,
(Division No.....)
member of(name of
the political party) and leader
of/sole member of
.....(name of legislature
party) voted/abstained from
voting,contrary to the direction issued by....*(†person/authority/
party) without obtaining the prior permission of the said
*person/authority/party.2. On (date)the aforesaid matter was
considered by*(†person/authority/party) and
the said †voting/abstention was †condoned/was not
condoned by †her/him/it.

Date:

Yours faithfully,
(Signature).**FORM III**

(See Rule 4)

1. Name of the member (in block letters):

2. Father's/husband's name :

3. Permanent Address :

4. Delhi Address :

5. Date of election/nomination :

6. Party affiliation as on—

(i) Date of election/nomination :

(ii) The *28th February, 1985

(iii) Date of signing this form :

DECLARATION.....hereby declare that the information given above is
true and correct.In the event of any change in the information given
above, I undertake to intimate the Speaker immediately.

Date :

Signature/thumb
impression of member

†Strike out inappropriate words/portions.

*(here mention the name of the person/authority/party, as the case
may be, who had issued the direction).*To be filled in only by member elected or nominated before the
1st March, 1985, being the date of commencement of the
Constitution (52nd Amendment) Act, 1985.

[See Rule 5 (1)]

P. SREEDHARAN,
Secy.-General."

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2014

संख्या 29/2/सी1/2014.—5 मार्च, 2014 के लोक सभा समाचार भाग-2 में प्रकाशित निम्नलिखित पैरा एतद्द्वारा सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है :-

“संख्या 6212

लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों का लिंग-तटस्थ बनाया जाना

अध्यक्ष ने लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों को लिंग-तटस्थ बनाया है तथा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (14वां संस्करण) के नियम 389 के अनुसरण में उक्त निदेशों को एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये निदेश 13 फरवरी, 2014 से प्रभावी समझे जाएंगे।

अध्याय 1**शपथ या प्रतिज्ञान**

1. शपथ या प्रतिज्ञान(1).—जैसे ही किसी सदस्य को निर्वाचित घोषित किया जाता है वह संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसरण में शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने पर सभा में अपना स्थान ग्रहण करने का हकदार है।

(2) नियम 5 के उपबंध के अनुसार, यदि कोई सदस्य सभा की बैठक के आरंभ में शपथ या प्रतिज्ञान नहीं कर पाता/पाती तो ऐसा सदस्य सभा की बैठक के दौरान किसी सुविधाजनक समय पर, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, शपथ या प्रतिज्ञान कर सकेगा/सकेगी।

अध्याय 2**कार्य का क्रम****सभा के समक्ष कार्य**

1[2. कार्य के विभिन्न वर्गों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता.—यदि किसी विधि-ट अवसर पर अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें तो सभा के समक्ष कार्य के निम्न निर्दिष्ट वर्गों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता निम्नलिखित क्रम में होगी, अर्थात्:—

- (एक) शपथ या प्रतिज्ञान।
- (दो) संसद की दोनों सभाओं में रा-द्रूपति के अभिभा-ण का रखा जाना।
- (तीन) मंत्रियों का परिचय।
- (चार) निधन संबंधी उल्लेख।
- (पांच) प्रश्न (अल्प सूचना प्रश्नों समेत)।
- (छह) सभा का कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति।
- (सात) विशेष-ाधिकार भंग संबंधी प्रश्न।
- (आठ) सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।
- (नौ) रा-द्रूपति के संदेश सुनाना।

- (दस) राज्य सभा के संदेश सुनाना।
- (ग्यारह) विधेयकों पर रा-द्रूपति की अनुमति के बारे में सूचना।
- (बारह) सभा के सदस्यों की गिरफ्तारी अथवा नज़रबंदी अथवा रिहाई के बारे में मजिस्ट्रेटों अथवा अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचनाएं।
- (तेरह) सभा की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में अध्यक्ष की घो-णा।
- (चौदह) सभा के सदस्यों के पद त्याग, सदस्यों के स्थानों का रिक्त होना, सभापति तालिका, समितियों, आदि में नाम-निर्देशन आदि विविध वि-यों के बारे में अध्यक्ष द्वारा घो-णाएं।
- (पन्द्रह) अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय।
- (सोलह) समितियों के प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया जाना, उनकी बैठकों के कार्यवाही सारांश, आदि का रखा जाना।
- (सत्रह) विधेयकों संबंधी प्रवर/संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का रखा जाना।
- (अठारह) याचिकाओं का प्रस्तुत किया जाना।
- (उन्नीस) मंत्रियों द्वारा वक्तव्य।
- (बीस) समितियों के लिए निर्वाचन के प्रस्ताव।
- (इक्कीस) समितियों के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाए जाने के प्रस्ताव।
- (बाइस) ध्यानाकर्-ण सूचनाएं।
- (तेइस) अपने पदत्याग के स्प-टीकरण में भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा व्यक्तिगत वक्तव्य।
- (चौबीस) निदेश 115 के अधीन वक्तव्य।
- (पच्चीस) नियम 357 के अधीन व्यक्तिगत स्प-टीकरण (यदि वाद-विवाद के दौरान न किया गया हो)।
- (छब्बीस) कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदनों को स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव।
- (सत्ताइस) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव।
- (अट्ठाइस) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव।
- (उनत्तीस) मंत्रि-परि-द् में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव।
- (तीस) रेल बजट/रा-द्रूपति शासन के अधीन किसी राज्य के बजट का प्रस्तुत किया जाना।
- (इक्तीस) अनुदानों की अनुपूरक/अतिरिक्त मांगों (सामान्य, रेल और रा-द्रूपति शासन के अधीन किसी राज्य के संबंध में) का प्रस्तुत किया जाना।
- (बत्तीस) वापस लिए जाने वाले विधेयक।
- (तैंतीस) पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक।

¹दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा प्रतिस्थापित।

(चौंतीस) अध्यादेशों द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारणों को बताने वाले व्याख्यात्मक विवरणों का सभा पटल पर रखा जाना।

(पैंतीस) नियम 377 के अधीन ऐसे मामले उठाना जो औचित्य प्रश्न नहीं हैं।

(छत्तीस) विशेष-आधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार।]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का बैलट

3. बैलट.—गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए नियत किए गए दो निरन्तर दिनों के संबंध में नियम 27(2) के अधीन एक बैलट होगा। बैलट ऐसे दिन, जो किसी मास के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए नियत किए गए प्रथम दिन से कम से कम सात दिन पहले पड़ता हो, और ऐसी रीति से, होगा जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें।

4. स्थगित वाद-विवाद को पुनः आरंभ करने की सूचनाएं.—ऐसे मामलों में जहां विधेयकों पर स्थगित वाद-विवाद को पुनः आरम्भ करने की सूचनाएं बैलट होने के बाद प्राप्त हुई हों वे विधेयक कार्य-सूची में पहले बैलट हुए विधेयकों के नीचे रखे जायेंगे।

5. विधेयकों के बैलट का क्रम.—गैर-सरकारी सदस्यों को विधेयकों के बैलट के लिए नियत किए गए दिन पर्याप्त संख्या में विधेयकों का बैलट होगा जिससे कि दो दिन के लिए कार्य का प्रबन्ध हो सके:

परन्तु विधेयकों का बैलट निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा, अर्थात्:—

(1) ऐसे विधेयक जिनका वर्गीकरण गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति ने वर्ग "क" के अंतर्गत किया है।

(2) ऐसे विधेयक जिनका वर्गीकरण गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति ने वर्ग "ख" के अंतर्गत किया है।

(3) ऐसे विधेयक जो पुरःस्थापित किए जा चुके हैं किंतु गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति द्वारा जिनका वर्गीकरण नहीं किया गया।

6. बैलट का परिणाम.—प्रत्येक बैलट के परिणाम की घो-णा समाचार-भाग दो में की जाएगी।

7. बैलट के पश्चात् पुरःस्थापित विधेयकों पर कार्यवाह.—ऐसे विधेयक, जो बैलट होने के बाद पुरःस्थापित किए जायेंगे और जिनके बारे में अगले प्रस्तावों की सूचनाएं कार्य-सूची के जारी होने से पूर्व प्राप्त हो जाएंगी, सारे विधेयकों पर बैलट होने के बाद ही उस दिन की कार्य-सूची में रखे जायेंगे।

8. अगले प्रस्तावों की सूचनाओं पर कार्यवाही तथा कार्य की व्यवस्था.—²[(1) बैलट का परिणाम समाचार-भाग दो में प्रकाशित होने के बाद गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के बैलट के प्रथम बीस विधेयकों के संबंध में अगले प्रस्तावों की सूचना संबंधित सदस्यों द्वारा समाचार में निर्धारित तारीख तक होगी ताकि उनके विधेयक कार्य-सूची में सम्मिलित किए जा सकें।]

(2) ऐसे मामलों में जहां अगले प्रस्तावों की सूचनाएं नियत किए गए दो दिनों में से प्रथम दिन की कार्य-सूची तैयार होने के बाद प्राप्त हुई हों, विधेयक जिनके बारे में वे सूचनाएं प्राप्त हुई हों, नियत किए गए अगले दिन की कार्य-सूची में ऐसे उपयुक्त स्थानों पर रखे जायेंगे जो कि उन दोनों दिनों के लिए किए गए बैलट द्वारा निश्चित किए गए हों।

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों का बैलट

9. बैलट की प्रक्रिया(1).—उन सभी सदस्यों के नाम का, जो नियम 170 के अधीन सूचनाएं देंगे कि वे गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत दिन को संकल्प पेश करना चाहते हैं, बैलट किया जाएगा।

(2) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत प्रत्येक दिन के लिए पृथक्-पृथक् बैलट किया जाएगा।

(3) बैलट करने के समय तथा स्थान की घो-णा समाचार-भाग दो में की जाएगी।

(4) जो सदस्य बैलट में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करेंगे उनसे बैलट की तारीख के पश्चात् दो दिन के अन्दर एक-एक संकल्प की सूचना देने का अनुरोध किया जाएगा।

कार्य-सूची में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की व्यवस्था

9क. प्रथम प्राथमिकता वाले संकल्प का बचाव.—यदि किसी दिन की कार्य-सूची में दर्ज ऐसे संकल्प पर, जिस पर आंशिक रूप से चर्चा हो चुकी है, चर्चा के लिए निर्धारित समय को सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा बढ़ाया जाता है तो उस संकल्प को आंशिक रूप से चर्चा किए गए संकल्प, यदि कोई हो, के पश्चात् गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए उसी सत्र के दौरान नियत अगले दिन के कार्य की पहली मद के रूप में रखा जायेगा।

सांविधिक संकल्प

9ख. सांविधिक संकल्प(1).—ऐसे संकल्प का, जिसकी सूचना संविधान अथवा संसद के किसी अधिनियम के उपबंध के अनुसरण में दी गई हो, नियम 28 के अधीन बैलट नहीं किया जाएगा।

(2) यदि अध्यक्ष ऐसे संकल्प की सूचना ग्रहण कर लें, तो उसकी सूचना समाचार में "सांविधिक संकल्प" शीर्षक के नीचे

²दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा प्रतिस्थापित।

तुरन्त दी जाएगी, और उसकी एक प्रति सरकार को भेज दी जाएगी।

(3) अध्यक्ष, सभा में कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद और सभा-नेता से परामर्श करके ऐसे किसी संकल्प पर चर्चा के लिए एक या अधिक दिन अथवा दिन का कोई भाग नियत कर सकेगा/सकेगी।

अध्याय 3

प्रश्न

10. एक ही अथवा संबद्ध वि-य पर प्रश्नों का समेकन.—

जब एक ही या संबंधित वि-य पर अनेक सदस्यों से प्रश्नों की सूचनाएं बड़ी संख्या में प्राप्त होती हैं तो अध्यक्ष, यदि उसकी राय में सदस्यों द्वारा पूछी गई सभी महत्वपूर्ण बातों को सम्मिलित करके एक सम्पूर्ण प्रश्न बनाना उचित हो, निदेश दे सकेगा/सकेगी कि सभी सूचनाओं को एक सूचना में समेकित कर दिया जाये:

¹[परन्तु मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में रखे जा रहे ऐसे समेकित प्रश्न के मामले में पूर्ववर्तिता के क्रम में निर्धारित दो से अनधिक सदस्यों के नाम ऐसे प्रश्न के सामने नहीं दिखाये जायेंगे और इनसे अधिक सदस्यों की सूचनाओं को अस्वीकृत कर दिया जायेगा:

परन्तु यह और भी कि लिखित उत्तरों के लिए प्रश्नों की सूची में रखे जा रहे ऐसे किसी समेकित प्रश्न के मामले में, सभी संबंधित सदस्यों के नाम पूर्ववर्तिता के क्रम में एक को-ठक में दिखाए जायेंगे।]

²[10क. प्रश्नों की ग्राह्यता.—नियम 41 में उल्लिखित ग्राह्यता की शर्तों के अतिरिक्त प्रश्न निम्न किसी भी कारण के आधार पर अग्राह्य होगा:

(एक) यदि उसमें ऐसे मामलों की बाबत जानकारी मांगी गई हो जिनसे विखण्डनवादी और अलगाववादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता हो और देश की एकता और अखण्डता कमजोर होती हो;

(दो) यदि वह दिन-प्रतिदिन के प्रशासन से संबंधित हो अथवा उससे किसी एक अथवा कुछ व्यक्तियों के हितों का संवर्धन होता हो;

(तीन) यदि वह किसी ऐसे मामले से संबंधित हो जो मुख्य रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, न्यायालयों और ऐसी अन्य संस्थाओं के क्षेत्राधिकार में आता हो;

(चार) यदि वह मंत्रियों द्वारा प्राप्त ऐसी याचिकाओं और ज्ञापनों से संबंधित है जो लोक महत्व के नहीं हैं;

(पांच) यदि वह किसी ऐसे मामले से संबंधित हो, जिस पर किसी अन्य देश की सरकार के साथ बातचीत चल रही हो और उसके प्रकटन से रा-द्र के अहित में बातचीत प्रभावित होती हो; और

(छह) यदि वह अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले किसी मामले से संबंधित हो।]

³[10ख. प्रश्नों की संख्या सीमा.—किसी सदस्य को, किसी दिन के लिए, मौखिक तथा लिखित उत्तर दोनों के लिए, कुल मिलाकर, दस से अधिक सूचनाएं देने की अनुमति नहीं होगी। किसी सदस्य से, किसी दिन के लिए प्राप्त दस से अधिक सूचनाओं को केवल उसी सत्र की अवधि के दौरान उस मंत्री से संबंधित पश्चात्पूर्वी दिन (दिनों) के लिए रखे जायेंगे। जो सदस्य पूरे सत्र के लिए सूचनाएं देना चाहते हैं वे अपना परस्पर अधिमान दर्शाते हुए ऐसा कर सकते हैं। यदि ऐसे किसी अधिमान को नहीं दर्शाया जाता है तो प्रतिदिन दस से अधिक प्रश्नों की सूचनाओं पर उनकी प्राप्ति के समय के आधार पर उत्तरपूर्वी दिन (दिनों) के लिए विचार किया जाएगा। तथापि, प्रतिदिन प्रति सदस्य कुल पांच गृहीत प्रश्नों की विद्यमान सीमा जारी रहेगी।]

11. तारांकित प्रश्नों की सूची.—मौखिक उत्तर के लिए किसी एक दिन के प्रश्न नियम 37 के अंतर्गत प्रश्न-सूची में इस हेतु किए गए बैलट में प्रत्येक सदस्य द्वारा प्राप्त पूर्ववर्तिता के अनुसार रखे जायेंगे।

12. कार्यवाही में प्रश्नों का मुद्रण.—जब किसी दिन की मौखिक या लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में एक से अधिक सदस्यों के नाम रखे गए किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाए, तो लोक सभा की कार्यवाही के मुद्रित विवरण में प्रश्न के साथ ऐसे सभी सदस्यों के नाम दिखाये जायेंगे:

परन्तु जिस प्रश्न का मौखिक उत्तर दिया जाए उसके वि-य में उस सदस्य का नाम, जिसने वास्तव में प्रश्न पूछा हो, पहले लिखा जाएगा और उसके नाम एक तारांक लगाया जाएगा।

13. तारांकित प्रश्नों के उत्तर में दिए जाने वाले विवरणों की अग्रिम प्रतियां संबंधित सदस्यों को देना तथा उनके सम्बन्ध में कार्यवाही(1).—जब मौखिक उत्तर के लिए किसी प्रश्न के उत्तर में सभा पटल पर कोई विवरण रखा जाना हो अथवा जब किसी पूर्व प्रश्न के उत्तर का उल्लेख किया गया हो तो उस प्रश्न और उत्तर की एक प्रति के साथ, जिसका उल्लेख किया गया हो, विवरण की एक प्रति प्रश्न-काल से आधे घंटे पूर्व सदस्य को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(2) ऐसे विवरण की अथवा मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित पूर्व प्रश्न के उत्तर की प्रति मांगें जाने

¹ दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा प्रतिस्थापित।

² दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा प्रतिस्थापित तथा दिनांक 05.10.1990 के लोक सभा समाचार भाग दो के पैरा संख्या 817 द्वारा पुनः प्रतिस्थापित।

³ दिनांक 16.04.2010 के लोक सभा समाचार भाग दो के पैरा संख्या 1354 में जोड़ा गया।

पर केवल उसी सदस्य को दी जाएगी, जिसके नाम में वह प्रश्न हो अथवा ऐसे सदस्य को दी जाएगी, जिसे उसने अपनी ओर से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया हो अथवा ऐसे किसी व्यक्ति को दी जाएगी जिसे कि उसने विवरण अथवा उत्तर पाने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत कर दिया हो।

(3) जब तक कि प्रश्न का उत्तर न दिया जाए या प्रश्न-काल समाप्त होने तक इन दोनों में से जो भी पहले हो, तब तक इस प्रकार के विवरणों या उत्तरों को गोपनीय समझा जाएगा और इन्हें प्रकाशन के लिए नहीं भेजा जाएगा। यदि किसी कारण से ऐसा विवरण पटल पर न रखा जाए या उत्तर न दिया जाए या मंत्री उत्तर देते समय उसके वि-य में परिवर्तन कर दें, तो मूल विवरण प्रकट नहीं किया जाएगा।

13क. प्रश्नों के उत्तर पूर्ण होंगे(1).—सभा में दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण होंगे तथा, यथासम्भव, उसके प्रत्येक भाग का उत्तर पृथक् रूप में दिया जाएगा।

(2) यदि, किसी उत्तर की ओर ध्यान दिलाए जाने पर, अध्यक्ष संतुष्ट हो जाए कि यह इस शर्त को पूरा नहीं करता है, तो अध्यक्ष, मंत्री को पूर्ण उत्तर देने के लिए निदेश दे सकता/सकती है।

14. एक ही अथवा संबद्ध वि-य के तारांकित प्रश्नों का एक साथ उत्तर दिया जाना.—जब उसी या सम्बद्ध वि-य पर किसी मंत्री को मौखिक उत्तर के लिए सम्बोधित दो या अधिक प्रश्न किसी विशेष दिन की प्रश्न सूची में हो और जब उनमें से पहला उत्तर के लिए लिया जाए तो अध्यक्ष स्वतः या किसी सदस्य के अनुरोध पर, निदेश दे सकेगा/सकेगी कि कोई या ऐसे सभी प्रश्न, सूची में उनके क्रम पर ध्यान दिए बिना, उत्तर के लिए एक साथ ले लिए जाएं।

⁴[15. ****]

16. मंत्रियों द्वारा ⁵[*] प्रश्नों के उत्तरों ⁷[***] को शुद्ध करने की प्रक्रिया.**—जब कोई मंत्री उस जानकारी में किसी अशुद्धि को ठीक करना चाहे जो उसने किसी तारांकित प्रश्न ⁶[अतारांकित] अल्प-सूचना प्रश्न या अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में ⁸[***] दी हो तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी, अर्थात्:—

(एक) मंत्री वक्तव्य देने के अभिप्राय की सूचना महासचिव को देगा/देगी। सूचना के साथ मंत्री द्वारा दिए जाने वाले प्रस्तावित वक्तव्य की एक प्रति दी जाएगी।

(दो) जब सभा का सत्र चल रहा हो, तो महासचिव किसी उपयुक्त दिन कार्य-सूची में उस मद को शामिल

करेगा/करेगी और अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर मंत्री सभा में वक्तव्य देगा/देगी।

(तीन) जब सभा का सत्र न हो रहा हो, तो महासचिव इस बात पर विचार करेगा/करेगी कि क्या मंत्री द्वारा वक्तव्य अगले सत्र में दिया जाएगा और इस स्थिति में अध्यक्ष के आदेश लिए जायेंगे। यदि उस वि-य को अगले सत्र तक न रोका जा सकता हो, तो वक्तव्य सदन में वाद-विवाद के शासकीय वृत्तान्त में सम्मिलित कर लिया जाएगा और वाद-विवाद में निम्नलिखित रीति से एक पाद टिप्पण दे दिया जाएगा:

“मंत्री द्वारा दिया गया मूल उत्तर या वक्तव्य निम्न प्रकार से है:

“.....”

ऊपर मुद्रित उत्तर मंत्री द्वारा बाद में मूल उत्तर के स्थान पर भेजा गया था।”

टिप्पण: जिन मामलों में मूल उत्तर प्रकाशित करना वांछनीय न समझा जाए, उनमें एक उपयुक्त पाद टिप्पण के साथ केवल संशोधित उत्तर ही छापा जाएगा।

(चार) मंत्री सामान्यतया अपने उत्तर या वक्तव्य को शुद्ध करने के अभिप्राय की सूचना उसके एक सप्ताह के अन्दर महासचिव को देगा/देगी परन्तु अध्यक्ष संतो-जनक कारण होने पर इस अपेक्षा को हटा सकेगा/सकेगी।

⁹[पांच ***]

¹⁰[16क. ****]

17. मंत्रियों द्वारा उत्तरों को शुद्ध करने के वक्तव्यों की अग्रिम प्रतियां और वक्तव्य दिए जाने के बाद की प्रक्रिया(1).—किसी तारांकित/¹¹(अतारांकित)/अल्प-सूचना ¹²(अथवा अनुपूरक प्रश्न) के उत्तर को शुद्ध करने के लिए मंत्री द्वारा दिए जाने वाले प्रस्तावित वक्तव्य की प्रतियां उस दिन, जिस दिन वक्तव्य दिया जाने वाला हो, सदस्यों की जानकारी के लिए लोक सभा की बैठक प्रारम्भ होने से आधा घंटा पहले संसदीय सूचना कार्यालय में रख दी जायेगी।

(2) ऐसे वक्तव्य की प्रतियां गोपनीय समझी जाएंगी और उन्हें तब तक प्रकाशन के लिए नहीं दिया जाएगा जब तक कि वास्तव में वक्तव्य न दे दिया जाए।

(3) वक्तव्य दिए जाने के बाद, अध्यक्ष सदस्यों को, मंत्री द्वारा की गई शुद्धि की वि-य वस्तु से पूर्णतया सुसंगत अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकेगा/सकेगी।

⁴ दिनांक 16.03.2010 के लोक सभा समाचार भाग दो के पैरा संख्या 1354 द्वारा लोप किया गया।

⁵ दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा लोप किया गया।

⁶ दिनांक 16.04.2010 के लोक सभा समाचार भाग दो के पैरा संख्या 1354 द्वारा अंतःस्थापित किया गया।

⁷⁻⁸ दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा लोप किया गया।

⁹ दिनांक 16.04.2010 के लोक सभा समाचार भाग दो के पैरा संख्या 1354 द्वारा लोप किया गया।

¹⁰ दिनांक 16.04.2010 के लोक सभा समाचार भाग दो के पैरा संख्या 1354 द्वारा लोप किया गया।

¹¹⁻¹² अंतःस्थापित किया गया, तदेव।

18. अनुपस्थित सदस्यों के अल्प-सूचना प्रश्नों के उत्तर देना.—यदि अल्प-सूचना प्रश्न के पुकारे जाने पर वह सदस्य द्वारा पूछा न जाए अथवा वह सदस्य जिसके नाम में वह प्रश्न हो, अनुपस्थित हो अथवा यदि सदस्य ने किसी दूसरे सदस्य को अपनी ओर से प्रश्न पूछने के लिए प्राधिकृत न किया हो, तो ¹³अध्यक्ष ऐसे प्रश्न का उत्तर देने का निदेश दे सकेगा/सकेगी।

¹⁴[****] परन्तुक का लोप किया गया ।

अध्याय 4

आधे घंटे की चर्चा

19. उत्तर में विवरण का सभा पटल पर रखा जाना.—जब नियम 55 के उप-नियम (1) के अधीन आधे घंटे की चर्चा में गणपूर्ति न होने के कारण व्यवधान पड़ जाए या जब मंत्री द्वारा वाद-विवाद का पूर्ण उत्तर दिए जाने के लिए समय न हो, तो मंत्री अध्यक्ष की अनुमति से एक विवरण सभा पटल पर रख सकेगा/सकेगी।

अध्याय 5

विधान

विधेयकों का पुरःस्थापन और प्रकाशन

19क. सरकारी विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए सूचना(1).—विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करने का इच्छुक मंत्री अपने उस अभिप्राय की लिखित सूचना देगा/देगी।

(2) इस निदेश के अधीन विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना की अवधि सात दिन होगी जब तक अध्यक्ष अल्प-सूचना पर प्रस्ताव करने की अनुमति न दे।

19ख. पुरःस्थापन के लिए विधेयकों का पूर्व परिचालन.—विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए किसी दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसकी प्रतियां उस दिन से जब कि विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का विचार हो, कम से कम दो दिन पूर्व सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न की गई हों:

परन्तु विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक और ऐसे गुप्त विधेयक जो कार्य-सूची में नहीं रखे जाते, सदस्यों को पहले प्रतियां बांटे बिना ही पुरःस्थापित किये जा सकेंगे:

परन्तु यह भी कि अन्य मामलों में जिन में मंत्री यह चाहता / चाहती हो कि प्रतियां परिचालित करने के पश्चात् दो दिन से पहले अथवा उस दिन के परिचालित किए बिना भी, विधेयक पुरःस्थापित किया जाए, तो मंत्री, अध्यक्ष के विचार के लिए एक ज्ञापन में, जिसमें यह बताया गया होगा कि

सदस्यों को पहले से प्रतियां न दिए बिना विधेयक क्यों पुरःस्थापित किया जा रहा है, पूरे-पूरे कारण देगा/देगी, और यदि अध्यक्ष अनुमति दे तो विधेयक उस दिन की, जबकि विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का विचार हो, कार्य-सूची में सम्मिलित कर दिया जाएगा।

विधेयकों पर राय

20. राय जानने के लिए विधेयक का परिचालन(1).—जब यह प्रस्ताव कि किसी विधेयक को उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाए, पारित हो जाए, तो विधेयक राज्य सरकारों को परिचालित किया जाएगा, जिनसे कहा जाएगा कि—

(क) विधेयक के उपबंधों पर अपनी राय।

(ख) राज्य विधानमंडलों के सदस्यों और ऐसे सार्वजनिक निकायों, चुने हुए पदाधिकारियों और किन्हीं दूसरे व्यक्तियों, जिनसे परामर्श करना राज्य सरकारें उचित समझें की रायों की दो-दो प्रतियां यथाशीघ्र भेजने के लिए कहा जाएगा, किंतु वे विधेयक के परिचालन के प्रस्ताव में, निर्दिष्ट तारीख की समाप्ति के बाद नहीं भेजी जाएंगी।

(2) यदि भारत सरकार इस बारे में ऐसा करना आवश्यक समझे, तो राज्य सरकारों से उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श करने के लिए भी कहा जाएगा।

(3) राज्य सरकारों से विधेयक को अपने राजपत्र में प्रकाशित करने और उनमें यह स्पष्ट कर देने के लिए कहा जाएगा कि व्यक्तियों या सार्वजनिक निकायों द्वारा रायें राज्य सरकारों की मार्फत ही भेजी जायेंगी और महासचिव या भारत सरकार के किसी मंत्रालय के पास सीधे नहीं भेजी जायेंगी।

21. राय जानने हेतु समय-सीमा.—जब राय जानने के लिए विधेयक के परिचालन की कोई तिथि प्रस्ताव में निर्दिष्ट न की गई हो, तो राज्य सरकारों से कथित प्रस्ताव के स्वीकृत होने के तीन महीने के अन्दर रायों को भेजने के लिए कहा जाएगा।

22. रायों का विधेयक के पत्रों के रूप में छापा जाना.—रायों के प्राप्त हो जाने के बाद उनको सम्पादित किया जाएगा और विधेयक के पत्रों के रूप में सुविधाजनक संग्रहों में छापा जाएगा। इन पत्रों में क्रमवार क्रमांक दिए जायेंगे।

23. हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में प्राप्त रायों पर कार्यवाही.—हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में प्राप्त रायों को विधेयक पर अभ्यावेदन समझा जाएगा और उन्हें भारत सरकार को दिखाने के बाद संसद के पुस्तकालय में रख दिया जाएगा। सदस्यों को इन अभ्यावेदनों के बारे में लोक सभा समाचार-भाग दो में एक अधिसूचना द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।

¹³दिनांक 16.04.2010 के लोक सभा समाचार भाग दो के पैरा संख्या 1354 प्रतिस्थापित किया गया ।

¹⁴परन्तुक का लोप किया गया ।

24. विधेयक सम्बन्धी पत्रों का सभा-पटल पर रखा जाना.—(1) विधेयक पर राय प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र वे प्रभारी सदस्य द्वारा सभा-पटल पर रख दी जाएंगी:

परन्तु एक गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के वि-य में प्रभारी सदस्य की अनुपस्थिति में, राय विधेयक से संबंधित मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखी जा सकेंगी।

(2) सभा पटल पर रखी गई सभी राय मुद्रित की जाएंगी और उनकी प्रतियां सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएंगी:

परन्तु जब सभा का सत्र न हो रहा हो, तो अध्यक्ष निदेश दे सकेगा/सकेगी कि रायों को, उनके सभा-पटल पर रखे जाने से पहले ही सदस्यों को परिचालित कर दिया जाए। उस स्थिति में रायों को उसके बाद यथासंभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

25. विधेयकों के पत्रों को रखे जाने की रीति.—विधेयक का प्रभारी सदस्य सभा पटल पर पत्र रखते समय अपने कथन को निम्नलिखित रूप में एक वक्तव्य तक ही सीमित रखेगा/रखेगी :

“महोदय/महोदया, मैं (विधेयक का पूरा नाम) विधेयक संबंधी पत्र संख्या 1 को सभा-पटल पर रखता/रखती हूं जो 20..... को सभा के निदेश द्वारा उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया गया था।”

26. रायों के सारांश.—जो विधेयक सभा के निदेश द्वारा उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया गया हो, उसके नियम 75 के उप-नियम (3) के अधीन/प्रवर/संयुक्त समिति को सौंपे जाने के बाद सभा-पटल पर रखी गई विधेयक संबंधी रायों के सारांश की प्रतियां उस विधेयक संबंधी प्रवर/संयुक्त समिति के सदस्यों को उपलब्ध कर दी जाएंगी।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

27. वर्गीकरण और समय नियत करना.—गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने के बाद यथाशीघ्र उसको गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के समक्ष नियम 294(1) के खण्ड (ख) और (ग) के अंतर्गत वर्गीकरण तथा समय के नियतन के लिए रखा जाएगा। विधेयक के प्रभारी सदस्य और विधेयक से संबंधित मंत्रालय के प्रतिनिधि को समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जा सकेगा/सकेगी। समिति प्रभारी सदस्य तथा मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा जिन बातों का अनुरोध किया जाए उन पर उचित ध्यान देने के बाद विधेयक का वर्गीकरण करेगी और उसके लिए समय नियत करेगी।

28. समान विधेयकों की सूचनाओं के मामले में नामों का एक साथ रखा जाना(1).—उन सभी सदस्यों के नाम,

जिन्होंने एक जैसे विधेयक की अलग-अलग सूचनाएं दी हों, कार्य-सूची में विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव के सामने एक साथ दिखाए जाएंगे।

(2) ऐसे सदस्यों के नाम विधेयक के साथ उस क्रम में रखे जाएंगे, जिसमें समय की दृष्टि से सूचनाएं प्राप्त हुई हों।

(3) जिस सदस्य का नाम पहले आता हो वह विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा/करेगी:

परन्तु यदि पहला सदस्य अनुपस्थित हो, तो दूसरा उपस्थित सदस्य अपने विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकेगा/सकेगी।

29. विधेयक के पुरःस्थापन के लिए प्राधिकार का दिया जाना.—जिस सदस्य ने विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करने के अपने अभिप्राय की सूचना दी हो, वह किसी दूसरे सदस्य को अपनी ओर से प्रस्ताव करने का प्राधिकार दे सकेगा/सकेगी:

परन्तु प्राधिकार लिखित होगा, और उसमें यह स्प-ट उल्लेख होगा कि विधेयक के आगे के और प्रक्रमों के संबंध में बाद के सभी प्रस्तावों के लिए इस प्रकार प्राधिकृत किया गया सदस्य प्रभारी होगा/होगी:

परन्तु यह और भी कि विधेयक के राजपत्र में प्रकाशित होने के पहले विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर उस सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसने उसे वास्तव में पुरःस्थापित किया हो।

30. पुरःस्थापन के बाद विधेयक को आगे चलाने के लिए प्राधिकार का दिया जाना.—अध्यक्ष विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा इस बारे में एक आवेदन किए जाने पर इस बात से संतु-ट होने पर कि ऐसा सदस्य ऐसे कारणों से, जिनको अध्यक्ष पर्याप्त समझता/समझती हो, विधेयक के पुरःस्थापन के बाद के किसी या सभी प्रक्रमों को स्वयं आगे चलाने में असमर्थ है, विधेयक के प्रभारी सदस्य को विधेयक के उस प्रक्रम या प्रक्रमों को आगे चलाने के लिए, जिनके संबंध में उससे आवेदन किया गया हो, दूसरे सदस्य का नाम निर्देशन करने की अनुमति दे सकेगा/सकेगी।

विधेयकों में संशोधन

31. नये खण्ड का जोड़ा जाना.—जब किसी विधेयक में एक नया खण्ड अन्तःस्थापित करने का संशोधन सभा द्वारा स्वीकृत हो जाए, तो अध्यक्ष प्रश्न को इस प्रकार रखेगा/रखेगी:

“प्रश्न यह है कि

खण्ड (नये खण्ड की संख्या बताते हुए) विधेयक में जोड़ दिया जाए।”

विधेयकों में शुद्धियां

32. विधेयकों को शुद्ध करने की प्रक्रिया.—किसी विधेयक के पुरःस्थापित रूप में या किसी विधेयक में प्रवर

समिति/संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में सभा द्वारा स्वीकृत संशोधन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परन्तु अध्यक्ष एक शुद्धि-पत्र निकाल कर विधेयक के किसी भी प्रक्रम में, छपाई या लिपिक की गलती को शुद्ध करेगा/करेगी ।

परन्तु यह और भी कि किसी गुप्त विधेयक के मामले में जिसे सम्बन्धित मंत्रालय ने पुरःस्थापना से पहले छपा हो विधेयक के पुरःस्थापित रूप में इस प्रकार की शुद्धि किसी ऐसी अशुद्धि के बारे में नहीं होगी, जिसका करारोपण पर प्रभाव पड़े।

विधेयकों में प्रत्यक्ष गलतियों की शुद्धि के बारे में वाद-विवाद में संकेत

33. मुद्रित वाद-विवादों में शुद्धियां करना.—(1) ऐसे मामले में जहां किसी खण्ड के संबंध में कोई संशोधन प्रस्तुत किया गया हो, और सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो और बाद में सरकारी प्रारूपकार ने, विधेयक की, संशोधित रूप में, जांच करते समय किसी शुद्धि का सुझाव दिया हो जिसे अध्यक्ष ने प्रत्यक्ष गलती मान लिया हो, तो वह शुद्धि मुद्रित वाद-विवाद में कोई पाद टिप्पण दिए बिना संशोधन में ही अंतर्वि-ट कर ली जाएगी।

(2) ऐसे मामले में जहां अध्यक्ष ने कोई ऐसी शुद्धि मान ली हो जो सरकारी प्रारूपकार ने किसी खंड के बारे में बताई हो और जो किसी ऐसे खंड पर संशोधन के बारे में न हो, जो सभा द्वारा स्वीकार किया गया हो, तो वह शुद्धि मुद्रित वाद-विवाद में नीचे बताए गए रूप में एक उपयुक्त पाद टिप्पण के साथ दिखाई जाएगी :

“सभा द्वारा स्वीकृत (यथास्थिति) खंड.....के उप-खंड () के खंड...../भाग () के संशोधन को ध्यान में रखते हुए (यथास्थिति) खंड..... के उप-खंड () के खंड...../भाग () में आने वाले ‘.....’ शब्दों का अध्यक्ष के निदेश के अधीन प्रत्यक्ष गलतियों के रूप में लोप कर दिया गया अथवा उन्हें निवि-ट कर दिया गया।”

पारित रूप से विधेयक

34. जांच-पड़ताल, वर्ग-परिवर्तन और प्रमाणीकरण.—

(1) जब कोई विधेयक सदनों द्वारा पारित रूप में लोक सभा के पास हो, तो उसकी एक प्रति नियम 128 के अधीन रा-ट्रपति के समक्ष उपस्थित किए जाने से पहले प्रारूपकार, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के पास जांच के लिए भेजी जाएगी।

(2) यदि प्रारूपकार की राय में विधेयक पर उसी वर्ग अनुमति प्राप्त होने की संभावना न हो, जिसमें विधेयक पारित किया गया हो और प्रारूपकार यह सुझाव दे कि नाम वाले खंड में वर्ग बदल दिया जाए, तो अध्यक्ष सुझाव को मंजूर कर सकेगा/सकेगी और विधेयक के खंड 1 और दूसरे

खंडों में जहां आवश्यक हो, आनु-ांगिक परिवर्तन कर सकेगा/सकेगी।

(3) ऐसे मामले में विधेयक को उसी वर्ग में प्रमाणित किया जाएगा, जिस में उस पर अनुमति मिलने की संभावना हो।

35. रा-ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने पर विधेयकों का सभा-पटल पर रखा जाना.—संविधान के अनुच्छेद 111 के अधीन संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा रा-ट्रपति की अनुमति प्राप्त प्रत्येक विधेयक महासचिव द्वारा सभा पटल पर रखा जाएगा:

परन्तु ऐसे विधेयक के मामले में जिस पर अनुमति राज्य सभा सचिवालय द्वारा प्राप्त की गई हो, रा-ट्रपति की अनुमति प्राप्त विधेयक सभा पटल पर रखने से पूर्व राज्य सभा के महासचिव द्वारा यथाविधि प्रमाणित किया जाएगा।

विधेयकों का वापस लिया जाना और हटाया जाना

36. सरकारी विधेयकों के वापस लिए जाने के कारणों का अग्रिम परिचालन.—जब सरकार लोक सभा के विचाराधीन किसी विधेयक को वापस लेना चाहे तो संबंधित मंत्रालय द्वारा विधेयक को वापस लेने के कारणों का एक विवरण सदस्यों को उस दिन से काफी पहले परिचालित किया जाएगा जिस दिन उसे वापस लेने का प्रस्ताव किया जाता हो।

37. विधेयकों के रजिस्टर से किसी विचाराधीन विधेयक का हटाया जाना.—जब कोई विचाराधीन विधेयक किसी अधिनियम का संशोधन करने के वि-य में हो जो बाद में निरसित किया जाए तो उसे सभा के विचाराधीन विधेयकों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।

अध्याय 6

याचिकाएं

38. जांच और प्रस्तुतीकरण.—(1)जैसे ही कोई याचिका प्राप्त हो उसकी प्राप्ति स्वीकृति प्रथम अनुसूची में दिए गए प्रपत्र में भेजी जाएगी।

(2) प्रत्येक याचिका का उसे सभा में प्रस्तुत करने से पहले यह देखने के लिए परीक्षण किया जाएगा कि क्या वह —

(क) समुचित रूप में है;

(ख) सम्मानपूर्ण, शि-ट और संयत भा-ना में लिखी गई है;

(ग) नियमों और निर्णयों के, जो समय-समय पर दिए जाएं, अनुरूप है।

[(3) याचिका का परीक्षण हो जाने और उसके साधारणतः नियमानुकूल पाए जाने के बाद वह सभा में सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जायेगी:

परन्तु सभा के समक्ष विचाराधीन विधेयक संबंधी याचिका के मामले में, वह उसकी प्राप्ति के बाद यथासंभव शीघ्र सभा को प्रस्तुत की जायेगी;

परन्तु यह और भी कि एक प्रवर या संयुक्त समिति के समक्ष विचाराधीन विधेयक संबंधी याचिका के मामले में याचिका सभा में प्रस्तुत किए बिना ही समिति को निर्दिष्ट की जा सकेगी और याचिकादाता को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।]

39. दो-पूर्ण याचिकाओं का वापस लिया जाना.— यदि कोई याचिका प्रस्तुत किए जाने के बाद दो-पूर्ण पाई जाए, तो वह अध्यक्ष के आदेश से वापस ली जा सकेगी और याचिकादाता को तदनुसार सूचना दे दी जाएगी।

40. याचिकाओं की ग्राह्यता.—(1) याचिका रद्द कर दी जाएगी अथवा याचिकादाता को वापस कर दी जाएगी, यदि वह —

(एक) निजी या व्यक्तिगत शिकायतों के बारे में हो; अथवा

(दो) प्रक्रिया नियमों के नियम 160 के खण्ड (3) में उल्लिखित मामलों के बारे में हो।

(2) यदि याचिका की ग्राह्यता का निश्चय करने के लिए संबंधित मंत्रालय से कुछ तथ्यों की जानकारी लेना आवश्यक समझा जाए, तो उसे मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जा सकेगा और तथ्य इकट्ठे किए जाएंगे अथवा उनके द्वारा उस पर जो कार्यवाही की गई होगी, उसका पता लगाया जाएगा।

अध्याय 7

प्रस्ताव

41. प्रस्तावों का वर्गीकरण.—(1) सब प्रस्तावों का, जिनकी सूचनाएं, नियमों के अंतर्गत लोक सभा सचिवालय में प्राप्त होंगी, निम्न श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाएगा, अर्थात् :—

(एक) मौलिक प्रस्ताव;

(दो) स्थानापन्न प्रस्ताव; और

(तीन) गौण प्रस्ताव, जो कि आगे तीन श्रेणियों में बांटे गए हैं :—

(क) सहायक प्रस्ताव,

(ख) अवक्रामक प्रस्ताव, और

(ग) संशोधन।

(2) उपरोक्त (1) में उल्लिखित वर्गीकरण उपयुक्त प्रस्तावों के मामले में प्रयोग किया जाएगा। इन प्रस्तावों पर लागू होने वाले नियम इस प्रकार होंगे :—

(एक) **मौलिक प्रस्ताव** — मौलिक प्रस्ताव वह स्वयंपूर्ण स्वतंत्र प्रस्थापना है जिसे सदन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया

गया हो और जिसका प्रारूप इस प्रकार तैयार किया गया हो कि उससे सदन का विनिश्चय व्यक्त हो सके उदाहरणार्थ, सब संकल्प मौलिक प्रस्ताव हैं।

(दो) **स्थानापन्न प्रस्ताव** — ये प्रस्ताव जो किसी नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य वि-य पर विचार करने के मूल प्रस्ताव के स्थान पर रखने के लिए प्रस्तुत किए गए हों, स्थानापन्न प्रस्ताव कहलाते हैं। यद्यपि इन प्रस्तावों का प्रारूप ऐसे बनाया जाता है कि इनसे स्वतः कोई राय व्यक्त हो सके तथापि यथार्थरूप से ये मौलिक प्रस्ताव नहीं होते, क्योंकि ये मूल प्रस्ताव पर निर्भर होते हैं।

(तीन) **गौण प्रस्ताव** — ये अन्य प्रस्तावों पर निर्भर या उनसे संबंधित होते हैं या सभा की किन्हीं कार्यवाहियों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता और इनके द्वारा मूल प्रस्ताव या सभा की कार्यवाहियों की ओर निदेश किए बिना सभा का कोई निर्णय नहीं बताया जा सकता।

गौण प्रस्तावों को आगे निम्न रूप में बांटा गया है :—

(क) सहायक प्रस्ताव,

(ख) अवक्रामक प्रस्ताव, और

(ग) संशोधन।

(क) **सहायक प्रस्ताव** — ये ऐसे प्रस्ताव हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार का काम चलाने के लिए सभा में प्रचलित होने के कारण स्वीकृत नियमित तरीका माना गया है। सहायक प्रस्तावों के निम्न उदाहरण हैं, अर्थात् :—

(एक) कि विधेयक पर विचार किया जाए।

(दो) कि विधेयक को पारित किया जाए।

(ख) **अवक्रामक प्रस्ताव** — ये ऐसे प्रस्ताव हैं, जो कि यद्यपि रूप में स्वतंत्र होते हैं तथापि किसी अन्य प्रश्न पर वाद-विवाद में प्रस्तुत किए जाते हैं और जिनके द्वारा उस प्रश्न का अवक्रमण करना अपेक्षित होता है। सब विलम्बकारी प्रस्ताव इसी श्रेणी में आते हैं। किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में निम्न प्रस्ताव अवक्रामक प्रस्ताव होते हैं :—

(एक) कि विधेयक पुनः प्रवर समिति को सौंपा जाए।

(दो) कि विधेयक पुनः सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाए।

(तीन) कि विधेयक पर राय जानने के लिए इसे पुनः परिचालित किया जाए।

(चार) कि विधेयक पर विचार या वाद-विवाद अनिश्चित काल तक के लिए या किसी अगली तिथि तक के लिए स्थगित कर दिया जाए।

(ग) **संशोधन** — ये ऐसे गौण प्रस्ताव होते हैं, जिनके द्वारा मुख्य प्रश्न और उनके निर्णय के बीच प्रश्न और निर्णय की एक नई प्रक्रिया रखी जाती है। संशोधन विधेयक के

खण्ड में, संकल्प में या प्रस्ताव में या किसी विधेयक संकल्प या प्रस्ताव के खण्ड के संशोधनों में हो सकते हैं।

42. सदस्य, जिसे कार्यवाही में प्रस्ताव, संशोधन अथवा कटौती प्रस्ताव का प्रस्तावक दिखाया जाएगा.—जब कार्य-सूची में कई सदस्यों के नाम में रखा हुआ कोई प्रस्ताव, संशोधन या कटौती प्रस्ताव उन सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचना देने पर प्रस्तुत समझा जाए; तो उसे उस सदस्य द्वारा प्रस्तुत समझा जाएगा, जिसका नाम कार्य-सूची में पहले आता हो यदि उस सदस्य ने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के अपने अभिप्राय की सूचना न दी हो या वह सभा में उपस्थित न हो, तो दूसरे या तीसरे आदि सदस्य द्वारा, जो कि उपस्थित हो और केवल उसी सदस्य का नाम, यथास्थिति, उस प्रस्ताव, संशोधन या कटौती प्रस्ताव के प्रस्तावक के रूप में कार्यवाही में दिखाया जाएगा।

43. संशोधन अथवा कटौती प्रस्ताव जो पेश किया गया परन्तु मतदान के लिए नहीं रखा गया.—जब कोई संशोधन या कटौती प्रस्ताव पेश किया जाए परन्तु अध्यक्ष द्वारा सभा के सामने मतदान के लिए न रखा जाए और मूल प्रस्ताव या अनुदान की मांग सभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो वह संशोधन या कटौती प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत समझा जाएगा।

44. ऐसा संशोधन अथवा प्रस्ताव जो पेश किया गया परन्तु जिस पर आग्रह नहीं किया गया.—यदि वाद-विवाद के अन्त में कोई सदस्य जिसने ऐसा संशोधन या प्रस्ताव पेश किया हो जिसे अध्यक्षपीठ ने भी प्रस्तावित किया हो, अध्यक्षपीठ को सूचित करे कि वह उस पर आग्रह नहीं करना चाहता/चाहती और यदि इसके पश्चात् संशोधन या प्रस्ताव अध्यक्षपीठ द्वारा सभा के सामने मतदान के लिए न रखा जाए तो ऐसा संशोधन या प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया माना जाएगा:

परन्तु यदि कोई सदस्य अध्यक्षपीठ से निवेदन करे कि संशोधन अथवा प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखा जाए तो संशोधन अथवा प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखा जाएगा।

45. स्थानापन्न प्रस्तावों को मतदान के लिए रखने का क्रम.—(1) जब नियम 342 के अधीन किसी प्रस्ताव के स्थान पर रखने के लिए सदस्यों द्वारा मौलिक प्रस्ताव पेश किए गए हों तो अध्यक्ष स्वविवेकानुसार उन्हें निम्न क्रम से सभा के सामने मतदान के लिए प्रस्तुत कर सकेगा/सकेगी :—

(एक) मूल प्रस्ताव में उल्लिखित सरकार की नीति या कार्यवाही का अनुमोदन करने वाला प्रस्ताव; और

(दो) मूल प्रस्ताव में उल्लिखित सरकार की नीति या कार्यवाही का अनुमोदन करने वाला प्रस्ताव।

(2) जब नियम 342 के अधीन किसी प्रस्ताव के स्थान पर रखने के लिए प्रस्तुत मौलिक प्रस्तावों में से कोई प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा सभा के सामने मतदान के लिए रखा जाए और

उसी प्रस्ताव के स्थान पर रखने के लिए इस प्रकार का कोई अन्य मौलिक प्रस्ताव सभा द्वारा पारित कर दिया जाए, तो उस प्रस्ताव को, जो सभा के सामने रखा न गया हो, सभा द्वारा, यथास्थिति, अस्वीकृत या अवरुद्ध समझा जाएगा।

46. प्रवर/संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने के प्रस्ताव में प्रतिवेदन देने की तिथि का उल्लेख.—जब किसी विधेयक को प्रवर समिति या राज्य सभा की सहमति से दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव किया जाए तो प्रस्ताव में एक निश्चित तिथि उल्लिखित की जानी चाहिए, जिस तिथि को या जिससे पहले प्रवर समिति या संयुक्त समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाएगा।

परन्तु यदि उल्लिखित तिथि को सभा का सत्र न हो रहा हो तो प्रतिवेदन अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा, जो सभा के पुनः समवेत होने के यथाशीघ्र बाद उसे सभा के सामने रखवाएगा/रखवाएगी।

47. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक को वापस लेना.—गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को निबटाने के लिए नियत किसी दिन को कोई विधेयक जिसके संबंध में प्रस्ताव यह हो कि विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए, उस दिन की कार्य-सूची में पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयकों के तुरन्त बाद रखा जाएगा।

अध्याय 7क

ध्यानाकर्ण

47क. एक दिन के लिए ग्रहीत दो ध्यानाकर्ण सूचनाओं संबंधी प्रक्रिया.—(1) जब नियम 197(3) के अधीन किसी दिन की कार्य-सूची में यदि ध्यानाकर्ण के दो मामले दर्ज किए गए हों, तो संबंधित मंत्री प्रथम मामले के बारे में संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता/सकती है। दूसरे मामले में संबंधित मंत्री द्वारा सभा पटल पर वक्तव्य रखा जा सकता है। इस प्रकार रखे गए वक्तव्य की प्रतियां उन सदस्यों को दी जाएंगी, जिनके नाम उस मद के लिए कार्य-सूची में दिए गए हों¹[और मंत्री उस पर स्प-टीकरण के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देगा/देगी]।

(2) यदि किसी दिन ध्यानाकर्ण के दो में से किसी एक मामले पर प्रधानमंत्री को वक्तव्य देना हो तो उसमें उस मामले को कार्य-सूची में प्राथमिकता दी जाएगी।

अध्याय 7ख

सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

47ख. सभा की सदस्यता से त्यागपत्र (1).—प्रक्रिया नियमों के नियम 240 के अधीन त्यागपत्र तभी प्रभावी होगा जब वह अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा।

(2) त्यागपत्र उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख को वह अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है और अध्यक्ष द्वारा उसे

¹ दिनांक 10-05-1989 के लोक सभा समाचार भाग-दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा जोड़ा गया।

स्वीकार किए जाने के पश्चात् सदस्य त्यागपत्र वापस नहीं ले सकेगा/सकेगी।

(3) यदि सदस्य ने अपने त्यागपत्र के लिए आगे की तारीख विनिर्दिष्ट की है, तो त्यागपत्र इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से लागू होगा यदि अध्यक्ष ने उस तारीख तक त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

(4) त्यागपत्र उस तारीख से पहले की तारीख से स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसको कि वह अध्यक्ष या लोक सभा सचिवालय को प्राप्त हुआ है।

अध्याय 8

संसदीय समितियां

सामान्य निदेश

48. संसदीय समिति.—इस अध्याय में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो 'समिति' का तात्पर्य है और उसमें सम्मिलित है नियम 2 के उप-नियम (1) में परिभाषित "संसदीय समिति"।

48क. ¹[समितियों के लिए निर्वाचन की रीति.]—संसदीय समितियों के लिए निर्वाचन अध्यक्ष द्वारा समितियों के निर्वाचन के लिए बनाए गए विनियमों के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किए जाएंगे।

49. संसदीय समितियों पर सामान्य निदेशों का लागू होना.—ऐसे मामलों को छोड़कर जिनके लिए किसी विशेष समिति के बारे में निदेशों में विशेष उपबंध किया गया हो, अध्याय के सामान्य निदेश सब समितियों पर लागू होंगे; और यदि किसी समिति संबंधी विशेष निदेशों में कई उपबंध सामान्य निदेशों में असंगत हो तो पहला माना जाएगा।

50. बैठकों का स्थल.—(1) किसी समिति/उप-समिति की औपचारिक अथवा अनौपचारिक बैठकें जिनमें लोक सभा सचिवालय के पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों की उपस्थिति अपेक्षित हो, सदा संसद भवन की परिधि के अन्दर ही होगी। यदि किसी कारण से संसद भवन के बाहर की समिति की बैठक करना आवश्यक हो जाए तो वह मामला अध्यक्ष के निदेश के लिए सौंपा जाएगा।

(2) जब कोई समिति अध्ययनार्थ दौरे पर हो तो दौरे के स्थान पर अनौपचारिक बैठक की जा सकेगी किन्तु ऐसी बैठकों में न तो कोई निर्णय किए जाएंगे और न कोई साक्ष्य लिया जाएगा।

51. सभा की बैठक के समय समिति की बैठकों का समय .—जब तक अध्यक्ष अन्यथा अनुमति न दे, उन दिनों में जबकि सभा की बैठक चल रही हो, सभा की बैठक आरम्भ हो जाने के बाद और 15.00 बजे से पहले किसी समिति की कोई बैठक नहीं होगी।

²[51क. समितियों की बैठकों को अंतिम क्षणों में रद्द किया जाना.]—समिति के सभापति द्वारा समिति की किसी पूर्व निर्धारित बैठक को सभापति की अनुपस्थिति या उस बैठक के लिए सभापति की तत्काल अनुपलब्धता के कारण मात्र से रद्द या नियत समय से पूर्व आयोजित या स्थगित नहीं किया जाएगा।

52. समितियों में बोलने के लिए प्रक्रिया.—(1) किसी समिति की बैठक में कुछ कहने का/की इच्छुक सदस्य सभापति को सम्बोधित करेगा/करेगी और सभापति को सम्बोधित करके ही अन्य सदस्यों से सारी बातें करेगा/करेगी।

(2) जब तक सभापति न पुकारे, तब तक कोई सदस्य नहीं बोलेगा/बोलेगी।

(3) जब कोई सदस्य, जो अन्य सदस्य के भा-गण के बीच में कुछ कहना चाहे तो उसे ऐसा करने के लिए सभापति से अनुमति लेनी होगी।

52क. सदस्य का व्यक्तिगत, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित.

(1) जहां किसी समिति के सदस्य का किसी वि-य में, जिस पर समिति द्वारा विचार किया जाना हो, व्यक्तिगत, आर्थिक अथवा प्रत्यक्ष हित हो, तो ऐसा सदस्य उसमें अपने हित को समिति के सभापति के द्वारा अध्यक्ष को बता देगा/देगी।

(2) अध्यक्ष उस वि-य पर विचार करने के पश्चात् अपना निर्णय देगा/देगी जो अन्तिम होगा।

53. मतदान के लिए प्रश्न का रखा जाना.—सभापति, यदि यह समझे कि किसी प्रश्न पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है तो वह आगे और चर्चा के बिना प्रश्न मतदान के लिए रख सकेगा/सकेगी और उसके बारे में किसी निश्चय पर पहुंच सकेगा/सकेगी।

54. प्रश्न पर पुनर्विचार.—यदि कोई सदस्य किसी ऐसे प्रश्न पर पुनर्विचार कराना चाहे जिस पर समिति पहले ही निर्णय कर चुकी हो तो सदस्य को वैसा करने के लिए पहले, सभापति की अनुमति लेनी होगी।

55. कार्यवाही तथा कुछ दस्तावेज गोपनीय समझे जाएंगे.—(1) समिति की कार्यवाही गोपनीय समझी जाएगी और समिति के किसी सदस्य को या किसी को जिसकी उस कार्यवाही तक पहुंच है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसकी कार्यवाही और प्रतिवेदन या अन्तिम रूप से या अस्थायी रूप से निकाले गए नि-क-र्णों के बारे में, प्रतिवेदन के सभा में उपस्थापन से पहले प्रेस को कोई जानकारी देने की आज्ञा नहीं होगी।

(1क) खण्ड (1) के उपबंध, आवश्यक परिवर्तनों सहित उन बैठकों की कार्यवाहियों के संबंध में भी लागू होंगे जो

¹दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग-दो के पैरा संख्या 2931 अन्तःस्थापित किया गया।

²दिनांक 25.06.2010 के लोक सभा समाचार भाग-दो के पैरा संख्या 1522 द्वारा जोड़ा गया।

अध्यक्ष द्वारा लोक सभा के दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ की जाएगी।

(2) जब कभी 'गुप्त' या 'गोपनीय' अंकित कोई पत्र या दस्तावेज किसी समिति के सदस्यों को परिचालित किया जाए, तो किसी भी सदस्य द्वारा उस पत्र या दस्तावेज की वि-य-वस्तु अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विमत टिप्पण में या सभा में, या अन्यथा प्रकट नहीं की जाएगी; और जब ऐसी आज्ञा मिल जाए, तो उस रीति या उस सीमा के बारे में, जिसके अनुसार उस दस्तावेज में आई हुई जानकारी प्रकट की जाए, अध्यक्ष द्वारा लगाए गए किसी बन्धन का कठोरता के साथ पालन किया जाएगा।

56. उप-समितियों संबंधी प्रक्रिया.—(1) यदि कोई समिति विशेष बातों पर विचार करने के लिए नियम 263(1) के अधीन एक उप-समिति नियुक्त करे, तो उप-समिति का प्रतिवेदन, उप-समिति की ओर से सभापति के समुचित हस्ताक्षरों सहित विहित अवधि तक प्रस्तुत किया जाएगा और उसकी प्रतियां समिति के सभी सदस्यों को उनके उप-समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए समवेत होने से पहले उपलब्ध करा दी जाएंगी।

(2) समिति का सभापति, उप-समिति के सभापति को नियुक्त करेगा/करेगी।

(3) उप-समिति में यथासम्भव उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, जिसका सम्पूर्ण समिति में किया जाता है।

57. विशेष-ज्ञों एवं संबद्ध पक्षों का साक्ष्य.—(1) समिति अपने आप या अनुरोध किए जाने पर विशेष-ज्ञों, या दिलचस्पी लेने वाले पक्षों का साक्ष्य ले सकेगी।

(2) जो साक्षी किसी समिति के समक्ष आने की इच्छा व्यक्त करेंगे वे लिखित ज्ञापनों की पर्याप्त प्रतियां समिति के सदस्यों को परिचालन के लिए भेजेंगे, जो अपनी बैठक में उन पर विचार और फिर निर्णय कर सकेंगे कि क्या उन साक्षियों को समिति के समक्ष आने के लिए बुलाया जाए।

58. सार्वजनिक समझा जा सकने वाला साक्ष्य.—जब साक्षी समिति के समक्ष साक्ष्य देने आए, तो सभापति साक्षियों को यह स्पष्ट कर देगा/देगी कि उनका साक्ष्य सार्वजनिक समझा जाएगा और प्रकाशित किया जा सकता है, जब तक कि वे स्पष्टतः यह न चाहें कि उनके द्वारा किए गए साक्ष्य का पूरा या कोई अंश गोपनीय समझा जाए। फिर भी साक्षियों को यह स्पष्ट बताया जाएगा कि भले ही वे यह चाहें कि उनका साक्ष्य गोपनीय समझा जाए, वह साक्ष्य संसद सदस्यों को उपलब्ध किया जा सकेगा।

59. भारत सरकार तथा उपक्रमों के अधिकारियों का साक्ष्य.—(1) ऐसे मामले में जहां किसी मंत्रालय अथवा विभाग या उपक्रम को किसी मामले पर समिति के समक्ष साक्ष्य देना हो तो उस मंत्रालय या विभाग या उपक्रम की ओर से यथास्थिति, उसका सचिव अथवा विभागाध्यक्ष साक्ष्य देगा/देगी:

परन्तु समिति का सभापति इस निमित्त निवेदन किए जाने पर किसी अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी को समिति के समक्ष मंत्रालय अथवा विभाग या उपक्रम का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे सकेगा/सकेगी।

(2) समिति मंत्रालय अथवा विभाग या उपक्रम से इस बात की मांग कर सकती है कि वे लोक सभा सचिवालय को ऐसे ज्ञापनों की प्रतियां पर्याप्त संख्या में दें जिनमें चर्चाधीन वि-य पर उनके विचार हों ताकि वे समिति के सदस्यों को उस तिथि से पहले जिसको मंत्रालय अथवा विभाग या उपक्रम के प्रतिनिधि समिति के समक्ष साक्ष्य देना चाहें, को परिचालित किया जा सके।

(3) मंत्रालय अथवा विभाग या उपक्रम के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए साक्ष्य का सारांश बैठकों के कार्यवाही सारांश में सम्मिलित किया जा सकेगा अथवा परिशिष्ट के रूप में लगाया जा सकेगा।

60. राज्य सरकार के पदाधिकारियों का साक्ष्य.—

(1) जब किसी राज्य सरकार के पदाधिकारी को किसी समिति के समक्ष अपने साक्षी के रूप में उपस्थित होने का आमंत्रण देना या राज्य सरकार से कोई दस्तावेज या पत्र समिति के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहना आवश्यक समझा जाए, तो उस पदाधिकारी या राज्य सरकार से प्रार्थना करने से पहले अध्यक्ष के आदेश ले लिए जाएंगे।

(2) यदि अध्यक्ष यह निर्णय करें कि राज्य के किसी विशिष्ट पदाधिकारी को साक्षी के रूप में बुलाना आवश्यक नहीं है या राज्य सरकार से कोई पत्र, दस्तावेज या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, तो संबंधित समिति का सभापति यदि आवश्यक समझे, तो वह समिति को अध्यक्ष के निर्णय से अवगत करा सकेगा/सकेगी।

61. साक्षियों द्वारा दिए गए ज्ञापनों पर विचार.—

समिति पहले तो साक्षियों द्वारा दिए गए ज्ञापनों पर, जब उनकी प्रतियां समिति के सभी सदस्यों को परिचालित की गई हों, विचार करेगी और साक्षियों से पूछे जाने वाले प्रश्न उनके ज्ञापनों में शामिल की गई किन्हीं बातों के स्पष्टीकरण या चर्चा से उठने वाली किन्हीं दूसरी नई बातों के रूप में होंगे।

62. साक्षियों की जांच की रीति.—(1) सभापति पहले कोई प्रश्न पूछ सकेगा/सकेगी और उसके बाद वह एक-एक करके समिति के दूसरे सदस्यों से प्रश्न पूछने के लिए कह सकेगा/सकेगी।

(2) साक्षी सभापति की अनुमति से समिति के सामने कोई दूसरी संगत जानकारी रख सकेंगे जो पहले समिति के समक्ष न रखी जा चुकी हो।

63. समिति के विचाराधीन वि-यों के बारे में संदेश भेजने की रीति.—किसी समिति के समक्ष विचाराधीन वि-यों के बारे में मंत्रालयों से सारे संदेश और व्यक्तियों, संस्थाओं और सार्वजनिक निकायों से प्राप्त होने वाले सारे सुझाव, ज्ञापन तथा अभ्यावेदन इत्यादि महासचिव के नाम भेजे जाएंगे

और यदि किसी मामले में कोई पत्र, ज्ञापन इत्यादि सभापति के नाम अथवा उनको सीधे भेजा जाए तो सभापति ऐसे पत्र, ज्ञापन आदि लोक सभा सचिवालय को कार्यवाही करने तथा अभिलेख के लिए भेज सकेगा/सकेगी।

63क. मंत्रालयों के विचार अध्यक्ष को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया.—यदि कोई मंत्रालय या विभाग किसी वि-य के बारे में जिस पर किसी समिति ने विचार कर लिया हो, या वह उसके समक्ष विचाराधीन हो, अध्यक्ष को अपने विचार प्रस्तुत करना चाहे, तो वह जिन बातों पर अध्यक्ष का निर्णय चाहता हो उन्हें ठीक-ठीक लिख कर एक लिखित विवरण लोक सभा सचिवालय को भेजेगा। इसके बाद वह विवरण समिति के विचारों से सम्बद्ध पत्रों सहित अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा जो कोई निर्णय करने से पूर्व यदि आवश्यक हो, तो उसे उस वि-य पर संबंधित मंत्री और/या समिति के सभापति से चर्चा कर सकेगा/सकेगी।

64. समितियों के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में से शब्दों आदि का निकाला जाना.—(1) यदि सभापति की राय में समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज, जैसे अभ्यावेदन, ज्ञापन इत्यादि में ऐसे शब्द, वाक्य खण्ड अथवा अभिव्यक्तियां हों जो असंसदीय, असंगत हों अथवा जो विनम्र, शि-ट और संयत भा-ना में न हों अथवा अन्यथा अनुचित हों, तो वह ऐसे शब्दों, वाक्य खण्डों अथवा अभिव्यक्तियों को उस दस्तावेजों से निकालने का आदेश दे सकेगा/सकेगी।

(2) उपरोक्त (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष को ऐसी ही परिस्थितियों में किसी चीज को निकालने का आदेश देने अथवा उस प्रकार के दस्तावेजों से किसी चीज के निकालने के संबंध में किए गए उन सब विनिश्चयों के पुनरीक्षण का अधिकार होगा और उनके संबंध में अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

65. शब्दशः कार्यवाही.—(1) समिति की शब्दशः कार्यवाही, यदि रखी गई हो तो, गोपनीय समझी जाएगी और अध्यक्ष के आदेश के बिना किसी को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

(2) जिस बैठक में साक्ष्य दिया गया हो उसकी शब्दशः कार्यवाही के संगत अंश संबंधित और सदस्यों को पु-टि करने और लोक सभा सचिवालय द्वारा निश्चित की गई तिथि तक वापस करने के लिए भेज दिए जाएंगे। यदि कार्यवाही की शुद्ध की हुई प्रतियां निश्चित तिथि तक नहीं लौटाई जाएंगी, तो रिपोर्टर की प्रति को ही अधिकृत माना जाएगा।

(3) शब्दशः कार्यवाही में शुद्धियां, यदि कोई हों, तो यथास्थिति साक्षी या सदस्य द्वारा अपने हाथ से साफ-साफ अक्षरों में लिख कर स्याही से की जाएंगी और वे केवल ऐसी अशुद्धियों को ठीक करने तक सीमित रहेंगी, जो लिखने में रह गई हों और उनका साहित्यिक रूप सुधारने या उनमें परिवर्द्धन करके या निकाल कर सारांश को बदलने के प्रयोजन से नहीं की जाएंगी।

66. कार्यवाही सारांश.—(1) समिति के निर्णय संक्षेप में समिति के कार्यवाही सारांश में अभिलिखित किए जाएंगे।

(2) कार्यवाही सारांश का प्रारूप लोक सभा सचिवालय द्वारा तैयार किया जाएगा और सभापति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक बैठक का कार्यवाही सारांश समिति के सदस्यों को भेजा जा सकेगा। उसमें से संगत अंश यदि आवश्यक समझा जाए तो किसी मंत्रालय अथवा पदाधिकारी को भी भेजे जा सकेंगे।

(4) यदि कोई सदस्य कार्यवाही सारांश में इस आधार पर कोई रूप भेद करना चाहे कि वे किए गए निर्णय के अनुरूप नहीं हैं तो वह मामला समिति की अगली बैठक में रखा जाएगा और उस संबंध में समिति जो निर्णय करेगी उसको बैठक के कार्यवाही सारांश में समावि-ट कर लिया जाएगा।

(5) जब तक कार्यवाही सारांश सभा में प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते, तब तक उन्हें गोपनीय समझा जाएगा।

67. कार्यवाही सारांश का सभा पटल पर रखा जाना.—

(1) सभापति द्वारा अथवा सभापति की अनुपस्थिति में, समिति के उस सदस्य द्वारा जिसने कि बैठक अथवा बैठकों का जैसी भी स्थिति हो, सभापतित्व किया हो, समिति की बैठक अथवा बैठकों के कार्यवाही सारांश का अनुमोदन किए जाने के बाद, उसकी एक प्रमाणीकृत प्रति सभा पटल पर रखी जा सकेगी।

(2) उस दिन की कार्य-सूची में सभा पटल पर कार्यवाही सारांश के रखे जाने के बारे में एक प्रवि-टि की जाएगी।

(3) सभापति अथवा समिति के सदस्य द्वारा कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखते समय केवल निम्नलिखित रूप में वक्तव्य दिया जाएगा:—

‘श्रीमान, मैं.....को हुई.....समिति की.....बैठक (अथवा बैठकों) के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता/रखती हूं। ‘

68. प्रतिवेदन.—(1) समिति समय-समय पर सभा को अथवा अध्यक्ष को जैसी भी स्थिति हो, प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

(2) प्रतिवेदन का प्रारूप लोक सभा सचिवालय द्वारा तैयार किया जाएगा और सभापति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद समिति के समक्ष रखा जा सकेगा।

(3) प्रतिवेदन के संबंध में कोई विमत टिप्पण नहीं होगा।

69. प्रतिवेदनों के प्रारूपों का परिचालन और उस पर विचार.—(1) समिति का/की सभापति यह निदेश दे सकेगा/सकेगी कि प्रतिवेदन के प्रारूप तथा उसके साथ सम्बद्ध किन्हीं अन्य दस्तावेजों की टाइप की हुई, साइक्लोस्टाइल की हुई अथवा प्रूफ की प्रतियां प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार के

लिए नियत तिथि से पहले समिति के सदस्यों में परिचालित की जाएं।

(2) प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार के लिए नियत तिथि को सभापति प्रतिवेदन के प्रारूप को कंडिकावार पढ़ेगा/पढ़ेगी और प्रत्येक कंडिका के अन्त में समिति के सामने यह प्रश्न रखेगा/रखेगी “कि कंडिका प्रतिवेदन का अंग बने”। प्रतिवेदन के किसी अंश के किए गए विनिश्चयों के अनुरूप न होने की आपत्ति करने वाला सदस्य उसे विनिश्चयों के अनुरूप बनाने के लिए अपना संशोधन प्रस्तुत करेगा/करेगी। संशोधन यदि स्वीकृत हो जाए तो, कथित कंडिका में समाविष्ट कर लिया जाएगा।

70. प्रतिवेदन में साक्ष्य का उल्लेख और उनका परिचालन.—(1) समिति प्रतिवेदन में जहां कहीं आवश्यक हो, इस बात का उल्लेख करेगी कि उसके समक्ष साक्ष्य दिया गया था।

(2) साक्ष्य का अभिलेख, यदि समिति वैसा विनिश्चय करे तो छापा जाएगा और उसकी प्रतियां सभा के सब सदस्यों में परिचालित की जाएंगी।

71. समिति के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर.—सभापति अथवा सभापति की अनुपस्थिति में नियम 258(3) अथवा नियम 277(3) के अधीन समिति द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य, यथास्थिति समिति की ओर से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करेगा/करेगी ।

71क. सभा का सत्र न होने पर समिति के प्रतिवेदन का अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाना.—(1) साधारणतया समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाएगा, परन्तु यदि समिति ऐसे समय अपना प्रतिवेदन पूरा कर ले जब सभा का सत्र न हो रहा हो तो समिति का/की सभापति उसे अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा/सकेगी।

(2) अध्यक्ष नियम 280 के उपबन्धों के अधीन प्रतिवेदन के सभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व उसके मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन के लिए आदेश दे सकेगा/सकेगी ।

(3) यदि प्रतिवेदन अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो अथवा उसके मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन के लिए अध्यक्ष द्वारा आदेश दिया गया हो, तो इस बात की सूचना समाचार भाग-दो में दी जाएगी।

(4) अध्यक्ष प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन अथवा परिचालन और बाद में उसके सभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व समिति द्वारा प्रार्थना किए जाने पर अध्यक्ष निदेश दे सकेगा/सकेगी कि तथ्यात्मक बातों अथवा प्रत्यक्ष गलतियों को शुद्ध कर लिया जाए।

(5) प्रतिवेदन अगले सत्र में प्रथम सुविधाजनक अवसर पर सभापति द्वारा या सभापति की अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय सभापति या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला सदस्य इस आशय का एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा/देगी कि जब सभा का सत्र नहीं हो रहा था उस समय यह प्रतिवेदन अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और अध्यक्ष द्वारा इसके मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन के लिए नियम 280 के अधीन आदेश दिया गया था।

(6) यदि प्रतिवेदन के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद और सभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व लोक सभा विघटित हो जाए तो प्रतिवेदन महासचिव द्वारा प्रथम सुविधाजनक अवसर पर नई लोक सभा के पटल पर रखा जाएगा। प्रतिवेदन को पटल पर रखते समय महासचिव इस आशय का एक वक्तव्य देगा/देगी कि प्रतिवेदन को पहली लोक सभा के विघटन से पूर्व उसके अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और यदि अध्यक्ष द्वारा नियम 280 के अधीन उसके मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन के लिए आदेश दिए गए हों, तो महासचिव इस बात की सूचना भी सभा को देगा/देगी।

71ख. प्रतिवेदनों में प्रत्यक्ष गलतियों अथवा तथ्य संबंधी वि-याँ में शुद्धि.—समिति/उप-समिति के सभापति को समिति/उप-समिति द्वारा स्वीकृत प्रतिवेदन में उसके यथास्थिति सभा/अध्यक्ष अथवा सम्पूर्ण समिति को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्रत्यक्ष गलतियों अथवा तथ्य संबंधी वि-याँ को शुद्ध करने की शक्ति होगी।

72. प्रतिवेदनों का मुद्रण तथा परिचालन.—(1) प्रतिवेदन उससे संबंधित दस्तावेजों सहित यदि कोई हों तो उसके सभा में अथवा अध्यक्ष को जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तुत किए जाने से पहले अथवा बाद में छापा जाएगा।

(2) जब तक प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत न किया जाए तब तक वह गोपनीय समझा जाएगा।

(3) सभा में प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के यथाशीघ्र बाद प्रतिवेदन की छपी हुई प्रतियां लोक सभा के सदस्यों और भारत सरकार के मंत्रालयों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों, प्राधिकारियों इत्यादि को भेजी जाएंगी जिन्हें भेजने का समय-समय पर निर्णय किया जाए।

73. नियम 280 के अधीन सदस्यों को परिचालित प्रतिवेदनों के समाचारपत्रों के विमोचन का समय.—जब नियम 280 के अधीन किसी समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व सदस्यों को परिचालित कर दिया जाए, तो सदस्यों को प्रतियां भेजने की तिथि के एक सप्ताह पश्चात् वह समाचारपत्रों को दे दिया जाएगा।

³[समिति प्रतिवेदनों पर मंत्री द्वारा वक्तव्य]

73क. समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन.—मंत्री संबंधित मंत्रालय से संबंधित लोक सभा की विभागों से

सम्बद्ध स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में अंतर्वि-ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सभा में छह महीनों में एक बार एक वक्तव्य देगा/देगी।]

विधेयकों संबंधी प्रवर/संयुक्त समितियां

74. प्रवर/संयुक्त समितियों को भेजे गए ज्ञापन या अभ्यावेदन.— जब किसी विधेयक संबंधी प्रवर/संयुक्त समिति को भेजा गया कोई ज्ञापन/अभ्यावेदन समिति की बैठक के बाद किसी समय लोक सभा सचिवालय में प्राप्त हो तो वह समिति के अभिलेखों का अंश बन जाएगा और जब तक कि उसे समिति के प्रतिवेदन के साथ या अलग से सभा में प्रस्तुत न कर दिया जाए कोई व्यक्ति अध्यक्ष की अनुमति के बिना उसमें उद्धरण नहीं दे सकेगा/सकेगी या किसी और को उसकी प्रतियां नहीं भेज सकेगा/सकेगी।

75. संशोधन की सूचना और ग्राह्यता.—(1) यदि कोई सदस्य प्रवर/संयुक्त समिति की बैठक में संशोधन प्रस्तुत करना चाहता/चाहती हो तो सदस्य को एक दिन पहले उन संशोधनों की सूचना की एक प्रति लोक सभा सचिवालय को भेजनी होगी। संशोधनों की प्रतियां लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रवर/संयुक्त समिति की बैठकों में चर्चा की सुविधा के लिए प्रवर/संयुक्त समिति के सभी सदस्यों के पास भेजी जाएंगी।

(2) यदि कोई प्रश्न उठे कि क्या कोई विशेष संशोधन विधेयक के क्षेत्र में है, तो इस प्रश्न का निर्णय प्रवर/संयुक्त समिति के सभापति द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

76. विधेयक पर सामान्य चर्चा नहीं होगी.—विधेयक को प्रवर/संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकार करके सभा द्वारा उसका सिद्धांत मंजूर किए जाने के बाद समिति में समूचे विधेयक पर आगे सामान्य चर्चा करने की आज्ञा नहीं होगी।

77. विधेयक पर खंड-वार चर्चा.—सभापति सामान्यतः विधेयक को प्रवर/संयुक्त समिति के समक्ष खण्ड-वार रखेगा/रखेगी और सदस्यों से उनकी टिप्पणियां यदि कोई हों, तो करने के लिए कहेगा/कहेगी और उसके बाद सदस्य अपने संशोधन, यदि कोई हों तो, प्रस्तुत कर सकेगा/सकेगी।

78. प्रतिवेदन के प्रारूप और विधेयक के यथासंशोधित रूप पर विचार.—विधेयक पर खण्ड-वार विचार पूरा हो जाने के बाद सभापति प्रतिवेदन के प्रारूप और यथासंशोधित विधेयक पर विचार करने के प्रयोजन से उसके बाद, तीन दिन से पहले नहीं, जब तक कि समिति द्वारा एकमत से कम अवधि निर्धारित न की जाए, प्रवर/संयुक्त समिति की एक बैठक निश्चित करेगा/करेगी।

79. समिति की प्रगति की सूचना अध्यक्ष को दी जाएगी.—(1) सभापति प्रवर/संयुक्त समिति के काम की प्रगति के बारे में अध्यक्ष को समय-समय पर सूचित करता रहेगा/करती रहेगी।

(2) जब कभी किसी प्रवर/संयुक्त समिति में उसके समक्ष विधेयक के बारे में प्रगति ऐसी हो जिससे प्रतिवेदन के सभा में प्रस्तुतिकरण में देर हो जाने की सम्भावना हो, तो जैसे ही सभापति को यह स्प-ट हो जाए कि वैसी देर होने की सम्भावना है, वैसे ही उस मामले को अध्यक्ष के ध्यान में लाया जाएगा। सभापति उन परिस्थितियों को, जो इस देर के लिए जिम्मेदार हैं तथा काम पूरा होने में लगने वाले अनुमानित समय को और किसी दूसरे मामले को, जो सभापति के विचार से अध्यक्ष के ध्यान में लाया जाना चाहिए संक्षेप में बताएगा/बताएगी।

80. प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण का समय बढ़ाना.—(1) सभापति या सभापति की अनुपस्थिति में समिति का कोई सदस्य, जिसे समिति ने प्राधिकृत किया हो, निदेश संख्या 79(2) के अनुसार अध्यक्ष को सूचित करने के बाद सभा में प्रस्ताव करेगा/करेगी कि प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण का समय प्रस्ताव में उल्लिखित किसी निश्चित तिथि तक बढ़ा दिया जाए।

(2) वह तिथि जिस तक कि प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण का समय बढ़ाना अपेक्षित हो इस तर्कसंगत धारणा पर निश्चित की जा सकती है कि उस तिथि को सभा का सत्र हो रहा होगा। किन्तु यदि ऐसा हो कि इस प्रकार निश्चित की गई तिथि को सभा का सत्र न हो रहा हो, तो प्रतिवेदन उस तिथि को या उससे पहले जैसा कि समिति निर्णय करे, अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा और अध्यक्ष सभा के पुनः समवेत होने के बाद यथासंभव शीघ्र उसे सभा के सामने रखवाएगा/रखवाएगी।

81. सदस्यों द्वारा विधेयकों पर ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना.—(1) प्रवर/संयुक्त समिति द्वारा विधेयक पर अंतिम रूप से विचार समाप्त किए जाने से पूर्व किसी समय समिति का कोई भी सदस्य कोई ज्ञापन अथवा टिप्पण जिसमें विधेयक के संबंध में अपने विचार लिख कर दिए हों, प्रस्तुत कर सकेगा/सकेगी।

(2) सभापति, यदि उचित समझे, तो यह निदेश दे सकेगा/सकेगी कि टिप्पण या उसके उद्धरणों की प्रतियां समिति के सदस्यों में परिचालित की जाएं।

82. विधेयकों संबंधी याचिकाएं प्रवर/संयुक्त समितियों को निर्दि-ट समझी जाएंगी.—सभी याचिकाएं जो लोक सभा सचिवालय में प्राप्त हों और नियमों के अधीन ग्राह्य मानी जाएं, उस विधेयक जिससे उनका संबंध हो, संबंधी प्रवर/संयुक्त समिति को, यदि वैसी कोई समिति बनाई गई हो, निर्दि-ट समझी जाएगी। समिति द्वारा उन याचिकाओं का परीक्षण किया जाएगा, जो उन याचिकादाताओं की, जिनको वह आवश्यक समझे, सुनवाई भी कर सकेगी।

83. याचिकाओं आदि का ब्यौरा और उन पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदनों में उल्लेख.—जब किसी प्रवर/संयुक्त समिति को कोई याचिका, अभ्यावेदन अथवा ज्ञापन प्राप्त हो,

तो समिति के प्रतिवेदन में प्राप्त होने वाले ऐसे दस्तावेजों की संख्या बताई जाएगी और उसके साथ एक परिशि-ट भी जोड़ा जाएगा जिसमें संक्षेप में उनका ब्यौरा और उन पर की गई कार्यवाही दी हुई होगी।

84. प्रतिवेदन का प्रतिरूप.—जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे, तो किसी विधेयक संबंधी प्रवर/संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में, प्रत्येक मामले के तथ्यों को देखते हुए आवश्यकतानुसार प्राक्कथनात्मक कण्डिकाएं होंगी जैसी कि द्वितीय अनुसूची में दी हुई हैं।

85. विमत-टिप्पण.—यदि कोई सदस्य प्रवर/संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में विमत-टिप्पण जोड़ना चाहे तो सदस्य फुलस्केप आकार के कागज पर स्याही में लिखा हुआ या टाइप किया हुआ विमत-टिप्पण का सारांश समिति के सभापति द्वारा निश्चित की गई तिथि और समय तक या उससे पहले प्रवर/संयुक्त समितियों के प्रभारी पदाधिकारी को दे देगा/देगी।

86. विमत-टिप्पण की तिथि.—यदि सदस्य द्वारा भेजे गए किसी विमत-टिप्पण में तिथि न दी हुई हो, तो जिस तिथि को वह लोक सभा सचिवालय में प्राप्त हो वह तिथि हस्ताक्षर करने वाले के नाम के आगे निम्न रूप में दिखाई जाएगी:—

“[.....20.....को प्राप्त हुआ]”

87. समिति द्वारा प्रतिवेदन स्वीकृत करते समय अनुपस्थित सदस्य का विमत-टिप्पण.—कोई सदस्य जो किसी समिति की उस बैठक या बैठकों में, जिसमें समिति के प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार किया गया हो और उसे संशोधनों सहित अथवा उनके बिना जैसे भी स्थिति हो स्वीकृत किया गया हो, अनुपस्थित था, लिखित रूप में यह प्रमाणित करने के बाद कि उसने प्रतिवेदन को पढ़ लिया है विमत-टिप्पण दे सकेगा/सकेगी।

88. समिति को निदेश 87 की सूचना दी जाएगी.—विधेयक पर खण्ड-वार चर्चा समाप्त होने के बाद सभापति समिति को निदेश 87 के उपबन्धों की सूचना देगा/देगी।

89. प्रतिवेदन स्वीकृत हो जाने के पश्चात् विमत-टिप्पण का दिया जाना.—विमत-टिप्पण केवल समिति द्वारा प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार और स्वीकृत हो जाने के बाद दिया जाएगा और इसके साथ किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होगी।

90. प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के बाद विमत-टिप्पण स्वीकार नहीं होगा.—प्रतिवेदन के सभा में प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद कोई विमत-टिप्पण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

91. विमत-टिप्पण से शब्दों आदि का निकाला जाना.—

(1) यदि सभापति की राय में किसी विमत-टिप्पण में ऐसे शब्द, वाक्यांश या अभिव्यक्तियां हों, जो असंसदीय, असंगत या अन्यथा अनुपयुक्त हों, तो वह ऐसे शब्दों, वाक्यांशों या अभिव्यक्तियों

को विमत-टिप्पण में से निकाल देने का आदेश दे सकेगा/सकेगी।

(2) उपरोक्त (1) में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष को इसी प्रकार की परिस्थितियों में शब्द आदि निकालने का आदेश देने या विमत-टिप्पण में से शब्दों आदि के निकाले जाने से संबंधित निर्णयों का पुनरीक्षण करने का अधिकार होगा और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

92. प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज.—प्रवर/संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी सभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात्—

(एक) प्रवर/संयुक्त समिति की विभिन्न बैठकों के कार्यवाही सारांश;

(दो) सरकारी संशोधन, यदि कोई हों; और

(तीन) अन्य महत्वपूर्ण पत्र, यदि कोई हों, जो प्रवर/संयुक्त समिति के सदस्यों को उपलब्ध किए गए हों, और समिति के सभापति द्वारा सभा में प्रस्तुतिकरण के लिए अनुमोदित किए गए हों।

93. प्रतिवेदन का मुद्रण तथा परिचालन.—(1) जैसे ही प्रवर/संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाए, प्रतिवेदन को निम्नलिखित पत्रों के साथ छापा जाएगा और सभा के सदस्यों में परिचालित किया जाएगा:—

(क) टिप्पण और विमत-टिप्पण, यदि कोई हो;

(ख) विधेयक प्रवर/संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में;

(ग) प्रवर/संयुक्त समिति की विभिन्न बैठकों में कार्यवाही सारांश;

(घ) सरकारी संशोधन, यदि कोई हों; और

(ङ) प्रवर/संयुक्त समिति के सदस्यों को उपलब्ध किए गए अन्य महत्वपूर्ण पत्र, यदि कोई हों।

(2) मद (ग) से (ङ) में बताए गए पत्र, जहां आवश्यक हो, अलग से छापे जा सकेंगे।

याचिका समिति

94. याचिकाओं पर विचार.—सभा के समक्ष याचिका के प्रस्तुतिकरण के बाद याचिका समिति उस पर विचार करने के लिए यथाशीघ्र समवेत होगी:

परन्तु यदि कोई याचिका ऐसे विधेयक के संबंध में हो, जो सभा के विचाराधीन हो, तो सभा में उसके प्रस्तुतिकरण अथवा प्रतिवेदन के बाद याचिका समिति यथाशीघ्र समवेत होगी और सभा में विधेयक के लिए जाने से पर्याप्त पहले यथास्थिति, सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी या सदस्यों को इस याचिका के परिचालन का निदेश देगी:

परन्तु यह और भी कि पहले से ही सभा के चर्चाधीन किसी विधेयक पर याचिका की स्थिति में याचिका समिति

उसकी प्राप्ति के पश्चात् उसके प्रस्तुत किए जाने पर तुरन्त उस पर विचार करने के लिए समवेत होगी और सभा द्वारा उस विधेयक को पारित किए जाने से पर्याप्त पहले, यथास्थिति सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी या सदस्यों को उस याचिका के परिचालन का निदेश देगी।

95. अभ्यावेदनों आदि पर विचार.—समिति विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों, पत्रों और तारों पर, जो याचिका संबंधी नियमों के अंतर्गत नहीं आते, विचार करने के लिए भी आवश्यकतानुसार समय-समय पर अपनी बैठक करेगी और उनको निबटाने के लिए निदेश देगी:

परन्तु उन अभ्यावेदनों पर, जो निम्नलिखित श्रेणी में आते हैं, समिति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, किन्तु उन्हें सचिवालय में उनकी प्राप्ति पर फाइल कर दिया जाएगा:—

(1) गुमनाम पत्र या ऐसे पत्र जिन पर भेजने वाले के नाम और/या पते न दिए हों या वे स्प-ट न हों; और

(2) अध्यक्ष या सभा के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों को सम्बोधित पत्रों की नामांकित प्रतियां, जब तक कि ऐसी किसी प्रति पर शिकायत को दूर करने की विशेष-प्रार्थना का उल्लेख न हो।

96. याचिकादाता को सूचित किया जाना.—प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के बाद याचिकादाता को इसके बारे में सूचित किया जाएगा।

वित्तीय समितियां—प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

4[96क** **** ****]**

97. वित्तीय समितियों के सभापति या सदस्यों की सरकारी समितियों के सदस्यों के रूप में नियुक्ति.—(1) जब कभी प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के किसी सदस्य या सभापति को सरकार द्वारा गठित किसी समिति की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया जाए तो नियुक्ति स्वीकार करने से पूर्व वह मामला अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा।

(2) यदि अध्यक्ष यह बात ठीक न समझे कि प्राक्कलन या लोक लेखा अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का कोई सदस्य या सभापति सरकार द्वारा गठित समिति में काम करे जब तक कि सभापति या सदस्य प्राक्कलन या लोक लेखा अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सदस्य रहता है तो वह सदस्य या सभापति सरकार द्वारा बनाई गई समिति की सदस्यता की नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा/करेगी।

(3) जहां संसदीय कार्य के हित में अध्यक्ष प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति या सदस्य को, जैसी भी स्थिति

हो, सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति की सदस्यता स्वीकार करने की अनुमति दे दे तो अध्यक्ष यह मांग कर सकेगा/सकेगी कि सरकारी समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करने से पूर्व, यथास्थिति, प्राक्कलन या लोक लेखा अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के समक्ष ऐसी टिप्पणी के लिए जैसा कि वह समिति ठीक समझे, रखा जाएगा।

97क. सरकारी समिति के सदस्यों की वित्तीय समितियों के सभापति या सदस्यों के रूप में नियुक्ति.—(1) जब कभी कोई सदस्य, जो सरकार द्वारा गठित किसी समिति का सदस्य हो, प्राक्कलन समिति अथवा लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सदस्य निर्वाचित हो जाए, जो इस वि-य को अध्यक्ष के समक्ष इस बात का निर्णय करने के लिए रखा जाएगा कि क्या उस सदस्य को पहली समिति की सदस्यता बनाए रखने की अनुमति होगी।

(2) जहां अध्यक्ष किसी सदस्य के यथास्थिति, प्राक्कलन समिति अथवा लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए निर्वाचित हो जाने पर उसका सरकारी समिति के सदस्य के रूप में काम करना अनुपयुक्त समझे, तो यदि अध्यक्ष ऐसा चाहेगा/चाहेगी, तो उस सदस्य को सरकार द्वारा गठित समिति की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा।

(3) जहां संसदीय कार्य के हित में, अध्यक्ष प्राक्कलन समिति अथवा लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए निर्वाचित किसी सदस्य को सदस्य बने रहने की अनुमति दे दें तो अध्यक्ष यह मांग कर सकेगा/सकेगी, कि सरकारी समिति का प्रतिवेदन, सरकार को प्रस्तुत करने से पूर्व, यथास्थिति, प्राक्कलन समिति अथवा लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के समक्ष ऐसी टिप्पणी के लिए जैसे कि वह समिति ठीक समझे रखा जाएगा।

98. प्राक्कलन समिति द्वारा नीति संबंधी मामलों की जांच.—(1) नियम 310 के खण्ड (क) में उल्लिखित 'नीति' शब्द केवल उन नीतियों के संबंध में है जो संसद ने संविधियों द्वारा या समय-समय पर विशि-ट संकल्प पारित करके निर्धारित की हों।

(2) समिति को किसी ऐसे मामले की जांच करने का अधिकार होगा जिसका निर्णय सरकार ने अपने कार्यपालिका संबंधी कृत्यों के निर्वहन में नीति के रूप में किया हो।

(3) नियम 310 के खण्ड (ख) के संबंध में समिति संसद द्वारा अनुमोदित नीति के विरुद्ध नहीं जाएगी, किन्तु जहां यह बात साक्ष्य द्वारा सिद्ध हो जाए कि किसी विशि-ट नीति से प्रत्याशित या अपेक्षित फल प्राप्त नहीं हो रहे या उससे अपव्यय हो रहा है तो समिति का यह कर्तव्य है कि वह सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाए कि नीति में परिवर्तन करने

की आवश्यकता है। समिति के मूल उद्देश्य मितव्ययिता, प्रशासन में कार्यकुशलता और यह सुनिश्चित करना है कि धन ठीक ढंग से लगाया जाए, किन्तु यदि सावधानी से परीक्षा करने के बाद यह मालूम हो कि किसी विशेष नीति का अनुसरण करने से बड़ी-बड़ी राशियों का अपव्यय हो रहा है, तो समिति त्रुटियों की ओर ध्यान दिला सकेगी और सभा के विचारार्थ नीति में परिवर्तन के लिए कारण बता सकेगी।

99. वित्तीय समितियों के समक्ष मंत्रियों को न बुलाया जाना।—(1) प्राक्कलन समिति अथवा लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति किसी विशेष मंत्रालय अथवा उपक्रम से संबंधित प्राक्कलनों और लेखों की परीक्षा के संबंध में साक्ष्य देने के लिए अधिकारियों को बुला सकेगी। किन्तु प्राक्कलनों अथवा लेखों की परीक्षा के संबंध में साक्ष्य या परामर्श देने के लिए किसी मंत्री को समिति के समक्ष नहीं बुलाया जाएगा।

(2) तथापि, समिति का सभापति जब आवश्यक समझे, परन्तु पर्यालोचन समाप्त होने के बाद उस मंत्री से अनौपचारिक रूप में बातचीत कर सकेगा/सकेगी, जिसके मंत्रालय अथवा उपक्रम के प्राक्कलन अथवा लेखों, समिति के विचाराधीन थे ताकि वह मंत्री को निम्नलिखित मामलों के बारे में बता सके:

(क) मंत्रालय अथवा उपक्रम द्वारा निर्धारित नीति संबंधी वे मामले जिनसे समिति पूर्णतः सहमत नहीं है; और

(ख) कोई गुप्त या गोपनीय मामले जो समिति अपने प्रतिवेदन में अभिलिखित न करना चाहे।

(3) इस बातचीत के आधार पर समिति अपने नि-क-रों पर पुनर्विचार कर सकेगी किन्तु सभापति द्वारा उसमें से किन्हीं मामलों पर संबद्ध मंत्री का ध्यान दिलाए जाने के बाद उन पर मंत्री के साथ अन्यथा आगे और बातचीत नहीं करेगी।

100. वित्तीय समितियों द्वारा गैर-सरकारी समवायों अथवा गैर-सरकारी निकायों के प्रतिनिधियों की जांच।—

⁵[जब प्राक्कलन समिति अथवा लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति] किसी ऐसे करार के कार्यकरण का परीक्षण करे जो भारत सरकार या किसी सरकारी उपक्रम और किसी गैर-सरकारी समवाय या किसी अन्य गैर-सरकारी निकाय के बीच हुआ हो तो समिति, यदि उचित समझे, समवाय या गैर-सरकारी निकाय के, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिनिधियों को जिस वि-य में समिति कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहती हो या प्रतिनिधि कुछ स्प-टीकरण करना चाहता हो, उससे उत्पन्न होने वाली किसी बात पर साक्ष्य देने की इच्छा से बुला सकती है या समिति के सामने आने का अवसर दे सकती है।

101. रक्षा मंत्रालय के प्राक्कलनों की जांच के लिए प्राक्कलन समिति की प्रक्रिया।—रक्षा मंत्रालय के प्राक्कलनों

की जांच करने के लिए प्राक्कलन समिति द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:—

(एक) प्रक्रिया नियमों के नियम 263(1) के अंतर्गत प्राक्कलन समिति की एक उप-समिति नियुक्त की जाए और उसे रक्षा मंत्रालय के प्राक्कलनों की जांच करने का काम सौंपा जाए।

(दो) समिति का सभापति पहले से इस बात का निश्चय करे कि रक्षा संगठन के किन-किन कार्यों की ओर उप-समिति को ध्यान देना है अथवा किन-किन कार्यों की जांच करनी है।

(तीन) समिति का सभापति जैसा वह आवश्यक समझे उप-समिति के कार्यों की प्रक्रिया तथा संगठन को विनियमित करेगा/करेगी।

(चार) उप-समिति जांचाधीन प्राक्कलन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए पदाधिकारियों को बुला सकेगी या उनको सुन सकेगी अथवा कोई अन्य साक्ष्य ले सकेगी।

(पांच) (क) उप-समिति के सदस्य 'गुप्त' दस्तावेजों के संबंध में प्रचलित प्रथाओं का पालन करेंगे।

(ख) समिति के सभापति को स्वविवेकानुसार यह अधिकार होगा कि वह सदस्यों को 'सर्वाधिक गुप्त' दस्तावेजों की बात बताए अथवा नहीं और वह रक्षा मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कही गई किसी बात पर विचार करेगा। यदि किसी वि-य में सभापति मंत्रालय की बात मानने में असमर्थ हो, तो वह वि-य अध्यक्ष को उनसे मार्गदर्शन के लिए निर्दि-ट किया जाएगा।

(ग) समिति का/की सभापति इस बात का निश्चय करेगा/करेगी कि क्या कुछ मामलों में 'गुप्त' दस्तावेजों की प्रतियां सदस्यों को न बांटी जाएं और वे प्रतियां केवल सदस्यों के निदेश के लिए लोक सभा सचिवालय में एक विशि-ट स्थान पर ही उपलब्ध की जाएं।

(छह) ऐसे मामलों में जहां सरकार किसी दस्तावेज को इस आधार पर प्रस्तुत न करना चाहे कि उसे प्रकट करना राज्य की सुरक्षा और उसके हित के प्रतिकूल होगा और दस्तावेज प्रस्तुत न करने के आधार के बारे में किसी संदेह की स्थिति में, इस समिति का सभापति उस वि-य को अध्यक्ष के सामने उनसे मार्गदर्शन के लिए रख सकेगा/सकेगी।

(सात) प्राक्कलनों की जांच समाप्त हो जाने पर उप-समिति नि-क-र निकाल सकेगी और ऐसे प्रतिवेदन तैयार कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(आठ) (क) सभापति उप-समिति के प्रतिवेदनों को समिति के विचार के लिए सम्पूर्ण समिति के समक्ष रखेगा/रखेगी:

⁵ दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग-दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु उप-समिति के प्रतिवेदन के वे भाग जो सभापति के विचार में गोपनीय वि-यों से संबंधित हों और जिन्हें प्रकट करना सुरक्षा के हित में वांछनीय न हो, सम्पूर्ण समिति के समक्ष नहीं रखे जाएंगे, किन्तु सभापति द्वारा अध्यक्ष को भेजे जा सकेंगे।

(ख) सभापति उप-समिति द्वारा देखे गए ऐसे साक्ष्यों और पत्रों को सम्पूर्ण समिति को उपलब्ध करा सकेगा/सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे।

(नौ) (क) उप-समिति के प्रतिवेदन के ऐसे भाग, जो उपरोक्त (आठ) (क) के अन्तर्गत सम्पूर्ण समिति के समक्ष रखे जाएं और सम्पूर्ण समिति द्वारा अनुमोदित कर दिए जाएं, सम्पूर्ण समिति का प्रतिवेदन माने जाएंगे।

(ख) प्रतिवेदन के ऐसे भाग जो सभापति द्वारा उपरोक्त (आठ) (क) के परन्तुक के अंतर्गत अध्यक्ष को भेजे गए हों, समिति का प्रतिवेदन नहीं माने जाएंगे परन्तु सभापति द्वारा अध्यक्ष को दिए गये विशेष-1 और तदर्थ प्रतिवेदन माने जाएंगे।

(ग) अध्यक्ष ऐसा तदर्थ प्रतिवेदन ऐसे रूप में जैसे वह ठीक समझे सरकार को भेज सकेगा/सकेगी और ऐसा करते समय सरकार को प्रतिवेदन भेजे जाने की सूचना सभा को दे सकेगा/सकेगी।

(दस) उप-समिति के प्रतिवेदन को जिसे सभापति सम्पूर्ण समिति के समक्ष लाए, मुख्य समिति द्वारा स्वीकार किए जाने तथा सभा में प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया वर्तमान नियमों के अनुसार होगी।

101क. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के अन्तर्गत न आने वाले सांविधिक और सरकारी संगठनों के प्राक्कलनों की जांच के लिए प्राक्कलन समिति की प्रक्रिया.—उन सांविधिक तथा सरकारी संगठनों के जो सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, प्राक्कलनों की जांच करने के लिए प्राक्कलन समिति द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:—

(एक) प्रत्येक व-ई के आरम्भ में प्राक्कलन समिति के गठन के पश्चात् प्रक्रिया नियमों के नियम 263(1) के अधीन प्राक्कलन समिति की सांविधिक तथा सरकारी संगठनों संबंधी एक स्थायी उप-समिति नियुक्त की जा सकेगी।

(दो) उप-समिति के सदस्य सभापति द्वारा समिति के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(तीन) उप-समिति जांचाधीन सांविधिक अथवा सरकारी संगठन के प्राक्कलनों के संबंध में जानकारी मांग सकेगी या पदाधिकारियों को सुन सकेगी या कोई भी अन्य साक्ष्य ले सकेगी।

(चार) किसी सांविधिक अथवा सरकारी संगठन के प्राक्कलनों की जांच पूरी हो जाने पर, उप-समिति नि-क-ई निकाल सकेगी और ऐसे प्रतिवेदन तैयार कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(पांच) उप-समिति के प्रतिवेदनों को सम्पूर्ण समिति के समक्ष उसके विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

(छह) समिति का/की सभापति उप-समिति के कार्य की प्रक्रिया और संगठन का ऐसी रीति से विनियमन करेगा/करेगी जैसाकि वह आवश्यक समझे।

टिप्पण:—यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि कौन-से सांविधिक तथा सरकारी संगठन इस स्थायी उप-समिति के क्षेत्राधिकार में आने चाहिए तो यह प्रश्न अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम होगा।

102. 'प्राक्कलन समिति अथवा लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही.—(1) सरकार प्राक्कलन समिति ⁷[अथवा लोक लेखा समिति] अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के यथाशीघ्र पश्चात् सबसे पहले समिति को प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही का एक विवरण देगी। विवरण में सभी सिफारिशों के बारे में जिसमें सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशें भी सम्मिलित होंगी, सरकार के विचार निहित होंगे।

(2) उत्तर प्राप्त होने के यथाशीघ्र पश्चात् समिति उन पर विचार करेगी और अंतिम रूप से यह निश्चय करेगी कि उसे उत्तर स्वीकार्य हैं या नहीं। सरकार द्वारा जो सिफारिशें स्वीकार न की गई हों उनके उत्तरों के बारे में समिति अपने विचार व्यक्त कर सकती है, यदि वह सरकार के उत्तरों को स्वीकार न करे।

⁶[तत्पश्चात् समिति उसके द्वारा की गई मूल सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही के बारे में सभा में और प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। प्रतिवेदन में निम्नलिखित पांच अध्याय होंगे:—

(एक) प्रतिवेदन;

(दो) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है;

(तीन) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती;

(चार) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं; और

(पांच) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।]

⁶ दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग-दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁷ दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग-दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा अंतःस्थापित।

⁸ दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग-दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा जोड़ा गया।

⁹[(3) सरकार प्राक्कलन समिति अथवा लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्वि-ट सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्वि-ट सिफारिशों के बारे में अंतिम उत्तरों के विवरण प्रस्तुत करेगी। इस प्रकार प्राप्त हुए उत्तरों को एक विवरण के रूप में समेकित किया जाएगा और सभापति के अनुमोदन के पश्चात् सभा पटल पर रखा जाएगा।]

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

103. कृत्य.—(1) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति उन सारे 'आदेशों' की जांच कर सकेगी जो संविधान अथवा किसी अधीनस्थ प्राधिकार को इस प्रकार के आदेश बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित करने वाली किसी संविधि के उपबन्धों के अनुसरण में बनाए गए हों चाहे सभा पटल पर रखे गए हों अथवा नहीं।

(2) समिति ऐसे विधेयकों के उपबन्धों की जांच कर सकेगी जिनसे:—

(एक) 'आदेश' देने की शक्तियों का प्रत्यायोजन होता हो; अथवा

(दो) ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले पहले अधिनियमों में संशोधन होता हो;

ताकि वह यह देख सके कि उनमें सभा पटल पर 'आदेश' रखने के लिए उपयुक्त उपबंध कर दिए गए हैं।

(3) समिति 'आदेश' से संबंधित किसी अन्य मामले अथवा उससे उठने वाले अधीनस्थ विधान के किसी प्रश्न पर विचार कर सकेगी।

103क. अध्यक्ष द्वारा समिति को निर्दिष्ट विधेयकों की जांच.—(1) अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी उपबंधों वाले विधेयकों को भी समिति को निर्दिष्ट कर सकेगा/सकेगी और यदि कोई विधेयक इस प्रकार सौंपा जाए तो समिति निम्न बातों की जांच करेगी:—

(एक) जो शक्तियां प्रत्यायोजित की जानी हों उनकी सीमा; और

(दो) यदि शक्तियां किन्हीं सहायक उपबंधों को कार्यान्वित करने अथवा आगे कोई नियम व विनियम बनाने के लिए राज्य सरकारों अथवा अन्य प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित की जानी हों, तो ऐसे प्रत्यायोजन की आवश्यकता और संबंधित अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा ऐसी शक्तियों के प्रयोग की सीमा तथा रीति।

(2) यदि समिति की राय हो कि विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले विधेयक में निहित उपबंध पूर्णतः

अथवा अंशतः रद्द कर दिए जाएं अथवा उनमें किसी प्रकार संशोधन कर दिया जाए तो सभा में उस विधेयक पर विचार आरम्भ होने से पूर्व वह अपनी राय और उसके आधारों को सभा को बताएगी।

104. मंत्रालयों आदि द्वारा दस्तावेजों का दिया जाना.— समिति के उपयोग के लिए मंत्रालय अथवा अन्य प्राधिकारियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां पर्याप्त संख्या में देनी होंगी:—

(एक) संविहित तथा संवैधानिक 'आदेश'।

(दो) ऐसे 'आदेशों' के संशोधन।

(तीन) ऐसे 'आदेशों' के पुनर्मुद्रित संस्करण जब भी वे पुनर्मुद्रित किए जाएं।

105. आदेश, विधेयक आदि की जांच की प्रक्रिया.—

(1) (एक) किसी 'आदेश' के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद लोक सभा सचिवालय यह निश्चय करने के लिए उसकी जांच करेगा कि क्या उसको नियम 320 में दिए गए किसी आधार पर अथवा समिति की किसी प्रथा अथवा निदेश के अनुसार समिति के ध्यान में लाना आवश्यक है।

(दो) किसी विधेयक के सभा में पुरःस्थापित किए जाने अथवा उसके सभा पटल पर रखे जाने के बाद लोक सभा सचिवालय यह निश्चय करने के लिए उसकी जांच करेगा कि क्या निदेश में दिए गए आधार पर उसे समिति के ध्यान में लाना आवश्यक है।

(2) यदि किसी आदेश की जांच में किसी बात के संबंध में कोई स्प-टीकरण आवश्यक समझा जाए तो वह संबंधित मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस वि-य पर, यदि आवश्यक हुआ तो, उस उत्तर को दृष्टि में रखते हुए पुनर्विचार किया जाएगा।

(3) यदि किसी 'आदेश' विधेयक अथवा किसी अन्य मामले पर विचार करने के बाद कोई बात या बातें समिति के ध्यान में लाना आवश्यक समझा जाए, तो उस वि-य पर एक परिपूर्ण ज्ञापन तैयार किया जाएगा और उसे सभापति के अनुमोदन के पश्चात् समिति के समक्ष रखा जाएगा।

106. ज्ञापनों का परिचालन.—संगत 'आदेश' की प्रतियां अथवा उद्धरणों सहित अनुमोदित ज्ञापन जहां आवश्यक हो, समय रहने पर, पहले से समिति के सदस्यों को परिचालित किया जा सकेगा।

107. प्रतिवेदन के साथ दस्तावेज का प्रस्तुतीकरण.— प्रतिवेदन के साथ सभा में निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाएंगे:—

(एक) प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का सारांश।

⁹ दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग-दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा जोड़ा गया।

(दो) जिन बैठकों में प्रतिवेदन में उल्लिखित वि-यों पर विचार किया गया हो, उनके कार्यवाही-सारांश के संगत अंश।

(तीन) ऐसी अन्य सामग्री, जो आवश्यक समझी जाए।

108. समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई.—

(1) मंत्रालयों को लोक सभा सचिवालय को समय-समय पर समिति द्वारा अपने प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों तथा समिति के साथ पत्र-व्यवहार में मंत्रालयों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर उनके द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई के विवरण देने होंगे। इस प्रकार से प्राप्त होने वाली जानकारी सभापति के अनुमोदन से एक ज्ञापन के रूप में समिति के समक्ष रखी जाएगी।

(2) ऐसे मामलों में जिनमें कोई मंत्रालय समिति द्वारा की-गई- सिफारिश को कार्यान्वित करने की स्थिति में न हो, अथवा उसको पूरा करने में कोई कठिनाई अनुभव करता हो, तो मंत्रालय अपने विचार समिति के समक्ष रखेगा, जो यदि वह ठीक समझे तो उस मामले में मंत्रालय के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद सभा के समक्ष एक और प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेगी।

सरकार द्वारा गठित समितियां तथा अन्य निकाय जिनमें

लोक सभा का प्रतिनिधित्व होता है

108क. सरकारी समितियों आदि के लिए निर्वाचन प्रणाली जिनमें लोक सभा का प्रतिनिधित्व होता है.—जब सरकार द्वारा (किसी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत अथवा अन्यथा) गठित किसी समिति; आयोग अथवा अन्य किसी निकाय के लिए सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, सदस्यों के निर्वाचन का उपबंध हो, तो निर्वाचन, यदि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, अध्यक्ष द्वारा समितियों के निर्वाचन के लिए बनाए गए विनियमों के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा।

अध्याय 9

सामान्य निदेश

सूचनाएं

¹ [109 ***** 112]

113. विधेयकों अथवा संकल्पों पर संशोधन की सूचनाएं.—सदस्यों द्वारा किसी विधेयक अथवा संकल्प के कार्य-सूची में रखे जाने से पूर्व उसके संबंध में संशोधनों की सूचनाएं दी जा सकेंगी। ऐसे संशोधन संगत मद की कार्य-सूची में ²[अथवा अगले सप्ताह के कार्य के बारे में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में] रखे जाने के दिन सदस्यों को परिचालित किए जायेंगे।

113क. मंत्री के रूप में नियुक्ति हो जाने पर सदस्य की सूचना का व्यपगत हो जाना.—यदि कोई सदस्य, नियमों के

अंतर्गत किसी वि-य के बारे में लिखित रूप से सूचना देने के बाद मंत्री नियुक्त हो जाए, तो वह सूचना इस प्रकार की नियुक्ति की तारीख से व्यपगत समझी जाएगी।

113ख. कुछ प्रकार की सूचनाओं के लिए समय-सीमा.—(1) स्थगन प्रस्तावों, अविलम्बनीय लोक महत्व के वि-य की ओर ध्यान दिलाने के प्रस्तावों, मंत्रिपरि-द् में अविश्वास के प्रस्तावों, विशेष-ाधिकार के प्रश्नों की सूचनाएं, अथवा अन्य कोई सूचना जो कि उस दिन की सभा की बैठक के आरम्भ होने से पूर्व दी जानी चाहिए जिस दिन के वि-य को सभा में उठाया जाना है, उस दिन 10.00 बजे तक दे दी जाएगी।

ऐसी सूचनाएं यदि 10.00 बजे के पश्चात् प्राप्त होंगी तो उन्हें अगली बैठक के लिए दी गई सूचनाएं माना जाएगा।

113खख. ³[नियम 184 के अधीन या नियम 193 के अधीन अल्पकालिक चर्चा पर प्रस्तावों के लिए सूचनाएं देने की प्रक्रिया (1).—नियम 184 के अधीन प्रस्तावों तथा नियम 193 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चाओं के लिए सूचनाएं सत्र के लिए आमंत्रण जारी करने की तारीख के अगले दिन से स्वीकार की जाएंगी।

(2) सभा में मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्यों अथवा सभा पटल पर रखे जाने वाले विवरणों, प्रतिवेदनों अथवा पत्रों के बारे में ऐसी सूचनाएं उस दिन 10.00 बजे से ली जाएंगी, जिस दिन वह कार्य-सूची, जिसमें उस मद को शामिल किया गया है सदस्यों को परिचालित की जाती है।

(3) उस दशा में, जहां किसी वक्तव्य के बारे में अनुपूरक कार्य-सूची सभा में परिचालित की जाती है, वहां उस वक्तव्य की बाबत कार्य-सूची के परिचालन के 15 मिनट के भीतर प्राप्त हुई सूचनाओं के बारे में यह समझा जाएगा कि वे उसी समय प्राप्त हुई हैं और उनकी सापेक्ष पूर्ववर्तिता बैलट द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(4) उस दशा में, जहां सभा में किसी मंत्री द्वारा दिए जाने वाले किसी वक्तव्य के बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई घो-णा की जाती है, वहां उस वक्तव्य की बाबत सूचनाएं उसी समय स्वीकार की जाएंगी जिस समय पीठासीन अधिकारी द्वारा सभा में घो-णा की जाती है।

(5) उस दशा में, जहां कोई वक्तव्य कार्य-सूची अथवा अनुपूरक कार्य-सूची में शामिल किए बिना दिया जाता है, वहां ऐसे वक्तव्य की बाबत सूचनाएं उस समय से स्वीकार की जाएंगी जब वक्तव्य सभा में वास्तव में दिया जाता है।

(6) खण्ड (4) और (5) के अधीन क्रमशः पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घो-णा अथवा मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के बाद 15 मिनट के भीतर प्राप्त हुई सभी सूचनाओं

¹ दिनांक 19.04.1973 के लोक सभा समाचार भाग-दो के द्वारा निदेश संख्या 109 से 112 का लोप कर दिया गया ।

² दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग-दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा जोड़ा गया ।

³ दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग-दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा जोड़ा गया ।

को एक ही समय पर प्राप्त हुआ समझा जाएगा और उनकी सापेक्ष पूर्ववर्तिता बैलट द्वारा निर्धारित की जाएगी।

व्याख्या—खण्ड (3) और (6) में उल्लिखित 15 मिनट की अवधि की गणना यथास्थिति, कार्य-सूची के परिचालन अथवा पीठासीन अधिकारी की घो-णा अथवा मंत्री के वक्तव्य के पूरा होने के समय से की जाएगी।

प्रस्ताव तथा अल्पकालिक चर्चाएं

113ग. एक सदस्य द्वारा सत्र में प्रस्तावों तथा अल्पकालिक चर्चाओं की संख्या पर सीमा.—जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें अनियत दिन वाले प्रस्तावों तथा अल्पकालिक चर्चाओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि कोई सदस्य किसी सत्र में इनमें से दो से अधिक प्रस्ताव पेश न कर सके अथवा चर्चा न उठा सके।

सभा में सदस्यों अथवा भूतपूर्व सदस्यों की उपस्थिति के बारे में जानकारी

114. सदस्यों अथवा भूतपूर्व सदस्यों की उपस्थिति के बारे में जानकारी.—(1) जब कोई सदस्य अथवा भूतपूर्व सदस्य किन्हीं विशेष-दिनों अथवा किसी विशि-ट अवधि के लिए लोक सभा सचिवालय के अभिलेखों के अनुसार सभा में अपनी उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहे तो उस सदस्य या पूर्व सदस्य से यह पूछा जाएगा कि यह जानकारी किस प्रयोजन के लिए चाहिए।

(2) प्रत्येक प्रार्थना पर उसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

(3) यदि उस प्रार्थना को पूरा करने का निश्चय किया जाए, तो सम्बद्ध व्यक्ति को उत्तर में यह बता दिया जाएगा कि सदस्य या पूर्व सदस्य ने किस-किस तिथि को उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर किए हैं।

सभा में दिए गए वक्तव्यों में गलती अथवा त्रुटि

114क. 4[वाद-विवाद में मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों में गलती या त्रुटि ठीक करने की प्रक्रिया.—(1) वाद-विवाद के दौरान मंत्री द्वारा दी गई किसी जानकारी में किसी गलती या त्रुटि को ठीक करने का/की इच्छुक मंत्री, अध्यक्ष की सहमति से ऐसी गलती या त्रुटि को ठीक करने के लिए सभा में वक्तव्य दे सकेगा/सकेगी।

(2) ऐसे वक्तव्य देने की प्रक्रिया यथा आवश्यक परिवर्तन सहित वही होगी जो निदेश 16 में दी गई है।

115. मंत्रियों अथवा सदस्यों द्वारा दिए गए वक्तव्यों में गलती अथवा त्रुटि की ओर ध्यान दिलाने की प्रक्रिया.—(1) कोई सदस्य जो किसी मंत्री या अन्य सदस्य द्वारा दिए गए वक्तव्य में किसी भूल या अशुद्धि की ओर ध्यान दिलाना चाहे तो सभा में उस वि-य का उल्लेख करने से पूर्व अध्यक्ष को भूल या अशुद्धि का ब्यौरा लिखेगा/लिखेगी और उस वि-य

को सभा में उठाने के लिए अध्यक्ष की अनुमति मांगेगा/मांगेगी।

(2) आरोप के समर्थन के लिए सदस्य के पास जो साक्ष्य हो, वह सदस्य उसे अध्यक्ष के सामने रख सकेगा/सकेगी।

(3) यदि अध्यक्ष उचित समझे तो आरोप के संबंध में वस्तुस्थिति जानने के लिए उस मामले की ओर संबंधित मंत्री या सदस्य का ध्यान दिला सकेगा/सकेगी।

(4) इसके बाद यदि अध्यक्ष उचित समझे, तो वह उस सदस्य को जिसने आरोप लगाया था, उस वि-य को सभा में उठाने की अनुमति दे सकेगा/सकेगी और इस प्रकार से अनुमति प्राप्त सदस्य को वक्तव्य देने से पूर्व उसकी सूचना मंत्री अथवा संबंधित सदस्य को देनी होगी।

(5) संबंधित मंत्री अथवा सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से और संबंधित अन्य सदस्य को सूचना देने के बाद उत्तर में वक्तव्य दे सकेगा/सकेगी।

(6) सदस्य द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य और प्रत्युत्तर में मंत्री द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य संबंधी मद को उस समय तक कार्य-सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जब तक उन वक्तव्यों की लिखित प्रतियां पर्याप्त समय पूर्व अध्यक्ष को न दी जाएं और अध्यक्ष उनका अनुमोदन न कर दे। यदि ऐसे शब्द, वाक्यांश और अभिव्यक्तियां प्रयोग की जाती हैं जो अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित वक्तव्यों में नहीं हैं, तो वे सभा की कार्यवाही का भाग नहीं होगी।

वाद-विवाद में भाग लेने की रीति

115क. वाद-विवाद में भाग लेने की रीति और वक्ताओं का चयन.—(1) जो सदस्य किसी वाद-विवाद या चर्चा में भाग लेने की अपनी इच्छा की सूचना अध्यक्ष को देना चाहें वे निम्नलिखित तीन उपायों में से किसी एक का आश्रय ले सकते हैं:—

(क) जो सदस्य किसी विशेष-वाद-विवाद या चर्चा में भाग लेना चाहे उनके नाम अध्यक्ष को संसदीय दलों अथवा वर्गों द्वारा दे दिए जाएं।

(ख) जो सदस्य अध्यक्ष को सीधे लिखना चाहे वह संसदीय दल अथवा वर्ग की व्यवस्था में से गुजरे बिना ऐसा कर सकता/सकती है।

(ग) जो सदस्य अपने दल, के द्वारा अपना नाम अध्यक्ष को न देना चाहे अथवा अध्यक्ष को सीधे न लिखना चाहे किंतु अध्यक्ष की दृष्टि में आने की सर्वविदित संसदीय प्रथा को अपनाना चाहे, वह सदस्य जब कभी वाद-विवाद में भाग लेना चाहे तब अपने स्थान पर खड़ा हो सकता है/खड़ी हो सकती है।

(2) जब तक कोई सदस्य अपने स्थान पर खड़ा/खड़ी न हो और अध्यक्ष की दृष्टि में न आए तब तक सदस्य को

⁴ दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग-दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा अंतःस्थापित किया गया।

अध्यक्ष द्वारा बोलने के लिए नहीं कहा जाएगा, चाहे उस सदस्य ने अपने दल या वर्ग, जिससे सदस्य संबंधित है, के द्वारा अपना नाम भेजा हो या सीधे अध्यक्ष को लिखा हो।

(3) अध्यक्ष, उन सूचियों अथवा क्रम से बाध्य नहीं होगा/होगी जिसमें कि दलों या वर्ग अथवा व्यक्तियों द्वारा सीधे नाम भेजे जायेंगे। सूचियां केवल अध्यक्ष के मार्गदर्शन के लिए होंगी और जब कभी आवश्यक हो अध्यक्ष को उसमें सदा परिवर्तन करने का अधिकार होगा ताकि अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार वाद-विवाद का विनियमन हो सके।

⁴[(4) यदि कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा न पुकारे जाने पर बोलता/बोलती है अथवा भा-ण को तुरन्त समाप्त करने के लिए अध्यक्ष के निदेशों के बावजूद बोलना जारी रखता/रखती है तो अध्यक्ष यह निदेश दे सकेगा/सकेगी कि यथास्थिति, ऐसा भा-ण अथवा उसके अंश सभा की कार्यवाही वृत्तांत का भाग नहीं बनेंगे।]

⁶[हिन्दी अथवा अंग्रेजी से भिन्न भा-आओं में भा-ण

115ख. हिन्दी अथवा अंग्रेजी से भिन्न भा-आओं के बारे में प्रक्रिया.—(1) कोई सदस्य लोक सभा में निम्नलिखित भा-आओं में से किसी एक भा-आ अर्थात् असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, ⁷[मैथिली] मलयालम, ⁸[मणिपुरी] मराठी, ⁹[नेपाली] उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु या उर्दू में भा-ण दे सकेगा/सकेगी। बशर्ते कि सदस्य कम से कम आधे घण्टे पहले इस आशय की सूचना पटल अधिकारी को दे देता/देती है ताकि संबंधित भा-आन्तरकार अपने बूथ में भा-आन्तरण के लिए आ सके। उस भा-ण का हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ भा-आन्तरण किया जाएगा।

तत्पश्चात् उस सदस्य के भा-ण का हिन्दी अथवा अंग्रेजी रूपान्तर तैयार किया जाएगा और सभा की कार्यवाही के शासकीय वृत्तांत में यह रूपान्तर एक पाद टिप्पण के साथ मुद्रित किया जाएगा जिसमें वह भा-आ दर्शायी जाएगी जिसमें मूल भा-ण दिया गया हो।

(2) हिन्दी, अंग्रेजी और खंड (1) में वर्णित भा-आओं से भिन्न किसी भा-आ में भा-ण देने के इच्छुक सदस्य को भा-आन्तरकारों के उपयोग तथा बाद में सभा की कार्यवाही के शासकीय वृत्तांत में शामिल करने हेतु अपने भा-ण के हिन्दी अथवा अंग्रेजी रूपान्तर की तीन सत्यापित प्रतियां पटल अधिकारी को अथवा संसदीय सूचना कार्यालय में पहले देनी होगी:

परन्तु यदि सदस्य ऐसा रूपान्तर प्रदान नहीं करता / करती है, तो यह तथ्य कि वह सदस्य हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा खंड (1) में वर्णित भा-आओं से भिन्न किसी अन्य भा-आ में बोला था/बोली थी, सभा की कार्यवाही के शासकीय

वृत्तांत में इस टिप्पणी के साथ वर्णित किया जाएगा कि उस सदस्य ने भा-ण का हिन्दी अथवा अंग्रेजी रूपान्तर नहीं दिया।

(3) कोई सदस्य या (दो से अनधिक सदस्य) जिनके नाम से तारांकित प्रश्नों की सूची में कोई प्रश्न है, खंड (1) में उल्लिखित भा-आओं में से किसी एक भा-आ में अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेगा/सकेगी, बशर्ते कि जिस दिन की प्रश्न सूची में मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न को सम्मिलित किया गया हो, उससे पहले के कार्य दिवस को 3 बजे से पूर्व इस बारे में अग्रिम सूचना दे दी जाती है।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्प-टीकरण

115ग. वैयक्तिक स्प-टीकरण.—किसी सदस्य को नियम 357 के अधीन तब तक वैयक्तिक स्प-टीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि सदस्य द्वारा लिखित रूप में उसकी एक प्रति काफी समय पूर्व अध्यक्ष को प्रस्तुत न की गई हो और अध्यक्ष ने उसका अनुमोदन न कर दिया हो। यदि ऐसे शब्दों, वाक्यांशों और पदावलियों का प्रयोग किया जाता है जो अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित वक्तव्य में शामिल न हों तो वे सभा के कार्यवाही वृत्तांत का अंग नहीं बनेंगे।

पत्रों का सभा पटल पर रखा जाना

116. कार्य-सूची में प्रविष्टि.—(1) सभा पटल पर रखने के लिए विधिवत तथा प्रमाणीकृत रूप में किसी मंत्री से प्राप्त प्रत्येक पत्र या दस्तावेज के संबंध में कार्य-सूची में एक प्रविष्टि की जाएगी।

(2) यदि संबंधित मंत्रालय द्वारा कोई विशिष्ट तिथि न सुझाई गई हो, तो पटल पर रखने के लिए मंत्रालयों से प्राप्त पत्र सामान्यतया दो दिन पश्चात् की कार्य-सूची में सम्मिलित किए जाएंगे।

(3) सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र मंत्रालयों द्वारा साधारणतया उस दिन से जिस दिन कि उन्हें रखने का विचार हो, दो दिन पूर्व भेजे जाने चाहिए। तथापि विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष किसी मंत्री को प्रार्थना करने पर कम समय की सूचना पर पत्र पटल पर रखने की अनुमति दे सकेगा/सकेगी।

117. गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा पत्रों का पटल पर रखा जाना.—अध्यक्ष द्वारा अधिकृत होने पर कोई गैर-सरकारी सदस्य सभा पटल पर कोई पत्र रख सकेगा/सकेगी।

118. गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा पत्रों को पटल पर रखे जाने की प्रक्रिया.—(1) यदि कोई गैर-सरकारी सदस्य सभा पटल पर कोई पत्र अथवा दस्तावेज रखना चाहे, तो सदस्य पहले से उसकी एक प्रति अध्यक्ष को देगा/देगी ताकि अध्यक्ष यह निश्चय कर सके कि क्या पत्र अथवा दस्तावेज को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए। यदि अध्यक्ष सदस्य को पत्र अथवा दस्तावेज को पटल पर रखने की अनुमति दे दे, तो

⁵ दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग-दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा जोड़ा गया।

⁶ दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग-दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा प्रतिस्थापित।

⁷⁻⁹ दिनांक 17.02.2014 के लोक सभा समाचार भाग-दो के पैरा संख्या 6175 द्वारा जोड़ा गया।

सदस्य द्वारा उसे उचित समय पर सभा पटल पर रखा जा सकेगा।

¹⁰[(2) यदि कोई गैर-सरकारी सदस्य भा-ण के दौरान किसी गुप्त सरकारी दस्तावेज, पत्र अथवा रिपोर्ट से उद्धृत करना चाहे तो वह सदस्य पहले से उसकी एक प्रति अध्यक्ष को देगा/देगी तथा सदस्य जो अंश उद्धृत करना चाहता/चाहती है उसके बारे में भी बताएगा/बताएगी ताकि अध्यक्ष यह निश्चय कर सके कि क्या अनुमति दी जानी चाहिए। यदि अध्यक्ष सदस्य को उस दस्तावेज में से उद्धृत करने की अनुमति दे देता/देती है तो सदस्य उचित समय पर ऐसा कर सकेगा/सकेगी। यदि अध्यक्ष आवश्यक अनुमति नहीं देता/देती है, तो सदस्य न तो उस दस्तावेज में से उद्धृत करेगा/करेगी और न ही उसकी वि-य-वस्तु का उल्लेख करेगा/करेगी।]

¹¹[(3)(एक) किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा सभा पटल पर रखे जाने के लिए आशयित किसी पत्र अथवा दस्तावेज को पटल पर रखने के लिए केवल तभी विचार किया जाएगा यदि सदस्य ने उस पत्र अथवा दस्तावेज में से उद्धृत किया हो। यदि कोई सदस्य उसे सभा पटल पर रखना चाहता/चाहती है तो वह उसे पटल पर दे सकेगा/सकेगी किंतु वह तब तक सभा पटल पर रखा गया नहीं समझा जाएगा, जब तक अध्यक्ष उसकी जांच करने के बाद आवश्यक अनुमति न दे दें।

(दो) यदि अध्यक्ष आवश्यक अनुमति न दे, तो वह पत्र अथवा दस्तावेज सदस्य को वापिस कर दिया जाएगा और बात छपे हुए वाद-विवाद में बता दी जाएगी।]

¹²[118क. गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों का प्रमाणीकरण.—(1) जब कोई सदस्य निदेश 118 के अधीन किसी पत्र अथवा दस्तावेज को सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष की अनुमति मांगता/मांगती है, तो वह सदस्य उस पत्र, दस्तावेज पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रपत्र में यथास्थिति प्रमाणपत्र देगा/देगी:—

(क) "मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी से यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि यह मूल दस्तावेज है, जो प्रामाणिक है।"

(ख) "मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी से यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि यह मूल दस्तावेज, जो प्रामाणिक है, की सही प्रतिलिपि है।"

(ग) "मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस दस्तावेज की वि-य-वस्तु सही है और प्रामाणिक जानकारी पर आधारित है।"

(2) यदि पत्र अथवा दस्तावेज एक से अधिक पृ-ठ का है, तो सदस्य उसके प्रत्येक पृ-ठ पर तारीख सहित अपने हस्ताक्षर करेगा/करेगी।]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

119. मंत्री द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य की पूर्व सूचना और अग्रिम प्रति देना.—नियम 372 के अधीन सभा में वक्तव्य देने के इच्छुक मंत्री को पहले से यह बताना होगा कि किस तिथि को उसका वक्तव्य देने का विचार है और अध्यक्ष की जानकारी के लिए उसे अपने वक्तव्य की एक प्रति भी लोक सभा सचिवालय को भेजनी होगी।

¹³[स्प-टीकरण—वक्तव्य उस वि-य से संबंधित होगा जिसके लिए वह मंत्री उत्तरदायी है तथा वह लोक महत्व अथवा सामयिक महत्व के किसी विशि-ट वि-य पर सरकार की नीति को स्प-ट करने के लिए दिया जाएगा।]

संसदीय दलों और ग्रुपों को मान्यता तथा सुविधाएं देना

120. दल या ग्रुप को मान्यता देना.—अध्यक्ष सभा में कार्य करने के प्रयोजन के लिए सदस्यों की किसी संस्था को संसदीय दल अथवा ग्रुप के रूप में मान्यता दे सकेगा/सकेगी और अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

121. मान्यता देने की शर्त.—किसी संसदीय दल अथवा ग्रुप को मान्यता देने में अध्यक्ष निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखेंगे:—

(एक) सदस्यों की संस्था, जो कोई संसदीय दल बनाना चाहे जिसने—

(क) सामान्य निर्वाचन के अवसर पर एक स्प-ट विचारधारा तथा संसदीय कार्यक्रम की, जिसके आधार पर वे इस सभा के लिए चुने गए हों, घो-णा की हो;

(ख) सभा के बाहर और भीतर एक-एक संगठन बना रखा हो; और

(ग) सभा की बैठक गठित करने के लिए निश्चित गणपूर्ति जितनी, अर्थात् सभा के सदस्यों की कुल संख्या के दसवें हिस्से के बराबर सदस्य संख्या बना ली हो।

(दो) संसदीय ग्रुप बनाने के लिए सदस्यों की संस्था इस निदेश के खण्ड (एक) के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करेगी और उस के कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए।

122. दलों और ग्रुपों को सुविधाएं.—(1) अध्यक्ष सभा के किसी दल को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान कर सकेगा/सकेगी, अर्थात्:—

¹⁰ दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग-दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹¹ दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग-दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा प्रतिस्थापित।

¹² दिनांक 09.05.1983 के लोक सभा समाचार भाग-दो के पैरा 2175 द्वारा अंतःस्थापित।

¹³ दिनांक 10.05.1989 के लोक सभा समाचार भाग-दो के पैरा संख्या 2931 द्वारा जोड़ा गया।

(क) दल की सदस्य संख्या तथा सभा भवन में उपलब्ध स्थानों की कुल संख्या के अनुपात में सभा में स्थानों को नियत करना।

(ख) दल के संसदीय कार्य के प्रयोजन के लिए संसद भवन में एक कमरा नियत करना।

(ग) दल की बैठक के लिए समिति-कक्ष अथवा उपलब्ध अन्य स्थान नियत करना।

(घ) उन संसदीय अथवा सरकारी पत्रों या प्रकाशनों का संभरण जिनका निश्चय अध्यक्ष समय-समय पर करे।

(ङ) दल के सदस्यों की संख्या के अनुपात में किसी संसदीय समिति के लिए नाम-निर्देशन करना।

(च) वाद-विवाद में बोलने के लिए बुलाए जाने हेतु सदस्यों के चुनाव के लिए नामों की एक तालिका अध्यक्ष को देना।

(छ) जहां कहीं आवश्यक हो, सभा के कार्य विन्यास अथवा सभा के समक्ष आने वाले किसी भी अन्य महत्वपूर्ण मामले पर परामर्श लेना।

(2) अध्यक्ष, किसी संसदीय गुप को इस निदेश में उल्लिखित सुविधाओं में से वे सुविधाएं दे सकेगा/सकेगी, जिनको अध्यक्ष गुप के लिए ठीक अथवा सम्भव समझे।

(3) किसी संसदीय दल अथवा गुप को सुविधाएं देने के बारे में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

123. सदस्यों के ऐसे समूह को सुविधाएं देना जिन्हें दल अथवा गुप के रूप में मान्यता प्राप्त न हो.—सदस्यों की संस्था जो संसदीय दल अथवा गुप के रूप में मान्य होने की शर्तों को पूरा न करे अध्यक्ष कुछ सुविधाएं प्रदान कर सकेगा/सकेगी, यदि अध्यक्ष के मत में, ऐसा करने से सभा के कार्य-संचालन में सुविधा होगी।

सभा तथा संसद भवन सम्पदा के परिसर

124. सभा तथा संसद भवन सम्पदा के परिसर.—नियमावली में प्रयुक्त “सभा के परिसर” अथवा “संसद भवन के परिसर” में, नियम 374 के प्रयोजनों को छोड़कर, नियम 2 में उल्लिखित स्थानों के अतिरिक्त, संसद भवन सम्पदा में निम्नलिखित स्थान सम्मिलित होंगे:—

- (एक) “सैण्ट्रल हॉल” और उसकी लॉबियां;
- (दो) सदस्यों के प्रतीक्षालय;
- (तीन) समिति कक्ष;
- (चार) संसद ग्रंथालय;
- (पांच) सदस्यों के जलपान गृह, भोजन कक्ष तथा भोज कक्ष (बैंक्वेट हॉल);
- (छह) संसद भवन, संसदीय सौध में लोक सभा कार्यालय तथा संसद भवन और संसदीय सौध के बाहरी स्वागत कार्यालय;
- (सात) उपरोक्त विभिन्न कमरों को जाने वाले अथवा उनके सम्बद्ध बरामदे और मार्ग; और
- (आठ) संसद भवन सम्पदा और संसद भवन तथा संसदीय सौध को जाने वाले मार्ग।

स्प-टीकरण—“संसद भवन सम्पदा” में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

(क) संसद भवन, संसदीय सौध और बाहरी स्वागत कार्यालय से संलग्न सभी भवन, संरचनाएं, संस्थापनाएं, लॉन तथा रिक्त भूमि; और

(ख) प्लॉट संख्या 118 (रेड क्रॉस रोड, रायसीना रोड और संसद भवन के बीच) और प्लॉट संख्या 115 (तालकटोरा रोड, पन्त मार्ग और संसद भवन के बीच), जो अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में है।

124क. संसद भवन सीमा क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखना.—

(1) लोक सभा का/की ¹⁴[निदेशक सुरक्षा] संसद भवन के सीमा क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी और वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव कार्रवाई करेगा/करेगी कि संसद सदस्यों को संसद भवन में आने अथवा वहां से जाने में कोई बाधा अथवा अड़चन न हो।

(2) संसद भवन का सम्पूर्ण क्षेत्र और सभी मार्ग संसद सदस्यों के लिए किसी बाधा अथवा अड़चन से मुक्त और खुले रखने के लिए संसद भवन सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियां निषिद्ध हैं:—

- (एक) सार्वजनिक सभा का आयोजन;
- (दो) पांच अथवा इससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना;
- (तीन) आग्नेय अस्त्र, झण्डे, इश्तिहार, लाठियां, भाले, तलवारें, डंडे, ईंट, पत्थर आदि लेकर चलना;
- (चार) नारे लगाना;
- (पांच) भा-गण आदि देना;
- (छह) जुलूस अथवा प्रदर्शन;
- (सात) प्रवेशरोधन अथवा धरना; और
- (आठ) कोई अन्य गतिविधि अथवा आचरण जिससे संसद सदस्यों के लिए बाधा अथवा अड़चन उपस्थित हो अथवा होने की आशंका हो।

(3) लोक सभा का/की ¹⁵[निदेशक सुरक्षा] अध्यक्ष के अनुदेशों अथवा अनुज्ञा के अंतर्गत, संसद भवन सीमा-क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस से, जब भी आवश्यक हो, सहायता के लिए प्रार्थना कर सकता/सकती है।

सदस्यों को भेजने के लिए मंत्रालयों आदि से प्राप्त पत्र और दस्तावेज

125. सदस्यों को भेजने के लिए मंत्रालयों आदि से प्राप्त पत्रों और दस्तावेजों पर कार्रवाई.—(1) लोक सभा सचिवालय भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के सदस्यों को भेजने के लिए प्राप्त पत्रों, दस्तावेजों और प्रतिवेदनों को सदस्यों को या तो उनके घर पर अथवा प्रकाशन काउन्टर के द्वारा भेज सकेगा;

परन्तु लोक सभा सचिवालय किसी ऐसे पत्र, दस्तावेज अथवा प्रतिवेदन को जिस पर “गोपनीय” अथवा “गुप्त” लिखा हो तब तक नहीं भेजेगा जब तक कि वह किसी संसदीय समिति के सदस्यों के लिए न हो और उसका संबंध उनके काम से न हो :

¹⁴ दिनांक 10.12.1987 के लोक सभा समाचार भाग-दो के पैरा संख्या 2005 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹⁵ दिनांक 11.12.1987 की विधि, 46/2/सी-एक/88, अ.रा. (1-1) में प्रकाशित।

परन्तु यह भी कि अध्यक्ष, यदि उचित समझे, तो निदेश दे सकेगा/सकेगी कि सदस्यों को भेजने हेतु लोक सभा सचिवालय के पास भेजा गया कोई पत्र, दस्तावेज अथवा सदस्यों को न भेजा जाए।

व्याख्या—इस निदेश के प्रयोजन के लिए “पत्र” शब्द में रा-द्रूपति, प्रधानमंत्री, भारत सरकार के मंत्रियों और मंत्रालयों से, उनके द्वारा आयोजित किसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए, सदस्यों को भेजने के लिए निमंत्रण पत्र भी सम्मिलित हैं।

(2) लोक सभा सचिवालय निम्नलिखित से सीधे प्राप्त किसी पत्र, दस्तावेज, प्रतिवेदन अथवा अन्य सामग्री को सदस्यों को नहीं भेजेगा:—

- (क) राज्य सरकारें;
- (ख) विदेशी दूतावास;
- (ग) निजी निकाय अथवा व्यक्ति; और
- (घ) संसद सदस्य जब तक कि उनसे प्राप्त पत्रों का सभा के कार्य से सम्बन्ध न हो।

प्रथम अनुसूची

[देखिए निदेश संख्या 38(1)]

लोक सभा सचिवालय

प्रे-क.....

नई दिल्ली, दिनांक.....20

(नाम तथा पदनाम)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

सेवा में,

श्रीमती/सुश्री/श्री.....

वि-य:—

महोदया/महोदय,

मुझे उपर्युक्त वि-य पर आपकी दिनांक.....
की याचिका की पावती स्वीकार करने का निदेश मिला है।
भवदीय

द्वितीय अनुसूची

(देखिए निदेश संख्या 84)

प्रवर/संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की प्रारम्भिक कण्डिकाएं
मैं, उस प्रवर/संयुक्त समिति का/की सभापति जिसे..... (यहां विधेयक का पूरा नाम लिखिए) विधेयक सौंपा गया था उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर उसका प्रतिवेदन जिसके साथ समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक संलग्न है, प्रस्तुत करता/करती हूं।

2. यह विधेयक लोक सभा में.....
.....(तिथि) को पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक को सभाओं की प्रवर/संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव (प्रस्ताव प्रतिवेदन के परिशि-ट के रूप में दिया जाएगा) सुश्री/श्रीमती/श्री.....(नाम) द्वारा.....
(तिथि) को प्रस्तुत किया गया था।

3. राज्य सभा ने(तिथियों) को प्रस्ताव पर चर्चा की थी और उक्त प्रस्ताव पर(तिथि) को सहमति प्रकट की (प्रस्ताव प्रतिवेदन के परिशि-ट के रूप में दिया जाएगा)।

4. राज्य सभा से प्राप्त संदेश.....(तिथि) को लोक सभा को पढ़ कर सुनाया गया था।

5. समिति की कुल.....(संख्या) बैठकें हुईं।

6. समिति की पहली बैठक.....(तिथि) को कार्यक्रम तैयार करने के लिए हुई थी। इस बैठक में समिति ने उन संस्थाओं के साक्ष्य सुनने का निर्णय किया जो.....(तिथि) तक इस अभिप्राय की प्रार्थना करें। समिति नेदौरे के प्रयोजन के लिए.....(तिथियों) को.....(स्थान) का दौरा करने का भी निश्चय किया।

7. समिति ने तदनुसार(केन्द्रों के नाम) का.....(तिथियों) को दौरा किया।

8. समिति ने निम्नलिखित संस्थाओं के प्रतिनिधियों का साक्ष्य उन तिथियों को जो उनके नाम के सामने दी हुई हैं सुना:—

(1)

(2)

इत्यादि।

दिए गए साक्ष्य का संक्षेप इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। (समिति ने सविस्तार दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखने का निश्चय किया)।

9. समिति ने(तिथियों) की बैठकों में विधेयक पर खण्डशः विचार किया।

10. समिति ने.....(तिथि) को(उद्देश्य) पर विचार करने के लिए(संख्या) सदस्यों की उप-समिति नियुक्त की। उप-समिति का प्रतिवेदन(तिथि) को समिति को प्रस्तुत किया गया था। (प्रतिवेदन परिशि-ट के रूप में दिया जाएगा)।

11. प्रवर/संयुक्त समिति का प्रतिवेदन.....(तिथि) तक प्रस्तुत किया जाना था। समिति को(तिथि) तक और समय दिया गया था। (दो या इससे अधिक बार समय बढ़ाए जाने के मामले में) समिति को.....(दो या तीन बार आदि) और समय दिया गया था।

पहली बार.....(तिथि) को(तिथि) तक और बाद में.....(तिथि) को.....(तिथि) तक।

12. समिति ने.....(तिथि) को प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

13. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के बारे में समिति के विचार आगामी कण्डिकाओं में दिए गए हैं।

पी. श्रीधरन, महासचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2014

No. 29/2/CI/2014.—The following paragraphs published in the Lok Sabha Bulletin-Part II dated 5th March, 2014, are hereby published for general information :—

“No. 6212

**MAKING DIRECTIONS BY THE SPEAKER
LOK SABHA
AS GENDER NEUTRAL**

The Directions by Speaker Lok Sabha have been made Gender Neutral by the Speaker and the same are hereby published in pursuance of rule 389 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fourteenth Edition). These Directions shall be deemed to have come into force on the 13th day of February, 2014.

CHAPTER I**OATH OR AFFIRMATION**

1. Oath or affirmation.—(1) A member, once declared elected is entitled to take seat in the House subject to making and subscribing an oath or affirmation in pursuance of article 99 of the Constitution.

(2) If a member is not able to make and subscribe the oath or affirmation at the commencement of a sitting of the House as provided in rule 5, such member may do so at any convenient time during the sitting of the House as the Speaker may direct.

CHAPTER II**ARRANGEMENT OF BUSINESS****BUSINESS BEFORE THE HOUSE**

¹[**2. Relative precedence of different classes of business.**— Unless the Speaker otherwise directs on any particular occasion, the relative precedence of the classes of business before the House specified below shall be in the following order, namely:—

- (i) Oath or affirmation.
- (ii) Laying of President's Address to both Houses of Parliament.
- (iii) Introduction of Ministers.
- (iv) Obituary references.
- (v) Questions (including short notice questions).
- (vi) Leave to move motions for adjournment of the business of the House.
- (vii) Questions involving a breach of privilege.
- (viii) Papers to be laid on the Table.
- (ix) Communication of messages from the President.
- (x) Communication of messages from the Rajya Sabha.

- (xi) Intimation regarding President's assent to Bills.
- (xii) Communications from magistrates or other authorities regarding arrest or detention or release of members of the House.
- (xiii) Announcements by the Speaker regarding leave of absence of members from the sittings of the House.
- (xiv) Announcements by the Speaker regarding various matters, *e.g.*, resignations of members of the House, vacation of seats of members, nominations to Panel of Chairpersons, Committees, etc.
- (xv) Ruling by the Speaker.
- (xvi) Presentation of reports of Committees/laying of minutes of sittings thereof etc.
- (xvii) Laying of evidence tendered before Select/Joint Committees on Bills.
- (xviii) Presentation of petitions.
- (xix) Statements by Ministers.
- (xx) Motions for elections to Committees.
- (xxi) Motions for extension of time for presentation of Reports of Committees.
- (xxii) Calling Attention Notices.
- (xxiii) Personal statements by ex-Ministers in explanation of their resignation.
- (xxiv) Statements under direction 115.
- (xxv) Personal explanations under rule 357 (if not made during the debate).
- (xxvi) Motions for adoption of reports of Business Advisory Committee.
- (xxvii) Motions for election of Speaker and Deputy Speaker.
- (xxviii) Motions for leave to move Resolution for removal of Speaker/Deputy Speaker.
- (xxix) Motion for leave to make a motion of no-confidence in the Council of Ministers.
- (xxx) Presentation of Railway Budget/Budget in respect of a State under President's Rule.
- (xxxi) Presentation of Supplementary /Excess Demands for Grants (General, Railways and in respect of a State under President's Rule).
- (xxxii) Bills to be withdrawn.
- (xxxiii) Bills to be introduced.
- (xxxiv) Laying of explanatory statements giving reasons for immediate legislation by Ordinances.
- (xxxv) Raising of matters under rule 377, which are not points of order.

¹ Sub. by L.S. Bn. (II) dated 10.5.1989, para 2931.

(xxxvi) Consideration of reports of Committee of Privilege.]

BALLOT OF PRIVATE MEMBERS' BILLS

3. Ballot.—There shall be one ballot under rule 27(2) in respect of two consecutive days allotted for private members' Bills. The ballot shall be held on such day not being less than seven days before the first day allotted for Private Members' Bills during a month, and in such manner as the Speaker may direct.

4. Notices of resumption of adjourned debate.—In case where notices of resumption of the adjourned debate on Bills are received after a ballot has been held, such Bills may be entered in the list of business below the Bills already balloted.

5. Order of ballot of Bills.—On a day allotted for the ballot of Private Members' Bills adequate number of Bills which will provide business for two days shall be balloted:

Provided that the Bills shall be balloted in the following order, namely:—

(1) Bills classified by the Committee on Private Members' Bills and Resolutions under category A.

(2) Bills classified by the Committee on Private Members' Bills and Resolutions under category B.

(3) Bills which have been introduced but not yet classified by the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

6. Result of ballot.—The result of every ballot shall be announced in Bulletin- Part II.

7. Treatment of Bills introduced after ballot.—As regards Bills which are introduced after the ballot is over and the notices of next motions in respect of which are received before the issue of the list of business, they may be set down in the list of business for the day after the Bills already balloted.

8. Treatment of notices of next motions and arrangement of business.—²[(1) After the result of ballot has been published in Bulletin-Part II, notices of next motions in regard to Bills as have secured a place among the first twenty Bills in the ballot of Private Members' Bills, shall be given by the members concerned by the dates specified in Bulletin so as to enable their Bills being included in the list of business.]

(2) In cases where notices of next motions are received after the list of business for the first of the two allotted days has been finalised, Bills in respect of which such notices are received may be included in the list of business for the next allotted day at their appropriate places as determined by the ballot held in respect of the two days.

BALLOT RELATING TO PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

9. Procedure of ballot.—(1) The names of all members who give notices under rule 170 that they wish to move resolutions on a day allotted for private members' resolutions, shall be balloted.

(2) There shall be a separate ballot for each day allotted for private members' resolutions.

(3) The time and place for holding the ballot shall be announced in Bulletin-Part II.

(4) The members who secure the first three places in the ballot shall be requested to give notice of one resolution each within two days after the date of the ballot.

ARRANGEMENT OF PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS IN LIST OF BUSINESS

9A. Saving of first priority resolution.—If time allotted for discussion of a part discussed resolution entered in the list of business for a day is increased by the House or the Speaker and as a result thereof the next resolution entered in the list of business on the basis of the first priority obtained at the ballot is not moved on that day, the said resolution shall be set down as the first item for the next day allotted during the same session for private members' resolutions after the part-discussed resolution, if any.

STATUTORY RESOLUTIONS

9B. Statutory resolutions.—(1) A resolution, notice of which has been given in pursuance of a provision in the Constitution or in an Act of Parliament, shall not be balloted under rule 28.

(2) If the Speaker admits notice of such a resolution, it shall be immediately notified in the Bulletin under the heading 'Statutory Resolutions', and a copy thereof sent to the Government.

(3) The Speaker may, after considering the state of business in the House and in consultation with the Leader of the House, allot a day or days or part of a day for the discussion of any such resolution.

CHAPTER III

QUESTIONS

10. Consolidation of questions on same or allied subject.—Where a large number of notices of questions are received from several members on the same or allied subject, the Speaker may direct that all the notices be consolidated into a single notice if, in the opinion of the Speaker, it is desirable to have a single self-contained question covering all the important points raised by members :

² Sub. by L.S. Bn. (II) dated 10.5.1989, para 2931.

¹[Provided that in the case of such a consolidated question being placed on the list of questions for oral answer, the names of not more than two members, determined in the order of precedence, shall be shown against such question and the notices of such members as are in excess shall be disallowed:

Provided further that in the case of such a consolidated question being placed on the list of questions for written answer the names of all the members concerned shall be bracketed and shown in the order of precedence.]

²[**10A. Admissibility of questions.**—Besides the conditions of admissibility of questions mentioned in rule 41, a question shall be inadmissible on any of the following grounds:—

- (i) It seeks information on matters which tend to encourage fissiparous and divisive tendencies and weaken the unity and integrity of the country;
- (ii) It relates to a matter of day-to-day administration or tends to further the interest of an individual or a few individuals;
- (iii) It relates to a matter falling primarily within the jurisdiction of the Chief Election Commissioner, C&AG, courts and other such functionaries;
- (iv) It relates to petitions and memoranda received by Ministers which are not of public importance;
- (v) It relates to a matter under negotiation with a government of other country and its disclosure may affect the course of negotiations to the detriment of the national interests; and
- (vi) It relates to a matter within the jurisdiction of the Speaker.]

³[**10B. Limit of Number of questions.**—A member shall be allowed to give not more than ten notices of questions both for oral and written answers, in all, for any day. Notices received in excess of ten from a member for a day shall be kept for subsequent day(s) concerning that Minister(s) during the period of that session only. Members who intend to give notices for the entire session may do so by indicating their *inter se* preference. In case, no such preferences are indicated, notices of questions in excess of ten per day shall be considered for subsequent day(s) on the basis of point of time of their receipt. However, the existing overall limit of five admitted questions per day per Member shall continue.]

11. List of starred questions.—Questions in the list of questions for oral answer on a day under rule 37 shall be arranged in accordance with the priority secured by each member at the ballot held for the purpose.

12. Printing of questions in proceedings.—When a question, placed on the list of questions for oral or written

answer on any day in the name of more than one member, is answered, the names of all such members shall be shown on the question in the printed report of the proceedings of Lok Sabha:

Provided that in the case of a question orally answered the name of the member who actually asked the question on the floor of the House shall be stated first and indicated by an asterisk mark.

13. Supply of statements in answer to starred questions to members concerned in advance and treatment thereof.—(1) When a statement is to be laid on the Table of the House in answer to a question for oral answer or where reference is made to an answer to a previous question, a copy of the statement together with a copy of the question and answer to which reference is made shall be made available to the member concerned half an hour in advance of the question hour.

(2) The copy of such a statement or answer to previous question referred to in the answer to a question for oral answer shall be supplied on request only to the member in whose name the question stands or to the member authorised by such member to ask the question on that member's behalf or to any person who has been duly authorised by such member in writing to receive the statement or answer.

(3) Copies of such statements or answers shall be considered as confidential and shall not be released for publication till after the question is answered or the question hour is over, whichever is earlier. If for any reason such a statement is not laid on the Table or the answer is not given or the contents thereof are altered by the Minister while answering the question in the House, the original statement shall not be made public.

13A. Answers to questions to be complete.—(1) Answers to questions given in the House shall be complete and, as far as possible, each part thereof shall be answered separately.

(2) On the attention being drawn to an answer, if the Speaker is satisfied that it does not fulfil this condition, the Speaker may direct the Minister to give a complete answer.

14. Answering together of starred questions on same or allied subject.—Where two or more questions on the same or allied subject addressed to a Minister for oral answer appear on the list of questions for any particular day and when the first of them comes up for answer, the Speaker may herself/himself or on the request of any member, direct that any or all such questions be taken up together for answer, irrespective of the order in which they stand in the list.

⁴[15. *****]

¹ Sub. by L.S. Bn. (II) dated 10.5.1989, para 2931.

² Sub. by L.S. Bn. (II) dated 10.5.1989, para 2931 and further sub. by L.S. Bn. (II) dated 5.10.1990, para 817.

³ Added by L.S. Bn. (II) dated 16.4.2010, para 1354.

⁴ Omitted by L.S. Bn. (II) dated 16.4.2010, para 1354.

16. Procedure for Ministers correcting answers to ⁵* questions ⁷***].**—When a Minister wishes to correct any inaccuracy in the information which the Minister has given in answer to a starred/ ⁶[unstarred]/ short notice question or a supplementary question⁸[*****], the following procedure shall be followed namely:—

(i) The Minister shall give to the Secretary-General notice of one's intention to make a statement. The notice shall be accompanied by a copy of the statement proposed to be made by the Minister.

(ii) When the House is in session, the Secretary-General shall include the item in the list of business on an appropriate day; and the Minister shall, when called upon by the Speaker, make the statement in the House.

(iii) When the House is not in session, the Secretary-General shall consider whether the statement shall be made by the Minister during the next session in which case the orders of the Speaker shall be taken. If the matter cannot wait till the next session, the statement shall be included in the official report of the proceedings of the House and a foot-note given in the proceedings in the following manner:

“The original reply or statement by the Minister reads as follows:—

‘.....’

The reply as printed above was sent by the Minister afterwards in substitution of the original reply.”

NOTE:— In cases where it is not considered desirable to publish the original answer, the revised answer only shall be printed with a suitable foot-note.

(iv) The Minister's intention to correct the answer or statement shall ordinarily be intimated within one week to the Secretary-General provided that the Speaker may, on being satisfied with the reasons given, waive this requirement.

⁹[(v) * * *]

¹⁰[16A * * *]

17. Advance copies of statements by Ministers correcting answers and Procedure after statements made.—(1) Copies of the statement proposed to be made by a Minister correcting the answer given by the Minister to a starred/¹¹[Unstarred]/short notice question ¹²[or a supplementary question] shall be placed in the Parliamentary Notice Office half an hour before the sitting of the Lok Sabha on the day on which the statement is to be made, for the information of members.

⁵Omitted *ibid.*

⁶ Ins. by *ibid.*

⁷⁻⁸Omitted by L.S. Bn. (II) dated 10.5.1989, para 2931.

(2) Copies of such statements shall be considered as confidential and shall not be released for publication until the statement is actually made.

(3) After the statement has been made, the Speaker may permit members to ask supplementary questions which are strictly relevant to the subject matter of the correction made by the Minister.

18. Answering of short notice questions of absent members.—If on a short notice question being called, it is not asked by the member or the member in whose name it stands is absent or if the member has not authorised another member to ask the question on her/his behalf, the Speaker ¹³[may direct that the answer to it be given].

¹⁴[* * *]

CHAPTER IV

HALF-AN-HOUR DISCUSSIONS

19. Laying of statement in reply.—When half-an-hour discussion under sub-rule (1) of rule 55 is interrupted for want of quorum or when there is no time for the Minister to give a full reply to the debate, the Minister may, with the permission of the Speaker, lay a statement on the Table of the House.

CHAPTER V

LEGISLATION

INTRODUCTION AND PUBLICATION OF BILLS

19A. Notice for leave to introduce Government Bills.—(1) A Minister desiring to move for leave to introduce a Bill shall give in writing the notice of one's intention to do so.

(2) The period of notice of a motion for leave to introduce a Bill under this direction shall be seven days unless the Speaker allows the motion to be made at shorter notice.

19B. Prior circulation of Bills for introduction.—No Bill shall be included for introduction in the list of business for a day until after copies thereof have been made available for the use of members for at least two days before the day on which the Bill is proposed to be introduced:

Provided that Appropriation Bills, Finance Bills, and such Secret Bills as are not put down in the list of business may be introduced without prior circulation of copies to members:

Provided further that in other cases, where the Minister desires that the Bill may be introduced earlier than

⁹Omitted by L.S. Bn. (II) dated 16.4.2010, para 1354.

¹⁰Omitted *ibid.*

¹¹⁻¹² Ins. *ibid.*

¹³Sub. *ibid.*

¹⁴Proviso omitted *ibid.*

two days after the circulation of copies or even without prior circulation, the Minister shall give full reasons in a memorandum for the consideration of the Speaker explaining as to why the Bill is sought to be introduced without making available to members copies thereof in advance, and if the Speaker gives permission, the Bill shall be included in the list of business for the day on which the Bill is proposed to be introduced.

OPINION ON BILLS

20. Circulation of Bills for eliciting opinion.—(1)

Where a motion that a Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon is carried, the Bill shall be circulated to the State Governments who shall be asked to forward in duplicate —

(a) their opinion on the provisions of the Bill;

(b) the opinions of members of State Legislatures and of such public bodies, selected officers and any other persons as the State Governments may think fit to consult, as soon as possible but not later than the expiry of the date for circulation of the Bill specified in the motion.

(2) The State Governments shall also be asked to consult High Courts in case the Government of India consider it necessary to do so in this regard.

(3) The State Governments shall also be asked to publish the Bill in their Gazettes, and to make it clear therein that opinions by persons or public bodies shall be sent only through the State Governments and not direct to the Secretary-General or any Ministry of the Government of India.

21. Time limit for eliciting opinion.—Where a date for circulation of the Bill for eliciting opinions has not been specified in the motion, the State Governments shall be asked to send opinions within three months of the adoption of the said motion.

22. Printing of opinions as papers to Bills.—After opinions have been received, they shall be edited and printed in convenient batches as Papers to the Bill. These Papers shall bear consecutive serial numbers.

23. Treatment of opinions in languages other than English and Hindi.—Opinions received in languages other than English and Hindi shall be treated as representations on the Bill and shall be kept in the Parliament Library after showing them to the Government of India. Members shall be informed about such representations through a notification in Bulletin-Part II.

24. Laying of Papers to Bills.—(1) As soon as opinions on a Bill are received they shall be laid on the Table by the member in charge:

Provided that in the case of a private member's Bill, in the absence of the member in charge, the opinions may be laid on the Table by the Minister concerned with the Bill.

(2) All opinions laid on the Table shall be printed and copies thereof shall be made available to members:

Provided that when the House is not in session, the Speaker may direct that the opinions may be circulated to the members before they are laid on the Table. In that case the opinion shall be laid on the Table as soon as possible thereafter.

25. Mode of laying of Papers to Bills.—The member in charge of the Bill while laying a Paper on the Table shall confine to a statement in the following form:—

‘Madam/Sir, I beg to lay on the Table Paper No. 1 to the Bill..... (stating long title of the Bill) which was circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the direction of the House on..... 20.....’

26. Precis of opinions.—After the Bill, which has been circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the direction of the House, has been referred to a Select/Joint Committee under sub-rule (3) of rule 75, copies of precis of opinions on the Bill laid on the Table shall be made available to members of the Select/Joint Committee on the Bill.

PRIVATE MEMBERS' BILLS

27. Classification and allocation of time.—As soon as possible after introduction of a private member's Bill, the Bill shall be placed before the Committee on Private Members' Bills and Resolutions for classification and allocation of time under clauses (b) and (c) of rule 294(1). The member in charge of the Bill and the representative of the Ministry concerned with the Bill may be invited to appear before the Committee to present their views. The Committee shall classify the Bill and allot time to it after giving due weight to the considerations urged by the member in charge and the representative of the Ministry.

28. Clubbing of names in case of notices of identical Bills.—(1) The names of all members who have given separate notices of an identical Bill shall be shown together in the list of business against the motion for leave to introduce the Bill.

(2) The names of such members shall be appended to the Bill in the order in which the notices have been received in point of time.

(3) The member whose name appears first shall move the motion for leave to introduce the Bill:

Provided that in case the first member is absent, the next member present may make the motion for leave to introduce the Bill.

29. Giving of authority for introduction of Bill.—A member who has given notice of one's intention to move for leave to introduce a Bill, may authorise any other member to make the motion on that member's behalf:

Provided that the authority shall be in writing and shall specifically state that all subsequent motions in

respect of the further stages of the Bill shall be in charge of the member so authorised:

Provided further that before the Bill is published in the Gazette, the Statement of Objects and Reasons accompanying the Bill shall be signed by the member who has actually introduced it.

30. Giving of authority to pilot Bill after introduction.—The Speaker may, on being satisfied on an application made in this behalf by the member in charge of a Bill that such member for reasons which the Speaker considers adequate is unable to pilot by oneself any or all stages of a Bill subsequent to its introduction, permit the member in charge of the Bill to nominate another member to pilot the stage or stages of the Bill in respect of which a request has been made to the Speaker.

AMENDMENTS TO BILLS

31. Insertion of new clause.—When an amendment for the insertion of a new clause in a Bill is adopted by the House, the Speaker shall put the question thus:

‘The question is:

That clause (*quoting the number of the new clause*) be added to the Bill.’

CORRECTION IN BILLS

32. Procedure for corrections in Bills.—No alteration shall be made in a Bill as introduced or in a Bill as reported by a Select/Joint Committee except by way of an amendment adopted in the House:

Provided that the Speaker shall correct any obvious printing or clerical error at any stage of the Bill by issue of a corrigendum to the Bill:

Provided further that in the case of a secret Bill printed by the Ministry concerned before introduction, such a correction in the Bill, as introduced, shall not relate to an error affecting taxation.

INDICATION IN DEBATES REGARDING CORRECTION OF PATENT ERRORS IN BILLS

33. Incorporation of corrections in Debates.—(1) Where an amendment to a clause has been moved and adopted by the House and subsequently the Official Draftsperson, while scrutinizing the Bill, as passed, has suggested any correction which has been accepted by the Speaker as a patent error, such a correction shall be incorporated in the body of the amendment itself without any foot-note in the printed debate.

(2) Where the Speaker has accepted a correction suggested by the Official Draftsperson relating to a clause and not to an amendment to a clause which has been adopted by the House, such a correction shall be indicated with an appropriate foot-note, in the printed debates as indicated below:—

“In view of the amendment to clause..... part () of sub-clause () of clause..... (as the case may be) adopted

by the House the words ‘.....’ occurring in clause...../part () of sub-clause () of clause..... (as the case may be) were omitted or inserted as patent errors under the direction of the Speaker.”

BILLS AS PASSED

34. Scrutiny, change of year and authentication.—

(1) Where a Bill, as passed by the Houses, is in possession of the Lok Sabha, a copy thereof shall be sent to the draftsman, in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice for scrutiny before it is presented to the President under rule 128.

(2) If in the opinion of the draftsman the Bill is not likely to be assented to in the same year in which the Bill is passed and the draftsman makes a suggestion that the year in the title clause be changed, the Speaker may accept the suggestion and make the consequential change in clause 1 and other clauses of the Bill, wherever necessary.

(3) In such a case the Bill shall be authenticated in the same year in which it is likely to be assented to.

35. Laying of Bills after assent.—Every Bill passed by the Houses of Parliament and assented to by the President under article 111 of the Constitution shall be laid by the Secretary-General on the Table:

Provided that in the case of a Bill on which assent is obtained by the Rajya Sabha Secretariat, the Bill, as assented to by the President, shall be duly authenticated by the Secretary-General of Rajya Sabha before being laid on the Table.

WITHDRAWAL AND REMOVAL OF BILLS

36. Advance circulation of reasons for withdrawal of Government Bills.—When a Bill pending in Lok Sabha is sought to be withdrawn by Government, a Statement containing the reasons for which the Bill is being withdrawn shall be circulated to members by the Ministry concerned sufficiently in advance of the date on which the motion for withdrawal is sought to be made.

37. Removal of pending Bills from Register of Bills.—Where a pending Bill seeks to amend an Act which is subsequently repealed, it shall be removed from the Register of Bills pending in the House.

CHAPTER VI

PETITIONS

38. Examination and presentation.—(1) As soon as a petition is received it shall be acknowledged in the form specified in the First Schedule.

(2) Every petition before presentation to the House shall be examined in order to see whether it is —

(a) in proper form;

(b) couched in respectful, decorous and temperate language;

(c) in conformity with the rules and decisions that may be taken from time to time.

(3) After the petition has been examined and is found to be generally in order, it shall be presented to the ¹[House by the Member]:

Provided that in the case of a petition on a Bill pending before the House, ²[it shall be presented to the House, as soon as possible after its receipt]:

Provided further that in the case of a petition on a Bill pending before a Select or Joint Committee, the petition may be referred to that Committee without being presented to the House and the petitioner informed accordingly.

39. Withdrawal of defective petitions.—If a petition, after presentation, is found defective, it may be withdrawn by an order of the Speaker and the petitioner informed accordingly.

40. Admissibility of petitions.—(1) A petition shall be rejected or returned to the petitioner if it—

- (i) relates to personal or individual grievances; or
- (ii) relates to matters specified in clause (iii) of rule 160 of the Rules of Procedure.

(2) In case it is considered necessary to ascertain the facts from the Ministry concerned in order to determine the admissibility of the petition, a reference may be made to the Ministry and facts gathered or action taken by them ascertained.

CHAPTER VII

MOTIONS

41. Classification of motions.—(1) All motions, notice of which is received in the Lok Sabha Secretariat under the rules, shall be classified under the following categories, namely:—

- (i) Substantive Motions;
- (ii) Substitute Motions; and
- (iii) Subsidiary Motions which are further divided into three classes:—
 - (a) Ancillary Motions,
 - (b) Superseding Motions, and
 - (c) Amendments.

(2) The classification referred to in (i) above shall be used in the case of appropriate motions. The rules governing these motions shall be as follows:—

(i) *Substantive Motions.*— A substantive motion is a self-contained independent proposal submitted for the approval of the House and drafted in such a way as to be capable of expressing a decision of the House, *e.g.*, all resolutions are substantive motions.

(ii) *Substitute Motions.*— Motions moved in substitution of the original motion for taking into

consideration a policy or situation or statement or any other matter are called substitute motions. Such motions, though drafted in such a way as to be capable of expressing an opinion by themselves, are not strictly speaking substantive motions inasmuch as they depend upon the original motion.

(iii) *Subsidiary Motions.*—They depend upon or relate to other motions or follow upon some proceedings in the House. They by themselves have no meaning and are not capable of stating the decision of the House without reference to the original motion or proceedings of the House.

Subsidiary motions are further divided into:—

- (a) Ancillary Motions;
- (b) Superseding Motions; and
- (c) Amendments.

(a) *Ancillary Motions.*—They are motions which are recognized by the practice of the House as the regular way of proceeding with various kinds of business. The following are the examples of ancillary motions, namely:—

- (i) That the Bill be taken into consideration.
- (ii) That the Bill be passed.

(b) *Superseding Motions.*—They are motions which, though independent in form, are moved in the course of debate on another question and seek to supersede that question. In that class fall all the dilatory motions. The following motions are superseding motions in relation to the motion for taking into consideration a Bill:—

- (i) That the Bill be re-committed to a Select Committee.
- (ii) That the Bill be re-committed to a Joint Committee of the Houses.
- (iii) That the Bill be re-circulated for eliciting further opinion thereon.
- (iv) That consideration of the Bill or the debate on the Bill be adjourned *sine die* or to some future date.

(c) *Amendments.*—They are subsidiary motions which interpose a new process of question and decision between the main question and its decision. Amendments may be to the clause of a Bill, to a resolution or to a motion, or to an amendment to a clause of a Bill, resolution or motion.

42. Member to be shown in proceedings as mover of motion, amendment or cut motion.—Where a motion, an amendment or a cut motion placed on the order paper in the names of several members is treated as moved on an indication being given by such members in writing to the Speaker, it shall be deemed to have been moved by the member whose name appears first on the order paper and if

¹⁻²Sub. by L.S. Bn. (II) dated 17.2.2014 para 6175.

that member has not indicated the intention to move or is not present in the House then, by the second member or the third member etc., who may be present and the name of only such member shall be shown in the proceedings as the mover of that motion, amendment or cut motion, as the case may be.

43. Amendment or cut motion moved but not put to vote.—When an amendment or a cut motion is moved but not put to the vote of the House by the Speaker and the original motion or demand for grant is passed by the House, the amendment or cut motion shall be deemed to have been negated by the House.

44. Amendment or motion moved but not pressed.—If at the end of the debate, a member who has moved an amendment or a motion which has also been proposed by the Chair, informs the Chair that the member does not want to press it and if thereupon the amendment or motion is not put by the Chair to the vote of the House such amendment or motion shall be deemed to have been withdrawn by the leave of the House:

Provided that if any member requests the Chair to put the amendment or motion to the vote of the House, the amendment or motion shall be put to the vote of the House.

45. Order of putting substitute Motions to vote.—(1) When substantive motions have been moved by members in substitution of a motion under rule 342, the Speaker may, in own discretion, put them to the vote of the House in the following order:—

(i) Motions expressing disapproval of the policy or action of Government referred to in the original motion; and

(ii) Motions expressing approval of the policy or action of Government referred to in the original motion.

(2) Where any of the substantive motions moved in substitution of a motion under rule 342, is not put to the vote of the House by the Speaker, and any such other substantive motion in substitution of the same motion is passed by the House, the one not put to the House shall be deemed to have been negative by the House or barred, as the case may be.

46. Date for report in motion for reference of a Bill to Select/Joint Committee.—When a motion is moved for reference of a Bill to a Select Committee or to a Joint Committee of the Houses with the concurrence of the Rajya Sabha, the motion shall specify a definite date on or before which the Select Committee or the Joint Committee shall be instructed to report:

Provided that if on the date specified the House is not in session, the report shall be submitted to the Speaker who shall cause it to be laid before the House as soon as possible after the reassembly of the House.

47. Withdrawal of private members' Bill.—On a day allotted for the disposal of private members' Bills, a Bill in respect of which the motion is that leave be granted to withdraw the Bill, shall be set down in the list of business for that day immediately after the Bills for introduction.

CHAPTER VIIA

CALLING ATTENTION

47A. Procedure when two calling attention admitted for a day.—(1) Where under rule 197(3) two calling attention matters have been included in the list of business for a day, the Minister concerned may make a brief statement in respect of the first matter. In respect of the second matter, a statement may be laid on the Table by the Minister concerned. Copies of the statement so laid shall be supplied to the members in whose names the item stands in the list of business ¹[and the Minister shall reply at the end to the clarificatory questions asked thereon].

(2) If the Prime Minister is to make a statement in response to one of the two calling attention matters on a day, that matter may be given *inter se* priority in the list of business.

CHAPTER VIIB

RESIGNATION OF SEATS IN THE HOUSE

47B. Resignation of seats in the House.—(1) A letter of resignation under rule 240 of the Rules of Procedure shall become effective only after it is accepted by the Speaker.

(2) The resignation shall take effect from the date from which the resignation is accepted by the Speaker and it shall be not open to a member to withdraw the resignation after it is accepted by the Speaker.

(3) If the member has specified a future date for her/his resignation to take effect, the resignation shall take effect from the date so specified if the Speaker has accepted the resignation by that date.

(4) The resignation shall not be accepted from a date earlier than the one on which it is received by the Speaker or in the Lok Sabha Secretariat.

CHAPTER VIII

PARLIAMENTARY COMMITTEES

GENERAL DIRECTIONS

48. Parliamentary Committee.—In this Chapter, unless the context otherwise requires, 'Committee' means and includes 'Parliamentary Committee' as defined in sub-rule (1) of rule 2.

48A. ¹[Manner of election to Committees.]—Elections to Parliamentary Committees shall be held in accordance

¹Added by L.S. Bn. (II) dated 10.5.1989, para 2931.

¹Ins. by L.S. Bn. (II) dated 10.5.1989, para 2931.

with the regulations made by the Speaker for holding of elections to Committees by means of the single transferable vote.]

49. Applicability of general directions to Parliamentary Committees.—Except for matters for which special provision is made in the directions relating to any particular Committee, the general directions in this Chapter shall apply to all Committees; and if and so far as any provision in the special directions relating to a Committee is inconsistent with general directions, the former shall prevail.

50. Venue of sittings.—(1) Sitting of a Committee/ Sub-Committee, whether formal or informal, at which Officers or staff of the Lok Sabha Secretariat are required to be present, shall invariably be held within the precincts of the Parliament House. If, for any reasons, it becomes necessary to hold a sitting of the Committee outside the Parliament House, the matter shall be referred for directions of the Speaker.

(2) When the Committee is on a study tour, informal sittings may be held at the place of the visit, but at such sittings, no decisions shall be taken nor any evidence recorded.

51. Time of sittings whilst House sitting.—Unless the Speaker otherwise permits, no sitting of a Committee shall be held after the commencement of a sitting of the House and before 15.00 hours on days when the House is sitting.

²[**51A. Last minute cancellation of sittings of Committees.**—No sitting of a Committee shall be cancelled or preponed or postponed by the Chairperson of a Committee by reason only of immediate non-availability of the Chairperson, for the sitting or, for the absence from the sitting already fixed.]

52. Procedure for speaking in Committees.—(1) A member desiring to make any observations at the sitting of a Committee shall address the Chairperson and make all remarks to other members through the Chairperson.

(2) A member shall not speak unless the Chairperson calls.

(3) Any member, who desires to interrupt while another member is speaking, shall seek the permission of the Chairperson to do so.

52A. Personal, pecuniary or direct interest of member.—(1) Where a member of a Committee has a personal, pecuniary or direct interest in any matter which is to be considered by the Committee, such member shall state one's own interest therein to the Speaker through the Chairperson of the Committee.

(2) After considering the matter, the Speaker shall give decision which shall be final.

53. Putting of question to vote.—The Chairperson, if considers that sufficient discussion has taken place on a question, may, without further discussion, put the question to vote and arrive at a decision.

54. Reopening of question.—If a member desires to reopen a question on which a Committee has already taken a decision the member shall, in the first instance, obtain the permission of the Chairperson to do so.

55. Proceedings and certain documents treated as Confidential.—(1) The proceedings of a Committee shall be treated as confidential and it shall not be permissible for a member of the Committee or any one who has access to its proceedings to communicate, directly or indirectly, to the press any information regarding its proceedings including its report or any conclusions arrived at, finally or tentatively, before the report has been presented to the House.

^{2A}[(1A) The provisions of clause (1) shall also *mutatis mutandis* apply to the proceedings of meetings held by the Speaker with the Leaders of Parties and Groups in Lok Sabha.]

(2) Whenever a paper or document, marked 'secret' or 'confidential' is circulated to the members of the Committee, the contents of such paper or document shall not be divulged by any member either in the minute of dissent or on the floor of the House, or otherwise, without the permission of the Speaker; and where such permission has been obtained any restriction imposed by the Speaker in regard to the manner in which, or the extent to which, the information contained in the document may be divulged, shall be strictly observed.

56. Procedure regarding Sub-Committees.—(1) If a Committee appoints a sub-Committee to consider special points under rule 263(1), the report of the Sub-Committee duly signed by the Chairperson on behalf of the Sub-Committee shall be submitted by the prescribed period and copies of the same shall be made available to all members of the Committee before they meet to consider the report of the Sub-Committee.

(2) The Chairperson of the Committee shall appoint the Chairperson of the Sub-Committee.

(3) The procedure in the Sub-Committee shall, as far as practicable, be the same as is followed in the whole Committee.

57. Evidence of experts and interested parties.—(1) A Committee may take evidence of experts or interested parties on their own initiative or on requests made.

²Added by L.S. Bn. (II) dated 25.6.2010, para 1522.

^{2A}Inserted by L.S. Bn. (II) dated 9.9.1974, para 1933.

(2) The witnesses who express their desire to appear before the Committee shall supply sufficient number of copies of written memoranda for circulation to the members of the Committee who may consider the same at their sitting and then decide whether such witnesses should be called to appear before the Committee.

58. Evidence liable to be treated as public.—Where witnesses appear before a Committee to give evidence, the Chairperson shall make it clear to the witnesses that their evidence shall be treated as public and is liable to be published, unless they specifically desire that all or any part of the evidence given by them is to be treated as confidential. It shall, however, be explained to the witnesses that even though they might desire their evidence to be treated as confidential such evidence is liable to be made available to the members of Parliament.

59. Evidence of officials of Government of India and Undertakings.—(1) Where a Ministry or Department or Undertaking is required to give evidence before a Committee on any matter, the Ministry or Department or Undertaking shall be represented by the Secretary or the Head of the Department or Undertaking, as the case may be:

Provided that the Chairperson of the Committee may, on a request being made in this behalf, permit any other senior officer to represent the Ministry or Department or Undertaking before the Committee.

(2) The Committee may require the Ministry or Department or Undertaking to furnish to the Lok Sabha Secretariat a sufficient number of copies of any memorandum containing its views on the matter under discussion for circulation to members of the Committee in advance of the date on which the representative of the Ministry or Department or Undertaking has to give evidence before the Committee.

(3) A 'resume' of the evidence given by the representative of the Ministry or Department or Undertaking may be embodied in or appended to the minutes of the sittings.

60. Evidence of officials of State Governments.—(1) Whenever it is felt necessary to invite an official of a State Government to appear as a witness before a Committee or to ask the State Government to produce a document or paper before the Committee, the orders of the Speaker shall be obtained before the official or the State Government is asked to comply with the request.

(2) In case the Speaker decides that it is not necessary to summon a particular State official as a witness, or that the State Government need not be asked to produce a paper, document or record, the Chairperson of the Committee concerned, if thinks necessary, may apprise the Committee of the Speaker's decision.

61. Consideration of memoranda supplied by witnesses—A Committee shall, in the first instance,

consider the memoranda supplied by the witnesses, when copies are circulated to all the members of the Committee, and the nature of questions that may be asked of the witnesses shall be for clarification of any points included in their memoranda or any other fresh point arising out of the discussion.

62. Mode of examination of witnesses.—(1) The Chairperson may first ask any question and thereafter may call other members, one by one, to ask questions.

(2) Witnesses may, with the permission of the Chairperson, place before the Committee any other relevant information which has not been already placed before the Committee.

63. Mode of addressing Communications on matters before Committees.—All Communications from Ministries and all suggestions, memoranda and representations etc., in respect of matters pending before a Committee which are received from individuals, associations and public bodies shall be addressed to the Secretary-General and if in any case a letter, memorandum etc., is addressed or sent direct to the Chairperson, such letter, memorandum, etc. may be sent to the Lok Sabha Secretariat for its disposal and record.

63A. Procedure for presenting views of Ministries to Speaker.—If any Ministry or Department wish to present their views to the Speaker on any matter which has been considered by, or is pending before, a Committee, they shall forward to the Lok Sabha Secretariat a written statement formulating precisely the points on which the decision of the Speaker is desired. The statement, together with the relevant papers showing the views of the Committee, shall then be submitted to the Speaker who may, if necessary, discuss the matter with the Minister concerned and/or with the Chairperson of the Committee before arriving at a decision.

64. Expunction from documents presented to Committees.—(1) If in the opinion of the Chairperson, a document such as representation, memorandum etc., presented to a Committee contains words, phrases or expressions which are unparliamentary, irrelevant or are not couched in respectful, decorous and temperate language, or are otherwise inappropriate, the Chairperson may order such words, phrases or expressions to be expunged from such document.

(2) Notwithstanding anything contained in (1) above, the Speaker shall have the power to order expunctions in like circumstances or to review all decisions regarding expunction from such documents and the decision of the Speaker thereon shall be final.

65. Verbatim proceedings.—(1) Verbatim proceedings of a Committee, if taken, shall be treated as confidential and shall not be made available to anyone without the orders of the Speaker.

(2) Relevant portions of the verbatim proceedings of the sitting, at which evidence has been given, shall be

forwarded to the witnesses and members concerned for confirmation and return by a date fixed by the Lok Sabha Secretariat. If corrected copies of the proceedings are not received back by the specified date, the reporter's copy may be treated as authentic.

(3) Corrections in the verbatim proceedings, if any, shall be made neatly and legibly by the witness or the member, as the case may be, in ink and one's own handwriting and shall be confined to correction of inaccuracies which may have occurred in the process of reporting and not for the purpose of improving their literary form or altering their substance by additions and deletions.

66. Minutes.—(1) The decisions of a Committee shall be recorded briefly in the minutes of the Committee.

(2) The draft minutes shall be prepared by the Lok Sabha Secretariat and approved by the Chairperson.

(3) The minutes of each sitting may be circulated to members of the Committee. Relevant extract therefrom may also be circulated to any Ministry or Officer, if considered necessary.

(4) If any member desires any alterations in the minutes, on the ground that they are not in conformity with the decision arrived at, the matter shall be referred to at the next sitting of the Committee and the decision of the Committee taken thereon shall be incorporated in the minutes of the sitting.

(5) Until the minutes are presented to the House, they shall be treated as confidential.

67. Laying of minutes—(1) After the minutes of a sitting or sittings of a Committee have been approved by the Chairperson, or in the absence of the Chairperson, by the member of the Committee who presided at the sitting, or sittings, as the case may be, an authenticated copy thereof may be laid on the Table of the House.

(2) An entry shall be made in the list of business for the day regarding the laying of the minutes on the Table.

(3) The Chairperson or a member of the Committee shall, while laying the minutes on the Table, confine oneself to a statement in the following form:—

‘Madam/Sir, I beg to lay on the Table of the House the minutes of the Sitting (or Sittings) of the Committee on... held on....’

68. Reports.—(1) A Committee shall present reports to the House or to the Speaker, as the case may be, from time to time.

(2) The draft of the report shall be prepared by the Lok Sabha Secretariat and may be placed before the Committee after it is approved by the Chairperson.

(3) There shall be no minute of dissent to the report.

69. Circulation and consideration of draft reports.—

(1) The Chairperson of a Committee may direct that the

typed, cyclostyled or proof copies of the draft report together with any other documents connected therewith, be circulated amongst the members of the Committee before the date fixed for the consideration of the draft report.

(2) On the date fixed for the consideration of the draft report, the Chairperson shall read out the draft report, paragraph by paragraph, putting the question to the Committee at the end of each paragraph, ‘That the paragraph do stand part of the report’. A member objecting to any portion of the report, not being in conformity with the decisions arrived at, shall propose amendment to bring it in line with the decisions. The amendment, if accepted, shall be incorporated in the said paragraph.

70. Mention in report and circulation of evidence.—

(1) A Committee shall mention in the report, wherever necessary, the fact that evidence was given before it.

(2) The record of evidence if so decided by the Committee, shall be printed and copies thereof circulated to all members of the House.

71. Signing of report of Committee.—The Chairperson or in the absence of Chairperson another member chosen by the Committee under rule 258(3) or rule 277(3), as the case may be, shall sign the report on behalf of the Committee.

71A. Presentation of report of Committee to Speaker when House not in session.—(1) Ordinarily the report of a Committee shall be presented to the House, but in case the Committee complete their report when the House is not in session, the Chairperson of the Committee may present it to the Speaker.

(2) The Speaker may under the provisions of rule 280 order the printing, publication or circulation of the report before it is presented to the House.

(3) Where a report is presented to the Speaker or where its printing, publication or circulation have been ordered by the Speaker, the fact shall be notified in Bulletin-Part II.

(4) The Speaker may, if so requested by the Committee, direct that matters of factual nature, or patent errors may be corrected in the report presented to the Speaker by a Committee, before the report is printed, published or circulated and later presented to the House.

(5) The report shall be presented to the House during the next session at the first convenient opportunity by the Chairperson or in the absence of Chairperson by a member of the Committee. While presenting the report, the Chairperson or in the absence of Chairperson the member presenting the report shall confine oneself to a brief statement to the effect that the report was presented to the Speaker when the House was not in session and that orders for its printing, publication or circulation were given by the Speaker under rule 280.

(6) Where the Lok Sabha is dissolved, after the presentation of the report to the Speaker, and before the presentation of the report to the House, the report shall be laid by the Secretary-General on the Table of the new House at the first convenient opportunity. While laying the report, the Secretary-General shall make a statement to the effect that the report was presented to the Speaker of the preceding Lok Sabha before its dissolution and where it was ordered by the Speaker to be printed, published or circulated under rule 280, the Secretary-General shall also report that fact to the House.

71B. Correction of patent errors or factual matters in reports.—The Chairperson of a Committee/Sub-Committee shall have power to correct patent errors or matters of factual nature in the report adopted by the Committee/Sub-Committee, before its presentation to the House/Speaker or whole Committee, as the case may be.

72. Printing and circulation of reports.—(1) The report, together with the documents connected therewith, if any, shall be printed before or after presentation to the House or the Speaker, as the case may be.

(2) Until the report is presented to the House, it shall be treated as confidential.

(3) As soon as possible after presentation of the report to the House printed copies of the report shall be circulated to members of the Lok Sabha and the Ministries of the Government of India and to such other persons, authorities etc. as may be determined from time to time.

73. Time gap for release to press reports circulated to members under rule 280.—Where, under rule 280, a report of a Committee is circulated to members prior to its presentation to the House, it shall be released to the press after a week from the date of despatch of copies to members.

³[STATEMENT BY MINISTER ON COMMITTEE REPORTS]

73A. Implementation of Committees' recommendations.—The Minister, with regard to the Ministry concerned, shall make once in six months a statement in the House regarding the status of implementation of recommendations contained in the Reports of Departmentally Related Standing Committees of Lok Sabha.]

SELECT/JOINT COMMITTEES ON BILLS

74. Memoranda or representations addressed to Select/Joint Committees.—When any memorandum/representation addressed to a Select/Joint Committee on a Bill is received in the Lok Sabha Secretariat at any time after the Committee has met, it shall form part of the records of the Committee and no person shall, without the Speaker's permission, quote therefrom or send copies thereof to anyone else, unless it has been presented to the House either along with the report of the Committee or separately.

75. Notice and admissibility of amendments.—(1) If a member wants to move amendments at a sitting of a Select/Joint Committee, the member shall send, one day in advance, a copy of the notice of such amendments to the Lok Sabha Secretariat. Copies of the amendments shall be circulated by the Lok Sabha Secretariat to all members of the Select/Joint Committee to facilitate discussion at the sittings of the Select/Joint Committee.

(2) If any question arises whether a particular amendment is within the scope of the Bill, the question shall be decided by the Chairperson of the Select/Joint Committee whose decision shall be final.

76. No general discussion on Bill.—The principle of the Bill having been accepted by the House by adoption of the motion for reference of the Bill to the Select/Joint Committee, further general discussion on the Bill as a whole shall not be permissible in a Committee.

77. Clause by Clause discussion of Bill.—The Chairperson shall ordinarily put the Bill before a Select/Joint Committee, clause by clause, and invite members to offer their comments, if any, and thereafter members may move their amendments, if any.

78. Consideration of draft report and Bill as amended.—After the clause by clause consideration of the Bill is over, the Chairperson shall fix a sitting of a Select/Joint Committee not earlier than three days thereafter to consider the draft report and the Bill as amended unless a shorter period is fixed by the Committee by a unanimous vote.

79. Speaker to be kept informed of Committee's Progress.—(1) The Chairperson shall keep the Speaker informed of the progress in the work of a Select/Joint Committee from time to time.

(2) Whenever the progress of the Select/Joint Committee in regard to the Bill before them is such that there is likelihood of there being delay in the presentation of the report to the House, the matter shall be brought to the notice of the Speaker as soon as it becomes clear to the Chairperson that such delay is likely to occur. The Chairperson shall briefly state the circumstances which are responsible for such delay, the estimated time that it would take to complete the work and any other matter which, in the opinion of Chairperson, should be brought to the notice of the Speaker.

80. Extension of time for presentation of report.—(1) The Chairperson or in the absence of the Chairperson any member of a Committee, shall, if so authorised by the Committee and after informing the Speaker as laid down in direction 79(2), move in the House for extension of time for the presentation of the report to a definite date which shall be specified in the motion.

³Added by L.S. Bn. (II) dated 1.9.2004, para 456.

(2) The date upto which the time of presentation of the report is sought to be extended may be specified on the reasonable presumption that the House might be in session on that date. If, however, it happens that the House is not in session on the date so specified, the report shall be submitted to the Speaker on or before that date as the Committee may decide and the Speaker shall cause it to be laid before the House as early as possible after the House reassembles.

81. Submission of memoranda on Bills by members.—(1) At any time before the consideration of the Bill is finally concluded by a Select/Joint Committee, any member of the Committee may submit a memorandum or note containing the views of that member on the Bill in writing to the Committee.

(2) The Chairperson, if thinks fit, may direct that copies of the note or extracts therefrom be circulated to the members of the Committee.

82. Petitions on Bills stand referred to Select/Joint Committees.—All petitions which are received in the Lok Sabha Secretariat and are considered as admissible under the rules shall stand referred to the Select/Joint Committee on the Bill to which they relate, if such a Committee has been constituted. Such petitions may be examined by the Committee which may also give a hearing to such petitioners if deemed necessary.

83. Particulars of petitions etc., and action taken to be stated in reports.—Where any petition, representation or memorandum is received by a Select/Joint Committee, the report of the Committee shall state the number of such documents received and shall also attach an appendix giving briefly the particulars thereof and action taken thereon.

84. Pattern of report.—Unless the Speaker otherwise directs, the report of a Select/Joint Committee on a Bill shall have introductory paragraphs as given in the Second Schedule, with such changes as may be necessary in the light of the facts of each case.

85. Minute of dissent.—If a member desires to append a minute of dissent to the report of a Select/Joint Committee, the member shall hand over the minute of dissent, written in ink or typed on foolscap size paper, to the officer in charge of the Select/Joint Committee on or before the date and time fixed by the Chairperson of the Committee.

86. Date of minute of dissent.—If a minute of dissent sent by a member does not bear any date, the date on which the same is received in the Lok Sabha Secretariat shall be indicated against the name of the signatory in the manner shown below:—

‘[Received on the 20.....]’

87. Minutes of dissent from member absen when report adopted by Committee.—A member who has been absent from the sitting or sittings of a Committee at which the draft report of the Committee was considered and

adopted with or without amendments, as the case may be, may give a minute of dissent if that member certifies in writing of having read the report.

88. Committee to be informed by direction 87.—At the conclusion of the clause by clause consideration of the Bill, the Chairperson shall inform the Committee of the provisions of direction 87.

89. Minute of dissent to be given after adoption of report.—A minute of dissent shall be given only after the draft report has been considered and adopted by a Committee and it shall not be conditional in any respect.

90. Minute of dissent not acceptable after presentation of report.—A minute of dissent shall not be accepted after the report has been presented to the House.

91. Expunction from minute of dissent.—(1) If in the opinion of the Chairperson, a minute of dissent contains words, phrases or expressions which are unparliamentary, irrelevant or otherwise inappropriate, the Chairperson may order such words, phrases or expressions to be expunged from the minutes of dissent.

(2) Notwithstanding anything contained in (1) above, the Speaker shall have the power to order expunctions in like circumstances or to review all decisions regarding expunction from minutes of dissent and the decision of the Speaker shall be final.

92. Documents to be presented along with report.—Along with the report of a Select/Joint Committee, the following documents shall also be presented to the House, namely:—

- (i) the minutes of the various sittings of the Select/Joint Committee;
- (ii) Government amendments, if any; and
- (iii) other important papers, if any, made available to the members of the Select/Joint Committee and approved by the Chairperson of the Committee for presentation to the House.

93. Printing and circulation of reports.—(1) As soon as the report of a Select/Joint Committee is presented to the House the report together with the following papers shall be printed and circulated to the members of the House, namely:—

- (a) notes and minutes of dissent, if any;
 - (b) the Bill as reported by the Select/Joint Committee;
 - (c) the minutes of the various sittings of the Select/Joint Committee;
 - (d) Government amendments, if any; and
 - (e) other important papers, if any, made available to members of the Select/Joint Committee.
- (2) The papers mentioned against items Nos. (c) to (e) may, where necessary, be printed separately.

COMMITTEE ON PETITIONS

94. Consideration petitions.—After the presentation of a petition to the House, the Committee on Petitions shall meet to consider it as early as possible:

Provided that in the case of a petition on a Bill pending before the House, it shall meet as soon as possible after it has been presented or reported to the House and submit its report to the House or direct the circulation of the petition to the members, as the case may be, well in advance of the Bill being taken up in the House:

Provided further that in the case of a petition received on a Bill already under discussion in the House, the Committee shall meet to consider it immediately on its presentation after its receipt and submit its report or direct the circulation of the petition to the members, as the case may be, well in advance of the Bill being disposed of by the House.

95. Consideration of representations etc.—The Committee shall also meet as often as necessary to consider representations, letters and telegrams from various individuals, associations etc., which are not covered by the rules relating to petitions, and give directions for their disposal:

Provided that representations, which fall in the following categories shall not be considered by the Committee, but shall be filed on receipt in the Secretariat:—

(i) anonymous letters or letters on which names and/or addresses of senders are not given or are illegible; and

(ii) endorsement copies of letters addressed to authorities other than the Speaker or House unless there is a specific request on such a copy praying for redress of the grievance.

96. Intimation to petitioner.—After the report has been presented, the petitioner shall be informed about it.

FINANCIAL COMMITTEES – COMMITTEE ON ESTIMATES,
COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS AND COMMITTEE ON
PUBLIC UNDERTAKINGS

⁴[96A *** *** ***]

97. Appointment of Chairpersons or members of Financial Committees as members of Government Committees.—(1) Whenever the Chairperson or any member of the Committee on Estimates or the Committee on Public Accounts or the Committee on Public Undertakings is invited to accept membership of any Committee constituted by Government the matter shall be placed before the Speaker before the appointment is accepted.

(2) Where the Speaker considers it inappropriate that the Chairperson or a member of the Committee on Estimates or the Committee on Public Accounts or the Committee on Public Undertakings should serve on the Committee constituted by Government so long as the Chairperson or the member remains a member of the Committee on Estimates or the Committee on Public Accounts or the Committee on Public Undertakings the latter shall not accept the appointment of membership of the Committee constituted by Government.

(3) Where in the interest of parliamentary work, the Speaker permits the Chairperson or a member of the

Committee on Estimates or the Committee on Public Accounts or the Committee on Public Undertakings, as the case may be, to accept the membership of a Committee constituted by Government, the Speaker may require that the report of the Government Committee shall be placed before the Committee on Estimates or the Committee on Public Accounts or the Committee on Public Undertakings, as the case may be, for such comments as the latter Committee may deem fit to make before it is presented to Government.

97A. Appointment of members of Government Committees as Chairpersons or members of Financial Committees.—(1) Whenever a member, who is a member of a Committee constituted by Government, is elected to the Committee on Estimates or the Committee on Public Accounts or the Committee on Public Undertakings, the matter shall be placed before the Speaker for deciding whether the member shall be permitted to continue with the membership of the former Committee.

(2) Where the Speaker considers it inappropriate that a member should continue to serve on the Government Committee on being elected to the Committee on Estimates or the Committee on Public Accounts or the Committee on Public Undertakings, as the case may be, the member shall, if so required by the Speaker, resign membership of the Committee constituted by Government.

(3) Where in the interest of parliamentary work, the Speaker permits a member elected to the Committee on Estimates or the Committee on Public Accounts or the Committee on Public Undertakings to continue to hold the membership of a Committee constituted by the Government, the Speaker may require that the report of the Government Committee shall be placed before the Committee on Estimates or the Committee on Public Accounts or the Committee on Public Undertakings, as the case may be, for such comments as the latter Committee may deem fit to make before it is presented to Government.

98. Examination of matters of policy by Estimates Committees.—(1) The term ‘policy’ referred to in clause (a) of rule 310 relates only to policies laid down by Parliament either by means of statutes or by specific resolutions passed by it from time to time.

(2) It shall be open to the Committee to examine any matter which may have been settled as a matter of policy by the Government in the discharge of its executive functions.

(3) With regard to clause (b) of rule 310 the Committee shall not go against the policy approved by Parliament; but where it is established on evidence that a particular policy is not leading to the expected or desired results or is leading to waste, it is the duty of the Committee to bring to the notice of the House that a change in policy is called for. The fundamental objectives of the Committee are economy, efficiency in administration and ensuring that money is well laid out; but, if on close examination, it is revealed that large sums are going to waste because a certain policy is

⁴Omitted by L.S. Bn. (II) dated 10.5.1989, para 2931.

followed, the Committee may point out the defects and give reasons for the change in the policy for the consideration of the House.

99. Ministers not to be called before Financial Committees.—(1) The Committee on Estimates or the Committee on Public Accounts or the Committee on Public Undertakings may call officials to give evidence in connection with the examination of the estimates and accounts, respectively, relating to a particular Ministry or Undertaking. But a Minister shall not be called before the Committee either to give evidence or for consultation in connection with the examination of estimates or accounts by the Committee.

(2) The Chairperson of the Committee may, however, when considered necessary but after its deliberations are concluded, have an informal talk with a Minister, the estimates or accounts of whose Ministry or undertaking were under consideration by the Committee in order to apprise the Minister of :

(a) any matters of policy laid down by a Ministry or undertaking with which the Committee do not fully agree; and

(b) any matters of secret and confidential nature which the Committee would not like to bring on record in their report.

(3) The Committee may reconsider its conclusions in the light of such talk but shall not otherwise pursue further any of the matters with the Minister after they are brought to the notice of the Minister concerned by the Chairperson.

100. Examination of representatives of private companies or non-Government bodies by Financial Committees.—⁵[Where the Committee on Estimates or the Committee on Public Accounts or the Committee on Public Undertakings] takes up examination of the working of an agreement entered into by the Government of India or a public undertaking with a private company or any other non-Government body, the Committee may, if it deems fit summon or give an opportunity to the representatives of the Company or the non-Government body, as the case may be, to appear before the Committee and to give evidence on any point arising therefrom on which the Committee might desire to have further information or the representatives desire to give elucidation.

101. Procedure for Estimates Committee examining estimates of Defence Ministry.—The following procedure shall be adopted by the Committee on Estimates in examining the estimates of the Ministry of Defence:

(i) A sub-Committee of the Committee on Estimates may be appointed under rule 263 (1) of the Rules of Procedure and entrusted with the task of examining the estimates of the Ministry of Defence.

(ii) The activities of the Defence Organisation on which the sub-Committee may concentrate or to which they

may limit their enquiries may be determined in advance by the Chairperson of the Committee.

(iii) The Chairperson of the Committee shall regulate the procedure and organization of the work of the sub-committee in such manner as the Chairperson may consider necessary.

(iv) The sub-Committee may call for information or hear officials or take any other evidence connected with the estimates under examination.

(v) (a) The usual conventions regarding 'secret' documents shall be observed by members of the sub-Committee.

(b) The discretion whether to reveal the contents of 'top secret' documents to the members shall be vested in the Chairperson of the Committee, who shall consider any submission that may be made in this regard by the Ministry of Defence. In case the Chairperson is unable to comply with the submissions of the Ministry, the matter shall be referred to the Speaker for guidance.

(c) The Chairperson of the Committee may determine whether in certain cases copies of 'secret' documents may not be distributed to members and only such copies may be made available for reference by members at a specified place in the Lok Sabha Secretariat.

(vi) Where Government decline to produce a document on the ground that its disclosure would be prejudicial to the safety or interest of the State, and in case of any doubt regarding the ground for not producing the documents, the Chairperson of the Committee may place such matter before the Speaker for guidance.

(vii) On completion of the examination of the estimates, the sub-Committee may arrive at conclusions and prepare such reports as they consider necessary.

(viii) (a) The Chairperson shall place the reports of the sub-Committee before the whole Committee for the consideration of the Committee:

Provided that such portions of the report of the sub-Committee as are considered by the Chairperson to deal with confidential matters, which it is not advisable to make public in the interest of security, may not be placed before the whole Committee but may be forwarded by the Chairperson to the Speaker.

(b) The Chairperson, may make available to the whole Committee such of the evidence and papers seen by the sub-Committee as the Chairperson thinks fit.

(ix) (a) Such portions of the report of the sub-Committee as are placed before the whole Committee under (viii) (a) above and are approved by the whole Committee shall be deemed to be the report of the whole Committee.

(b) Such portions of the report as are forwarded by the Chairperson to the Speaker under proviso to (viii) (a) above may not be treated as a report of the Committee but

⁵Sub. by L.S. Bn. (II) dated 10.5.1989, para 2931.

shall be treated as a special and *ad hoc* report from the Chairperson to the Speaker.

(c) The Speaker may, transmit such *ad hoc* report to Government in such manner as is considered fit and while doing so, inform the House of the fact of having sent the report to Government.

(x) The procedure for the adoption by the main Committee of the report of the sub-Committee, which the Chairperson may bring before the whole Committee, and for the presentation thereof to the House shall be governed by the existing rules.

101A. Procedure for Estimates Committee examining estimates relating to statutory and Government organizations not covered by Public Undertakings Committee.—The following procedure shall be adopted by the Committee on Estimates in examining the estimates relating to Statutory and Government organisations which do not come within the purview of the Committee on Public Undertakings:—

(i) A standing sub-Committee of the Committee on Estimates on Statutory and Government organisations may be appointed under rule 263(1) of the Rules of Procedure at the beginning of each year after the constitution of the Committee on Estimates.

(ii) The members of the sub-Committee shall be nominated by the Chairperson from amongst the members of the Committee.

(iii) The sub-Committee may call for information or hear officials or take any other evidence connected with the estimates of the Statutory or Government organisation under examination.

(iv) On completion of the examination of the estimates of a Statutory or Government organisation, the sub-Committee may arrive at conclusions and prepare such reports as they may consider necessary.

(v) The reports of the sub-Committee shall be placed before the Whole Committee for their consideration and approval.

(vi) The Chairperson of the Committee shall regulate the procedure and organisation of the work of the sub-Committee in such manner as the Chairperson may consider necessary.

NOTE:— If a question arises as to which statutory and Government organisations should come within the purview of the standing sub-Committee, it shall be referred to the Speaker whose decision shall be final.

102. [Action taken on recommendations of Estimates Committee or Committee on Public Accounts or Committees on public Undertaking.]—(1) Government shall as early as possible, after the presentation of the report of the Committee on Estimates ⁷[or the Committee on Public Accounts] or the Committee on Public Undertakings, furnish the Committee, in the first instance,

with a statement showing action taken on the recommendations contained in the report. The statement shall contain the views of Government on all the recommendations including those which are accepted by Government.

(2) As early as possible after the receipt of the replies, the Committee shall consider them and finalise their views as to whether the replies are acceptable to them or not. In respect of the replies to recommendations which are not accepted by Government, the Committee may express their own views, in case they do not accept the replies of Government.

⁸[Thereafter the Committee shall present further report to the House regarding the action taken on the original recommendations made by the Committee. The report shall consist of five Chapters as follows:—

- I. Report;
- II. Recommendations/Observations which have been accepted by Government;
- III. Recommendations/Observations which the Committee do not desire to pursue in view of Government's replies;
- IV. Recommendations/Observations in respect of which replies of Government have not been accepted by the Committee; and
- V. Recommendations/Observations in respect of which final replies of Government are still awaited.]

⁹[(3) Government shall, as early as possible, after the presentation of the Action Taken Report of the Committee on Estimates or the Committee on Public Accounts or the Committee on Public Undertakings, furnish statements of action taken or proposed to be taken by them on the recommendations contained in Chapter I and the final replies to the recommendations contained in Chapter V of the report. The replies so received shall be consolidated in the form of a statement and after the approval of the Chairperson, laid on the Table of the House.]

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

103. Functions.—(1) The Committee on Subordinate Legislation may examine all 'Orders', whether laid on the Table of the House or not, framed in pursuance of the provisions of the Constitution or a statute delegating power to a subordinate authority, to make such Orders.

(2) The Committee may examine provisions of Bills which seek to—

- (i) delegate powers to make 'Orders', or
- (ii) amend earlier Acts delegating such powers,

with a view to see whether suitable provisions for the laying of the 'Orders' on the Table of the House have been made therein.

(3) The Committee may examine any other matter relating to an 'Order' or any question of subordinate legislation arising therefrom.

⁶Sub. by L.S. Bn. (II) dated 10.5.1989, para 2931.

⁷Ins. by *ibid.*

⁸Sub. by *ibid.*

⁹Add. by L.S. Bn. (II) dated 10.5.1989, para 2931.

103A. Examination of Bills referred to Committee by Speaker.—(1) The Speaker may also refer Bills containing provisions for delegation of legislative powers to the Committee and where a Bill is so referred, the Committee shall examine —

- (i) the extent of such powers sought to be delegated; and
- (ii) where powers are sought to be delegated to State Governments or other authorities for bringing into operation any subsidiary provisions or to make any further rules or regulations, the necessity for such delegation as well as the extent and manner in which such powers shall be exercised by the subordinate authorities concerned.

(2) Where the Committee is of opinion that the provisions contained in the Bill delegating legislative powers should be annulled wholly or in part, or should be amended in any respect, it may report that opinion and the grounds thereof to the House before the Bill is taken up for consideration in the House.

104. Supply of documents by Ministries etc.— A Ministry or other authority may be required to supply, for the use of the Committee, a sufficient number of copies of the following documents, namely:—

- (i) Statutory and Constitutional ‘Orders’.
- (ii) Amendments to such ‘Orders’.
- (iii) Reprinted editions of such ‘Orders’ as and when they are re-printed.

105. Procedure for examination of Order, Bill, etc.—

(1) (i) After an ‘Order’ is published in the Gazette, it shall be examined by the Lok Sabha Secretariat to determine whether it is required to be brought to the notice of the Committee on any of the grounds laid down in rule 320, or in accordance with any practice or direction of the Committee.

(ii) After a Bill is introduced, or laid on the Table of the House, it shall be examined by the Lok Sabha Secretariat to determine whether it is required to be brought to the notice of the Committee on the ground laid down in the direction.

(2) If, in the course of examination of an ‘Order’, it is considered necessary to seek any clarification regarding any point, it shall be referred to the Ministry concerned and the matter, if necessary, re-examined in the light of such reply.

(3) If, after examination of an ‘Order’, a Bill or any other matter, it is considered necessary to bring any point or points to the notice of the Committee, a self-contained memorandum shall be prepared on the subject and, after the approval of the Chairperson, placed before the Committee.

106. Circulation of memoranda.— The approved memorandum together with copies or extracts of the relevant

‘Order’, wherever necessary, may, time permitting, be circulated to members of the Committee in advance.

107. Presentation of documents with reports.—

Along with the report, the following documents shall also be presented to the House:—

- (i) Summary of recommendations made in the report.
- (ii) Relevant portions of the minutes of the sittings at which the matters referred to in the report were considered.
- (iii) Such other material as may be considered necessary.

108. Action taken on recommendations of Committee.—

(1) The Ministries shall be required to furnish from time to time to the Lok Sabha Secretariat, statements of action taken or proposed to be taken by them on the recommendations made by the Committee in their reports and on the assurances given by the Ministries in the course of their correspondence with the Committee. The information so received shall be placed before the Committee in the form of a memorandum with the approval of the Chairperson.

(2) In cases where any Ministry is not in a position to implement, or feels any difficulty in giving effect to a recommendation made by the Committee, the Ministry shall place its views before the Committee which may, if it thinks fit, present a further report to the House after considering the views of the Ministry in the matter.

COMMITTEES AND OTHER BODIES CONSTITUTED BY
GOVERNMENT ON WHICH LOK SABHA
IS REPRESENTED

108A. Manner of election to Government Committees etc. on which Lok Sabha is represented.—

Where a motion adopted by the House provides for the election of members to a Committee, Commission or other body constituted by the Government (under the provisions of an Act or otherwise) in such manner as the Speaker may direct, the election shall, unless the Speaker otherwise directs, be held in accordance with the regulations made by the Speaker for holding of elections to Committees by means of the single transferable vote.

CHAPTER IX

GENERAL DIRECTIONS

NOTICES

¹[109 to * * * * 112]

113. Notices of amendments to Bills or resolutions.— Notices of amendments to a Bill or a resolution may be given by members in advance of the inclusion of the relevant item in the list of business. Such amendments shall be circulated to members on the day on which the relevant item is included in the list of business ²[or in the statement made by Minister of Parliamentary Affairs regarding Government Business for next week.]

¹Directions 109 to 112 omitted by L.S. Bn. (II) dated 19.4.1973.

113A. Lapsing of notices by member when appointed as Minister.— If a member, subsequent to giving notice in writing in respect of any matter under the rules, is appointed a Minister such notice shall be treated as having lapsed from the date of such appointment.

113B. Time limit for notices of certain categories.—

(1) Notices of adjournment motions calling attention to matters of urgent public importance, motions of no-confidence in the Council of Ministers, questions of privilege, or any other notice required to be given before the commencement of the sitting on the day on which the matter is proposed to be raised in the House, shall be given by 10.00 hours on that day.

Such notices, if received after 10.00 hours, shall be treated as notices given for the next sitting.

³[**113BB. Procedure for giving notices for motions under rule 184 or on short duration discussion under rule 193.**—(1) Notices of Motions under rule 184 and Short Duration Discussions under rule 193 shall be accepted from the date following the date of issue of summons for a session.

(2) Such notices regarding statements to be made in the House by Ministers or statements, reports or papers to be laid on the Table shall be accepted from 10.00 hours on the day the list of business wherein the item has been included, is circulated to members.

(3) In a case where a supplementary list of business is circulated in the House in regard to a statement, notices in respect of that statement, received within fifteen minutes of circulation of the list of business, shall be deemed to have been received at the same point of time and their *inter-se* priority determined by ballot.

(4) In a case where an announcement is made by the Chair about a statement to be made by a Minister in the House, notices in respect of that statement shall be accepted from the time the announcement is made by the Chair in the House.

(5) In a case where a statement is made without being included in the list of business or supplementary list of business, notices in respect of such statement shall be accepted from the time the statement is actually made in the House.

(6) All notices received within fifteen minutes of announcement by the Chair, or statement by the Minister under clauses (4) and (5) respectively, shall be deemed to have been received at the same point of time and their *inter-se* priority determined by ballot.

Explanation.—The period of fifteen minutes referred to in clauses (3) and (6) shall be computed from the time of completion of circulation of list of business or the announcement by the Chair or the statement of the Minister, as the case may be.]

MOTIONS AND SHORT DURATION DISCUSSIONS

113C. Limit on number of Motions and Short Duration Discussions by a member in a session.— Unless the Speaker otherwise directs, the No-Day-Yet-Named

Motions and Short Duration Discussions shall be arranged in such a way that no member moves or raises more than two of these during a session.

INFORMATION REGARDING ATTENDANCE OF MEMBERS
OR

EX-MEMBERS IN THE HOUSE

114. Information regarding attendance of members or ex-members.—(1) When a request is received from the member or ex-member for the supply of information regarding such member's attendance in the House on particular days or for a specified period according to the records of Lok Sabha Secretariat, the member or ex-member shall be asked to furnish the purpose for which the information is required.

(2) Each request shall be considered on merits.

(3) In case it is decided to comply with the request, it shall be indicated in the reply to the person concerned on which dates the member or ex-member had signed the attendance register.

MISTAKE OR INACCURACY IN STATEMENTS MADE
IN THE HOUSE

⁴[**114A. Procedure for Ministers correcting a mistake or inaccuracy in statements made in debate.**—

(1) A Minister wishing to correct a mistake or inaccuracy, in the information given by such Minister during a debate may make a statement in the House correcting such mistake or inaccuracy with the consent of the Speaker.

(2) The procedure for making such statement shall be *mutatis mutandis* the same as laid down in direction 16.]

115. Procedure for pointing out mistake or inaccuracy in statements made by Ministers or members.—(1) A member wishing to point out any mistake or inaccuracy in a statement made by a Minister or any other member shall, before referring to the matter in the House, write to the Speaker pointing out the particulars of the mistake or inaccuracy and seek the permission of the Speaker to raise the matter in the House.

(2) The member may place before the Speaker such evidence as that member may have in support of the allegation.

(3) The Speaker, if thinks fit, may bring the matter to the notice of the Minister or the member concerned for the purpose of ascertaining the factual position in regard to the allegation made.

(4) The Speaker, if thinks fit, may, permit the member who made the allegation to raise the matter in the House and the member so permitted shall, before making the statement, inform the Minister or the member concerned.

(5) The Minister or the member concerned may make a statement in reply with the permission of the Speaker and after having informed the other member concerned.

(6) The item regarding statement to be made by the member and the statement to be made by the Minister in reply thereto shall not be put down in the list of business unless copies thereof have been submitted in writing to

²⁻³Add. by L.S. Bn. (II) dated 10.5.1989, para 2931.

⁴Ins. by L.S. Bn. (II) dated 10.5.1989, para 2931.

the Speaker sufficiently in advance and the Speaker has approved them. Words, phrases and expressions which are not in the statements as approved by the Speaker, if spoken, shall not form part of the proceedings of the House.

METHODS FOR PARTICIPATION IN DEBATE

115A. Methods for participation in debate and selection of speakers.—(1) Any one of the following three methods may be adopted by members who desire to notify the Speaker of their intention to take part in a debate or discussion:—

- (a) The names of members who wish to participate in a particular debate or discussion may be supplied to the Speaker by the Parliamentary Parties or Groups.
- (b) A member who prefers to write direct to the Speaker may do so without having to go through the machinery of Parliamentary Party or Group.
- (c) A member who may not like to give one's own name to the Speaker through the Party or to write direct to the Speaker but wishes to adopt the well-known parliamentary practice of catching the Speaker's eye may stand in own seat whenever the member wishes to take part in a debate.

(2) Unless a member rises in own seat and catches the Speaker's eye, the member shall not be called upon by the Speaker to speak, irrespective of whether that member has sent one's own name through Party or Group to which the member belongs or has written direct to the Speaker.

(3) The Speaker shall not be bound by the lists or order in which names have been given by Parties or Groups or individuals directly. The lists shall be for the guidance of the Speaker only and it shall always be open to the Speaker to make changes whenever necessary in order that the debates are regulated in accordance with the general principles laid down by the Speaker from time to time.

⁵[(4) If a member speaks without being called by the Speaker to speak or continues to speak despite the directions of the Speaker to conclude the speech forthwith, the Speaker may direct that such speech or portions thereof, as the case may be, shall not form part of the proceedings of the House.]

⁶[SPEECHES IN LANGUAGES OTHER THAN HINDI OR ENGLISH]

115B. Procedure regarding speeches in languages other than Hindi or English.—(1) A member may make a speech in Lok Sabha in any of the following languages, namely, ^{6A}[Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu or Urdu] provided the member gives at least half-an-hour's notice to that effect to the officer at the Table in order to enable the Interpreter concerned to take position in the Interpreters' Booth. The Speech shall be simultaneously interpreted into Hindi and English.

⁵Add. by L.S. Bn. (II) dated 10.5.1989, para 2931.

⁶Sub. *Ibid.*

^{6A}Sub. by L.S. Bn. (II) dated 17.2.2014, para 6175.

The translation of the speech of that member in Hindi and English shall thereafter be prepared and printed in the official report of the proceedings of the House with a footnote indicating the language in which the original speech was delivered.

(2) A member desirous of making a speech in any language other than Hindi, English and the languages mentioned in clause (1) shall furnish to the officer at the table or the Parliamentary Notice Office, three authenticated copies of the translation of the speech of that member in Hindi or English in advance for use of the interpreters and later incorporation in the official report of the proceedings of the House:

Provided that where a member does not furnish such translation, the fact that the member spoke in a language other than Hindi or English or any of the languages mentioned in clause (1) shall be mentioned in the official report of the proceedings of the House with the remark that the member did not furnish the translation of the speech made in Hindi or English.

(3) A member or members (not more than two) in whose name(s) a question appears in the list of starred questions may ask supplementaries in any of the languages mentioned in clause (1) provided an advance notice in this regard is given not later than 3 P.M. on the working day preceding the day on which the question is listed for oral answer.]

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

115C. Personal explanation.—No member shall be permitted to make a statement by way of personal explanation under rule 357 unless a copy thereof has been submitted in writing by the member to the Speaker sufficiently in advance and the Speaker has approved it. Words, phrases and expressions which are not in the statement approved by the Speaker, if spoken, shall not form part of the proceedings of the House.

PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE

116. Entry in list of business.—(1) An entry shall be made in the list of business in respect of every paper or document which is received from a Minister duly authenticated for laying on the Table of the House.

(2) Papers received from Ministries shall generally be included in the agenda for laying on the Table after two days unless a specific date has been suggested by the Ministry concerned.

(3) Papers to be laid on the Table shall ordinarily be sent by Ministries two days in advance of the day on which the papers are proposed to be laid. In special circumstances, however, the Speaker may, on request, permit a Minister to lay a paper on the Table at shorter notice.

117. Laying of papers by private members.— A private member may lay a paper on the Table of the House when that member is authorised to do so by the Speaker.

118. Procedure for laying of papers by private members.— (1) If a private member desires to lay a paper or document on the Table of the House, the member shall supply a copy thereof to the Speaker in advance so as to enable the Speaker to decide whether permission should be given to lay the paper or document on the Table. If the Speaker permits the member to lay the paper or document on the Table, the member may at the appropriate time lay it on the Table.

⁷[(2) If a private member, in the course of making the speech wishes to quote from a secret Government document, paper or report, that member shall supply a copy thereof in advance to the Speaker and also indicate the portions thereof which the member wishes to quote in order to enable the Speaker to decide whether permission should be given. If the Speaker permits the member to quote from the document, the member may do so at the appropriate time. If the Speaker does not accord the necessary permission, the member shall not quote from the document nor refer to its contents.]

⁸[(3) (i) A paper or document sought to be laid on the Table by a private member may be considered for laying on the Table only if the member has quoted therefrom. The member seeking to lay the same may hand it over at the Table but it shall not be deemed to have been laid on the Table unless the Speaker, after examination, accords the necessary permission.]

(ii) If the Speaker does not accord the necessary permission, the paper or document shall be returned to the member and the fact indicated in the printed Debates.

[118A. Authentication of papers to be laid by private members.—(1) When a member seeks permission of the Speaker to lay a paper or document on the Table of the House under direction 118, that member shall record thereon a certificate in one of the following forms, as the case may be:—

(a) 'I certify from my personal knowledge that this is the original document which is authentic.'

(b) 'I certify from my personal knowledge that this document is a true copy of the original which is authentic.'

(c) 'I certify that the contents of this document are correct and based on authentic information.'

(2) If the paper or document consists of more than one page, the member shall put signature with date on every page thereof.]

STATEMENT BY MINISTER

119. Advance intimation and copy of statement by Minister.—A Minister desiring to make a statement in the

House under rule 372 shall intimate in advance the date on which the statement is proposed to be made and also send a copy of the statement to the Lok Sabha Secretariat for the information of the Speaker.

¹⁰[*Explanation.*— The statement shall pertain to a subject for which the Minister is responsible and shall be made to explain Government's policy in regard to a specific matter of public importance or topical interest.]

RECOGNITION OF AND FACILITIES TO PARLIAMENTARY PARTIES AND GROUPS

120. Recognition of Party or Group.— The Speaker may recognise an association of members as a Parliamentary Party or Group for the purpose of functioning in the House and the decision of the Speaker shall be final.

121. Conditions for recognition.—In recognising a Parliamentary Party or Group the Speaker shall take into consideration the following principles:—

(i) An association of members who propose to form a Parliamentary Party—

(a) shall have announced at the time of the general elections a distinct ideology and programme of Parliamentary work on which they have been returned to the House;

(b) shall have an organisation both inside and outside the House; and

(c) shall have at least a strength equal to the quorum fixed to constitute a sitting of the House, that is one-tenth of the total number of members of the House.

(2) An association of members to form a Parliamentary Group shall satisfy the conditions specified in parts (a) and (b) of clause (i) and shall have at least a strength of 30 members.

122. Facilities to Parties and Groups.—(1) The Speaker may grant the following facilities to a Party in the House, namely:—

(a) Allotment of blocks of seats in the House in proportion to the strength of the Party and the total number of seats available in the Chamber.

(b) Allotment of a room in the Parliament House for the purposes of Parliamentary work of the Party.

(c) Allotment of Committee rooms or other available accommodation for holding Party meetings.

(d) Supply of Parliamentary or Government papers or publications which the Speaker may determine from time to time.

(e) Nomination to a Parliamentary Committee in proportion to the strength of the Party.

⁷Sub. by L.S. Bn. (II) dated 10.5.1989, para 2931.

⁸Ins. by *ibid.*

⁹Ins. by L.S. Bn. (II) dated 9.5.1983, para 2175.

¹⁰Added by L.S. Bn. (II) dated 10.5.1989, para 2931.

- (f) Submission to the Speaker of a panel of names for selection of members to be called to speak in debates.
- (g) Consultation, where necessary, in the matter of arrangement of business of the House or any other important matter coming before the House.

(2) The Speaker may grant such of the facilities, specified in this direction as the Speaker deems fit or feasible to a Parliamentary Group.

(3) The Speaker's decision in regard to the grant of facilities to a Parliamentary Party or Group shall be final.

123. Certain facilities to association of members not recognized as Party or Group.—An association of members who do not fulfil the conditions for recognition as a Parliamentary Party or Group may be granted certain facilities by the Speaker, if such a course shall, in the opinion of the Speaker, facilitate the conduct of business in the House.

PRECINCTS OF THE HOUSE AND PARLIAMENT HOUSE ESTATE

124. Precincts of the House and Parliament House Estate.—The term 'precincts of the House' or 'precincts of the Parliament House' used in the Rules shall, except for the purposes of rule 374, include in addition to places specified in rule 2, the following places in Parliament House Estate:—

- (i) The Central Hall and its Lobbies;
- (ii) Members' Waiting Rooms;
- (iii) Committee Rooms;
- (iv) Parliament Library;
- (v) Members' Refreshment Rooms, Dining Rooms and Banquet Hall;
- (vi) Lok Sabha Offices located in Parliament House, Parliament House Annexe and Outer Reception Offices of Parliament House and Parliament House Annexe;
- (vii) Corridors and passages connecting or leading to the various rooms referred to above; and
- (viii) Parliament House Estate and approaches to the Parliament House and Parliament House Annexe.

Explanation.—'Parliament House Estate' includes —

(a) all buildings, structures, installations, lawns and vacant land adjoining Parliament House, Parliament House Annexe and Outer Reception Office; and

(b) plot No. 118 (between Red Cross Road, Raisina Road and Parliament House) and plot No. 115 (between Talkatora Road, Pant Marg and Parliament House),

Which are under the control of the Speaker.

124A. Maintenance of order within Parliament House Estate.—(1) The ¹¹[Director, Security] of Lok Sabha

shall be responsible for maintaining order within the compound of the Parliament House Estate and shall take all necessary steps to ensure that no obstruction or hindrance is caused to Members of Parliament in that area, in coming to, or going from, the Parliament House.

(2) In order to keep the area and passages within the Parliament House Estate free and open for Members of Parliament without any obstruction or hindrance, the following activities are prohibited within the area of the Parliament House Estate:—

- (i) holding of any public meeting;
- (ii) assembly of five or more persons;
- (iii) carrying of fire arms, banners, placards, lathies, spears, swords, sticks, brickbats;
- (iv) shouting of slogans;
- (v) making of speeches etc.;
- (vi) processions or demonstrations;
- (vii) picketing or dharna;
- (viii) any other activity or conduct which may cause or tend to cause any obstruction or hindrance to Members of Parliament.

(3) the ¹²[Director, Security] of Lok Sabha may, subject to the instructions or permission of the Speaker, request the police for assistance in maintaining order in the Parliament House Estate, as and when considered necessary.

PAPERS AND DOCUMENTS RECEIVED FROM MINISTRIES
ETC.

FOR CIRCULATION TO MEMBERS

125. Treatment of papers and documents received from Ministries etc. for circulation to members.—(1) The Lok Sabha Secretariat may circulate to members either at their residence or through the Publications Counter papers, documents and reports received for circulation to members from the Ministries and Departments of the Government of India:

Provided that the Lok Sabha Secretariat shall not undertake circulation of a paper, document or report marked 'Confidential' or 'Secret', unless it is meant for the members of a Parliamentary Committee and is connected with their business:

Provided further that the Speaker, if thinks fit, may direct that a paper, document or report forwarded to the Lok Sabha Secretariat for circulation to members may not be circulated.

Explanation.—For the purposes of this direction, the expression 'paper' includes invitations received from the President, Prime Minister, Ministers and Ministries of the Government of India for circulation to members to attend any function organised by them.

¹¹Sub. by L.S. Bn. (II) dated 10.12.1987, para 2005.

¹²*Ibid.*

(2) The Lok Sabha Secretariat shall not undertake circulation of any paper, document, report or other material received direct from:

- (a) State Governments;
- (b) Foreign Missions;
- (c) Private bodies or individuals; and
- (d) Members of Parliament, unless the papers received from them are connected with the business of the House.

FIRST SCHEDULE

[See Direction No. 38 (1)]

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 20

From

(Name and designation)

Lok Sabha Secretariat

New Delhi.

To

Smt./Kumari/Shri.....

Subject:—

Madam/Sir,

I am directed to acknowledge receipt of your petition dated the on the above mentioned subject.

Yours faithfully,

SECOND SCHEDULE

[See Direction No. 84]

Introductory Paragraphs of a Select/ Joint Committee Report

I, the Chairperson of the Select/Joint Committee to which the *Bill..... (here insert the long title of the Bill) was referred, having been authorised to submit the report on their behalf, present their Report, with the Bill as amended by the Committee annexed thereto.

2. The Bill was introduced in the Lok Sabha on the (date). The motion for reference of the Bill to a Select/Joint Committee of the Houses (motion to be given as appendix to the Report) was moved by Smt./Kumari/Shri..... (name) on the (date).

3. The Rajya Sabha discussed the motion on the (dates) and concurred in the said motion on the (date) (motion to be given as appendix to the Report).

4. The Message from Rajya Sabha was read out to the Lok Sabha on the (date).

5. The Committee held..... (number) sittings in all.

6. The first sitting of the Committee was held on the..... (date) to draw up a programme of work. The Committee at this sitting decided to hear evidence of associations which might make a request to that effect by the..... (dates). The Committee also decided to visit..... (place) on the (dates) in order to..... (purpose of visit).

7. The Committee accordingly visited..... (centres visited) on the (dates).

8. The Committee heard the evidence given by the representatives of the following association on the dates noted against each:—

(1)

(2)

etc. etc.

A summary of evidence given is appended to this Report (the Committee decided to lay on the Table of the House a copy of the evidence given in extenso).

9. The Committee considered the Bill clause by clause at the sitting held on the..... (dates).

10. The Committee appointed on the (date) a sub- Committee consisting of (number) members to consider..... (object). The Report of the Sub-Committee was presented to the Committee on the (date) (Report to be given as appendix).

11. The Report of the Select/Joint Committee was to be presented by the (date). The Committee were granted extension of time on the..... (date), upto the..... (date) (in the case of two or more extensions). The Committee were granted extension of time..... (twice or thrice etc.), the first time on the (date) upto the..... (date), and subsequently on the (date) upto the (date).

12. The Committee considered and adopted the Report on the (date).

13. The observations of the Committee with regard to the principal changes proposed in the Bill are detailed in the succeeding paragraphs.

P. SREEDHARAN, Secretary General.

* Published in Part II, Section 2 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the.....